

्राहर के दार का क्षेत्र का प्रकार के कि का कि कि का क

्रावेश में केश्यात के वातासामा है कि पूर्व एक्टाक्स के विकार देख की प्रमुख की वात्र के व्यवसाद की केश्यात मूक की प्रथम है कीप कहा है अध्यातमानी प्रभम्पता के वीचा अवस्था के वीचा वातास्था है क्षेत्र की वीचा वातास्था के वीची की विवयस प्रभावती का को क्षेत्र स्वायस वीची की विवयस प्रथम नवादी केश का वातास वीची !

હોલ જન્મણ છે ખાવના એ પ્રેમિય પક પ્રજ પાકનો છે સામદે પણ મેલા હોઇન્ડ્રેમ અથવા છે એ નવેલા વૈદ્યાલિક પોર વિજયવદીલ છે !

हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेषगा

लेखक केशवप्रसाद शर्मा

किता व महल उलाहाबाद • वन्वई

प्रथम संस्करण, १६४६

प्रकाशक—ंकताव महल, ४६-ए, जीरो रोड, इलाहाबाद मुद्रक—केसरवानी प्रेस, इलाहाबाद

समर्पित:--

हिन्दुस्तान के महात्मा मोहनदास कर्मचन्द गांधी श्रीर पाकिस्तान के कायदे श्राजम मोहम्मद श्राती जिचा को जो श्रय इस संसार में नहीं हैं।

-केशवपसाद शर्मा

पाठकों मे

हेश की ब्याजादी की वेदी पर हजारों क्रान्तिकारियों ने अपने प्राम् निञ्जाबर किये। लाखों वर्षों तक साम्राज्यशाही यूनियन जे ह के जेतों में मड़ते रहे। उन साथियों जैसा मैं भी वर्षा तक यूनियन जैक के नीचे जेलों में जीवन व्यतीत करता रहा। पूँजीवादी राष्ट्रीय विरंगे सरकार के नैनी सेन्ट्रल जेल में सन् १६४७ ई० के ऐतिहासिक १४ द्यास्त के उपरान्त महीनों तक भैंने जीवन व्यतीत किया। रान् १६४२ ई० की ऐतिहासिक च्यगस्त क्रान्ति और नेताजी के नेतृत्य में आजाद हिन्द फौज के सराध्य आक्रमण में जनना का क्रान्तिकारी मोर्चा विकसित हो रहा था। उसे अनुभवकर भारतीय तथा ब्रिटिश पूँजीवादी बरी दहल उठा। धाँठ-गाँउ की चालं उसके बीच होने लगी। भारतीय जनता के आध विश्वासवातकर भारतीय पुँजीवादी वर्ग और ब्रिटिश गामाज्यवाद के वीच समभौता हो गया। तिरंगे और दोरंगे के तीचे केन्द्र में अर्ध-राष्ट्रीय सरकार गठित की गई। परन्तु भारतीय पूँजीवादी वर्ग की आन्तरिक श्रसंगतियाँ दूर न हो सकीं, बल्कि ये और भी अवल हो उठीं। मुस्लिम पूँजीवित विना पाकिस्तान की स्थापना के चन्तुष्ट होने को नहीं थे। साम्प्रदाधिकता के विष् पैदाकर वे साम्प्रदासिक दंगों को सान्त्रदायिक युद्ध का रूप देने में व्यस्त हो गये। इसके मयानक क्व देखकर ब्रिटिश साम्राज्यशाही तथा भारतीय पूँजीवादी सुवारवादी नेतृत्व ने देश को साम्प्रदायिकता के श्राधार पर हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की स्थापना करने का निश्चय किया और इसकी घोपणा ३ जून, सन् १६४० ई० को ब्रिटिश साम्राज्यशाही की खोर से की गई।

इसका प्रभाव देश में अच्छा नहीं पड़ा। इससे साम्प्रदायिक युद्ध वन्द नहीं हो सका विलक चौर भी विकाल रूप इसने धारण किया। ना० २८-४-४७ से ही क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी की श्रोर से प्रान्तीय राजनीतिक शिक्षण शिविर शाहरण-पर जिला के नरसन कला गाँव में चल रहा था। इसके सामने से मुजफ्फरनगर-कड़की रोड जाती है। वहाँ प्रान्त के विभिन्न जिलों से काय-कर्त्ता आये हुए थे। आर० एस० पी० के जिला मन्त्री साथी मुकुन्दसिंह जी, वैद्य, का गाँव करीब ११ मील पर था। ता० १४-६-४० के लिये उन्होंने अपने यहाँ निमन्त्रित किया और श्रपने गाँव जरीदाजट और देवन्द के श्रास-रास कई स्थानों में सभा की श्रायोजना की थी। वहाँ पैदल ही जाना था। शाय को क्यान खत्म होने के बाद करीब २६ साथियों ने मना पाँच बजे वहाँ के लिखे प्रस्थान किया। यहाँ यह उल्लेख करना अन्यित न होगा कि पश्चिमी पंजाब में लाम्प्रदायिक युद्ध खूब जोरों पर था। उधर से काफी हिन्द-सिख आगहर यू० पी० के पश्चिमी जिलों में. विशेषतः शाहरणपुर जिले में आये थे। इसके कारण जवर की परि-स्थिति बहुत भयानक हो उठी थी, जिसका अन्दाजा हम नहीं कर पाये थे। पाँच ई मील चलने के बाद एक खाश्री के आयह करने पर उसके गाँव में हम सब तक गय और शर्बत पीने लगे। जब वहाँ से चर्ततो काफी अपन्यकार हो चुका था। इस यहाँ यह कहना असंगत नहीं समकते कि हम सब जुल्स के कप में जा रहे थे और पार्टी के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। शर्यंत पीने के बाद उस गाँउ में भी नारे लगे। बहाँ से दो-नोन फर्नाङ्ग पर ही मुमलमानों का एक छोटा गाँव पैरोली है।

नारे सुनकर वहाँ के मुसलमानों ने समभा कि हिन्दू उस गाँव के ऊपर आक्रमण करने आ रहे हैं। उसके आस-पास तीन-चार बड़े गाँव मुसलमानों के दें। परोली के सुमलमानों ने नारे की श्रावाज सुनते ही उन गाँव में श्रादमी भेज दिया कि हिन्दू उनके गाँवों पर आक्रमण कर रहे हैं। इधर हम इनसे एकदम अनिमञ्ज थे। पैरीली गाँव के पाल पहुँचन पर हमने नारे लगाये और आगे बढ़ते गये। कुछ दूर जाने पर आगे के गाँव से बहुत जोरों का हज़ा सुनाई दिया। मैंने साथियों को रुकने को कहा । चौर भी स्पष्टतः सुनने में आया और बात हुआ कि धाल्ला-हो-अक्षवर का नाग लगाते हुये वे गाँव के बाहर आ रहे थे। पोछे लौटने की मैंन साथियों की करा और हम पीके लोटे। पंीर्ला गाँव के पास आने पर तीन-चार आदमी खड़े भिले। उन लोगों ने कहा कि श्राप लोग क्यों जाँदे जा रहे हैं ? आप लोगों से क्या सतलब ? उन लोगों से वातें करने के बाद आगे आप लोग चले जायेंगे ।" भैंने यह सनकर साथियों को उहरंने को कहा। इतने ही में यहाँ तीस-चालिस आदमी पहुँचे। मैंने उनसे वाने की। उन लोगों ने कहा कि हम उनके गाँव से आगे चले जायेंगे। उनके साथ हम चले। में घपने साथियों के आगे-आगे चल गहा था। कुछ दूर जाने के बाद तीन-चार सी ऋादमी चलम, वर्छी, तलबार इत्यादि के नाथ आ गये और हमला कर दिया। सर्वप्रथम मेरे ऊपर आक्रमण हुया। चार लाठी सेरे सिर में लगी और मेरा सिर फट गया, मैं गिर गया । इस पर आठ-नव लाठी और लगी। मेरे सारे कपड़े खून से तर-वतर हो गये। साथी मन-भरसिंह, [आजाद हिन्द फौज का कप्तान] साथी, जबदेव

आजाद (बदाऊँ) साथी श्यामसुन्दर दृत्त (कलकत्ता) श्रीर में बुरी तरह घायल हुआ। तीन-चार सी की भीड़ में दस साथी इधर-उधर हो गरे। याकी हम १६ साथियों को वे साँपले गाँव में प इकर ते गये। वहाँ रस्ती से एक साथ ही हम सर्वो को याँवकर भूमे के घर में बन्द कर दिया। अन्त में उन्होंने यह निर्ण्य िया कि हम सब को दुकड़े-दुकड़े करके गाड़ दिया जाय। करल करने के लिये नंगी तलवार लेकर बहुत से लोग रीयार हो गये। भैंने उनसे कहा था कि "जो आप लागों में दो-तीन समभदार हैं, इनसे मैं दो-चार वातें कहाँगा उसके बाद आप लोग जो बाहें करें।" याँवने के समय मैंने यह अनुभव किया था कि दो-तीन श्रादमी उनमें कुछ अच्छे जात होते थे। सैंन उन कोगों को बुलाकर कुछ देर तक बालें की। मैंने जन्हें बतलाचा कि क्रान्तिकारा सभाजवादी पार्टी क्या चाहती है। क्रान्तिकारी समाजवाद क्या है ? हमसे न कांग्रेस से मतलब न सुस्लिम लीग से । हम न हिन्दू जानते और न मुसलमान । इस तो गरीव और अधीर को ही जानते हैं। इस गरीबी और अभीरी के खिलाफ लड़ रहे हैं! मेरी वातीं का काफी असर उनके ऊपर हुआ। उन लोगों ने और लोगों सं बातंं की और अन्त सें उन लोगों ने अपने निर्णय को पलट दिया। हम खोल दिवे गये और वर से बाहर निकाले गये। यहाँ यह कहना घमंगत न होगा हि एक चए। के लिये भी साम्प्रदायिकता की साबना से मेरा विचार कतुपित नहीं हुआ था। घर से निकालकर उन लोगों ने हमसे कहा कि अब हम जा सकते हैं। मैंने कहा कि इस रात में यहीं रहेंगे और सुबह मीटिंग करके हम जायेंगे । उन लोगों ने खाने का प्रबन्ध

किया। मालिश के लिये तेल लाये। सबसे ताब्जुब की बात यह थी कि जो लोग कत्ल करने के लिये तलवार निकालकर खड़े थे, वे पचास-साठ हाथ जोड़कर खड़े हो गये और चमा माँगी। यह थी क्रान्तिकारी समाजवाद की विजय।

सुबह होते ही हम हाथ-मुँह धोकर तैयार हो गये। इतने ही में देवन्द की पुलिस का धमकी। उनके साथ हम भी चले। चलने के समय गाँव वालों ने हमें दूध पिलाकर विदा किया। पुलिस के आते ही मैंने स्पष्टतः कह दिया था कि किसी को किसी प्रकार तंन न करों और न कोई निरफ्तार किया जायेगा और न किसी पर किसी प्रकार का गुरुदमा ही चलाया जायेगा। इसके बाद और अधिकारियों से बातें हुई। मैंने उनसे साफ-साफ कह दिया कि मैं मुकदमा नहीं चलाऊँगा। आज परिस्थित बहुत खराब है। छोटी गलती से हजारों आदिमयों की जान जा सकती है। युकदमा वगैरह से परिस्थित सँमलेगी नहीं बिलक और भी खराब होगी।

यहाँ यह उल्लेख करना में आवश्यक समभता हूँ कि भूसे के घर से हम वाहर निकाले गये और रोटी और शकर खाये। खाने के बाद साथी सब सो गये। परन्तु मुके दर्द के मारे नींद नहीं आई। लेकिन दिमाग तीज गति से काम कर रहा था। यह सोचने में मैं सारे दर्द को भूलता गया कि "आज साम्प्रदायिकता चरम सीमा पर पहुँच रही है। इसके कारण साम्प्रदायिकता के आधार पर पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की स्थापना की घाषणा की गई है। गुलामी और शोषण के खिलाफ श्रमिक शोषित जनता की लड़ाई के लिये यह भी घातक होगी। इससे जनता को आगाह करना आवश्यक है।"

उस समय यह विचार हुन्ना कि इस विषय पर मैं एक पुस्तक लिखूँ। परन्तु पार्टी संगठन कार्य में संलग्न होने के कारण सर्वदा समय का त्रमाव रहा। जिसके कारण नरसन कला में उदय हुए विचार को कार्योन्वित मैं नहीं कर सका था।

सन् १६४७ ई० का ऐतिहासिक १४ अगस्त आया। भारत-वर्ष विभाजित तथा आजाद घोषित किया गया। परन्तु विभा-जित भारत में आजादी का स्थान बरवादी तथा तवाही ले रही थी। देश भर में साम्प्रदायिक युद्ध ने भयानक रूप धारण किया और अपनी वास्तविकता से सामाजिक जीवन को हक जिया। फिर तो मानवता का नाम लोप होन लगा। किसी प्रकार बह वश में किया गया। परिस्थिति कुछ कायू में चाई। इसके विष में श्रपने जीवन को कलुपितकर श्रमिक शोपित जनता कुछ काल के लिये यह भूल गई कि अभी भी पूँजीवादी गुलामी श्रीर शोपण में जीवन व्यतीत करने के लिये वे बाध्य होती हैं। कुछ देर में उन्हें होश हुई जीर कान्तिकारी समाजवादी पार्टी के लाल मंडे के नीचे संगठित हो जहाँ तहाँ वे वर्ग संघर्ष का संचालन करने लगी । इसके अस्तित्व को अनुभवकर पूँजीवादी वर्ग तथा सरकार खतरा महसूस करने लगा। फिर क्या था ? सन् १६४७ ई० के जितम्बर महीने के छान्त से पूँजीवादी सरकार का आक्रमण क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी पर प्रारम्भ हो गया। बहुत से किसान, मजदूर, फ्रान्तिकारी समाजवादी कार्य-कर्त्ता जेलों में यन्द किये जाने लगे। मैं भी सन् १६४८ ई० के जनवरी में इलाहाबाद में गिरफ्तार किया गया और नैनी सेन्ट्रेल जेल में नजरवन्द ६ महीने तक रखा गया। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिये दमन का पूँजीवादी

सरकार काफी नहीं सममी । इसके ऋतिरिक्त साम्प्रदायिक भावनों को जीवित रखने का प्रयास यह करने लगी। यह नारा बुलन्द किया जाने लगा कि पाकि तान हिन्दुस्तान पर हमला करके हिन्दुस्तान को गुलाम बनाना चाहना है। इससे साम्प्र-दायिक भावनाएँ और भी उत्जित हुई।

दिन प्रतिदिन साम्प्रदायिकता और भी तीव हो उठने लगी। इसकी वेदी पर महात्मा गांधी की बाल चढ़ाई गई। यह थी इसकी चरम सीमा। महात्मा गांधी की मृत्यु की खवर मैंने नेनी सेन्ट्रेल जेल के सेल में सुनी थी। उस समय मैं तिरंगी सरकार के जेल में दुर्व्यवहार के खिलाफ भूख इड़ताल का रहा था। मैं सोचने लगा कि साम्प्रदायिकता हमें कहाँ ले जा रही है। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की स्थापना भी साम्प्रदायिक समस्याओं का इल नहीं कर सकी। बल्कि और भी इसने जटिल बना दिया है। मैं अनशन के समय तथा उसके बाद सोचने लगा कि इसका वास्तविक समाधान कहाँ है ? मैं इस परिसाम पर पहुँचा कि इसके लिये इसका ऐति-हासिक विश्लेपण करना आवश्यक है। उसके वाद ही हम इसका हल निकाल सकेंगे। इसके परिणाय-स्वरूप मैंने पाठकों के सामने "पाकिस्तान श्रीर हिन्दुस्तान का ऐतिहासिक विश्लेषण्" पुस्तक के रूप में रखा है। में आशा करता हूँ कि पाठकगण इसे अध्ययन करेंगे और क्रान्तिकारी समाजवाद के असार में सहायक होगे।

देवरा, — केशतप्रसाद शर्मा गया (विहार) मन्त्री—क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी ता० २२-१२-४८

विषय-सूची

| | | | ã8 |
|-------------|--|-------|-----|
| ₹. | वर्तमान भारतवर्ष "" | *** | \$ |
| ₹. | जनता की क्रान्तिकारी मनोष्टत्ति | | १५ |
| ₹. | प्रथम साम्राज्यवादी युद्ध ''' | • • • | 38 |
| 8. | "राष्ट्रीय मुस्तिम-दल" की स्थापना | | ¥8. |
| Ż. | स्लाव जातियों का पानस्लामिडम का नारा | | 60 |
| ε, | हिन्दू-मुस्लिम सगमोते के प्रयत्न | • • • | १०२ |
| O, | जापान और कांग्रेस का "भारत छोड़ो" प्रस्त | वि '' | १३४ |
| 즉. | देसाई-लियाकत पैक्ट | | १४३ |
| 3 | श्चन्तःकालीन सरकार की स्थापना | * * * | १८३ |
| १ 0. | उपसंहार | * * * | २२६ |
| | | | |

वर्तमान-भारतवर्ष

श्राज भारतीय श्रमिक शोषित जनता की गुलामी श्रोर शोषण के खिलाफ श्राजादी की लड़ाई विकट भौतिक परिस्थिति से होकर गुजर रही है। ता० १४-८-४७ को राष्ट्रीय और अन्त-र्राष्ट्रीय परिस्थिति से लाचार होकर बिटिश साम्राज्यवादी सरकार ने भारतीयों के हाथों में शासन की बागडोर सौंप दी। परन्तु श्राजाद हिन्दुस्तान संयुक्त भारतवर्ष के रूप में कार्यम नहीं रहा। साम्प्रदायिक श्राधार पर भारतवर्ष का विभाजन होकर पाकिस्तान श्रोर हिन्दुस्तान कार्यम किया गया।

हिन्दुस्तान श्रीर पाकिस्तान की स्थापना के उपरीन्त भी हिन्दू श्रीर मुस्लिम की समस्या हल नहीं हो सकी। विलक इसमें श्रीर भी भयानक रूप प्रह्ण कर लिया है। साम्प्रदायिकता के श्राधार पर भारतवर्ष के विभाजन के परिणामस्वरूप श्राज भारतीय शोषित श्रमिक जनता वँटी हुई है। इनके श्रन्दर साम्प्रदायिक विचार कूट-सूटकर भर गया है। वह श्राज भूल रहे हैं कि वह श्रभी भी शोषण की चक्की में पिसे जा रहे हैं। दूसरे साम्प्रवादी युद्ध के उपरान्त पूँजीवादी संसार श्रार्थिक

संकट का बुरी तरह शिकार हो रहा है। प्रत्येक मुल्क में पूँजीवाद तथा पूँजीवादी वर्ग का श्रस्तत्व संकट से विरा हुआ है। प्रत्येक देश का पूँजीवादी वर्ग अपने अपने छंग से अपने अस्तित्व की रहा करने का प्रयास कर रहा है। हिन्दुस्ता । अगेर पाकिस्तान के पूँजीवादी वर्ग का अस्तित्व भी खतरे से खाली नहीं है। सदियों से ब्रिटिश पूँजीवादी-सामाज्यवादी शोषण के परिणामस्वरूप भारतीय जनता की भौतिक श्रवस्था यों ही असहनीय हो उठी थी। इसके श्रातिरिक्त साम्राज्यवादी युद्ध के फलस्वरूप और भी खराब हो गई है। पूँजीवाद तथा पूँजीवादी व्यवस्था के खिलाफ बगावत की अग्नि शोषित जनता के श्रन्दर सुलग रही है। श्राज हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का पूँजीवादी वर्ग जी जान से भारतीय शोषित जनता की बगावत की श्रान्त को ठंडा करने का प्रयत्न कर रहा है। प्रथम प्रयास इसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ गँठवन्धन करके किया है। साथ ही साथ यह भारतीय प्रतिक्रियावादी सामन्तशाहियों के साथ सममौता करके कर रहा है।

तीसरा सबसे बड़ा श्रीर प्रवतशाली उपाय—भारतीय जनता को साम्प्रदायिकता के श्राधार पर विभाजित करके उनकी संयुक्त कान्तकारी शक्ति को नष्ट करके श्रपने श्रास्तत्व की रज्ञा करने को कोशिश भारतीय पूँजीवादी वर्ग कर रहा है। पाकिस्तान श्रीर हिन्दुस्तान में भारतीय जनता के विभाजन के उपरान्त भी इनका संकट नहीं दूर हो पाया; बल्कि दिन प्रतिदिन श्रार्थिक संकट के साथ भयानक होता जा रहा है। श्राज इस संकट से श्रपने को सुरिच्त रखने के लिये हिन्दुस्तान में यह प्रचार जोरों से किया जा रहा है कि किसी भी समय पाकिस्तान

हिन्दुम्तान पर आक्रमण कर सकता है। अत: इस खतरे को हमेशा के लिये खत्म करने के लिये यह आवश्यक है कि पाकि-स्तान पर हमलाकर हिन्दुस्तान में मिला लिया जाये श्रीर श्रखण्ड श्रविभाजित भारतवर्ष की स्थापना की जाये। दूसरी स्त्रोर पाकिस्तान में यह प्रचार किया जाता है कि हिन्द्स्तान पाकिस्तान को ध्वंसकर हिन्दुस्तान में शामिलकर हिन्दुओं का राज्य कायम करना चाहता है। ऋतः हिन्दु यों की गुलामी से बचने के लिये यह आवश्यक है कि पाकिस्तान हिन्दुस्तान के ऊपर आक्रमण करके पाकिस्तान में सिम्मलित कर ले। श्चतः इस प्रकार भारतीय शोधित अभिक जनता को पूँजीवादी शोपण और गुलामी के खिलाफ मुक्ति की लड़ाई से अलग रखने का प्रयत्न भारतीय पूँजीवादी वर्ग कर रहा है। कुछ हद तक इसे सफलता भी प्राप्त हुई है, जो श्रमिक शोषित जनता की आजादी की लड़ाई के लिये घातक है। मानव समाज के इतिहास के अध्ययन से यह स्पष्टतः ज्ञात होता है कि भारतीय समाज के सामाजिक-स्राधिक जीवन के विकास तथा प्रगति छोर समाजवादी समाज के विकास के लिये संयुक्त भारतवर्ष श्रातिश्रावश्यक है। परन्तु श्राज तो भारतवर्ष साम्प्रदायिक श्राधार पर पाकिस्तान श्रीर हिन्दुस्तान में बँटा हुश्रा है। फिर किस प्रकार विभाजित भारतवर्ष संयुक्त भारतवर्ष में विकसित हो सकता है। यह प्रश्न आज भारतीय समाज के सामने महत्वपूर्ण है। अतः इसका हल निकालने के लिये यह आव-रयक है कि यह हम देखें कि आखिर यह विभाजित ही क्यों हुआ। इसके तथा सही इल हासिल करने के लिये भी यह श्रावश्यक है कि वर्तमान भौतिक परिस्थिति के श्रातिरिक्त श्राजादी की लड़ाई के तथा पाकिस्तान की स्थापना के इतिहास का सिंहावलोकन करें और ऐसा करके ही हम सही साधन तक पहुँच सकेंगे और इसके द्वारा शोषित श्रीमक जनता के संयुक्त भारतवर्ष को विकसित कर पायेंगे।

१६वीं सदी के प्रारम्भ का राष्ट्रीय आन्दोलन

जब से जनता गुलामी की बेड़ी में जकड़ी जाती है, तभी से उसकी मुक्ति की भी लड़ाई प्रारम्भ होती है। यह महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नियम हिन्दुस्तान के उत्पर भी लागू होता है। गुलामी के साथ-साथ आजादी की लड़ाई का भी श्रीगरोश हो गया था। संसार में सर्वप्रथम पूँजीवाद का विकास ब्रिटेन में हुआ। पूँजीवाद के विकास के साथ-साथ ब्रिटेन पिछड़े हुए देशों के ऊपर अपना प्रभुत्व कायम करने का प्रयत्न सदियों तक करता रहा । इसके परिणाम स्वरूप १६वीं सदी के आरम्भ तक खंश्रेजों ने अरव के मुल्कों की आजादी हड़प उन्हें अपने साम्राज्यवादी पंजों में मजवूती से जकड़ तिया था। उक्त महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नियम को पालन करते हुए अरवी देशों ने भी अपनी आजादी के लिये प्रयत्न करना प्रारम्भ कर दिया। सर्वप्रथम उनके आन्दोलन ने धार्मिक सुधार का रूप धारण किया और प्राचीन धर्म में कुछ नवीनता की पुट दी जाने लगी। इसका उद्देश्य केवल धर्म सुधार नहीं था, प्रत्युत धार्मिक रूढ़ियों को दूर करके वर्तमान शासन व्यवस्था के प्रति रोप प्रकट करना भी था। साधारण जनता को धार्मिक सुधार के साथ ही त्राजादी की भा घूँटी पिलाई जाने लगी। इतिहास में यह आन्दोलन "वोहावीजमे" के नाम से मशहूर है।

वहुधा मुसलमान इज करने के लिये मक्काशरीफ जाया करते हैं। १६वीं सदी के प्रारम्भ में जितने हाजी मक्काशरीफ गये, वे इस आन्दोलन से काफी प्रभावित होते और ब्रिटिश विरोधी भावना लेकर वहाँ से भारतवर्ष लौटते थे। सन १८२० ई० में ऐसी भावना से त्रोत-प्रोत होकर सैय्यद ब्रहमद ब्रेलवी हज करके भारत लौटे। भारतवर्ष की राजनैतिक व्यवस्था में भी परिवर्तन करने के लिये उत्सुक हो उठे और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिये भारतीय जनता में "वोहाबी" नाम से ही प्रचार श्रीर संगठन करने लगे। थोडे दिनों में ही यह आन्दोलन काफी विकसित होकर आम जनता में फैल गया श्रीर दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होता गया। इतने शीघ इसकी सफलता का शेय इसकी धार्मिक स्वच्छन्दता को नहीं, विलक इसके क्रान्तिकारी कार्य-क्रम को है। साधारण जनता में वे क्रान्ति का सन्देश लेकर गये थे। उनकी ये क्रान्तिकारी भावनायं शोपित पीड़ित जनता में सुखी बारूद में चिनगारी की भाँति पड़ी और शीव ही एक महाभयंकर कान्तिकारी विस्फोट, हुआ। भारतीय आजादी की लडाई के इतिहास में १६वीं सदी के पूर्वार्ध का यह क्रान्तिकारी विस्फोट "वंगाल में कृषक विद्रोह" के नाम से विख्यात है। इस विद्रोह का नेतृत्व तित्तू मियाँ नामक एक मुसलमान क्रान्तिकारी के हाथ में था। इसके नेतृत्व में बंगाल के कई जिलों के ब्रिटिश साम्राज्यशाही द्वारा पीडित तथा शोषित कृषक संगठित होकर िशिए वासान्यको के घर हमला बोल दिया । उन पर लेका प्राप्तर में सहप्रदर्शियर मनोवृत्ति की छाप नहीं थी। सरकारी रिपोर्ट में इस ऋपक-विद्रोह का वर्णन इस प्रकार-

६ हिन्दुस्तान श्रीर पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेषण

है:—"एक लाख किसानों ने इस विद्रोह में भाग लिया था। इस विद्रोह का मूल सिद्धान्त भारतवर्ष में प्रजातंत्र की स्थापना था।" इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में भी कई कृपक विद्रोह हुए और कई स्थानों में विदेश जाने के प्रश्न पर सेना ने भी बगावत की। इन सभी विद्रोहों का प्रधानतः एक ही रूप था और था वह अंसन्तुष्ट भारतीयों का त्रिटिश साम्राज्यशाही के खिलाफ विद्रोह। इनमें कहीं भी साम्प्रदायिकता की गंध तक नहीं थी। शत्रु की गोलियों से हिन्दू और मुसलमान दोनों के सीने समान रूप से बिंध रहे थे। ये घटनाएँ १८४७ ई० की आजादी की लड़ाई से पूर्व घट रही थीं।

भारतीय समाज के ऊपर अंग्रेजी हुकूमत का प्रारम्भिक प्रभाव

यह कहना या सोचना सर्वथा गलत है कि मुसलमान स्वतंत्रता संप्राम से सदा दूर रहे हैं और भरसक इसके मार्ग में रोड़ अटकाये हैं। इतिहास अपने गर्भ में एक नहीं ऐसे अनेक स्थल छिपे हुए हैं, जहाँ हिन्दू-मुस्लिम एकता के वेजोड़ मिसाल देखने को मिलते हैं। इन ऐतिहासिक सत्यों से आँख मूँदने से भारतीय शोधित जनता का अहित ही होता है तथा इसका स्पष्ट प्रभाव अमिक शोधित जनता की आजादी की लड़ाई पर भी पड़ता है और गुमराह होती है। ऐसी आन्तिमूलक धारणाओं का निर्मूलन करने के लिये सन् १८४७ के स्वतंत्रत संयाम का जीता जागता नमूना अब भी हमारे सामने मौजूद है।

विदेशी सौदागरों के हाथ में शासन-सूत्र आते ही भारतीय उद्योग-धन्धा, ज्यापार और ज्यवसाय सभी पर अंभेज शासकों की कर दृष्टि पड़ी और सभी असामयिक तथा अप्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त हुए। एक ही केन्द्रीय सत्ता में वधे हुए, अयंकर शोषण और पीड़न से भारतीय जनता समान रूप से त्राहि-त्राहि कर उठी और इसके कारण ब्रिटिश विरोधी भावना की एक ही धारा में हिन्दू श्रीर मुस्लिम सभी वहने लगे। कुछ भागों को छोडकर अभी भारतवर्ष में अंत्रेजी शिचा का प्रसार प्रारम्भ नहीं हुआ था। जनता की वोल-चाल की भाषा उर्धी, जो वास्तव में हिन्दुस्तानी थी। ब्रिटिश शासकों के पूर्व अन्य भार-तीय शासक शिचा पर विशेष जोर देते थे और राज-कोष से उसके लिये विशेष सहायता भी दी जाती थी। भूभिकर का पर्याप्त श्रंश शिचा के लिये सुरचित छोडा जाता था। ब्रिटिश शासक इस प्रकार की शिचा के प्रवन्ध को अपने अस्तित्व के लिये घातक समकते थे। ब्रिटिश शासन सत्ता की स्थापना के उपरान्त एक श्रंप्रेज महोद्य जेम्स प्रान्ट ने हिसाव लगाकर दिखाया कि बंगाल की चौथाई भूमि शिचा संस्थाओं में लगी हुई है, जो राजकर से सर्वथा मुक्त है। अंग्रेजी हुकूमत इसे कव सहन कर सकती थी कि इतनी बड़ी रकम शिद्या के लिये व्यय की जाय जो उनके ऋार्थिक और राजनीतिक स्वार्थ के लिये घातक था। फलतः सन् १८२४ ई० में एक कानृत वनाकर सम्पूर्ण जमीन पर कर लगाने के लिये एक अदालत नियुक्त की गई; इसके परिणाम-स्वरूप राज कर में ३००००० पौंड की वृद्धि हुई। विदेशियों के कोष में तो लक्सी बैठ गई, परन्तु भारती सरस्वती की दशा शोचनीय हो गई। उनके आराधकों की संख्या दिन प्रतिदिन घटने लगी।

हमें यह नहीं मूलना चाहिये कि सोलहवीं श्रीर सत्तरहवीं

सदी में सामन्तवाद के गर्भ में पूँजीवाद का श्रंकुर उगने श्रौर बढ़ने लगा था। फलतः भारतवर्षे में क्रमशः भारतीय राष्ट्र श्रीर राष्ट्रीयता का उदय तथा विकास होने लगा। भारतीय जनता एक ऐसी राष्ट्रीयता के सूत्र में क्रमशः बँध रही थी, जिसकी संस्कृति और सभ्यता का आधार पूँजीवाद बनकर भारतीय पृष्टिभूमि में विकलित हो रहा था। इसके पूर्व कि यह भ्र्ण-सगाज सर्वाङ्गपूर्ण हो सामन्त समाज के गर्भ से जन्म लेता भारतवर्ष में विदेशी व्यापारियों का 'त्रागमन हुआ श्रीर श्रंथेजी शासन का सूत्रपात हो गया श्रीर इस समाज का हत्या गर्भ में हो कर दिया गया। अतः युरोप के देशों के जैसा पुँजीवाद श्रीर राष्ट्र तथा राष्ट्रीयता का विकास भारतवर्ष में नहीं हो सका। अंग्रेजी साम्राज्यवादी शोपण और गुलामी से पीड़ित होकर भारतीय जनता समान रूप से एकता के सूत्र में वैंधकर कंधे से कन्धा भिलाकर उठ खडी हुई। इतिहास इस बात का साची है कि भारतीय जनता ने स्वतंत्रता की बलिबेदी पर निद्यावर होकर अपनी एकता का परिचय दिया है। इस प्रसंग में इतना कह देना आवश्यक प्रतीत होता है कि भारतवर्ष में जहाँ भी कहीं प्रारम्भ में बुद्धि जीवी लोग अंत्रेजी शिक्षा के प्रभाव में आ गये थे वहाँ की जनता स्वतंत्रता की प्रथम लडाई में अपना उचित सहयोग न दे सकी।

भारतीय जनता की प्रारम्भिक एकता और उसे भंग करने का प्रशास

उपरोक्त बातों तथा घटनाओं से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि भारतीय जनता की एकता का आधार केवल अंग्रेजों के अत्याचार से पीड़ित होने के कारण विरोध की समान भावना ही न थी बल्कि साधारण बोल-चाल की भाषा की एकना, समान रहन-सहन ऋोर सभ्यता भी थी. साथ ही साथ बह एकता भी पैदा हो रही थी, जो पूँजीवादी समाज की देन है। किन्तु श्रंग्रेजों के श्रागमन ने उसका नाश कर डाला। चतः हमारे सामने भारतीय एकता मुख्यतः चंत्रेजी-विरोधी भावनाजन्य दिखाई पडती है। इसका एक श्रोर उदाहरण है। इसकां महत्व विशेषतः इसिलये है कि स्वयं एक श्रंग्रेज ने श्रपने मुख से स्वीकार किया है। यह एकता है सरकारी सेना में भारतीय सैनिकों की। मि० मैक, एक अंग्रेज महोदय इसका वर्णन इस प्रकार करते हैं-"सेना में मभी भिल-जुलकर हर एक श्रवसर का समान रूपसे सामना करते हैं। यहाँ जाति श्रीर रंग का कोई भेद-भाव नहीं है। समय पड़ने पर हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख श्रीर पृथिया विल्कुल एक हो जाते हैं।"यह है भारतीय जातियों की एकता का ज्वलन्त प्रमाण। किन्तु जिन श्रंप्रेज महोदय ने इसकी एक स्थान पर प्रशंसा की है, उन्हीं के भाई-वन्धुओं ने अपने अस्तित्व के लिये इसे खतरनाकं समक इसके म्लोच्छेदन में अपनी एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया। इस एका के भयावह परिगाम ने श्रंत्रेजों को सन् १८४७ ई० की घटनात्रों द्वारा त्रस्त कर दिया। सन् १८४७ ई० के गदर ने श्रंत्रेजों के भाग्य का लगभग निपटारा ही कर दिया था। यही एकता थी जो अंग्रेजों की आँखों की शुल थी। एक अंग्रेज महोदय ने जिनका नाम जानलारेन्स था, जो स्वयं इस भयानक अग्नि काएड की लपटों में मुलसे हुए हैं, इससे बचने की यह तरकीव पेश की है। आप का कथन है:- "गद्र के पूर्व की

१० हिन्दुस्तान श्रोर पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेपण

सेना का सबसे वड़ा दोप, जो निर्विवाद रूप से अत्यन्त भया-नक और हमारे लिये घातक था, वंगाल की सेना में ममना " और भ्रावत्व। इससे बचने की अमोघ औषधि है, उनमें वैषम्य स्थापित करना। जो इन दो उपायों के अवलम्बन से सफलतापूर्वक स्थापित किया जा सकता है। प्रथम-युरोपियनों की संख्या की वृद्धि, दूसरी विभिन्न जातियों की अलग-अलग रेजीमेन्ट बनाकर।"

बिटिश अफसरों ने इस प्रकार भारतीय सेना की एकता को नष्ट करने के लिये तथा उसमें एक देशीय भावना को उखाड़ फेंकने के लिये सेना के संगठन में चामृल परिवर्तन किया। उन्हीं के शब्दों में पढ़िये उनका नया संगठन किस प्रकार का है। सेना, बटालियन, कम्पनी, स्कैड्न तथा बहुधा निश्चित जातीय सादूनों में बाँट दी गई हैं। इन विभिन्न दुकड़ियों का विभाजन जाति, सम्प्रदाय तथा धर्म के आधार पर था। इस प्रकार से भारतीय सेना की एकता की भावना को कुचलने का उपाय काम में लाया गया था। त्राम जनता की राष्ट्रीय भावना तथा एकता सेना से किसी भी श्रंश में कम न थी। सन् १८४७ ई० का उदाहरण इसकी पुष्टि करने के लिये पर्ग्याप्त है, पर विद्रोह के बाद की कुछ घटनाएँ इस पर और ऋधिक प्रकाश डालती हैं। अतः उनका उल्लेख करना यहाँ आवश्यक प्रतीत होता है। हम सभी सर सय्वद अहमद खाँ के नाम से परिचित हैं। छोटी आयु में ही उन्होंने ब्रिटिश सरकार की सेवा स्वीकार कर ली .थी। अपनी नमकहलाली का परिचय उन्होंने "सन् १८४७ ई० के विद्रोह" में पूर्ण रूप से दिया था। भारतीय विद्रोही जनता के दमन में इन्होंने अंग्रेजों का खुब साथ दिया। इनके प्रयत्न से बहुतेरे अंग्रेजों के प्राण बच गये। जब इसका समाचार क्रान्तिकारी जनता को मिला तो उसने दिल्ली में उनके घर को लूटा और नप्ट-भ्रष्ट कर दिया।

सन् १८५७ ई० की क्रान्ति के उपगन्त

श्रंभेजी सरकार की श्राँखों में भारतीय जनता की यह एकता चुभने लगी और उसने किसी भी तरह इसकी नष्ट-भ्रष्ट करने में ही अपना कल्याण समका। विद्रोहियों का दमन करके तथा राजभक्तों को पुरस्कार और प्रतिष्ठा देकर पहला कदम उठाया गया। जनता के विद्रोहियों को "सर" का खिताव मिला और जिसे जनता ने सर पर उठाया था, उसका सर घड़ से अलग कर दिया गया। इन्हीं विभीपणों तथा भारतीय-हित घातकों को ही पाकर तो 'सर जीन शिली' को यह कहने का साहस हुआ कि "जानते हो, भारतीयों को ही एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करके हम गदर को दवाने में सफल हुए हैं, और जब तक जनता का, संगठित होकर, सरकार की अलोचना करने तथा उसके विरुद्ध विद्रोह करने का स्वभाव नहीं बन जाता, तब तक इंगलैएड से भारतवर्ष पर शासन करना असम्भव है" इसमें कोई विलक्त एता नहीं है.। जैसाकि पहले मैंने कह दिया है, यदि अवस्था परिवर्तित हो गई और जनता राष्ट्रीयता के सूत्र में वँधकर किसी कारण से विचार करने लगी, तो यह मैं नहीं कह सकता कि हमें अपने साम्राज्य के लिये भयभीत होना चाहिये, परन्तु इतना तो कहूँगा कि 'साम्राज्य के स्थायी होने के विचार की अवश्य परित्याग देना होगा।" इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 'दमन' और 'फूट' नीति का प्रयोग करना

प्रारम्भ कर दिया। चादुकार लोग उच पदों पर नियुक्त किये जाने लगे, जनता पर त्रातंक जमाने का प्रयत्न त्रारम्भ हुआ। उन तमाम प्रयत्नों के बावजूद भी जनता की विद्रोही मनोवृति कुचलने में अंग्रेजी सरकार सफल न हो सकी। उसकी शोपए नीति से जनता का असन्तोष दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। गद्र के दो वर्ष बाद सन् १८४६ ई० में बढ्ता हुआ यह असन्तोष विद्रोह के रूप में प्रकट हुआ। इतिहास में "'नील विद्रोह" के नाम से श्रसिद्ध है। अब तक अत्याचार का प्याला भर चुका था और आततायियों को हुवा देने के लिये समुद्र कर उफन पड़ा। इतना ही नहीं, देश और भी क्रान्तिकारी उपायों का अवलम्वन कर रहा था जिसमें भारतीय समान रूप से शरीक थे। इसमें "बहावी" मंघ का नाम उल्लेखनीय है। उस समय भारतवर्ष में इसका संगठन थानेश्वर के जाफिरन जाफर कर रहे थे। गुन्न उपायों द्वारा त्रिटिशं सरकार को खत्म करने के लिये लोग ऋत्यधिक संख्या में शरीक हो रहे थे। प्रथम क्रान्तिकारी प्रयास की असफलता के बाद कई वर्ष तक भारतवर्ष के कोने-कोने से स्वतंत्रता प्रेमियों तथा धन संप्रह करके यह संस्था बिटिश साम्राज्यशाही से लोहा लेती रही।

अंग्रेजी शिचा का भारतीय सामानिक जीवन पर प्रारम्भिक प्रभाव

सन् १८४७ ई० की जन बगावत के अवसर पर ब्रिटिश सरकार ने यह अनुभव कर लिया था कि जहाँ पर अंग्रेजी शिचा का असर हो चुका था, वहाँ पर क्रान्तिकारी भावनाएँ उतनी तीव्र और उम्र नहीं हो सकी। अब भारतीय जनता और शासक वर्ग के बीच में एक ऐसा पठित-भृत्य वर्ग बन चुका था, जो जन्म श्रीर संस्कार से भारतीय होने पर भी वेपभूषा तथा शिचा-दीचा के कारण अपने को भारतीय कहने में भी लिजित होता था और भारतीय जनता पर रोब-दाब दिखाकर तथा श्रंभेंजों का श्रत्याचार और शोषण में सहायक होकर श्रपने को सार्थक कर रहा था। उच पदों पर अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोगों के आसीन होने से तथा राज द्वारा अंग्रेजी शिचा का श्रादर होने के कारण देशीय भाषात्रों का पठन-पाठन क्रमश: चीए हो रहा था। यहाँ पर यह कहना आवश्यक प्रतीत होता है कि अब तक केवल हिन्दुओं ने ही अंग्रेजी शिचा को प्रहर्ण किया था। श्रतः सरकारी नीकरियों में उनका ही बाहुल्य था श्रीर विदेशी सत्ता के श्रागमन के समय भारतीय व्यापार प्रधानतः हिन्दुत्र्यों के ही हाथ में था। भूकर विभाग में तो प्राय: यही रात प्रतिरात होते थे। विदेशी व्यापारियों के पहले सम्पर्क में छाने के कारण गुलामी भी पहले इन्हीं के सर पड़ी। इसके विपरीत, मुसलमानों में पवल अंग्रेज विरोधी भावना के कारण, कुछ समय तक वे अंभेजी शिचा से वंचित रहे।

सन् १८४७ ई० की क्रान्ति की असफलता के बाद सुसलमानों की अंभेज विरोधी भावनाएँ इतनी तीब हो गई थीं कि प्रति-क्रिया स्वरूप उनका धार्मिक और राष्ट्रीय कट्टरता ने उम रूप धारण कर लिया था। वे अंभेजी शिक्षा को अपने धर्म और राष्ट्रीयता दोनों ही के लिये विषवत समक्ते थे। अंभेजी पढ़-लिख लोगों को वे तिरस्कार तथा अविश्वास की दृष्टि से देखते थे। अपर हम कह ही आये हैं कि अंभेजों ने यह अनुभव कर

१४ हिन्दुस्तान श्रोर पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेषण

लिया था कि अंग्रेजी शिचा बहुत अंश तक क्रान्ति के वेग की कम करने में सफल हुई थी। अतः उन्होंने इस परीचित अपिध का, मुसलमानों की राष्ट्रीयता का नाश करने के लिये, उनमें सर सैय्यद अहमद खाँ द्वारा प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया। सर सैय्यद अहमद खाँ ने मुसलमानों को बहुत ही सब्ज बाग दिखाये, अनेक प्रलोभन दिये, पर उनके विश्वासघात की बात अभी ताजी थी। अतः उनकी माया उन पर कुछ असर न खाल सकी। उल्टे उन्हीं को विधर्मी घोषित करके जातिच्युत कर दिया गया। लेकिन सर अहमद खाँ भी अपने प्रयत्न से बाज न आये। वे तो मुसलमानों के हृदय में अंग्रेजों के प्रति सद्भावना उत्पन्न करने पर तुले हुए थे। राष्ट्रीयता का गहरा रंग उन्हें अहचिकर प्रतीत हो रहा था। अतः कुछ समय परचात् वे अपने प्रयत्न में सफल होने लगे। उनकी मुसलमानों में एक पठित-भ्रत्य वर्ग की कामना फूलने फलने लगी। मुसलमानों में भी यह वर्ग क्रमशः विकिसत होने लगा।

जनता की क्रान्तिकारो मनोवृत्ति को बदलने के हेतु राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना

हिन्दू और मुस्लिम-पिठत-मृत्य वर्ग को पारस्परिक प्रतिहन्हना में खड़ाकर अंप्रजो सरकार बहुत अंश तक सफल
हो सकी, और सदा क्रान्ति की आशंका, जो उनके हृद्य में
बनी रहती थी, कुछ हद तक इससे दूर हुई। लेकिन एक दम
दूर नहीं हो सकी, क्योंिक क्रान्ति की असली जड़ तो साधारण
जनता में है, शोषण और अत्याचार की कठिन पीड़ा से व्याकुल
वहीं पर अधिक है। यही श्रेणी राज्य को उलटने में सदेव
प्रयत्नशील रहती है, और जिस दिन से गुलामी का जुआ
उसके कंघे पर पड़ा उसी दिन से उसे उतार फेंकने के लिए
व्याकुल रहती। अतः जब तक जनसाधारण की क्रान्तिकारी
मनोवृत्ति का प्रवाह नहीं रहता है, तब तक क्रान्ति का भीषण
प्रवाह राज्यसना को किसा भी चण बहा ले जा सकता है, यह
ख्याल अंप्रेज राजनीतिज्ञों को सदैव वेचैन बनाये रखती थी।
अतः उनके सामने अब यही प्रश्न था कि जिस किसी भी प्रकार

से सम्भव हो जनता की इस मनोवृत्ति की रोक-थाम की जाय। इस प्रश्न को हल करने के लिये सन् १८८५ ई० में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सर हूम द्वारा की गई! असन्तुष्ट जनना में जहाँ कहीं क्रान्ति की परिस्थितियाँ परिपक्व हो उठती थीं, क्रान्ति का सन्देश ले जाने से शिच्चित वर्ग सफजता के साथ कांग्रेस द्वारा रोका जाने लगा। वे अपने उद्देश्य एवं कर्तव्य को मूलकर कांग्रेस के द्वारा नौकरी तथा सरकारी पदों की प्राप्ति के लिये आवेदन-पत्र देने लगे। कांग्रेस ने जनता की क्रान्तिकारी सनोवृत्ति को मोड़कर सुधारवाद की तरफ ले जाकर वहुन आंशों तक क्रान्ति की आग को ठंडी करने में सरकार की सहायता की।

कांग्रेस के द्वारा जनता की क्रान्तिकारी मनोवृत्ति को ढीली पड़ती देखकर छांग्रेजों ने कुछ राहत की साँस ली, पर वे उससे सर्वथा सन्तुष्ट नहीं हुए। इसमें भी उन्हें अपने विनाश का एक अंकुर उतता हुआ नजर आने लगा। यह था भारनीय जातियों में सुधार-पथ पर मिलन। मिलन सुखे वा दु:खे किसी भी जगह उन्हें बांछनीय न था, इसका परिणाम सन् १०५७ ई० में उन्हें भोगना पड़ा था। इसके बाद से ही वे किस प्रकार पहले हिन्दुओं को अपने पद्म में.करके फूट डालकर शासन करने की नीति को ज्यवहार में ला रहे थे, इसका संकेत अपर हो चुका है। अतः पुनः उस मेल के अंकुर को हरा-भरा देखकर अंग्रेजी सरकार शंकित हो उठी और उसके नाश का उपाय ढूँहने लगी।

म्रुसलमानों में साम्प्रदायिक-विद्वेप की भावना का वीजारोपण

श्रव अंग्रेजों ने अपनी नीति को सफल बनाने के लिये निम्नांकित उपाय को अपनाया। सर सञ्यद अहमद खाँ अंग्रेजी हुकूमत के लिये काफो मद्दगार साबित हुए । इन्होंने अर्थकों को सहायता से अलीगढ़ में एक मुस्लिम कालेज जी अधायना की। वहाँ के अंग्रेजी शिचा प्राप्त मुस्लिम युवक अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार करने लगे और मुस्लिम पठित-भृत्यन्तर्ग विकसित होने लगा, जो हिन्दू पठित-भृत्य-वर्ग की अतिहरूकता में खड़ा किया गया। किन्तु सन् १८८५ ई० के बाह्य जुला उनकी एक खासी संख्या हो गई तो मुस्लिम सम्प्रदाय के लियो नीकरी वगैरह के रूप में अलग रियायतों की माँग उठवाई जाने ख़नी। त्रालीगढ़ मुस्लिम कालेज मुस्लिम राजनीति का केन्द्र हो गया था। अंग्रेजों ने अलीगढ़ कालेज को साम्प्रदायिक-विद्वेप की भावना का बीजारोपण करने का उपयुक्त चेत्र बनाकुर इसका अयोग भी अपनी स्वार्थपूर्ति के लिये करना आरम्भ कर दिया। यह कार्य सीधे सरकार द्वारा सम्पन्न न होकर एक गैरसर्कारी श्रंमेज कर्मचारी मि० बेक के द्वारा हुआ, यह महोद्य अलीगढ़ कालेज के त्रिंसपल पद पर नियुक्त किये गये। वहाँ आते ही इन्होंने "इन्स्टिच्यूट" गजेट के सम्पादन का चार्ज अपने ऊपर ले लिया। अब तक इसका सम्पादन तथा संचालन सर स्ट्यद श्रहमद खाँ के द्वारा हो रहा था। इस पत्र के उत्पर श्रिविकार करके मि० वेक मुसलमानों में साम्प्रदायिकता के विष् का बीज बोने लगे।

इस नीति का अवलम्बन करके सरकार हिन्दू और मुस्लिस शिच्तित वर्ग में फूट डालने में तो सफत हुई पर पूरी मकसद इससे पूरी नहीं हो रही थी। साधारण जनता अब भी कन्धे से कन्धा मिलाये अंभेजी शोषण और अत्याचार के विरुद्ध उठ रही थी। इनमें अभी ऐसी कोई चीज नहीं घुस पाई थी, जो वैषम्य उपस्थित करती। श्रतः उनमें फूट डालने का काम क्रिमी वाकी था श्रीर जब तक यह कार्य्य पूरा नहीं होता, तो खब तक के किये गये प्रयत्नों पर किसी भी च्रण पानी फिर जाने की श्राशंका बनी हुई थी। श्रतः श्रंगेजों के सामने यही प्रश्न विकट रूप धारण किये उपस्थित था। उनकी कूटनीनि की परीचा इसी कसौटी पर होने वाली थी। श्रव हम श्रागे देखें कि किस प्रकार श्रपनी कूटनीति को श्रंगेजों ने कार्यान्वित किया।

दो राष्ट्र के सिद्धान्त का बीजारीपगा

दमन-चक्र के द्वारा तथा क्रान्ति-विरोधी तथा सुधारवादी जीति के आधार पर राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करके भी जनता की क्रान्तिकारी मनोवृत्ति वदली या कुचली न जा सकी, प्रत्युन शनै: रानै: यह अप्रसर होती गई। अतः सरकार ने यह अच्छी तरह समभ लिया कि इस मनोवृत्ति के कारण उसके हाथ से राजनीतिक सुधार के रूप में कुछ ऐंठे जाने वाला है, और बिना उसके बचत का कोई उपाय नहीं। अतः सरकार अब इस बात के लिये परेशान हो उठी कि सुधार किसी भी तरह क्रान्ति के पौधे को सींचने में प्रयोग न हो सके। इस खतरे से अपनी रच्चा करने के लिये बिटिश सरकार ने मि० बेक की सहायता से अपना उल्लू सीधा करना प्रारम्भ किया। सन् १८८६ ई० ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में चार्ल्स ब्राह्म ने भारतवर्ष में राजनीतिक सुधार के सम्बन्ध में एक बिल भो उपस्थित किया। इस बिल का उरेश्य भारतवर्ष में प्रजातांत्रिक संस्था की बुनियाद डालना था। मि० बेक ने इस अवसर पर सुसलमानों का

 श्यान उनके द्यस्तित्व की तरफ खोंचना द्यारम्भ किया। उनमें इस प्रकार की मनोवृत्ति पैदा करने की चेटा वे करने लगे। मुसलमानों की खोर से उन्होंने एक प्रार्थना-पत्र तैयार किया । उसमें उन्होंने यह ऊल्लेख किया कि ''भारत एक राष्ट्र नहीं है। अतः लोकतंत्रीय सिद्धान्त यहाँ पर लागू नहीं हो सकता।" इस सिद्धान्त का प्रतिगादन प्रार्थना-पत्र में अच्छा तरह किया गया और इसके आधार पर सुधार का विरोध किया गया। बड़ो मकारी ऋोर घोके बाजो के साथ २० हजार मुसलमानों से यह कहकर हस्ताचर करवाया गया कि यह हिन्दु श्रों के तिरुद्ध जो गौकुशी को बन्द करना चाहते हैं, सरकार के पास भेजने का आवेदन-पत्र है। इस कार्य में भि० वेक को अली-गढ़ कालेज के विद्यार्थियों से काफी सहायता भिजी। वे स्वयं उनका एक जत्था लेकर दिल्ली पहुँचे और जामा मस्जिर के फाटक पर खड़े होकर नमाजी मुमलमाना को असत्य वाक्-जाल में फँसाकर ह्न्ताचर कराने लगे। म० वक ने इस अव-सर पर संगठन के प्रभाव को छातुभव किया और छातुमान किया कि साम्प्रदायिकता के आधार पर मुसलमानों का अलग संगठन अंगेजों की दुष्कामनाओं की पूर्ति में वड़ा सहायक खावित होगा ।

भारतीय ग्रुस तमानी और अंग्रेजी के बीच एकता का प्रयास

सर्वप्रथम सन् १८८८ ई० के अगस्त में अलीगढ़ में "दि युनाइटेड इंडियन पैट्रिआटिक एसोसियेसन" स्थापित किया गया था। लेकिन मि० बेक की पूरी मक्सद इससे पूरा नहीं हो पा रही थी। अतः अपने थिचार को कार्यक्ष में पूरी तरह परिएात करने के लिये सन् १८६३ ई० में "दि मोहम्मदन-ऐंग्लों श्रौरियन्टल डिफेन्स एसोसियेसन" के नाम से इन्होंने मुसलमानों की एक पृथक संस्था की नींव डाली। इसका मुख्य उदेश्य था :-(१) "साधारणतः श्रंप्रेज जाति श्रीर विशेषतया सरकार को मुस्लिम सम्प्रदाय के विचारों से अवगत करान! तथा मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रहा करना। (२) उन जपायों का समर्थन करना जिससे ब्रिटिश हुकूमत भारत में सुदृढ़ हो।(३) जनता में राजभक्ति का प्रचार करना श्रीर मसलमानों में राजनीतिक संघर्ष को रोकना"। इस संस्था के मन्त्री पद का भार स्वयं वेक साहत्र ने महुण किया। मि० बेक एक स्थान पर अपने पत्र "गंजट" में लिखते हैं कि "मुसलमानों श्रीर अंग्रेजों के लिये यह आवश्यक है कि संगठित होकर राजनीतिक हलचल श्रीर लोकतंत्रीय सिद्धान्तों पर निर्मित शासन व्यवस्था के समावेश का प्रतिरोध करें, क्योंकि यह मुलक की आवश्यकता और बुद्धि दोनों के ही विपरीत है। अतः हम राज के प्रति भक्ति और अंत्रेज-मुस्लिम मिलाप का जोरों से समर्थन करते हैं।"

क्रान्तिकारी आन्दोलन का श्रीगर्शेश

इन सब प्रयत्नों के बावजूद भी ब्रिटिश सरकार जनता की क्रान्तिकारी मनोवृत्ति को कुचल न सकी। इसके दमन तथा श्रन्य श्रत्याचारों ने श्राग में घी डालकर सुलगती हुई क्रान्ति की श्राग्न को प्रज्वलित कर दिया। श्रंग्रेजों के श्रत्याचारों से तंग श्राकर लाचार होकर प्रारम्भ में क्रान्तिकारियों को प्रत्यातंकवाद का श्राथय लेना पड़ा। प्राय: प्रारम्भिक श्रवस्था

में क्रान्तिकारी आन्दोलन का स्वभाविक रूप प्रत्यातंकवादी ही रहता है। हिन्दुस्तान में भी प्रारम्भिक अवस्था में यह प्रधानतः प्रत्यातंकवादी रहा । सर्वप्रथम सन् १८६८ ई० में यह (क्रान्तिकारी आन्दोलन) प्रगट रूप में प्रारम्भ होता है, जब चफे कर बन्धु सों को पूना के एक अंग्रेज किमश्नर की हत्या के अपराध में फाँसी दी गई थी। पूना निवासियों पर सेंग के समय कमिश्नर रौराङ का कठोर व्यवहार ही उसकी मृत्यु तथा अत्यातंकवाद के सूत्रपात का तात्कालिक कारण था। यह क्रान्ति की लहर विंध्याचल पर्वत को दिचाणी भारत से पारकर उत्तरी भारत को भी प्लावित करने लगी। वंगाल के नवयुवक भी इस थारा में बह चले। २०वीं सदी के ऊषाकाल में भारतीय ! वितिज पर कान्ति-सूर्य की प्रखर किरगों प्रस्फुटिन हो रही थीं। सरकार इस क्रान्तिकारी बेग को रोकने के लिये चिन्तित हो उठी। लार्ड कर्जन (तात्कालिक वायसराय) क्रान्ति के इस बढ़ते हुए वेग को रोकने में असफल हुए। उनकी दमन तथा आतंक की नीति असफल सिद्ध हुई। ब्रिटिश सरकार ने समफ लिया कि बिना सुधार दिये क्रान्ति की बढ़ती हुई लहर को नहीं रोका जा सकता है परन्तु सुवार भी सदैव निरापद नहीं है। क्रान्तिकारी इसके मोह में नहीं फँसते, प्रत्युत बलटे उसका प्रयोग अपने उदेश्य की पूर्ति के लिये करते हैं। अतः सरकार के हित में सुधार तभी लाभदायक सावित होता है, जब कि एक वर्ग इसी में उलभ जाता है और क्रान्ति के पथ का परित्याग कर देता है। सुधारवादी शक्तियाँ सुधार रूप में मिले दुकड़े पर लड़ने मगड़ने लगती है, देश की संगठित शक्ति को छिन्न-मिन्न करती है, सुवार के पीछे सरकार की यही मनीवृत्ति होती

है। यही कारण है कि सरकार हर सुधार के पीछे साम्प्रदायिक समस्या को जटिल बनाती गई और सुधारवादियों का एक दल पा जाने के कारण उसे (सरकार को) मनोवांछित सफलता भी मिलती गई है। सरकार ने सुधार के अवसर पर इसी नीति को प्रहण किया। अब हम देखेंगे कि किस रूप में यह प्रकट हुई और क्या इसका असर पड़ा।

वंगाल का विभाजन

१६१० ई० में भारतवर्ष में जो सुधार मिला, उसकी तैयारी पहले से ही हो रही थी, ब्रिटिश सरकार को अपनी उपरोक्त नीति के श्रनुसार ही कार्य करना था, यानी साम्प्रदायिक समस्या को उलकाकर क्रान्तिकारी शक्तियों को छिन्न-भिन्न करना। श्रत: इस दृष्टिकोण से लाई कर्जन ने सन् १६०४ में ढाका में यह घोपणा की कि आगामी सुधार में ब्रिटिश सरकार मुसलमानों को एक अलग प्रान्त देने जा रही है। यह बंगाल के विभाजन के द्वारा सम्पन्न होने को था। वंग-शंग की मुखालिफत भारत के कोने-कोने में की गई । वंग-भंग के पीछे कितनी मुस्लिम-हितों की शुभ कामना थी ख्रौर कितना इनका खपना स्वायं, यह उन्हीं के मुख से सुनिये। इस सम्बन्ध में सर हेनरी कालटन ने अपनी पुस्तक "इंडिया इन ट्रांजिशन" में लिखा है:-- "इस नीति का महत्व प्रान्त की एकता श्रीर संगठित शक्ति को छिन्न-भिन्न करना था। इस योजना के मूल में शासन सम्बन्धी कार्ण् थे। लार्ड कर्जन की नीति का मुख्य अभिपाय प्रान्त की बढ़ती हुई शक्ति को निर्वल तथा राष्ट्रीयता की श्रोर विकसित होते हुए राजनीतिक मनोभाव को नष्ट करना था।"

इन वाक्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वंग-भंग के पीछे। विटिश सरकार का क्या उरिय था।

इसके विरोध में भारत के कोने-कोने से हिन्दू-मुस्लिम की सम्मिलित जोरदार आवाज उठने लगी। सन् १६०६ ई० में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में नवाबजादा ख्वाजा खली खाँ ने घोषित कियाकि "में बिना हिचकिचाहर के आप को यह बतलाना चाहता हूँ कि यह विल्कुल असत्य हैं कि पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बंग-भंग के पच में हैं। वास्तविकता यह है कि कुछ बड़े-बड़े मुसलमान अपने व्यक्तिगत स्वार्थी के जिये इस योजना का समर्थन कर रहे हैं।" कलकत्ता के फेन्द्रीय मुस्लिम संघ के मन्त्री नवाब अली हसन ने भी इसका विरोध किया।

स्वदेशी आन्दोलन

हम सब स्वदेशी आन्दोलन से परिचित हैं। यह देश व्यापी आन्दोलन बंग-भंग की घोपणा के विरोध में किया गया था। इस आन्दोलन के कार्य-क्रम में विदेशी बस्तुओं का बहि-कार मुख्य था। सन् १६०६ ई० में राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस बार्षिक अधिवेशन में भी विदेशी बन्तुओं के बहिक्कार का अस्ताव पास किया गया। यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि स्वदेशी आन्दोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हारा संचालित नहीं होता था, बल्कि इसके संचालन का भार इंडियन एसोसियेसन के हाथों में था। स्वदेशी आन्दोलन के संचालन और सफल बनाने में भारतीय कान्तिकारियों का प्रमुख्य हाथ था, या यों कहिये कि सम्पूर्ण आन्दोलन के संचालन ही उनके हाथों में था। हिन्दू और मुस्लिम का समान सहयोग इस आन्दोलन को प्राप्त था। स्वदेशी आन्दोलन के अवसर पर वारिसाल (बंगाल) की इड़ताल का विशेष महत्व है। सारे नगर में गर्वनर के आने के उपलच्च में इड़ताल थी, हिन्दू-मुस्लिम दोनों जोश से इड़ताल को सफल बनाने में कंथे से कंया मिलाये थे। परिणाम भी उनके अनुकूल ही हुआ। क्या मजाल कि कोई भी वस्तु वाजार में ऊँचे से ऊँचे आफिसर को मिल सके। वारीसाल के मजिस्ट्रेट को भी तभी सामान मिला जब इड़ताल के नेता, अनुशीलन दल के सदस्य अस्विनी छुमार ने अपने इस्ताचर से आज्ञा दी। जनता पर क्रान्तिकारियों के इस प्रभाव को देखकर सरकार दहल उठी। किर बौखलाकर उसने आतंक का सहारा लिया, पर निष्फल, विवश होकर क्रान्तिकारी शक्तियों के आगे मुकना पड़ा। संगठित जनता ने अपने अंग-मंग को बचा लिया और सरकार को अपनी योजना वापस लेनी पड़ी।

क्रान्तिकारी संगठन का विकास

इतिहास हमें बतलाता है कि दमन क्रान्तिफारी शक्तियों को नष्ट नहीं कर पाता बल्कि उसके बेग को ही बढ़ाता है। यह जनता में शासक के प्रति रोष, घृणा और क्रान्तिकारियों के प्रति सहानुभूति, आदर और श्रेम का स्चन करता है। यह क्रान्ति के विकास के लिये अनुकूल परिस्थिति पैदा करता है, ऐसे ही समय में क्रान्तिकारी दल व्यापक होते हैं, उनके सदस्यों की संख्या बढ़ती है, दमन के समय उनके कतव्य, धैर्य्य और चरित्र की परख होती है। लार्ड कर्जन के दमन काल और स्वदेशी आन्दोलन के अवसर पर क्रान्तिकारी पार्टियों का विकास एवं उन्नति काफी हुई। अनुशीलन दल का संगठन काफी प्रभावशाली हो गया। कुछ समय के अन्दर केवल वंगाल में ही ६०० से अधिक केन्द्र स्थापित हो गये। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष के अन्य स्थानों में स्थापित केन्द्रों की संख्या अधिक थी। सरकार क्रान्तिकारी संगठन के व्यापक प्रसार से भयभीत हो उठी और सन्१६०८ ई० में उसने राजनीतिक संस्थाओं को गैरकान्नी घोषित करने का कान्न पास किया और अनुशीलन दल वगैरह क्रान्तिकारी संगठनों को अवैध करार दिया। अतः सुवार द्वारा फूट उत्पन्न करके तथा दमन का संयोग स्थापितकर क्रान्तिकारी शक्तियों को विछिन्न करने की नीति वरती गई।

मुप्तलमान पठित-मध्यम वर्ग को खुश करने की नोति

अपर हम देख आये हैं कि मुसलमान और हिन्दू दोनों ही बिटिश सरकार के विरुद्ध रहे और राष्ट्रीय आन्दोलन में सिक्षिय भाग एक साथ लेते रहे, किन्तु इस समय तक मुसल-मानों में पिठत-मध्यम वर्ग का उदय तथा विकास हो चुका था। सुधार रूप में प्राप्त सरकारी नौकरियों में इसका स्वार्थ निहित था। अतः सरकार इनको कुछ सुविधायें देकर अपनी तरफ खीचने में सफत हुई। इस समय तक इनको संख्या भी साधारण थी। अतः सरकार को इन्हें सन्तुष्ट करने में कोई असुविधा नहीं हुई। यह वर्ग धोरे-बोरे सरकार के प्रयत्नों द्वारा राष्ट्रीय आन्दोलन से अलग होता गया।

वाइसराय के पास सुमलमानां का प्रथम डेपुटेशन हम सब सन् १६०६ ई० में सर आगा खाँ के नेतृत्व में

बायसराय के पास मुसलमानों के डेपुटेशन जाने से परिचितः हैं। यह जानकर हम अचिम्भत हो जायंगे कि डेपुटेशन ले जाने का विचार न तो सर आगा खाँ के ही दिमाग में आया श्रीर न श्रन्य मुसलमानों के दिमाग में, बल्कि इसकी सृष्टि बाइसराय के दिमाग से हुई। ता० १०-८-१९०६ ई० की मि० आर्च बोल्ड ने नवाब मोशीनउल्मुल्क को एक पत्र लिखा, जिसमें वाइसराय के पास मुसलमानों की त्रोर से डेपुटेशन ले जाने की सलाह दी गई है। वे अपने पत्र में इस प्रकार लिखते हैं:-- "कर्नल डवलप स्मिथ हिज एक्सेलेन्सी के प्राइवेट सेकेटरी मुभे स्चित करते हैं कि हिन एक्सेलेन्सी मुसलमानों के डेपुटेशन से मिलने के लिये राजी हैं। वह यह सलाह देते हैं कि मुलाकात की आज़ा प्राप्त करने के लिये रिवाजन वाइसराय के पास एक छाबेदन-पत्र भेजें, इस सम्बन्ध में मैं बह सलाह ूँगा कि-वाइसराय के पास जो आवेदन-पत्र आये, उस पर मुसलमानों के प्रतिनिधियों का हस्ताचर होना चाहिये और डेपुटेशन में सभी प्रान्तों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये। तीसरी महत्वपूर्ण बात पत्र के विषय में हैं। मैं यहाँ पर सलाह ूँगा कि हमको सरकार के प्रति मिक्त दर्शाते हुए पत्र का आरम्भ करना चाहिये, तथा स्वायत्त शासन की तरफ कद्म उठाने के सरकार के फैसले की प्रशंसा करनी चाहिये। लेकिन हमारी शिकायतों की ऋर्जी यह होना चाहिये कि यदि चुनाय के सिद्धान्तों को लागू किया गया तो वह अल्पसंख्यक मुस्लिम हितों के लिये घातक होगा और विनयपूर्वक यह परामर्श दिया जाना चाहिये कि मुस्लिम हितों की रज्ञाके लिये धार्मिक आधार पर नामजद्गी या प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त

लागू करके मुस्लिम जनता के परामर्श का उचित सत्कार किया जा सकता है। हमें यह भी सलाह देनी होगी कि भारत ऐसे देश में जमीन्दारों के विचारों को उचित महत्व मिलना चाहिये।"

इस पत्र के उपरान्त मुसलमानों का हेपुटेशन हिज होली-नेश आगा खाँ के नेतृत्व में सन् १६०६ ई० में वाइसराय के पास गया। इसका उल्लेख वाइसराय ने इस प्रकार किया है:-- "त्रापके पत्र का मुख्य विषय जैसा कि मैंने समफा है, यह है कि प्रतिनिधित्व की जो कोई व्यवस्था चाहे इसका सम्बन्ध म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट वोर्ड या व्यवस्थापक सभा से हो और जिसमें चुनाव के सिद्धान्तों की लागू किया गया हो या उनकी वृद्धि की गई हो, वहाँ पर मुस्लिम सम्प्रदाय को एक श्रलग सम्प्रदाय माना जाना चाहिये श्रीर श्राप इस तरफ संकेत करते हैं कि बहुधा प्रतिनिधि संस्थाओं में जैसा कि इस समय उनका रूप है, मुस्लिम उम्मीदवार के चुनकर आने की बहुत कम सम्भावना है। यदि किसी मामले में ऐसा हो भी गथा तो वह केवल मुस्लिम उम्मीद्वार के द्वारा अपने विचारों को बहुमत के आगे बलिदान करके ही सम्भव हो सकता है। अतः वह अपने सम्प्रदाय का असली प्रतिनिधि नहीं हो सकता। श्रीर श्रापका यह कहना न्यायोचित है कि श्रापके प्रतिनिधित्व के अनुपात का आधार आप की संख्या नहीं बल्कि ज्ञापका राजनीतिक महत्व तथा साम्राज्य को अपित सेवायं होनी चाहिये। मैं श्राप लोगों से पूर्ण रूप से सहमत # [' [V. Buchan lord Minto]

हमने देखा है कि मुस्लिम डेपुटेशन का त्रिचार लार्ड

२८ हिन्दुस्तान खौर पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेषण

मिन्टों के ही दिमाग की उपज है। श्रतः इसको सफलता स्वयं सिद्ध है। श्रसफलता ही श्राश्चर्य की बात होती। श्रपनी पुस्तक "दि एवेकिनंग श्राफ इंडिया" में मुस्लिम डेपुटेशन के विषय में मि॰ रैमजे मैंकडोनल्ड लिखते हैं कि "मुस्लिम नेताश्रों को एंग्लो इंडियन श्राफिसरों के द्वारा उकसाया गया श्रोर शिमला श्रीर लंडन में बैठे-पैठे तार खींच रहे थे श्रोर मुसलमानों को बिशेप रियायतें देकर हिन्दू और मुस्लिम सम्प्रदायों में कदुता श्रीर वैमनस्य का बीज बो रहे थे।"

मुस्लिम लीग की स्थावना

भारतीय जनता क्रान्ति की स्रोर श्रमसर हो रही थी। उसके स्रन्दर बगायत की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन प्रवल तथा उमतर होती जा रही थी। क्रान्ति विरोधी तथा सुधारवादी नीति के स्राधार पर कांग्रेस का स्थापना की गई स्थोर कांग्रेस पूर्ण रूप से इस नीति को निभा रही था। लेकिन सूरत कांग्रेस में सन् १६०६ ई० में स्वर्गीय लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में स्वतंत्रता का प्रस्ताव उपस्थित किया गया, किन्तु बहुमत के विरोध से यह प्रस्ताव पास नहीं हो सका। श्री लोकमान्य तिलक जी को कांग्रेस से बाहर स्रा जाना पड़ा। क्रान्ति की यहती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिये दमन सुरू हुआ। उधर कुछ स्रोर राजनीतिक सुधार मिलने की सम्भावना दिखाई दे रही थी। स्रागा खाँ के डेपुटेशन को काफी सफलता मिली। इस सफलता से प्रोत्साहित होकर ३० दिसम्बर १६०६ ई० को नवाब सली सुल्लाह खाँ ने डाँका में जलसा के लिये प्रसिद्ध सुसलमानों को निमंत्रित किया। स्राल इंडिया सुस्लिम लीग का प्रथम स्रिध-

वेशन सन् १६०६ ई० के दिसम्बर के अन्तिम तिथि को ढाका में हुआ।

मुस्लिम लोग का उद्देश्य

अखित भारताय मुस्तिम लोग ने निम्नांकित चीजों को अपना उद्देश्य ठहराया। (१) भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश गवर्नमेंट की राज-भक्ति का प्रचार करना तथा उसको किसी। नीति से यदि किसो प्रकार की गलतफ इमो तथा असन्तोप फैले तो उसको दूर करना।

(२) भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक तथा अन्य अधिकारों की रचा करना और उनकी आवश्यकताओं को तथा भावनाओं एवं आकांचाओं को गवर्नमेंट के सामने विनम्न भाषा में उपस्थित करना। इन प्रधान उद्देश्यों पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग को स्थापना हुई। सर अली इमाम के सभापित्त में सन् १६०८ ई० में मुस्लिम लीग का सालाना जलसा अमृतसर में हुआ। वहाँ स्थानीय संस्थाओं में साम्प्रदायिक प्रतिनिधियों की संख्या बहाने का प्रस्ताव पास किया गया। और एक दूसरे प्रस्ताव में वंग-भंग के प्रति अखिल भारतीय कांवेस के उख के प्रति असन्तोप प्रकट किया गया।

मार्ले सिन्टो सुधार

सन् १६० में नया राजनीतिक सुधार हिन्दुस्तान में लागू किया गया। मार्ने मिन्टो, सुधार को लोकतंत्रीय सिद्धान्त पर निर्मित सुधार कहना सही न होगा। इस सुधार की विशेष्या यह थी कि साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के साथ ही साथ खास-खास हितों के प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया गया।

३० हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेषण

इसके अन्दर पृथक निर्वाचन के कारण विशेषतः सारे देश में विरोध किया गया, केवल राष्ट्रीय शक्तियाँ ही विरोध नहीं कर रही थीं, विलक अंग्रेजों का एक प्रमुख्य अंग "दि स्टेट्समैन" समाचार-पत्र ने भी इसका विरोध किया। पृथक निर्वाचन-प्रणाली को लागू करके बिटिश सरकार ने साम्प्रदायिकता के उस विष-वीज का आरोपण कर दिया जिसके लिये सन् १८८६ ई० से मि० वेक त्रेत्र तैयार कर रहे थे। ज्यों-ज्यों यह विष-वृक्त बढ़ने लगा, त्यों त्यों भारतीय-राष्ट्रीय आन्दोलन में वाधा उपस्थित होती गई और आज भारतवर्ष का साम्प्रदायिक आधार पर हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में विभाजन उसी विष-वृक्त का है, जो श्रमिक शोषित जनता के आजादी की लड़ाई के लिये घानक हो रहा है।

प्रथम साम्राज्यवादो युद्ध

इधर ब्रिटिश सरकार साम्प्रदायिक वैपम्य फैताने के लिये श्रयत्नशोल हो रही थी श्रीर मुसलमानों के श्रन्दर एक वर्ग विशेष को विशेष सुविधा प्रदान कर अपने पत्त में करने का प्रयास कर रही यो और किसी अंश में कुड़ सफतता भी इसे प्राप्त हो रही थी, उधर विश्व में कुछ और ही घटनाएँ घट रही थीं, जिसमें भारतीय जनता भी श्रञ्जूते न रह सभी। ब्रिटिश सरकार की सफलताओं पर भी लगभग पानी फिर गया। राजनीतिक नभ-मण्डल में युद्ध के वादल छाये हुये थे, साम्राज्यवादी शक्तियाँ अपनी साम्राज्य लिव्सा के कारण किसी भी च्या एक दूसरे पर दूट पड़ने का अवसर दूँ द रही थी। साम्राज्यवाद की शोपण नीति से अभिक जनता काफी असन्तुष्ट हो चुका थी और इस अवसर को बड़ी आशा और असुकता से प्रताचा कर रही थी कि जब साम्राज्यवादी राज-राकियाँ श्चापस में टकरायें तो उसे भी श्रपना बन्धन तोड़ने का श्रवसर मिले। ऐसे अवसरपर गुजाम जनता के सरुचे प्रतिनिधि-क्रान्तिकारी बड़ी लगन से काम करने लगे और बिटिश शासकों की कूटनीति व्यथं होने लगी। इसके पहले भी मुस्लिम जनता ने अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बनकर रहना अवांछनीय सममा। फलतः इनके विरोध से अलीगढ़ से मुस्लिम लीग का द्रफ्तर उठकर लखनऊ चजा आया और अलीगढ़ यूनि-धर्सिटी के प्रिंसिपल महादय के चंगुल से बाहर चलो गई।

टकीं में प्रजातन्त्र की स्थापना

ऊपर हम प्रथम विश्व-युद्ध के मङ्राते हुए बादल से भार-तीय वातावरण में परिवर्तन का संकेत कर चुके हैं। इसके श्रातिरिक्त यूरोप में एक श्रीर घटना घटी, जिससे परिवर्तित होती हुई भारतीय परिस्थितियों ने एक मूर्नेरूप धारण कर लिया, यह था मुस्लिम सम्प्रदाय का स्पष्ट रूप से अंधेजों के विरुद्ध संगठित हो जाना । घटनायें थों—बोसवीं सदी के प्रारम्भ से ही बालकन के प्रान्त जो तुर्क साम्राज्य के आधीन थे, स्वतन्त्र होने को चेटा कर रहे थे। रूमी जार तथा ब्रिटिश साम्राज्यवाद अपने राजनीतिक तथा आर्थिक स्वार्थी के कारण बालकन शान्तों की सहायता कर रहे थे। धार्मिक भावनाच्यों के कारण भारतीय मुसलमानों के ऊपर बुरा असर हुआ और अपने सह-धर्मियों (तुर्कों) के विरुद्ध विजातियों का यह संगठन उन्हें बहुत खला। भोले-भाले धर्म भीर मुसलमानों में पहले यह प्रचार किया गया था कि अंग्रेज मुस्लिम धर्म के शुभेच्छुक हैं, किन्तु इस विश्वास का इस प्रकार गला घुटते देखकर उनकी धार्मिक प्रवृत्ति विद्रोह कर उठी। सन् १६०८ ई० टकी के नौजवानों ने प्रजातन्त्र की स्थापना के लिये सुल्तान के विरुद्ध वगावत का करण्डा खड़ा किया। ब्रिटिश सरकार टर्की में प्रजातन्त्र की

स्थापना के विरुद्ध थी, मध्य एसिया में टर्की का सवल राष्ट्र होने देना उन्हें अपने स्वार्थ के लिये मयोत्पादक हिंगा पर हो रहा था। अतः उन्होंने क्रान्तिकारियों को कुचलने में सुल्तान की काफी मदद की। भारतीय मुस्लिम जनता धर्म के नाते टर्की की जनता के साथ सहानुभूनि रखती थी। अतः जनता के ऊपर अत्याचार करने में टर्की के सुल्तान की सहयोग देकर ब्रिटिश सरकार भारतीय मुस्लिम नोजवानों में और भी अप्रिय हो गई। अंग्रेजों से रुष्ट होने के साथ ही साथ तुर्की के क्रान्तिकारी आन्दोलन के सिद्धान्तों की द्याप भारतीय मुस्लिम नवयुवकी पर पड़ी और उन्होंने साम्प्रदायिकता के संकीर्य चेत्र से निकल-कर राष्ट्रीयता के विस्तृत द्याप भारतीय मुस्लिम नवयुवकी भी प्रजातन्त्र स्थापना के हेतु वे भारत की अन्य क्रान्तिकारी शिक्तियों के साथ एक-दूसरे के गले में हाथ डालकर क्रान्तिकारी पथ पर आ मिले।

उपरोक्त अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ-साथ राष्ट्रीय घटनाओं का भीअंभेजों के विक्र सुमलमान मावारण जनता के मनेभावों को करने में काफा असर पड़ा। वंग-भंग का उड्देश्य अंभेजों ने यह बनाया था कि हम मुसलमानों के लिये एक अलग प्रान्त का निर्माण कर रहे हैं, पर उक्त योजना को जानस लेते समय मुसलमानों से एक वार भी नहीं पूछा गथा। अतः मुसलमानों की आँखें खुल गईं, उन्हें अपनी वास्तिक स्थिति का ज्ञान हो गया। वे समक गये कि अंभेज केवल अपनी स्वार्थ-पूर्ति के लिये ही उन्हें अपने हाथों की कठपुतली बनाये रखना चाहते हैं, और अवसर पड़ने पर उन्हें दूध की भक्ती की भाँ वि अलग, फेंक सकते हैं। फलतः इससे उनके हदय में

३४ हिन्दुस्तान श्रीर पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेषण

अंत्रेज विरोधी भाव उठने लगे और राष्ट्रीय एकता उत्पन्न करने में अत्यन्त लाभदायक सिद्ध हुआ।

प्रथम साम्राज्यवादी युद्ध के पूर्व कान्तिकारी संगठन

इस प्रकार ऋन्तर्राब्ट्रीय और राष्ट्रीय परिस्थितियों ने भार-तीय जनता को एकता के सूत्र में बाँध दिया और अंग्रेजों के पंजे से मुक्त होने के संप्राम को सरल श्रीर शक्तिशाली बना दिया। भारतीय कान्तिकारी इस अवसर पर आगे आये और उन्होंने देश की संगठित शक्तियों का, क्रान्ति के लिये, नेतृत्व अपने हाय में लिया। प्रथम विश्वयुद्ध-किसी भी नगा अपनी विभीषिकाओं के साथ प्रकट हो सकता था—ने उनके लिये अनु-कूल अवसर उपस्थित कर दिया। वे इस मीके की ताक में थे श्रीर इससे समुचित लाभ उठाना चाहते थे। इसी दृष्टिकोग्। से वे तैयारी कर रहे थे। इमी समय सन् १६११ ई० में नयी राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय लाई हार्डिंग्जपर वम केंका गया। इसका उद्देश्य यह था कि भारतीय क्रान्तिकारी केवल बंग-भंग को ही खत्म करके सन्तुष्ट नहीं हुए. ैं, बल्कि भारतवर्ष की वे पूर्ण म्वाधीनता चाहते हैं। जब तक भारतीय जनता गुलामी की जंजीर से जकड़ी है, तब तक उनकी लड़ाई अविराम गति से चलती रहेगी।

मुस्तिम क्रान्तिकारी

अप्रेजों से असंतुष्ट होकर मुस्लिम नौजवान गुप्त संगठनों में सगठित हो रहे थे, परन्तु अभी तक उनका ध्येय भारतीय प्रजातंत्र की स्थापना नहीं था, वे धार्भिक संकीर्णता में अधिक फँसे थे। अतः उनकी इस प्रवृत्ति ने मुस्लिम राष्ट्रों का एक संघ स्थापित करने की कल्पना का उनके दिमाग में जन्म दिया । दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि उस समय पान इस्लामिज्म की भावना ही उनकी अंग्रेज विरोधी प्रवृत्ति का संचालन कर रही थी, परन्तु प्रसन्नता की बात यह है कि उनकी यह मिथ्या कल्पना वास्तविकता के सम्पर्क में त्राते ही तप्र हो गई। नव-तुर्की के राष्ट्रीय-प्रजातन्त्रीय आन्दोलन ने उनकी निराधार कल्पना की निर्शकता को स्पष्ट कर दिया, ध्यन्य मुस्लिम-राष्ट्रों के राष्ट्रीय रंग के सामने उनका धार्मिक रंग कच्चा श्रीर फीका मालूम हुआ। उन्होंने भी छाया का त्याग करके सत्य को बहुण किया। राष्ट्रीय प्रजातन्त्रीय क्रान्ति को अपना ध्येय बनाकर अपने कार्य कलाप का संचालन उसी च्योर करने लगे। इस समय मुस्लिम क्रान्तिकारियों का चैत्र देववन्द वन रहा था। यह स्थान फारसी और अरबी की शिका का संसार प्रसिद्ध केन्द्र है। दूर-दूर के देशों के विद्याव्यसनी मुसलमान अध्ययन के लिये यहाँ आते हैं। देवबन्द को केन्द्र बनाकर मुसलमान उत्तरी भारत में 'क्रान्तिकारी संगठन कर रहे थे। श्रन्य भारतीय क्रान्तिकारियों के साथ सम्पर्क स्थापित करके वे ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार को उखाड़ फेंकने के कार्य में उनके साथ पंक्तिबद्ध हो गये। इस एकता के परिणाम-स्वरूप देवबन्द के मौलवी शेख-उला-हिन्द, मौलाना महमूद-उल-इसन ने स्वर्गीय मौलाना खांबेदुल्लाइ सिन्धी को काबुल में टर्की और जर्मनी के राजदूतों से मारतीय मानी क्रान्ति में सहायता देने के सम्बन्ध में गुप्त बातें करने के लिये भेजा। श्रोवेदुल्लाह सिन्धा वहाँ से यूरोप चले गये और भारतवर्ष से बाहर रहकर भारतीयों को क्रान्ति के लिये संगठित करने

३६ हिंदुन्स्तान और पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेपण

लगे। उनके प्रयत्नों के भएडाफोड़ होने पर हिन्दुस्तान में "रेशमी क्सालों का पड़यन्त्र" चला था। यूरोप में उन्होंने अवन्य भारतीय कान्तिकारियों के साथ "भारतीय क्रान्तिकारी प्रजातन्त्रीय सरकार" की स्थापना की।

शिवली नोनानी नामक मुसलमानों में उर्दू के एक प्रसिद्ध लेखक हुये, साहित्य में उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना का चित्रण किया। असलमानों में राष्ट्रीय विचार की फैलाने में उनका निशेष हाथ रहा है। सन् १६१२ ई० में डा० अन्मारी एक मेडिकल मिशन टर्की को लेकर गये। मौ० अव्दुल कलाम आजाद ने "अलहेलाल" नाम का अखवार प्रकाशित किया, इनके अतिरिक्त मौ० गुहम्मद अली ने "कामरेड" (साथी) नामक अंग्रेजी और "हमदर्न" नामक उर्दू पत्रों का प्रकाशन प्रारम्भ किया। इन लोगों के प्रयत्न से मुसलमानों में भारतीय राष्ट्रीयता की मायना कूट-कूटकर भरी जाने लगी।

राष्ट्रीय रूप में ग्रुस्लिम लीग

सन् १६०६ ई० में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, उस समय इसका मुख्य उदेश्य था मुललमानों में राजभक्ति का प्रचार तथा मुस्लिम-चंत्रेज मैत्री काचम करना। परन्तु कालान्तर में खपने प्रतिक्रियावादी मिद्धान्तों पर टिकी न रह सकी। भारतीय राष्ट्रीयता के प्रभाव के सामने इसे भी मुकना पड़ा। सन् १६१३ ई० के अपने वार्षिक अधिवेशन, लखनऊ में अपने उद्देश्य में मुस्लिम लीग ने संशोधन किया कि ब्रिटिश सरकार की छत्रछाया में न्वायत्त-शासन कायम करना आवश्यक है। सन् १६०६ ई० के स्वीकृत प्रस्तावों और १६१३ ई० के

लखनऊ च्यिवेशन के स्वीकृत प्रस्तावों पर दृष्टि डालते ही ध्याकाश-पाताल का अन्तर दिखाई पड़ेगा। च्यव च्यपनी सात वर्ष की जिन्दगी के वाद मुस्लिम लीग राजमिक का प्रचार करने को शपथ लेने वाली संस्था नहीं रही; विक ब्रिटिश साम्राज्यवाद की छत्रद्वाया में स्वायत्त-शासन की स्थापना की ध्यपना डेश्य इसने वनाया है।

उक्त वातों से यह ररप्ट हो गया था कि भारतीय मुखल्मान अंत्रेजों द्वारा फैलावे नाह-जाल का भंग कर चुके थे। अब स्वायत्त-शासन की साँग करने लगे थे। वे प्रजातंत्र के कायल हो चुके थे, उसकी स्थापना को उचित और सहा समकते लगे। उन ही राजनीति प्रतिक्रियाबादी पथ का परित्याग कर प्रगति-शील पथ, अनुसरण कर रही थी। सन् १६१६ ई० में मुस्तिम लीग के लखनऊ वार्धिक श्रधियेशन के सभापति के पढ़ से दिये गये जिल्ला साह्य के भाषण पर आप एक दृष्टिपात की जिथे, श्रापको स्वष्ट ही दिखाई देगा कि मुस्लिम राजनीति का विल्कुल ही कायानलट हो गया है। जिल्ला साह्य के वक्तृता के उन अशीं की, जहाँ भारत में प्रजातंत्र की स्थापना के लिये उनकी व्यवता वकट होती है, हम पाठकों के ज्ञानार्थ उद्युत करते हैं -- 'वायहात राजनीतिक उक्तियों का निर्माण किया गया है च्योर बहुवा भारतीयों पर उन्हें च्यारोपित किया गया है। राजनीतिक के विद्यार्थी उनसे भली-भाँति परिचित हैं । उदा-हरणार्थ, यह कहा जाता है कि "प्रजानंत्रीय संस्थायें" पूर्व के लोगों की बुद्धि के प्रतिकृत हैं। क्या 'प्रजातंत्र' हिन्दू और मसलमानों के लिये अनोखी चीज है ? यह प्रश्न जिन्ना साहब ललकारते हुए पृष्ठते हैं और स्वयं ही उत्तर देते हैं—"तो फिर

ध्राम-पंचायतें क्या थीं ? इस्लाम का गौरवमय ऋतीत जिस बात को प्रमाणित करता है ? दुनिया की कोई भी राष्ट्रीय जाति भुसलमानों से अधिक प्रजातंत्रीय भावों और परम्पराओं की दावेदार नहीं हो सकती हैं।" इस स्थान पर जिन्ना साहब ने प्राचीन भारत में "प्रजातंत्रीय संस्थार्था" की श्रोर प्रमाणित करने के लिये प्राम-पंचायतों का जो प्रमाण उपस्थित किया, वह श्रकाट्य सत्य है। सामाजिक तथा श्रार्थिक जीवन में प्रजातंत्रीय सिद्धान्तों का निरूपण का यह जीता। जागता नमूना है। यह पद्धित सिद्यों ईसा पूर्व से चली आ रही थी। जब तक अंभेजों के लौह पंजे से यह मसल नहीं दी गई, तव तक भारतीय सामाजिक जीवन को प्रभावित करती रही और एक विशेष कार की एकता प्रदान करती रही। पंचायतों की एक ही प्रकार की व्यवस्था, एक ही प्रकार से उनके द्वारा आर्थिक जीवन का संचालन तथा सामाजिक एवं नागरिक नियमों का निर्माण, श्रादेश तथा न्याय, भारतीय जनता की एकता का शबल शमाण उपस्थित करती हैं। अंग्रेज अपनी शासनभित्ति को हढ़ बनाने के लिये भारतीयों को आपसी फूट श्रीर वैमनस्य को हढ़ आधार समकर जहाँ एकता के सभी चिन्हों तथा संस्थाओं को नष्ट कर रहे थे, वहाँ भारतीय-प्राम-पंचायतें भी इनकी क्रूर हिट से बची न रह सकीं।

लखनऊ पैक्ट:-हिन्दुस्तान श्रीर पाकिस्तान की नींव

सन् १६१४ ई० में प्रथम संसार-व्यापी साम्राज्यवादी युद्ध आरम्भ हुआ। संसार के प्रमुख्य पूँजीवादी औद्योगिक देश सब के सब करीब-करीव युद्ध के संचालन में व्यस्त हो रहे थे।

पिछड़े हुए उपनिवेशिक देशों को अपने यहाँ खौद्योगिक विकास करने का अवसर पात हुआ। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का प्रमुख्य उपनिवेश हिन्दुस्तान था । साम्राज्यवादी युद्ध को भारत य मध्यम वर्ग ने यहाँ श्रौद्योगिक तथा पूँजीवादी विकास करने के लिये अच्छा मौका समका । अतः ब्रिटिश चत्रद्वाया में भारतीय स्वायत-शामन की स्थापना गण्टीय कांग्रेस श्रीर मुस्लिम लीग दोनों का राजनीतिक डे श्य था ! परन्तु भारतीय जनता पूँजीवाद के विकास के लिये युद्ध-काल को सुअवसर समफकर किसी भी पकार का अड़चन लड़ाई के संचालन में नहीं डालना चाहतो था। एक श्रोर तो भारतीय क्रान्तिकारी नौजवान जान की बाजी लगाकर आजादी हासिल करने के हेतु सशस्त्र क्रान्ति की तैयारी तथा संगठन कर रहे थे, दूसरी ऋोर राष्ट्रीय कांग्रेस श्रीर मुस्लिम लीग साम्राज्यवादी युद्ध के संचालन में हर प्रकार की सहायता कर रही थी। इन्हें आशा थी कि युद्धोपरान्त "भारतीय स्वायत्त-शासन" के रूप में राजनीनिक सुधार अवश्य दिया जायेगा । अतः साचाज्ययादी युद्ध के संचालन में अधिक सहायता करने के और राजनीतिक सुधार के कार्यान्वित करने के हेतु राष्ट्रीय कांग्रेस श्रीर मुस्लिम लीग के बीच सन् १६१६ ई० में लखनऊ में एक समसौता हुआ जिसके अनुसार प्रजातंत्रीय संस्थाओं का चुनाव पृथक निर्वाचन कें।सिद्धान्त के अनुसार होगा। यह "लखनऊ पैक्ट" के नाम से मशहूर है।

क्रान्तिकारी अन्दोलन की वित्वेदी पर मुस्लिम क्रान्तिकारी जपर हम सन १६१४ ई० के विश्व-युद्ध के अवसर पर भारतीय क्रान्तिकारियों की तैयारियों का वर्णन कर चुके हैं। अब उनका परिणाम भी पाठकों के आगे आंशिक रूप में उपस्थित किया जाता है। हिन्दू-मुस्लिम क्रान्तिकारियों के संयुक्त प्रयत्न के विषय में हमने ऊपर देखा है। अब हम उनके संयुक्त बिलवान पर दृष्टिपाल करें। यहाँ पर केवल कुछ मुन्लिम क्रान्तिकारियों का ही इस उल्लेख करेंगे। स्वर्गीय अवेदुल्लाइ निन्धा, मौ० अब्दुल कलाम आजाद, मीलाना मुह्म्मदुल्ह्सन, जो सुललमानों के मुल्ला थे, भारतवर्ष के बाहर कारागार को यानकार्यं सह रहे थे। भारतीय जेलों में हसरत मोहानी, शोंकत ऋली श्रीर मृहस्मद श्रली वगेरह भारत की आजादी का मुल्य चुका रहे थे। जिस समय क्रान्तिकारी वीर फाँसी के नस्ते पर. जेजों के सीकचों के भीतर स्वतंत्रता के लिये जापना सब कुछ निछाबर कर रहे थे, उस समय गांधी जी तथा राष्ट्रीय कांत्रेस और मुस्लिम लीग ब्रिटिश सेना के लिये एंगरूट भरती कर रही थीं। सला ऐसे समय जब देश की एक वड़ी संख्या स्वयं ही क्यान्त की जड़ पए क्रुठाराघात कर रही हो, तो कान्तिकारी कहाँ से भापने जीवत उद्देश्य को कार्यान्वित बताने में सफल होते। वे भारतीय जनता की विदोहारिन को प्रज्वलिन रखने के लिये अपने प्राणों को स्वाहा करके शहीद पय के श्रतुगामी हो रहे थे। त्रिटिश सरकार समक गई कि क्रान्ति-कारियों का दमन यदि न किया गया तो वह भारतवर्ष में गिने दिनों का ही मेहमान है। इस डेश्य की पूर्ति के लिये रौलट एक्ट का निर्माण किया गया। सारा देश एक स्वर से इसका विरोध कर उठा, जनता के लिये क्रान्तिकारियों का दमन असध था । भारतीय हिन्दू-मुस्लिम जनता क्रान्ति के पन्न में किस हद

तक थी, क्रान्तिकारियों के लिये उनके दिलों में कितनी सहानुभूति और अद्धा थी, इसका यह ज्वलन्त प्रमाण है।

रौलट-एक्ट

सन् १६१४ ई० से विश्व-युद्ध का युग भारतीय पूँजीवाद के ऋविभाव और विकास का युग था। साम्राज्यवादी युद्ध छिड़ जाने के कारण भारतीय पूँजीवाद के विकास तथा उन्नति के लिये । स्वाभाविक संरक्तणे प्राप्त हो गया था। जिसके परिणाम-स्वरूप भारतीय पूँजीवाद गत महायुद्ध के अवसर पर उन्नति कर रहा था। अब क्या था, भारतीय पूँजीवादी वर्ग के दलालों का हित साथन ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार को सहायता करने पर निर्भर था। उन्होंने दिल खोलकर सहायता की। इसके वदले में उन्हें आशा थी कि युद्धोपरान्त उन्हें स्वायत्त-शायन प्राप्त होगा । युद्ध के समाप्त होते ही ब्रिटिश पूँजीबाद तथा पूँजीबादी वर्गको द्यपने ही व्यस्तित्व की रह्मा की ह्या पड़ी, उसे ह्यपनी उन्नतिशील नथा विकसित ह्यवस्था को कायम रखने के लिये हिन्दुस्तान से कच्चे माल तथा पक्के माल की खपत के लिये हिन्दुस्तान का बाजार आवश्यक था। श्रतः हिन्द्स्तान को किसी प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करना उनके हिन के लिये घातक था । उनके इस रुख से भारतीय पूँजीवाद को गहरी निराशा हुई, उसकी सभी आशाओं पर पानी फिर गया। भारतीय पुँजीबादी वर्ग ने यह अनुभव किया कि ब्रिटिश पूँजीवादी वर्ग के तथा उनके आधिक स्वार्थी . के वीच संघर्ष तीव हो उठा है और उन्हें इसमें सफलता की श्राशा तब तक नहीं करनी चाहिये जब तक उन्हें राज की श्रोर

से पंरत्तण नहीं प्राप्त होता अथवा भारतीय जनता भारतीय उद्योग-धन्धों को नहीं अपना लेती हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार से संरत्तण को आशा करना व्यथ था। भारतीय जनता के सीहार्द पर उनके रोजगार का भिविष्य निर्भर था। अतः उनकी (जनता की) सहानुभूति प्राप्त करना उनके लिये आवश्यक हो गया। लेकिन जनता के हितों की उन्होंने युद्ध के अवसर पर उपेत्ता की थी और उसमें काफी बदनाम हो चुके थे। अतः उनके दलालों को जनता के बीच जाने का साहस न था और वे इस अवसर की ताक में थे कि जनता के शुभ-चिन्नक बनकर उसके बीच में जा सकें और उसके अन्दर राष्ट्रीय भावना भरकर उन्हें संगठित करके सक्ज बाग दिखा कर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये उन्हें प्रयोग कर सकें।

हमने देखा है कि दमन के साथ-साथ राजनीतिक सुधार जनता की बिद्रोह प्रवृत्ति को शान्त करने के लिये श्रावश्यक होता है। ब्रिटिश सरकार शासन नीति के इस मूल मन्त्र का सदैव प्रयोग करती रही है। गत महायुद्ध के उपरान्त इस नियम का उल्लंघन उसने ठींक न समका। राष्ट्रीय कांग्रेम वगैरह सुधारवादी संस्थाएँ सुधार की तरफ टकटकी लगाये देख रही थीं। सुधार कपी रोटी के दुकड़े के बँटवारे की तैयारी भी वे कर चुकी थीं। "लम्बनऊ पैक्ट" जिमका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, इसी सुधार को कार्यान्वित करने के लिये ही किया गया था। इसका उरिय भारतीय कान्तिकारी लड़ाई को बढ़ाकर श्राजादो हासिल करना नहीं था; बिक सुधार भारतीय पूँजीवाद तथा पूँजीवादी वर्ग के विकास के वार्षिक अधिवेशन कई वर्ष तक एक समय और एक साथ, एक ही स्थान में होते रहे । मुस्लिम लीग और कांग्रेस के सम कौते में प्रगतिशील माँगे रक्खी गई थीं। प्रजातंत्र की जो माँग रक्खी गई थी, वह उस समय की हिन्दू-मुस्लिम जनता की भावना का द्योतक है, जिसको सन्तुष्ट करने के लिये इस मुस्लिम और हिन्दू पूँजीपतियों की गुट्टने विवश होकर स्वीकार किया था।

अन्ततोगत्वा सन् १६१६ ई० का सुधार भारतवर्ष में लागू किया गया, किन्तु भारतीय पूँजीवाद के विकास के लिये यह श्रपर्याप्त था। जनता को साथ लिये विना श्रीर सीधे संघर्ष किये विना ब्रिटिश सम्कार से श्रीर सुधार की श्राशा करना केवल वालू से तेल निकालने की आशा के समान ही हम पहले कह चुके हैं कि स्रवसरवादी-सुधारवादी भारतीय पूँजीयाद के समर्थक इस अवसर की ताक में थे ही कि किसी प्रकार भारतीय साधारण जनता में जाकर अपनी कलंक कालिमा को छोड़ा लें और उनका विश्वास प्राप्त कर सकें। यह श्रवसर उन्हें मिल गया । क्रान्तिकारियों के दमन के हेतु निर्मित रोलट एक्ट का विरोध जनता कर रही थी, इस अवसर को इन श्रवसरवादी सुधारवादियों ने श्रनुकुत सममा श्रीर गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय कांग्रेस ने रीजट-एक्ट के विरोध में प्रदर्शन किया और जनता के खोये हुए विश्वास को पुनः प्राप्त करने लगी। इस ऐक्ट का विरोध सबसे अधिक जलियाँ वाला बाग में प्रदर्शित हुआ।

"खिलाफत" आन्दोलन

प्रथम विश्व-च्यापी युद्ध की समाप्ति पर भारतीय मध्यम श्रीर

(ंजीवादी वर्गों की वड़ी-बड़ी खाशायें एक-एक कर**के** तप्ट होने लगी ब्रेभी हमने सुवार के द्वारा भारतीय पृंजापतियों की आशानता ार तुपारपात कः वर्णन किया है। श्रेयागे श्रव इस वात का वर्णन किया जायगा कि अंग्रेजी सरकार की दूसरी नीति ने किल प्रकार सारतीय मुसलमानों की धार्मिक मावनाच्यों को वक्का पहुँचाया च्योर उन्हें चांबेजी सरकार के विरुद्ध संवर्ष करने पर विवश कर दिया । प्रथम विश्व-ग्यापी युद्ध सित्र-राष्ट्री के पत्त में समाप्त हुआ। लड़ाई के दरम्यान ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार की चौर से मुमलमानों को यह चारवासन विया गया था कि युद्ध की सफलता के उपरान्त टर्की के साथ अनुचित व्यवहार तथा अरेत्रिया और मेसोपोटेणिया में मुस्तिम-धार्मिक स्थानों के विषय में कोई ऐसा काम नहीं किया जायेगा जिससे मुसलमानी की धार्मिक भावनात्रों को चोट पहुँचे। परन्तु विजय के उपरान्त इसके विपरीत रुख उसने श्रपनाया । सन् १६१८ ई० में बिटेन और फान्स के द्वारा यह कहा गया कि जर्मनी की महत्वा कांचा के कारण फान्स जीर. ब्रिटेन का पूर्व में युद्ध के संचालन का ध्येय निश्चित एवं पूर्ण इदप से उन लोगों का उद्धार करना जो श्रव तक तुर्की की पराधीनता में हैं, तथा स्वतंत्र राष्ट्री तथा स्वतंत्र राष्ट्रीय सर कार की स्थापना करना है, जो अपना अधिकार वहाँ की असली निवासी जनता को सुक्त इच्छा से प्रहण करेगी । परन्तु प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर जो शान्ति स्थापित हुई, उससे मुस्लिम-धार्मिक शहरों को स्वतंत्रता नहीं प्राप्त हुई । इसके खिलाफ हिन्दुस्तान में जोरों से आवाज उठाई गई और शीघ्र ही इस मुखालिफत की आवाज ने "खिलाफत" आन्दोलन का रूप धारण कर लिया। यहाँ से ''खिलाफत'' आन्दोलन का श्री-गणेश होता है। हिन्दू और मुसलमान दोनों ने इसमें भाग लिया। इसका संचालन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संयुक्त नेतृत्व के द्वारा होने लगा। इसके फलस्यरूप हिन्दू और मुस्लिम मध्यम और पूर्जावादी वर्गा के बाच प्रतिक्रियावादी धार्मिक आधार पर चीिएक कालीन एकता की स्थापना हुई। परन्तु त्रिटिश सामाज्यवादी सरकार इस मध्यम वर्गाय एकता के अन्दर भावी श्रनिष्टकारी क्रान्ति के निहित बीज से सरांकित एवं भयभीत हो उठी। अब उसे किसी न किसी प्रकार जनता की क्रान्ति के सार्ग पर चलने से रोकना था। इसके लिये तत्कालीन भारत सचिव मार्ग्टेम्यू और वाइसराय लार्ड रीडिंग ने परामर्श किया और इस नतीजे पर पहुँचे कि लार्ड रीडिंग सम्नाट् की सरकार के पास मुसलमानों को असन्तुष्ट करने वाली कार्रवाइयों को रोकने के लिये तार भेजें और इस बात को सम्राट की सरकार पर स्पष्ट कर दंकि मुख्लिस धार्सिक नगरों पर अपनी प्रभुता स्थापित करने की नीति का भारत में ब्रिटिश स्वार्थों पर घातक प्रभाव पड़ रहा है। भारत सचिव चौर वाइसराय के परासर्श तथा निष्कर्ष का वर्णन 'राय स्मिथ' ने अपनी पुस्तक "भारत में राष्ट्रीयता तथा सुधार" में इस प्रकार किया है। ब्रिटिश सरकार की तुर्क विरोधी नीति से मि० माय्टेग्यू और लाई रीडिंग दोनों ही भयभीत हो गये और मि॰ माएटेंग्यू ने एक साहसिक एवं स्वाभाविक उपाय का ऋवलम्बन किया। जन्होंने वाइसराय को अपने पास तार भेजने का आ**देश** दिया । तार में वाइसराय ने सम्राट्की सरकार का ध्यान भारतीय मुसलमानों के दावे का सम्पूर्ण भारत से प्राप्त समर्थन की छोर आकर्षित किया था, और इस प्रकार की प्रार्थना की गई थी कि कुन्तुन्तुनियाँ खाली कर दिया जाय और आरमन तथा समर्ना पुनः वापस कर दिये जायें। तार के अन्त में यह कहा गया था कि उन तीनों बातों का मान लेना भारत के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

जमायतुल-उलेमाय-हिन्द की स्थापना

सन् १६१६ ई० में दिल्ली में खिलाफत कान्प्रेंस हुई श्रीर इस अवसर पर उल्मा लोगों ने अपने को संगठित करने का प्रयत्न किया। सन् १८४७ ई० के बाद उल्मा लोग प्रायः राज-नैतिक जीवन से त्रिमुख हो गये थे। राजनीति में सकिय भाग न लेने पर भी उनका अंग्रेजी विरोधी भाव अभी तक पूर्ववत् विद्यमान थे। इस अवसर पर उनके ब्रिटिश-विरोधी भावों ने मकट रूप धारण किया श्रीर उन्होंने "जमायतुल-उलेमाय हिन्द्" नामक राजनीतिक संस्था की नींव डाली श्रीर श्रपनी दीर्घकालीन खदासीनता को त्यागकर वे राजनीति में सिकय भाग लेने लगे। इस नवजात संगठन के प्रथम सभापति मुसलमानों के प्रधान धार्मिक एवं विख्यात राष्ट्रीय क्रान्तिकारी मुहम्मदुल्हसन निर्वाचित हुए। महायुद्ध के अवसर पर बिटिश विरोधी भारतीय क्रान्तिकारी षड्यन्त्रीं से सम्पर्क होने के कार्ए उन्हें माल्टा के कारागार में बन्द रखा गया था। वहाँ से छूट कर जब वे पुनः अपने देश वापस आये, तो देशवासियों ने आपके प्रति यथेष्ठ सम्मान श्रीर प्रतिष्ठा का प्रदर्शन किया। 'जमायतुलडलेमा' के सभापति के पद से पुनः प्राग्णपण से

त्रिटिश विरोधी कार्य. में लीन हो गये। सन् १६२१ ई० में 'जमायतुल उलेमा' ने भारतीय मुसलमानों के नांम एक 'फतवा' निकाला। भारत की राजनीति में धर्म गुरुष्टों की श्रोर से स्वतन्त्रता संप्राम में मुसलमानों का श्रह्वान सन् १६४७ ई० के बाद यह प्रथम बार हुआ। 'फतवा' में मुसलमानों को श्रंप्रेजी सरकार के विरुद्ध श्रमहयोग करने का श्रादेश दिया गया था।

राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इसी अवसर पर आन्दोलन प्रारम्भ किया, परन्तु इसका अभिप्राय स्वतन्त्रता शिप्त के लिये जन-धान्दोलन चलाने का नहीं था। वह किसी प्रकार जनता को अपने साथ रखकर बिटिश सरकार पर दबाव डालकर अधिक से अधिक सुधार तथा सुविधायें प्राप्त करना चाहती थी। इस का हम उपर वर्णन कर आये हैं कि भारतीय जनता कान्ति-कारियों के दमन के हेतु निर्मित 'गैलट-ऐक्ट' से बहुत असन्तुष्ट थी। अतः कांग्रेस के सुधारवादी मध्यम वर्गीय नेतृत्व जनता की इस इच्छित माँग को आगे रखकर उनके प्रियपात्र बनकर उनका समर्थन, सहयोग और सहानुभूति प्राप्त करने में सफल हुये। यही उनका उद्देश्य था, इसके अतिरिक्त उनके द्वारा संचालित आन्दोलन का अन्य कोई उद्देश्य न था और न उन्होंने कोई स्पष्ट कार्यक्रम ही रखा था। वे सुधार प्राप्ति के लिये जनता को अपने साथ करना चाहते थे, जिसमें उन्हें काफी सफलता भी निला।

असहयोग आन्दोलन

सन् १६२१ ई० के श्रसहयोग श्वान्दोलन को स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये श्रान्दोलन समसना बड़ी भारी ऐतिहासिक भूल होगी। इसकी विशेषता यह था कि न तो यह जन-चान्डोलन ही कहा जा सकता था और न इसका घ्येय म्वतन्त्रता प्राप्ति ही था। यदि हम तत्कालीन आन्दोलन पर एक आलोचनात्मक हिट्ट डालं त्तो बास्तविकता स्वतः स्पष्ट हो जायगी। सन् १६२१ ई० में श्चस धोग श्चान्दोलन प्रारम्भ किया गया, पर फिर भी स्वतंत्रता की माँग नहीं रक्खी जाती है, जब कि भारतवर्ष के क्रान्तिकारी वर्षी से इम उद्देश्य की पूर्ति के लिये हजारी की संख्या में बिल चढ़ चुके थे चौर ऋधिक संख्या में जेलों की कठोर यात-नायें भुगत रहे थे। अपने प्रांगों की आहुति देकर जनता के हृद्य में भी उन्होंने स्वतन्त्रता की श्राप्त की प्रज्विता कर दिया था, फिर इस पर पटाचेप क्यों किया गया ? इसका उत्तर यही है कि राष्ट्रीय कांत्रेस ने शोपित एवं पीड़ित व्यायत जगता की माँग को लेकर आन्दोलन नहीं चलाया था। उनकी व्यथाओं श्रीर पीड़ाश्रों का विना स्वतन्त्रता के श्रन्त कहाँ था ? श्रतः यह जन-त्र्यान्दोलन नहीं कहा जा सकता। तो फिर यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि फिर इसका क्या रूप था? यह आन्दोलन मध्यम वर्ग का था, जो सुधार के लिये भूग्वा रहता है और बह जनता का सहयोग वहीं तक चाहता है जहाँ तक उसके अभीष्ट की सिद्धि हो और जैसे ही जनता अपने दुःख के निवार्गार्थ क्रान्ति पथ का श्रवसरण करती है तथा राज-सत्ता एवं श्रपनी निर्धनता के मूल कारण सामाजिक ढाँचे की जड़ पर प्रहार करती है, वैसे ही यह वर्ग जन-आन्दोलन का विरोधी हो जाता है; छान्दोलन को रोकना चाहता है, यदि शान्तिमय उपायों द्वारा न रोक सका, तो हिंसात्मक उपायों का भी इप्वलम्बन करता है। जनता तो किसी लड़ाई में जिसमें उसकी अवस्था को सुधारने का आश्वासन होता है, शरोक हो जाती है और इसे तुरन्त अपने हित साधन के लिये स्वाभाविक क्रान्तिकारी रूप प्रदान करती है। तो क्या यही अवस्था कांग्रेस आन्दोलन की भी हुई ? ठीक ऐसी ही । जैसे ही सन् १६२१ ई० में असहयोग च्यान्दोलन छिड़ा, जनता स्त्रराज्य के नाम पर दीवानी हो गई ष्प्रीर इसमें कृद पड़ी। श्रहिंसा की संकुचित सीमा में श्यान्दोलन सीमित रहने से उनकी समस्या हल नहीं होती। श्यत: तुरन्त ही इसका उल्लंघनकर श्रपना हित क्रान्ति के विशाल पथ पर ढूँढ्ना प्रारम्भ किया । जनता के हाथों पड़ कर ज्यान्दोलन ने जैसे ही क्रान्ति पथ का अनुसरण किया कि धनी वर्ग थरी उठा। उसे अपनी लदमी विचलित होती प्रतीत हुई। खतरे भी घंटी बज उठी। तुरन्त श्रान्दोलनं को रोकने का प्रयत्न किया जाने लगा। राष्ट्रीय कांग्रेस की अखिल भारतीय कार्यकारिगी कमेटी की बारदोली बैठक में एक प्रस्ताव पास करके इस आन्दोलन को वन्द करने का आदेश दिया गया।

यहाँ पर यह उल्लेख करना असंगत न होगा कि मुसलमानों में गुलामी के प्रति इतनी घृणा उत्पन्न हो गई थी कि ३६००० मुसलमानों ने गुलाम वनकर रहने की श्रपेत्वा अपनी जन्मभूमि का त्याग करना उचित समका और भारत छोड़कर दूसरे मुल्कों में चले जाना अंच्छा समका।

उपरोक्त बार्ती को ध्यान में रखते हुए क्या हम कांत्रेस द्वारा संचालित सन् १६२१ ई० के आन्दोलन को स्वतन्त्रता प्राप्ति का जन आन्दोलन कह सकते हैं ? कदापि नहीं। यहाँ पर एक बात ध्यान से देखने की आवश्यकता है। असहयोग आन्दोलन के इतिहास का आलोचनात्मक अध्ययन से यह स्तप्टतः ज्ञान होता है कि आम भारतीय जनता में किसी प्रकार का ।हन्दू-मुस्लिस भेदभाव दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था, उनका स्वार्थ एक था, उनका शत्रु एक था, जिसके विरुद्ध दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर खून की धारा बहाई। जब कभी शत्रु से लड़ने का अबसर हुआ, उनकी एकता स्पष्ट रूप से लिखत हुई है। यह उनकी परिस्थितजन्य स्वाभाविक एकता है। इस बात को ध्यान में रखकर ही हम उनके बीच उत्पन्न किये गये भेदभावों और मनोमालिन्य की कृत्रिमैता को पूर्णरूपेण समक सकेंगे।

श्रप्तह्योग श्रान्दोलन के बाद कांग्रेस का रचनात्मक कार्य-क्रम

सन् १६२२ ई० में असहयोग आन्दोलन बन्द कर दिया गया । राष्ट्रीय कांग्रेस के सुधारवादी मध्यम वर्गीय नेतृत्व ने आन्दोलन को बन्दकर चर्चा, हरिजन सेवा तथा आम-सुधार हिन्दू-मुस्लिम एकता आदि के रूप में 'रचनात्मक कार्य-क्रम को और एसेम्बली वर्गरह में जाकर स्वराज्य की लड़ाई' करने का बैधानिक कार्य-क्रम को अपनाया। अर्थात् जो कुछ बिटिश सरकार ने राजनीतिक सुधार प्रदान किया था उसे राष्ट्रीय कांग्रेस के सुधार-वादी मध्यम वर्गीय नेतृत्व कार्यान्वित करने लगाय हाँ यह। कहना अनुचित न होगा कि इसने संघर्ष के मार्ग की तिलाञ्जलि देकर सुधारवादी वैधानिक पय को प्रहण किया। इसका स्वामाविक परिणाम जो होता है वही हुआ। एक और तो कांग्रेस के कार्य-क्रम हिन्दू-सुस्लिम एकता का कार्य-क्रम सिमाजित है, दूसरी कोर इसके सुधारवादी और वैधानिक कार्य-क्रम को कार्यान्वित करने के फलस्वरूप हिन्दुस्तान भर में जहाँ-तहाँ हिन्दू-मुस्लिम दंगा होने लगा। यह है कांग्रेस के सुधारवादी और वैधानिक रचनात्मक कार्य-क्रम का परिणाम। भारतीय जनता की एकता के स्थान पर साम्प्रदायिकता की प्रतिक्रियाबादी प्रवृत्ति उत्पन्न की जाने लगी। यह कांग्रेस के रचनात्मक कार्य-क्रम! उत्पर हम देख चुके हैं और आगे भी देखेंगे कि राष्ट्रीय कांग्रेस के वैधा-निक तथा सुधारवादी कार्य-क्रम के विस्तार के साथ-साथ साम्प्रदायिकता का भी रूप उप्रतर होता गया।

साम्प्रदायिक दंगा

साम्प्रदायिक दंगे के सम्यन्ध में अपनी पुस्तक "इंडिया डिवाइडेड" (India Divided) में श्री डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद लिखते हैं कि "अगर निष्पत्त होकर गत् तीस साल के दर्रामयान के साम्प्रदायिक दंगे के इतिहास का अध्ययन किया जाये, तो यह ज्ञात होगा कि देश के राजनीतिक इतिहास की नाजुक परिस्थित में अपने ढंग के दंगे होते रहे हैं।" [पेज ११७] दूसरे स्थान में राजेन्द्र वाबू आगे कहते हैं कि "वास्तविकता यह है कि बहुत से साम्प्रदायिक दंगों का राजनीतिक कारण रहता है, हालाँकि अपर से यह जाहिर होता है कि धार्मिक पागजपन के कारण हुए हैं।" [पेज ११८]

बावजूद ब्रिटिश सरकार की कृटनीति के होते हुए भी सुधारवादी पथ पर हिन्दू-मुस्लिम एकता की स्थापना सम्भव ज्ञान हो रही थी, इसे मंग करने का उपाय ब्रिटिश सरकार करने लगी। कई वर्ष से यू० पी० में कचहरियों में देवनागरी लागू करने के लिये आन्दोलन चल रहा था। परन्तु जब ब्रिटिश सरकार ने देखा कि राजनीतिक सुधार देना आवश्यक है, उस समय सन् १६०० ई० में यू० पी० की कचहरियों में देव नागरी [Nagri Script] लागू करने की आज्ञा जारी की । इसके फलस्वरूप हिन्दू और मुसलमानों में वैषम्य पैदा अवश्य हुआ।

थह ठीक है कि कान्तिकारी अपने प्रयास में असफल श्रवश्य रहे, लेकिन कान्तिकारी शक्तियाँ कुत्रली नंहीं जा सकीं। श्रतः युद्धोपरान्त राजनीतिक सुधार हिन्दुस्तान में लागू करना त्रिटिश सरकार ने त्रावश्यक सममा । इसके पहले हिन्दू-मुस्लिम वातावरण को खराब करना आवश्यक समका। सन् १६१७ ई० के अनितम भाग में शाहाबाद जिले (विहार) में वड़ा भारी हिन्दू-मुस्लिम द्ंगा शुरू हुआ। यू० पी० में कानपुर शहर में भी सन् १६१८ ई० में जोरों का दंगा हुआ। इसके बाद फिर सन् १६२२ ई० के अन्त में साम्प्रदायिक दंगे प्रारम्भ हुए। यह करीव-करीब सन् १६२७ ई० तक हिन्दुस्तान में कहीं न कहीं होता रहा। यहाँ पर यह उल्लेख करना अनुचित न होगा कि श्रमहयोग आन्दोलन के वन्द होते ही सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और ६ वर्ष का कठोर दंड सिला। परन्तु दो वर्ष में ही जेल से छूट गये। बाहर त्राते ही साम्प्रदायिक दंगे के खिलाफ सन् १६२४ ई० में उन्होंने अनशन किया। इसका कुछ असर अवश्य हुआ। परन्तु दंगा एकदम बन्द नहीं हो सका।

क्रान्तिकारी आन्दोलन

सन् १६२० ई० तक फाँसी और गोली से बचे हुए क्रान्तिकारी

जेलों के सीकचों के अन्दर सड़ रहे थे। इसके बाद धीरे-धीरे जेलों से बाहर निकाले जाने लगे। सन् १६१७ ई० लेनिन के क्रान्तिकारी नेतृत्व में रूस की श्रमिक शोपित जनता शासन सत्ता पर कब्जाकर अपनी पंचायती व्यवस्था कायम कर चुकी थी, जिसका प्रभाव हिन्दुस्तान के क्रान्तिकारी आन्दोलन यर भी पड़ा । साम्राज्यवादी युद्धोपरान्त संसार के और देशों जैसा हिन्दुस्तान में भी क्रान्तिकारी परिस्थित विकसित तो अवश्य हुई परन्तु ब्रिटिश सरकार के दमन के कारण क्रान्तिकारी पार्टी का संगठन कमजोर श्रौर छिन्न-भिन्न हो रहा था। अभी भी बचे हुए क्रान्तिकारी अविकांश जेतों में ही बन्द थे। जब वे छोड़े गये, तब उनके सामने गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का श्रमह्योग श्रान्दोलन खड़ा था। उसका समर्थन करना उन्होंने उचित सममा श्रीर किया। परन्त शीघ ही यह बन्द कर दिया गया किन्तु क्रान्तिकारी मैदान में डटे रहे श्रीर श्रपने संगठन को विकसित तथा मजबूत बनाने के प्रयास में वे जुट गये। फिर क्या था ब्रिटिश सरकार के दमन के प्रखर सूर्य की किर्लें निर्मल श्राकाश से सीधे उन्हीं पर पड़ने लगीं। उन्हें न तो एसेन्बली की नर्म गदियों की ही आवश्यकता थी और न वह चुपचाप अपनी कुटिया में ही विश्राम कर सकते थे। उनके जीवन का गठवन्धन भारतीय स्वतंत्रता से हो चुका था। अब उनका जीवन उद्देश्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता तक ही सीमित न रहा, बल्कि इसके उपरान्त वे एक ऐसी सामाजिक ज्यवस्था कायम करना चाहते जिसमें मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण सम्भव न हो सकेगा। इस सामाजिक ऐतिहासिफ उद्देश्य से प्रेरित हो क्रान्तिकारी खान्दोलन तथा संगठन संचालित हो रहा था। दिन प्रतिदिन यह शिक्तशाली होने लगा। परन्तु ब्रिटिश सरकार की आँखों से बचा नहीं रह सका। इसकी हिए पड़ी और इसके विकास प्रगति को देखकर भयावह हो उठी। तुरन्त इस खतरे से अपने अस्तित्व को सुरिक्त रखने के लिये क्रान्तिकारी संगठन के ऊपर दमन-चक घुमाने लगी। इसके शिकार हो सैकड़ों की तादाद में कुछ दिन के अन्दर क्रान्तिकारी जेलों में बन्द कर दिये गये।

साइमन कमीशन का आगमन

हम उपर देख चुके हैं कि असहयोग आन्दोलन के बन्द होते ही साम्प्रदायिक दंगे ने काफी जोर पकड़ा। सारे देश में हिन्दू-मुस्लिम दंगों का कुहराम मच गया। कल जो अभी भाई-भाई के सामने स्वाधीनता संग्राम में अपने खून वहा रहे थे, बही आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। प्रतिकिया-वादी शिक्तयाँ मजवूत हो रही थीं। साम्प्रदायिकता राष्ट्रीयता से बीस पड़ रही थी।

इस विपम परिस्थिति में जब कि राष्ट्रीयता अपना पथ भूल-कर साम्प्रदायिकता के अन्धकृप में गिर पड़ी थी और अपनी विनाश लीला स्वयं अपने हाथों पूरा कर रही थी, उस समय भी भारतीय क्रान्तिकारी धैर्य के साथ अपने पथ पर उटे हुए थे और जनता की चीए होती हुई क्रान्तिकारी शक्तियों को शिक्त तथा जीवन प्रदान करने की भरपूर चेष्टा कर रहे थे। साम्प्रदायिकता के कीटाए, राष्ट्र के शरीर में प्रवेश करके उसे प्राय: निष्प्राण बनाने के प्रयत्न में थे, उस समय उन्होंने (क्रान्तिकारियों ने) अपने शरीर का स्वस्थ रक्त देकर पुनः राष्ट्र में इतनी शक्ति भर देने का प्रयत्न कर रहे थे कि वह स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिये कान्ति पथ पर चल सके । क्रान्तिकारियों के प्रयत्नों से पुनः जागृति के चिन्ह दिखाई देने लगे और जनता की गति धीरे-धीरे क्रान्ति पथ पर तीजनर होने लगी। यह स्थिति ब्रिटिश सरकार से छिपी न रह सकी। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि दमन पूर्ण रूप से जनता की कान्तिकारी मनोवृति को कुचलने में सफल नहीं हुआ है और न हो सकता है। जब क्रान्तिकारी शक्तियों को विनाश करने के प्रयत्न में उनका "मारण मन्त्र" निष्फल गया तो उन्होंने "मोहन मन्त्र" का आश्रय लिया और भारत को सुधार देने की तैयारी की जाने लगी। सन् १६२७ ई० में सर साइमन के नेतृत्व में एक कमीशन भारत-भाग्य विधाता बनाकर ब्रिटिश पार्लियामेन्ट हारा भारतवर्ष में भेजा गया । इसके सदस्य सब के सब श्रंमेज थे। इसे यह जाँच सुपुद की गई कि भारतवर्ष किस हद तक "वैधानिक सुधार" प्राप्त करने की त्तमना रखता है श्रीर उसको वह "सुधार" किस समय दिया जाय।

दिन प्रतिदिन भारतीय और ब्रिटिश पूँजीवादी वर्ग के बीच का संघर्ष स्पष्ट और तीव्रतर होता जा रहा था। इसका प्रभाव भारतीय वर्गों के अपर भी कुछ न कुछ अवश्य पड़ा। साइमन कभीशन कुछ सुधार देने आ रहा है, यह जानते ही प्रति-क्रियावादियों, विशेषतः मुस्लिम प्रतिक्रियावादियों, के मुख में पानी भर आया। इस अवसर से लाभ उठाने के लिये उन्होंने मुस्लिम लीग पर अपना अधिकार जमाना चाहा, जिस पर अभी राष्ट्रीय विचार वाले मुसलमानों का अधिकार था। इसलिये उन्होंने मुस्लिम लीग की आ जी बैठक लाहौर में निमन्त्रित किया। पर राष्ट्रीय विचार के मुसलमानों के बहुमत के विरोध के कारण बैठक लाहीर की जगह कलकता में होना निश्चय किया गया। प्रतिकियावादी मुसलमान इससे भड़क उठे छोर सर किरोज खाँ नून, सर मुहम्मद इकबाल बैठव छोड़कर चले गए। सर मुहम्मद सफी का अध्यक्ता में उन्होंने इसका अधिवेशन करके साइमन के स्वागत का प्रस्ताव पास किया। जब कि सारे देश में एक स्वर में विरोध की आवाज उठाई गई थी। आज जब बिटिश साम्राज्यशाही के विरोध का अवसर था, एक दूसरे के खून के प्यासे हिन्दू-मुस्लिम अपना कृतिम भेद-भाव।को भूलकर स्वामाविक एकता के सूत्र में वँधने लगे।

कलकत्ता में मि० मुहम्मद अली जिन्ना के सभापितत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ। इसमें दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत हुए, एक के अनुसार साइमन कमीशन का विह्कार और दूसरे के अनुसार राजनीतिक बन्दियों की रिहाई की माँग की गई। ये दोनों प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसके सिवाय एक और महत्वपूर्ण काम हुआ। भारत-सचिव लार्ड बर्कनहेड ने यह चुनौती दी थी कि भारत के लोग भारतवर्ष के लिये एक संयुक्त भावी विधान तैयार करें। लोग ने अपने कलकत्ता वाले अधिवेशन में इस चुनौती को स्वीकार किया और एक "विधान निर्मात्री कमेटी" की नियुक्त की गई, जो अन्य पार्टियों से मिलकर विधान का निर्माण करेगी। इसके अतिरिक्त दिल्ली में होने वाले नेशनल कान्वेशन में भी सम्मिलित होने का निश्चय किया।

लालानी की मृत्यु का बदला

हिन्दुस्तान में साइमन कमीशन का पदार्पण हुआ। हर जगह भारतीय जनता ने काले मंडे से उसका स्वागत किया। इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता था कि जनता की क्रान्तिकारी प्रवृत्ति कुचली नहीं जा सकी बल्कि श्रीर भी उपतर होती गई। श्रंत्रेजी सरकार इसे सहन नहीं कर सकी। भारतीय जनता को आतंकित करने के लिये दमन का आश्रय लिया। एक तरफ तो सुधार का भी दौर चल रहा था। सुधार ऋौर दमन दोनों का ध्येय एक है तथा दोनों का परछाई ऋौर शरीर का सा सम्बन्ध है। जनता पर कुछ श्रंश तक दमन का दबदबा बैठाया जा सका, पर उनकी क्रान्तिकारी प्रवृत्तियाँ सजीव थीं। इस दमन का श्री लाला लाजपतराय शिकार हुए। भारतीय जनता ने यह अनुभव किया कि साइमनकृत अपमान का बदला लेने में राष्ट्रीय कांग्रेस असमर्थ थी। भारतीय जनता श्रातंकित तथा हतोत्साह हो रही थी। यह परिस्थिति भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन के लिये घातकथी। देश के मत्थे पर लगी कलंक-कालिमा को दूर करने के लिये वे ब्यातुर दृष्टि से क्रान्ति-कारियों की श्रोर देखने लगीं। भारतीय क्रान्तिकारी भी इंस राष्ट्रीय अपमान को थों ही चुपचाप सहन नहीं कर सकते थे श्रीर सहन करना भावी क्रान्तिकारी आन्दोलन के लिये घातक भी समभते थे। उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, अपमा-नित भारतीय जनता के शिर का कलंक शत्रु-रक्त से घो दिया। लालाजी का खूनी सैन्डर्स कान्तिकारियों के हाथों से न वच सका और अपने कुकृत्यों का फल भोगने के लिये जहन्तुम की भेज दिया गया। अपमानित और निरुत्साहित जनता में पुनः गर्व और उत्साह का संचार हुआ। छिटपुट देश में होने वाली क्रान्तिकारी घटनायं इस बात की द्योतक थीं। क्रान्तिकारी देश की आजादी के लिये प्रयत्नशील थे। जनता ने भी क्रान्तिकारियों के प्रति अपनी सहानुभूति और आदर का प्रदर्शन किया, यही कारण था कि राष्ट्रीय कांग्रेस के सुधारवादी मध्यम वर्गीय नेतृत्व की जनता के दबाव से मजबूर होकर काकोरी घड्यन्त्र केस के शहीदों के प्रति सहानुभूति का प्रस्ताव पास करना पड़ा। आज भी भारतीय अमिक शोपित जनता की शोषण और गुलामी के खिलाफ मुक्ति की लड़ाई में शोपित पीड़ित जनता की सरदार भगतसिंह तथा यतीन्द्रनाथ दास प्रेरित करते हैं।

"राष्ट्रीय मुस्लिम-दल" की स्थापना

संसार व्यापी आर्थिक संकट क्रमशः विकसित हो रहा था और इस समय इसकी भयंकरता और भी बढ़ गई। भारतवर्ष इसकी लपट में आने से बचा न रह सका। यहाँ के भी सामाजिक तथा आर्थिक जीवन के ऊपर इसका प्रभाव पड़ते हुए दिखाई देने लगा। क्रान्तकारी-राक्तियों के लिये अनुकृल परिस्थिति विकसित हो रही थी। वह भारत की राजनीतिक तथा सामाजिक अवस्थाओं को प्रभावित करती हुई बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी।

लाहौर के अपने वार्षिक अधिवेशन में "शफी लीग" ने
मुसलमानों के सर्वदल सम्मेलन की आवाज उठाई। यह सन्
१६२६ ई० में हुआ। इसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग भी
शामिल हुई थी। इस कान्फ्रेन्स ने "नेहरू रिपोर्ट" जिसे कांग्रेस
ने कलकत्ता के अपने वार्षिक अधिवेशन में पास किया था,
जो कांग्रेस की खोर से भारतवर्ष के भावी दिवधान के रूप में
थी, को अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय
विचार वाली मुसलमान कुछ संशोधन के साथ रिपोर्ट को
स्वीकार करने के पन्न में थे। किन्तु जिल्ला साहब ने विना

६० हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का ऐतिहासिक त्रिश्लेषण

किसी नतीजे पर पहुँचे श्राधिवेशन को भंग कर दिया। इससे राष्ट्रीय मुसलमानों को काफी दुःख श्रीर निराशा हुई तथा विवश होकर उन्हें मुस्लिम लीग से श्रलग एक संस्था की स्थापना करनी पड़ी। यह "राष्ट्रीय-मुस्लिम-दल" के नाम से विख्यात हुआ। किन्तु इसका परिणाम यह हुआ कि मुस्लिम लीग पूर्णतः अतिक्रियायादियों के हाथों में चली गई।

"संविनय श्रवज्ञा" ग्रान्दोलन ग्रौर "दिरली पैक्ट"

जपर हम इस बात का उल्लेख कर आये हैं कि सन् १६२२ ई० में असहयोग आन्दोलन की समाप्ति के उपरान्त प्रतिक्रिया-वादी साम्प्रदायिकता जोर पकड़ रही थी, राष्ट्रीय शक्तियाँ काफी कमजोर होती जा रही थीं। सारे देश में आपसी फूट, वैमनस्य चढ़ता जा रहा था, परन्तु इस सबके बावजूद भी कान्तिकारी हतोत्साहित नहीं हुए, बड़ी लगन और उत्साह के साथ श्रपने पथ पर हदता के साथ अयसर होते गये। क्रमशः अपने अध्य-वसाय और अनवरत परिश्रम से वे जनता की क्रान्तिकारी शक्ति के ऊपर छाये हुए साम्प्रदायिकता के मोहान्धकार को दूर करने में सफत हो संके। जनता के अपमान का सैएडर्स को गोली का शिकार बनाकर बदला लेकर उन्होंने उनकी सची सहानुभूति श्रीर समर्थन प्राप्त किया। इस समय भारतीय कान्तिकारियों के प्रभाव में थी। यह बात राष्ट्रीय कांग्रेस के सुधारवादी पूँजीवादी नेतृत्व से छिपी नहीं थी। श्रतः कान्ति-कारियों के प्रभाव से भारतीय जनता को निकालकर भुलावे में डालने के लिये और क्रान्तिकारी शक्तियों के बढ़ते हुए प्रभाव के दवाव के कारण लाचार होकर सन् १६२६ ई० ३१ दिसम्बर को लाहौर के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस ने "पूर्ण स्वतंत्रता" का प्रस्ताव पास किया।

प्रस्ताव पास हो जाने ही से भारतीय जनता क्रान्तिकारी शिक्तयों के प्रभाव से निकलकर राष्ट्रीय कांग्रेस के सुधारवादी पूँजीवादी नेतृत्व के असर में नहीं आ जाती। अतः भारतीय जनता के अन्दर इसका (स्वतंत्रता के प्रस्ताव का) प्रचार करना इसने आवश्यक सममा। सर्वप्रथम सन् १६३० ई० के २६ जनवरी को हिन्दुस्तान भर में एक समय मंडा अभिवादन और स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रतिज्ञा आम जलसा में ली गई। तब से २६ जनवरी भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता की लड़ाई के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिवस हो गया है और तब से स्वतंत्रता दिवस के नाम से यह दिवस स्वतंत्रता दिवस के नाम विख्यात हो रहा है।

राष्ट्रीय सुधारवादी पूँजीवादी नेतृत्व यहीं पर नहीं कक जाता। आगे वड़कर वह "सिवनय अवज्ञा" आन्दोलन चलाने लगता है। इसके प्रारम्भ करने के पूर्व गांधी जी ने कांग्रेस की और से भारतवर्ष के वाइसराय को, आन्दोलन चलाने का क्या उद्देश्य है, लिखा। उसके उपरान्त ता० १२-३-३० को सावरमती आश्रम से ७६ लोगों के साथ गांधी जी ने विख्यात "डांडी मार्च" के लिये प्रस्थान किया। प्रस्थान करने के समय उन्होंने यह प्रतिचाकी थी, जवतक भारतवर्ष आजाद नहीं होगा, तब तक वे आश्रम में वापस नहीं आयेंगे। चाहे तो भारत स्वतंत्र होगा या उनकी लाश समुद्र में तैरेगी। २०० मील पैदल चलकर ता० ६-४-३० को समुद्र के किनारे से नमक वे

खठा लाये। यह सत्याप्रह धरराणा नमक सत्याप्रह नाम से मशहूर है। इसके साथ सारे देश में नमक बनाया जाने लगा। इस प्रकार सन् १६३० ई० में "सविनय खबज्ञा" ख्रान्दोलन प्रारम्भ हुखा।

उधर ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शासन विवान में सुधार करने के लिये "गोलमेज परिपद" आमन्त्रित किया, उसमें सम्मिलित होने का निमन्त्रण भारतवर्ष के दलों को दिया गया। कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 'सविनय अवज्ञा' आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। चान्दोलन का विगुल बजते ही स्वतंत्रता की चिर-प्रेमी, सोपित पीड़ित भारतीय जनता लड़ाई के मैदान में कूद पड़ी। उसकी प्रेरक शक्ति स्वतंत्रता की चिए-अभिलाषा तथा दारुण आर्थिक वन्वन मोचन की पृति, सत्य र्थाहंसा के रहस्यमय मन्त्रों से नहीं होने को थी, अतः आन्दोजन प्रारम्भ होने के वाद ही उसने क्रान्तिकारी पथ का अनुसरण किया और 'सविनय अवज्ञा' आन्दोलन जनकान्तिकारी आन्दोलन में तीव्र गति से विकिसत होने लगा था। ज्योंही "सविनय अवज्ञा" आन्दोलन भारतीय शोषित पीड़ित जनता के आन्दोलन में रूपान्तरित होने लगा, त्योंही भारतीय राष्ट्रीय सुवारवादी पूँजीवादी नेतृत्व तथा ब्रिटिश सरकार का ध्यान ऊवर गया और देखकर वे दहल उठे। उन्होंने समका कि अगर तुरन्त इसे रोका नहीं गया तो यह जनकान्तिकारी आन्दोलन की अग्नि ब्रिटिश सरकार के साथ ही साथ भारतीय पूँजीवादी वर्ग और उसके समर्थकों की भी भरम किये बग़ैर न छोड़ेगी। अतः वे रोक-थाम के उपायों में संलग्न हो गये।

त्रिटिश सरकार और राष्ट्रीय सुधारवादी पूँजीवादी नेतृत्व के बीच समसीते की वातचीत चलने लगी और अन्त में लाई इर्विन और गांधीजी के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार और राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच समसीता हो गया जो भारतवर्ष के मौजूदा राजनीतिक इतिहास में "दिल्लीपैक्ट" के नाम से प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय कांग्रेस के सुधारवादी पूँजीवादी नेतृत्व ने सुलह तो की, परन्तु स्वतंत्रता के खूनी अभिनय का तब तक पटाच्लेय नहीं होता जब तक राजनीतिक रंग-मंच पर क्रान्तिकारी उपस्थित थे। अतः उन्हें भी शान्त करने के लिये मरकार ने उनसे सुलह करना चाहा-परन्तु क्रान्तिकारी "स्वतंत्रता" के उपासक थे। उनका ध्येय एक सात्र स्वतंत्रता थी। उसके नीचे कहाँ पर वे सुलह करते। क्रान्तिकारी अपने सिद्धान्त के विरुद्ध किसी प्रकार का समसौता नहीं करता है। भारतीय क्रान्तिकारी इस मोह-पाश में न वँध सके। वे पूर्ववत् क्रान्ति की अग्नि को प्रज्वालत करते रहे।

दिल्ली पैकट के अनुसार कांग्रेस ने दूसरी "गोल मेज परिपद" में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया था। गांधीजी राष्ट्रीय कांग्रेस के एक मात्र प्रतिनिधि होकर लन्दन गये। एक और यह नाटक खेला जा रहा था और दूसरी तरफ इसके आड़ में बीर क्रान्तिकारी फाँसी के तख्तों पर तथा जेलों के सीकचों के मीतर स्वतंत्रता का मूल्य चुका रहे थे। भारतीय जनता गोलियों से भूनी जा रही थी। भारतीय जनता जिस कूर दमन का सामना कर रही थी, शायद किसी अन्य देश की जनता को इतना न करना पड़ा हो। एक तरफ यह दृश्य था और दूसरी तरफ राष्ट्रीय कांग्रेस गांधीजी के नेतृत्व में सुधार के लिये बेजान हो रही थी।

६४ हिन्दुस्तान और पाकिस्तान फा ऐतिहासिक विरले ग्ण

राष्ट्रीय मुसलमानों की लखनऊ कान्फेन्स

इस समय लखनऊ में सर ऋली इमाम की ऋध्यवता में राष्ट्रीय मुसलमानों की एक कान्फोन्स हुई। सन् १६०६ ई० में लार्ड मिन्टो से मिलने वाले मुस्लिम डेपुटेशन का सर अली इमाम एक सदस्य थे। किन्तु सन् १६०५ ई० से सन् १६०६ ई० के बीच के अवकाश में उन्हें इस प्रश्न पर गम्भीरता के साथ विचार करने का अवसर मिला और वे इस निश्चित परिणाम पर पहुँचे कि "पृथक् निर्वाचन" का श्रभावात्मक परिणाम केवल भारतीय राष्ट्रीयता के लिये ही घातक नहीं हुआ, अपितु उसका स्वीकार करना प्रत्यचारूप से मुसलमानों के लिये भी हानिकारक सिद्ध हुआ। आपने पुनः कहा—"यदि सुकसे यह प्रश्न किया जाय कि श्रापका भारतीय राष्ट्रीयता में क्यों हुड़ विश्वास है, तो मैं यही उत्तर दूँगा कि बिना इसके भारत की स्वाधीनता एक असम्भावना है। पृथक् निर्वाचन राष्ट्रीयता का नाशक है।" म्स्लिम-पठित-वर्ग पृथक निर्वाचन योजना से सहमत नहीं हैं। उनके पास कान्फ्रेन्स के निर्वाचित सभापति होने के कारण भारत के कोने-कोने से विभिन्न नेताओं के इस श्राशय के सन्देश आये हैं कि जिसमें सभी ने "संयुक्त निर्वाचन" के मूल सिद्धान्त पर जोर दिया है।

"दिल्ली पैक्ट" और किसान आन्दोलन

गांधीजी भारतीय विधान में राजनीतिक सुधार की आशा से विलायत गये हुए थे। सन् १६३१ ई० के प्रारम्भ में 'सविनय अवज्ञा' आन्दोलन बन्द कर दिया गया था। राष्ट्रीय कांभेस का सुधारवादी पूँजीवादी नेतृत्व राजनीतिक सुधार के

लियं हाथ फैलाये प्रतीचा कर रहा था। पर शोषित-पीड़ित जनना हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप बैठी हुई नहीं थी। भारतीय शोषित-पीडित किसान बगावत का मंडा लिये मैं जान में डटी थी। बगावत की श्राग्न की लहर देश के कोने-कोने में उठ रही थी। कांग्रेसजन बागी किसानों का, 'उनकी लड़ाई में साथ देने के लिये वाध्य हो रहे थे। लाचार होकर राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व ने भी ऐसे कांग्रेसजनों को किसानों का साथ देने की आज्ञा दे दी। साथ ही साथ किसानों की सरगर्मियाँ भी देश भर में उथल-पुथल मचा रही थी। अब तक भारतीय जनता पर कांत्रेस का प्रभाव कायम हो चुका था श्रीर वह उसे क्रान्ति-पथ से दूर रखने में वहुत श्रेश तक सफल भी होती रही थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार कांत्रेस का भी प्रभाव जनता के ऊपर श्रपने श्रस्तित्व के लिये घानक सममते लगी श्रीर इसे कायम रहने देना नहीं चाहती थी। फलतः गांधी जी के दूसरे 'गोलमेज परिषद' से लौटते ही सरकार ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया । सारे देश में श्रान्दोलन की लहर उठी श्रीर दमन का दौरा भी शुरू हो गया।

म्रुमलमानों द्वारा संयुक्त-निर्वाचन-प्रणालीं की माँग

सन् १६३१ ई० में सर श्राली इमाम के नेतृत्व में राष्ट्रीय मुसलमानों की लखनऊ में एक कान्फ्रोन्स हुई जिसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। इस कान्फ्रोन्स में यह माँग की गई थी कि "विधान में मौलिक श्राधिकार के समावेश की घोषणा की जाय।" श्रीर दूसरे प्रस्ताव में "सभी प्रमुख प्रश्नों का निर्णय संयुक्त-निर्वाचन-प्रणाली और बालिग-मताधिकार पर होना चाहिये। तथा जनसंख्या के आधार पर संघ-प्रान्तीय व्यव-स्थापक सभाओं में सदस्यों की जगहें निश्चित कर दी जायें। ३० फी सदी से कम अल्पनत वालों को अतिरिक्त स्थानों के लिये चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त हो।"

कमजोरी की अवस्था में मुस्लिम लीग

उक्त उदाहरण से यह स्पर हो जाता है कि सन् १६३१ ई० में तथा उसके बाद भारतीय विवान सम्बन्धी साधारण मुसल-मानों के विचार क्या थे। इस समय राष्ट्रीय मुसलमानों की शक्ति प्रवल हो रही थी और प्रतिक्रियावादियों की शक्ति क्रमश: चीए होती जाती थी। मुस्जिम लीग के ऊपर पूर्णतः प्रतिकिया-वादियों का प्रभाव था। इस फलस्वरूप इसका महत्व तथा शक्ति दिन प्रनिदिन कम होती जा रही थी । आम मुस्लिम जनता के ऋन्दर उसका प्रभाव लुप्त होता जा रहा था। अकती हुई दीपक की तरह यह भी टिमटिमा रही थी। राष्ट्रीय आन्दो-तन में सिक्रय भाग लेने के कारण राष्ट्रीय मुसलमान मुस्लिम जनना में प्रभावशाली होने लगे थे। इस परिस्थिति में ऋखिल भारतीय मुस्लिम लीग का वार्षिक ऋषिवेशन इलाहाबाद में बुलाया गया। पर सारे भारतवर्ष से केवल ७४ मुसलमान इसमें शामिल होने के लिये आये। यह संख्या किसी प्रकार की कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिये पर्याप्त नहीं थी इस अवसर पर महम्मद इकवाल इसके समापति निर्वाचित हुए। इसके पश्चान् श्रीर भी श्रिविल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन हुए पर उनकी भी दशा दयनीय रही। दिल्ली में मि० जफरुल्ला खाँ के समापतित्व में बुलाये गये मुस्लिम लीग के अधिवेशन की भी

पूरी दुर्गित हुई, सारे भारत से केवल १०० मुसलमान इसमें सम्मिलित होने के लिये आये और सारी कार्यवाही खुले मण्डप में न होकर, एक घर में सम्पन्न हुई।

प्रतिक्रियावादी साम्प्रदायिक शक्तियों का उत्थान

राष्ट्रीय मुसलमान अब नक शक्तिशाली श्रीर प्रभाववृर्ण होते जा रहे थे, पर राष्ट्राय आन्दोलन के रुकने के साथ ही साथ उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा की भी इतिश्री होने लगी। च्याजादी की लड़ाई ने जर्जर भारत की देह में नवीन तथा शुद्ध रक्त का संचार कर दिया था, जिसने साम्प्रदायिकता के विप-कीटासुओं को विल्कुल ही दवा अवश्य दिया था और भारतवर्ष एक सबज एवं संगठित राष्ट्र के रूप में विकसित बहुत अंश तक होने लगा था किन्तु इस उनेजक शक्ति के समाप्त होते ही पुन: विप-कीटाग्णु साम्प्रदायिकना के रूप में प्रवल होने लगे। 'सविनय अवज्ञा' आन्दोलन के वापस होते ही भारतवर्प प्रतिक्रियावादी शक्तियों का क्रीड़ा-स्थान बन गया। हिन्दू-मुस्लिम रंगे अपनी विभीपिकाओं के साथ पुनः प्रबल-वेग से उमड़ पड़े। कंघे से कंघा मिलाकर डटे हुये भारतीय चाएभर बाद ही किस जादू की शक्ति से एक दूसरे के प्राणी के प्राह्क बन गये। इस बात को जानने के लिये व्यथित पाठक त्रातुर होंगे। इसका उत्तर ऋत्यन्त सीधा श्रीर सरल है। "यह जादृकी शक्ति ब्रिटिश हुकूमत है।" जनता की एकता को उसने सदेव शंका की दृष्टि से देखा है और सन् १८४७ ई० के बाद से ही हम देखते आ रहे हैं कि जब कभी भारतीय जनता संगठित हुई श्रीर ब्रिटिश सरकार के प्रति अपनी विरोधी भावनाओं को प्रदर्शित करने लगी तो ब्रिटिश

साम्राज्यशाही ने उसे अपने अस्तित्व के लिये हानिकर समभ-कर नष्ट करने का प्रयत्न किया है। अब तक का इतिहास इस पर यथेष्ट प्रकाश डाल चुका है कि उन्होंने समय समय पर किन उपायों का प्रयोग किया, उन्हें फिर दुहराने की आव-श्यकता नहीं है। ब्रिटिश सरकार सर्वदा हिन्दू-मुसलमानों में गहरा मतभेद उत्पन्न करने का प्रयत्न करती रही है, पर राष्ट्रीय शक्तियों का उत्थान तथा राष्ट्रीय आन्दोलन की लहर उस विषमता की नींव को सुदृढ़ नहीं होने देती थी। परन्तु जैसे ही राष्ट्रीय आन्दोलन शान्त होते थे, वैसे ही उसे अपनी दुष्काम-नात्रों के पूरा करने का अवसर मिलता था। सन् १६३०-३२ ईं० के ज्ञान्दोलन की शान्ति के बाद उसने कुछ किराये के टट्डुओं को फॉसकर अपना उल्लू सीधा करना शुरू किया। प्रतिक्रियाबादी शक्तियाँ भारतीय रंग-मंच पर प्रकट हुई। उनके बढ़ावे के लिये चानुकूल परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। राष्ट्रीय शक्तियों के अभिनय का पटाचेप हो गया था। मुस्लिम जनता की आँखों के सामने राष्ट्रीय मुस्लिम नेता श्रोमल हो गये थे। श्रीर उनकी श्राँखों के सामने मुस्लिम लीग तथा इसके नेता नजर आने लगे। फलतः मुस्लिम लीग की शक्ति क्रमशः बढ़ने लगी। इस प्रतिक्रियावादी रंग-मंच के प्रधान अभिनेता भि० जिन्ना थे।

हिन्द्-मुस्लिम एकता अधिवेशन

दमन और सुधार का चोली-दामन का सम्बन्ध है। दमन के साथ ही साथ सुधार की भी तैयारी होने लगी। कृत्रिम साम्प्रदायिक समस्या को सुलक्षाने के लिये ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने भारतीय विधान में सुधार के नाम पर राष्ट्रीय हित घातक साम्प्रदायिक बँटवारा की घोषण की, जो 'कम्मुनल एवार्ड' के नाम से विख्यात है। सारे भारतवर्ष ने इसका घोर विरोध किया परन्तु मि० जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने इसका स्वागत किया। इस घोषणा के उपरान्त भारत सचिव सर सेमुखल होर वार-वार यह घोषणा करते रहे कि हिन्दू-मुस्लिम समस्तीता के द्वारा ही यह साम्प्रदायिक बँटवारा इस्तान्तरित किया जायगा।

इस विषय पर विचार करने के लिये तथा इस राष्ट्रीय हित घातक योजना को नष्ट करने के लिये पं० मदन मोहन मालवीय ने इलाहाबाद में हिन्दू-मुस्लिम समभौते के लिये 'एकता अधिवेशन' बुलाया। इस अधिवेशन में यह तय हुआ कि केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभात्रों में ३२% बत्तीस प्रतिशत प्रतिनिधित्व का अधिकार मुसलमानों को मिलना चाहिये और दूसरा सिन्ध, बाम्बे श्रेसिडेन्सी से अलग करके एक स्वतंत्र गवर्नर वाला प्रान्त बना देना चाहिये। यह 'एकता अधिवेशन' अभी चल ही रहा था कि सर सैमुअल होर ने यह घोषणा को कि "सम्राट् की सरकार ने ब्रिटिश भारत के मुसलमानों को केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभात्रों में ३३% तैंतील प्रतिशत प्रति-निधित्व का श्रिधिकार देने का निर्णय किया है और सिन्ध को केवल एक अलग प्रान्त ही नहीं स्वीकार किया है बल्कि केन्द्रीय सरकार के कर की श्राय से उसे पर्याप्त श्रार्थिक सहायता भी देगी। इस घोषणा ने हिन्दू-मुस्लिम सम्मौते को सुरंग लगा-कर उड़ा दिया। एकता अधिवेशन असफल रहा। भारतीय राज-नीतिज्ञों ने इस सत्य का कटु अनुभव किया कि पराधीन भारत-वर्प कोई एकता स्थापित नहीं कर सकता है।

७० हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेपण

सन् १९३५ ई० के विधान की घोषणा

श्रीखल भारतीय मुस्लिम लीग की कार्डन्सिल ने सन् १६३४ ई० के अप्रैल में 'कम्मुनल एवार्ड' को स्वीकार कर लिया। भारतीय विधान में सुधार करने के लिये ब्रिटिश सरकार की छोर से एक सरकारी घोषणा-पत्र प्रकाशित हुआ, जो 'ह्वाइट पेपर' कहलाता है और सन् १६३४ ई० के विधान के नाम से प्रसिद्ध है। इस विधान का विरोध सारे देश ने किया। सर बजीर हसन ने मुस्लिम लीग के अध्यत्त के पद से भापण देते हुए इस प्रकाशित विधान के विपय में कहा था कि 'यह लोकतंत्र और स्वतंत्रता की स्थापना करने वाली शक्तियों को वन्धन में जकड़ लेगा और कुचल डालेगा। मुस्लिम जनता को नये विधान से उतना ही दुःख उठाना पड़ेगा जितना कि भारत के अन्य किसी सम्प्रदाय को।" इस अधिवेशन का यही मुख्य प्रस्ताय था, जिसके द्वारा सन् १६३४ ई० का विधान स्पष्ट शब्दों में अस्वी-कार किया गया।

बाबू राजेन्द्र प्रसाद और भि० जिन्ना की समभौते को बात

इन दिनों श्राखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति बाबू राजेन्द्र प्रसाद थे। हिन्दू-मुस्लिम सममौते (श्रायांन् कांग्रेस-लीग सममौते) के लिये उन्होंने मुस्लिम लीग के सभापति भि० जिन्ना से बातचीत की। सममौते की सभी शांतें मान ली गई। ऐसा प्रतीत होता था कि मानों सममौता सफल हो गया है। पर ऐन मौके पर मि० जिन्ना ने यह कहकर सममौते के मसबिदे पर हस्ताच्चर करने से इन्कार कर दिया कि कांग्रेस राष्ट्रीय संस्था है, इसे साम्प्रदायिक प्रश्नों पर किसी सम्प्रदाय विशेष की तरफ से आश्वासन देने का अधिकार नहीं है। हिन्दू महासभा ने इस पर हस्ताचर नहीं किया। अतः ये शर्ते हिन्दुओं के लिये मान्य नहीं हैं।

साम्भदायिकता के विष-वृत्त को बढ़ाने बाले कान्ती माक्सवादी और पँजीवादी सुधारबादी राष्टीय नेतृत्व

भारतीय राजनीति चेत्र में दो धाराओं का उल्लेख हमने कार किया है: -राष्ट्रीय कांग्रेस के पूँजीवादी सुधारवादी नेतृत्व के मातहत सुधारवादी आन्दोलन के रूप में और दूसरी पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त और प्रजातंत्र की स्थापना के हेतु क्रान्तिकारी च्यान्दोत्तन । पाठकों के दिमाग में यह प्रश्न उठना स्वामाविक है कि जब सुधारवादी ऋान्दोलन बन्द किया जाता रहा, उस समय क्रान्तिकारी चान्दोलन को संचालित करने वाली शक्तियाँ कहाँ थीं जो प्रतिक्रियावादी शक्तियों को मिटाने में असमर्थ रहीं ? इस प्रश्न को सममते श्रीर उत्तर जानने के लिये वर्तमान राष्ट्रीय आन्दोलन पर एक विहंगम दृष्ट डालनी होगी। भार-तीय जनता इस समय दोनों प्रमुख राजनीतिक धारात्रों से प्रभावित होती रही थी। उन पर कभी गांधी जी के नेतृत्व का रंग जमता था तो कभी क्रान्तिकारियों का पच पवल होता था। राष्ट्रीय कांग्रेस के पूँजीवादी सुधारवादी नेतृत्व द्वारा संचा-लित ब्रिटिश सरकोर विरोधी सुधारवादी आन्दोलन में क्रान्तिकारियों ने सदैव सहयोग प्रदान किया पर सत्य और श्रहिंसा के नाम पर पूँजीवादी सुधारवादी नेतृत्व आजादी की लड़ाई के संचालन में संलग्न कान्तिकारी शक्तियों का गला घोटता रहा । गांधीवाद पूँजीवादी सुधारवाद के रूप में हाथ धोकर क्रान्निकारी आन्दोलन के पीछे पड़ा हुआ था, हर

७२ हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेपण

प्रकार से वह उसके विकास ऋौर प्रगति के मार्ग में बाधायें उपस्थित कर रहा था। क्रान्तिकारी ब्रिटिश सरकार के दमन और गांबीवाद की क्रान्ति-विरोधो नीति और विरोध के दोहरे पाटों के बीच पिट रहे थे। इसके अतिरिक्त, स्टैलिनवादियों के रूप में कानूनी मार्क्सवादियों का भी जनम हो गया था। मार्क्सवाद के नाम पर वे भी क्रान्ति हारी शक्तियों का तथा क्रान्तिकारी आन्दोलन का सर्वनाश करने में लग गये। ऐसी परिस्थिति में जब विदेशी सरकार घोर दमन कर रही हो और देश के अन्दर संगठित रूप में क्रान्तिकारी अान्दोलन का विरोध होता हो, वैसी अवस्था में क्रान्तिकारी श्रान्दोलन का निर्वल हो जाना श्राश्चर्य नहीं है। क्रान्ति-कारियों के ही रक्त से सींचित भूमि में उन्हीं का सहारा लेकर सुधारवादी आन्दोलन पनपने लगा था और अमर बेलि की तरह उन्हीं की शक्ति को चूसकर उन्हें निष्पाण करने की चेष्टा करने लगा । सुधारवादी स्त्रान्दोलन तथा नव-जात कान्नी मार्क्सवादी क्रान्तिकारी संगठन तथा आन्दोलन को समाप्त तो नहीं कर सके, पर उसकी शक्ति को चींग करने में वे सफल अवश्य हुए। क्रान्तिकारी आन्दोलन और संगठन को निर्वेत कर वास्तव में उन्होंने भारतीय राष्ट्र को ही निर्वेत किया जिसके परिणामस्वरूप साम्प्रदायिकता के कीटागा उसके शरीर में प्रवेश कर गये और प्रतिक्रियावादा संहारक शक्तियों के प्रकोप का भारतीय शोषित-पीड़ित जनता सफलतापूर्वक मुकावला नहीं कर सकी, जो बाद के भारतीय इतिहास ने नग्न रूप यें भारतीय अभिक-शोपित जनता के सामने रख दिया है। क्रमशः प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ बढ़ती ही गई।

राष्ट्रीय कांग्रेस की पूँजीवादी सुधारवादी नेतृत्व ने प्रति-क्रियावादी साम्प्रदायिकता के विष-वृत्त को वढ़ने, फूलने-फलने का पूरा ऋवसर दिया। परन्तु फिर भी सन् १६३४ ई० के भारतीय विधान के कार्यान्वित होने के पूर्व मुस्लिम आम जनता में इसकी जड़ अभी तक मजबूत नहीं हो पाई थी। यह सन् १६३७ ई० के साम्प्रदायिकता के आधार पर लड़ा हुआ मुस्लिम लीग के चुनाव के परिणाम से साबित होता है।

सन् १६३७ ई० के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग का रूप

सन् १६३७ ई० के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग के प्रति-कियावादी नेतृत्व ने यह भली-भाँति अनुभव कर लिया कि मुस्लिम आम जनता के ऊपर उसका कितना प्रभाव हैं। इसका अनुमान होते ही आम मुसलमानों को अपने प्रभाव में लाने के लिये इसने जी जान-से कोशिश की। फिर क्या था इस्लाम धर्म के नाम पर विकसित भारतीय राष्ट्र के गला पर प्रतिक्रियावादी साम्प्रदायिकता की कुल्हाड़ी चलाई जाने लगी। आखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन सन् १६३७ ई० के अक्टूबर में लखनऊ में हुआ। इस अधिवेशन का खागता-ध्यंत्र राजा महमूदाबाद थे। उन्होंने स्वागत करते हुए कहा, "हमारे देश में एक नाजुक राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। बहुसंख्यक सम्प्रदाय मुस्लिम सम्प्रदाय के अस्तित्व को ही इन्कार करता है और राष्ट्र की उन्नति के लिये, हमारे नेताओं के साथ सहयोग करने के लिये लेशमात्र भी तैयार नहीं है।"

उसी श्राधवेशन के श्रंभ्यज्ञ-पद से भाषण देते हुए मि०

जिन्ना ने कहा, "मुस्लिम लीग पूर्ण राष्ट्रीय सरकार की स्थापना चाहती है और कांग्रेस विधान तोड़ने वाली अपनी नीति का पालन न कर उल्टे विधान को कार्यान्वित करने की नीति की आलोचना करती है।"

सन् १६३७ ई० में सन् १६३४ ई० के भारतीय विधान के कार्योन्वित करने के सिलसिले के प्रारम्भ होने के वाद मुस्लिम लीग के अन्दर जो परिवर्तन हुआ है, उसे समफने के लिये हमें भारतीय राजनीतिक आन्दोलन की गति-विधि का सूदम निरीक्षण करना होगा। सन् १६३०-३२ ई० में गांधी जी के नेतृश्य में कांग्रेस द्वारा संचालित "सविनय अवज्ञा आन्दोलन" में शामिल हो भारतीय शोधित-पीड़ित जनता ज्योंही उसे कान्तिकारी जन-आन्दोलन में रूपान्तिरत करने लगी कि त्यों-ही पूँजीवादी सुधारवादी नेतृत्व बेचैन हो उठा और तुरन्त ही पूँजीवादी सुधारवाद की स्वार्थ-वेदी पर आन्दोलन बिल खड़ा दिया गया। इसके असफल होने के बाद कांग्रेस आन्दोलन के, गर्भ में कांग्रेस विचारधारा में भी परिवर्तन आने लगा।

क्रान्तिकारी समाजवाद का विकास

सन् १६३० ई० से क्रान्तिकारी सङ्गठन तथा आन्दोलनं को कुवलने के लिये ब्रिटिश सरकार का दमन-चक्र जोरों से आरम्भ हुआ। फाँसी और गोली से बचने पर, इसका शिकार हो हजारों की संख्या में क्रान्तिकारी नौजवान जेलों के सीकचों के अन्दर सड़ाये जाने लगे थे। वहाँ उन्हें अपने इतिहास पर एक आलोचनात्मक दृष्टि डालने का अवसर मिला और आलोच-नात्मक दृष्टिकोण से अपने आन्दोलन के इतिहास का श्राययन उन्होंने किया। भौतिक परिस्थितियों के श्राधार पर श्रपने भूत, वर्तमान तथा भिवष्य की नीति का विश्लेपण के करने लगे। सन् १६२० ई० के उपरान्त भारतीय समाज की भौतिक परिस्थिति में काफी परिवर्तन श्रा चुका था। श्रतः उसकी छाप उनके विचारधारा पर श्रवश्य पड़ने लगी। भारतीय पूँजीवाद स्पष्ट स्वरूप में विकसित हो चुका था। श्रन्य पूँजीवादी देशों जैसा यह श्रभी परस्पर-विरोधी पूँजीवादी श्रीर श्रमजीवी वर्गों को साथ लेकर श्रपने विकास श्रीर प्रगति-पथ पर श्रमसर होता जा रहा था। यह विकास की ऐसी श्रवस्था तक पहुँच चुका था कि इसका रूप श्रीर प्रश्रति भली-भाँति देखी तथा समभी जा सकती थी।

सामाजिक जीवन को प्रभावित करने के श्रितिरिक्त भारतीय पूँजीवाद के विकास तथा प्रगित ने क्रान्तिकारी श्रान्दोलन श्रार सङ्गठन की विचारधारा को भी प्रभावित किया। सन् १६३७-३८ ई० तक भारतीय क्रान्तिकारी श्रान्दोलन पूर्णेरूप से क्रान्तिकारी समाजवादी विचारधारा से सावित हो चुका था, "जो क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी" के रूप में विकसित होने लगी थी। फिर क्या था, समाजवाद का नारा भारतवर्ष के कोने-कोने में गूँजने लगा। शोपित-पीड़ित श्रीमक जनता श्राशा, हर्प श्रीर विकास के साथ क्रान्तिकारी श्रान्दोलन की प्रगित श्रीर विकास को देखने लगी। भारतीय राष्ट्रीय श्रान्दोलन की प्रगित श्रीर विकास को देखने लगी। भारतीय राष्ट्रीय श्रान्दोलन का रूप भी बदलने लगा। यह केवल विदेशी सरकार के ही विरुद्ध नही रहा, बल्कि शोपक वर्ग विरोध का रूप इसने धारण कर लिया। यह मुख्य कारण था कि गांधीजी ने सन् १६३७ ई० में राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 'मन्त्रीपद प्रहण्' का

७६ ाहन्दुस्तान आर पा किस्तान का ऐतिहासिक विश्लेषण

समर्थन करते हुए, एक स्थान पर कहा था कि 'कांग्रेस ने विधान को ध्वंस करने के लिये मन्त्रीपद महण नहीं किया है, बल्कि कान्ति तथा ऐसे जनमान्दोलन से भारत को बचाने के लिये उसने स्वीकार किया है जैसा कि भारतवर्ष में म्यभी तक नहीं हुमा है। मन्त्रीपद महण करने के उपरान्त कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता भी 'स्वराज्य प्राप्ति' के लिये वैधानिक उपायों को खथेष्ट सममने लगे।

स्लाव जातियों का पानस्लामिज्म का नारा

भारतवर्ष जैसा संसार के छोर देशों में भी समय-समय पर जातीय समस्या खड़ी हुई थी। १६वीं सदी में मध्य युरोप में स्लाव जातियों का जातीय प्रश्न उठा हुआ था। मध्य युरोप के विभिन्न भागों की विभिन्न स्लाव जातियाँ एक अपना अलग स्वतन्त्र राष्ट्रीय राज की स्थापना करने का प्रयत्न कर रही थीं। कस की जारशाही अपने स्वार्थ-सिद्धि के लिये उनके नारे का समर्थन कर रही थी। कस की जारशाही की स्वार्थ-सिद्धि के लिये एक साधन हो रहा था। इस तरह बोहिनियाँ और कोशिया (Crotia) की स्लाव जातियाँ सभी स्लाव जातियों का अलग स्वतन्त्र संयुक्त राज का नारा दे रही थीं। यह "पानस्लामिडम" के नाम से इतिहास में विख्यात है। इस नारे को देने वाले तथा समर्थन करने वाले कुछ जानकार तथा कुछ अनजान में रूस के प्रत्यच हितसाधन में संलग्न थे। उन्होंने राष्ट्रीयता की कलिपत छाया के पीछे पड़कर क्रान्ति के साथ विश्वासघात किया।

जर्मनी का विभाजन और कार्ज मार्क्स

कार्ल मार्क्स और एंगिल्स के राजनीतिक जीवन के प्रारम्भ के कुछ वर्षों के बाद जर्मनी-विभाजन का आन्दोलन जोर पकड़ने लगा। मार्क्स और एंगिल्स ने इसे क्रान्तिकारी शक्तियों के लिये घातक सममा और कम्युनिस्ट लीग की ओर से एक माँग उपिथत की। इस पर इन दोनों के आतिरिक्त अन्य लोगों के भी हस्ताचर थे। इस माँग को घोपणा-पत्र के रूप में जर्मन जनता के सामने उन्होंने रखा। इसमें उन्होंने जर्मन-विभाजन का विरोध किया था और अमिक-शोधित जनता की पार्टी की इस सम्बन्ध में नीति निर्धारित की। घोषणा के आरम्भ में ही यह कहा गया कि "सम्पूर्ण जर्मनी एक और अविभाज्य प्रजातन्त्र घोषित किया जायेगा।"

सन् १८५२ ई० में कम्युनिस्ट लीग की केन्द्रीय कमेटी को सम्बोधन करते हुए मार्क्स ने कहा था कि उसे होगे के लाग, या प्रजातन्त्रीय-संघ शासन के लिये प्रयत्न करेंगे या एक तथा अविभाज्य प्रजातन्त्र की स्थापना को विफल करने में असफल होने पर चाल केन्द्रीय शासन सत्ता को निर्वल करने के लिये प्रान्तों तथा लोक-सभाओं को स्वतन्त्र स्वायत्त शासन का अधिकार प्रदान करने की माँग उपस्थित करेंगे। इस अवसर पर जर्मनी की श्रमिक जनता को इस योजना के विरोध में केवल एक और अविभाज्य जर्मन प्रजातन्त्रा की स्थापना के लिये ही नहीं, बल्कि सरकार के हाथों में सम्पूर्ण शक्तियों का पूर्ण रूप से केन्द्रीयकरण के लिये भी प्रयत्न करना होगा। उन्हें डेमोकेट लोगों की लोक-सभाओं एवं प्रान्तों तथा स्थानीय समुदायों की स्वतन्त्राता की माँग से अपने को मुलावे में डालना

नहीं चाहिये। जर्मनी एसे देश में जहाँ सामन्तवाद के अवशेष को नष्ट करना वाकी है, यहाँ प्रान्तीयता एवं स्थानीयता की भिन्नता समाप्त कर देनी चाहिये। यह असहनीय है कि हर एक नगर, गाँव, प्रान्त क्रान्ति की गति का अवरोध करें। क्रान्ति का विकास केवल एक केन्द्रीय स्थान से ही हो सकता है। यह कभी भी बर्शरत नहीं किया जा सकता कि वर्तमान अवस्था पुनः स्थापित की जाय तथा प्रान्त, नगर और गाँवों में एक प्रकार की उन्नति के लिये अलग-अलग लड़ाई की जाय।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पाकिस्तान को माँग का समर्थन

उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि कार्ल मार्क्स किसा भा देश की श्रमिक-शोपित पीड़ित जनता के विभाजन के कहर विरोधों थे। परन्तु भारतीय कान्ती मार्क्सवादी (स्टेलीनबादी) मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की माँग का समर्थन करके भारतीय श्रमिक-शोपित जनता के साम्प्रदायिकता के श्राधार पर विभाजन में सहायक हुए। उनका इतिहास स्पष्ट कर देता है कि वे ऐसा करके क्रान्तिकारी मार्क्सवादी विचार-पथ से च्युत होकर शोपित जनता को मूल-भूलइया में हाल रहे हैं और अपने कुकृत्यों से मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद को उन्होंने वदनाम कर दिया। एक और मारतीय शोपित जनता का सन् १६४२ ई० की श्रमस्त क्रान्ति से विकसित संयुक्त क्रान्तिकारी मोर्चा हद हो रहा था और दूसरी और इस मोर्चे को भंग करने के लिये प्रतिक्रियावादी शक्तियों के साथ गुट बनाकर ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार प्रयत्न कर रही थी।

मुस्तिम लोग काफो सहायक हो रही थी। भारतीय स्टैलिनवादी त्रिटिश साम्राज्यवाद की साम्राज्यवादी युद्ध में हर प्रकार की सहायता करने में व्यक्त थे। पूर्ण सहायता प्रदान करने के लिये यह आवश्यक था कि हिन्दू और मुस्तिम पूँजीपितयों के बीच समभौता हो। अतः इस समभौता को सफत बनाने के हेतु मुस्लिम पूँजीपतियों की पाकिस्तान की प्रतिकियावादी माँग का समर्थन भारतीय स्टैलिनवादी करने लगे। साथ ही साथ ब्रिटिश साम्राज्यवाद की रच्चा की दृष्टिकोण से भारतीय शोषित-पीड़ित जनता को क्रान्ति-पथ से दूर रखने का भी प्रयत्न उन्होंने किया वे समाजवादी जामा पहनकर इसका समर्थन खुले आम करने लगे। इतना हो नहीं, बल्कि लेनिन के राष्ट्रों के आत्म निर्णय के क्रान्तिकारी सिद्धान्त को ढाल के रूप में आगे रखकर अपनी क्रान्ति-विरोबो तथा अवसरवादी नीति का समर्थन वे करने लगे। इस प्रकार ये भारतीय शोषित-पीड़ित जनता की क्रान्तिकारी शक्ति को निर्वल करके दुकड़ों-दुकड़ों में कर उन्हें प्रतिक्रियावादी शक्तियों का आहार बना रहे थे। यही था इनकी श्रमजीवी वर्ग के साथ सहानुभूति श्रीर बलिहारी थी इनके साहस को जो कि अपनी लज्जापूर्ण नीति का ढिंढोरा पीटते हुये भी शर्म नहीं आती थी। इतना ही नहीं, आश्चर्य तो होता है—नास्तिकों के मुख से श्री राम नाम का जप सुनकर, सदैव समाजवाद के नाम से कुड़कुड़ाने वाले श्री राजगोपालाचार्य भी आज पंचम स्वर से लेनिन के 'राष्ट्रों के आत्म-निर्णय' के र्ञ्यावकार के सिद्धान्त की बाँग देने लगे थे। श्रीर 'सोते भारत' को 'जगा' रहे थे। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि हम पाठकों के सामने लेनिन के 'राष्ट्रों के आत्म निर्णीय के

श्राधिकार 'के सिद्धान्त को, जिस पर इतनी तू-तू मैं-मैं हो रही थी स्पष्टरूप से रक्खें। सुधारवादियों तथा स्टैलिनवादी कान्नी मार्क्सवादियों के चिल्ल-पों से अनिभन्न समाज यह समफ्रने लगा था कि "राष्ट्रों के श्रात्म-निर्णय के श्रिधकार का सिद्धान्त, इन पाखंडियों को एक श्राधार मिल गया था। श्रतः हम उनके पाखर्डपूर्ण एव मिथ्या-प्रचार की पोल खोलकर यह स्पष्ट कर दें कि 'राष्ट्रों के श्रात्म निर्णय के श्रिधकार' का बास्तविक रूप क्या है तथा किस सामाजिक समस्या का हल है श्रीर किस प्रकार से उसे भारत में लागू करके गृथ की फूहड़ श्रीर भद्दी राक्त को छिपाने के लिए शेर की खाल श्रोड़ी गई है। लेनिन के "राष्ट्रों के श्रात्म निर्णय के श्रिधकार" का सिद्धान्त, जिसकी श्रोट सभी सुधारवादी तथा कथित साम्यवादी ले रहे थे। सन् १९१२ ई० में यह लेनिन के निरीच्या में स्टैलिन के द्वारा तथार किया गया था। उसमें उपरोक्त सिद्धान्त की व्याख्या इस प्रकार की गई है:—

राष्ट्रों के आतम निर्णय का अधिकार क्या है ?

"राष्ट्रों के आत्म निर्णय के अधिकार का अर्थ यह है कि स्वतः राष्ट्र को ही स्वभाग्य निर्णय का अधिकार प्राप्त है। आज किसी को वलपूर्वक किसी राष्ट्र के जीवन में हस्तचेप करने का, उनके विचारों तथा संस्थाओं को नष्ट करने का, उनकी परम्परा और संस्कृति को अष्ट करने का, उनकी भाषा को द्वाने का तथा उनके अधिकारों को काटने छाटने का अधिकार नहीं प्राप्त है। आत्म-निर्णय का अधिकार यह है कि राष्ट्र-विशेष को अपनी इच्छानुसार अपना जीवन निरिचत करने का अधिकार है। यह अपना जीवन स्वायत्त-शासन के

आधार पर निश्चित कर सकता है तथा उसे अन्य राष्ट्रों के साथ संघ सम्बन्ध स्थापित करने का अधिकार है। उसे पूर्णतया सम्बन्ध विच्छेद करने का भी अधिकार है। सभी राष्ट्र समान तथा अपने स्वतंत्र राज्य सत्ता के अधिकारी हैं।

"िकन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि सोशल डेमोकेंट लोग किसी राष्ट्र की हरएक माँग का समर्थन करेंगे। एक राष्ट्र की प्राचीन सामाजिक व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का अधिकार है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि सोशल डेमोकेंट्स किसी के उक्त निराय में सहयोग करेंगे।

"राष्ट्रों के आतम निर्णय के अधिकार के लिये लड़ने में सोशल डेनाकेट लोगां का ध्येय के बत यह है कि वे राष्ट्रां के द्वारा राष्ट्रों पर प्रभुत्व स्थापित करने की नीति का अन्त कर हो राष्ट्रों के बीच को शतुला और द्वेप असम्भव बनाने के लिये इसके आधार को ही नष्ट कर दें। शतुला और विद्वेष की तीली धार को कुंठित करके यथासम्भव कम कर दें।

अयर के उद्धरण यह संकेत करते हैं कि इस के जार के शासन के अन्तर्गत कई राष्ट्र थे। यह विल्कुल सत्य है कि उस समय इसी जार के साम्राष्ट्र के अन्तर्गत बहुत से राष्ट्र सिम्मिलित कर लिये गये थे, जो भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से पृथक् राष्ट्र थे। इनको बलात् महान् इस का अंग बनना पड़ा था। जिससे मुक्ति पाने के लिये वे सदेव वेष्टा करते थे और महान् इस को शोषक और शासक के इस में देखते थे। इस इन्हीं विभिन्न राष्ट्रों की विशाल काया था जिसके सभी अंग पृथकत्व और स्वतन्त्र सत्ता का ज्ञान रखने के कारण अपने को उसका अभिन्न अंग नहीं मानते थे।

म्रुगल शासन युग में भारतीय राष्ट्र तथा राष्ट्रीयता का उदय

यह ठीक है कि भारतवर्ष में पूँजीवाद का स्वामाधिक उदय तथा विकास न होने के कारण भारतीय राष्ट्र अन्य पूँजीवादी देशों के राष्ट्र के जैसा स्वाभाविक ढंग से पूर्ण राष्ट्रीयता के साथ पूर्ण राष्ट्र में विकसित नहीं हो सका। फिर भी भारतीय पूँजीवाद के विकास तथा प्रगति के साथ भारतीय राष्ट्र तथा राष्ट्रीयेता भी क्रमशः विकसित होने लगी थी। भारतवर्ष एक विशाल देश रहा। इसके इस विशाल काया के सभी द्यांग खपना पृथकु स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रखते रहे। इसका कोई भी श्रंग स्वतन्त्र पृथक् राष्ट्र के रूप में विकसित नहीं हुआ। इसकी तो विशाल संयुक्त काया रही। इनमें शासक एवं शोषित का सम्बन्ध नहीं है। यहाँ रूसी परिस्थिति का सर्वथा अभाव रहा । यहाँ यदि शोषक एवं शोपित तथा शासक एवं शासित का प्रश्न उठता रहा, तो इसका भारतीय राष्ट्र के छांग विशोप से कोई सम्बन्ध नहीं रहा, बल्कि विकसित भारत राष्ट्र श्रीर ब्रिटिश राष्ट्र के सम्बन्ध को सपष्ट करता था। भारतीय राष्ट्र श्रमी तक सर्वोङ्गपूर्ण राष्ट्र का रूप धारण नहीं कर सका था, अभी तक वह विकास की प्रक्रिया में ही था। दिन प्रति दिन इसका रूप स्पष्टतर होता जाता था। राष्ट्रों की उत्पत्ति विकासीन्मुख समाज पूँजीवाद के युग में पदार्पण करते ही राष्ट्र के स्वरूप का दर्शन करता है, पूँजीवाद अपनी प्रगति एवं उन्नति के साथ राष्ट्रीयता को भी हुढ़ और संगठित बनाता जाता है। अतः भारतीय समाज ने मुगल शासन कालं में जब संसार में सर्वप्रथम पूँजीवाद को गर्भ में घारण किया था, उसी समय भारतीय राष्ट्रीयता भी म्मंकुरित हुई थी। भारतीय पूँजीवाद की भ्रूण अवस्था

में ही अंग्रेजों के आगमन द्वारा हत्या कर दो गई थी। श्यतः भारतीय राष्ट्र उस समय तक सर्वोङ्गपूर्ण न हो सका. फिर भी उसने एक राष्ट्र का ढाँचा धारण कर लिया था। सांस्कृतिक, मौलिक, ऐतिहासिक एकता किमी भूखरड को राष्ट्र का आकार प्रदान करने लगनी है। यह श्राकार मुगल शासक श्रकवर के युग में भारतीय समाज शहरा कर रहा था। इस आधार पर भारत को एक राष्ट्र सिद्ध करते हुए सर यदुनाथ सरकार सन् १६४२ ई० के नवमबर के "माडर्न रिव्यु" में लिखते हैं कि "ऐतिहासिक एकता अच्छी तरह से समाज में लोगों द्वारा एक ही प्रकार की शापन-प्रणाली में कार्य करने तथा उसकी सफलता श्री एवं श्रमफल-ताओं में भाग लेने के लिए स्थापित होती है क्योंकि यह उनके संयुक्त प्रयत्नों का परिगाम होता है। ऐसी शासन सम्बन्धी एकता भारत के विभिन्न भागों को मुगल शाहनशाहों द्वारा दी गई थी। जिनके उपहार (प्रसाद) ये हैं:--(१) साम्राज्य के सभी भागों तथा प्रान्तों में एक प्रकार की शासन व्यवस्था, (२) एक सरकारी भाषा, (३) एक प्रकार के सिक्के तथा समान तील के बाँट, (४) श्राखिल भारतीय उच्च सरकारी नौकरियों के लिये कुशल व्यक्तियों का समुदाय जो तीसरे-चौथे साल एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त को बदलें जाते थे, (४) बड़ी-बड़ी सेनाओं का एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त की समय-समय पर जाना तथा प्रान्तों के विभिन्न नगरों में राजधानी से निरीक्तकों की नियक्ति।"

इस प्रकार की शासन सम्बन्धी एकता भारत के लगभग तीन-चौथाई प्रान्तों में थी। इससे विभिन्न प्रान्तों के बीच व्यापार तथा यात्रियों के लिये काफी प्रोत्साहन मिला। दिल्ली के शाही द्रवार ने सम्पूर्ण भारत में सांस्कृतिक तथा कला सम्बन्धी संयोग स्थापित करने की चेष्टा की। समाज के उच लेगी के लोग सरकारी पदाधिकारियों के समान आपस का पत्र व्यवहार फारसी में करते थे और साधारण लोगों की आम बोल-चाल के लिये एक नधी भाषा "जबाने हिन्द्भी" जिसे हिन्दुस्तानी या उर्दू कहते हैं, जो राष्ट्र-भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। कालान्तर में यही भाषा फारसी का स्थानान्तरित करके उत्तर भारत का प्रमुख सांस्कृतिक एवं सरकारी भाषा बन गई।

इस प्रकार से सारे भारत में ऐतिहासिक एकता स्थापित हो रही थी। श्रव हमें सांस्कृतिक एकता पर विचार करना है। जहाँ तक भाषा का सम्बन्ध है, उद्भाषा साधारण वोल-चाल श्रोर राष्ट्रीय-भाषा के रूप में क्रमशः विकसित हो रही थी। विभिन्न धमों के बीच समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की जा रही थी। उस युग में बहुत से सन्त लोगं मुख्यंतः हिन्दू श्रोर सुस्लिम धर्म के बीच सामन्जस्य ढूँढ़ रहे थे, श्रीर वे जोर-शोर से श्रपने मत का प्रचार कर रहे थे, उनके श्रवुधायियों की संख्या भी क्रमशः बढ़ती जा रही थी। धार्मिक एकता स्थापित करने का श्रान्दोलन सूफी लोगों के द्वारा श्रव्यक्य के पहले से ही चल रहा था। कबीर, नानक श्रीर चैतन्यदेव श्रादि इस प्रकार के ही धर्म की स्थापना के लिये उद्योग कर रहे थे। इन लोगों के प्रयत्नों का परिणाम यह हुश्रा कि दोनों धर्मों के लोग इनके पन्थों को श्रपनाने लगे। इस प्रकार हिन्दू-मुस्लिम सांस्कृतिक एकता स्थापित करने में इन सन्तों की भारी देन हैं। भारतवर्ष सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक आधार पर संयुक्त हो रहा था और एक राष्ट्र होने की सुदृढ़ नींव डाल चुका था। परन्तु कुकाल चक्र ने इसे ठीक समय पर सर्वाङ्गपूर्ण राष्ट्र बन जाने में बाधा उपस्थित की जिसकी किया आज भी जारी है।

रूस का क्रान्तिकारी आन्दोलन और आत्म निर्णय के अधिकार का सिद्धान्त

हम उपर देख चुके हैं कि "राष्ट्रों के आतम निर्णय का अधिकार" क्या है। कौन सी विशेष भौतिक परिस्थितियाँ इसे भारत में लागू करने का कहाँ तक समर्थन करती हैं, इसे भलीभाँति जानने के लिये हमें रूस की तत्कालीन सामाजिक तथा राजनैतिक अवस्था और वहाँ के क्रान्तिकारी आन्दोलन पर एक दृष्टि डालनी होगी। विना उन परिस्थितियों का अध्ययन किये हम मन्त्रयत इसे भारतवर्ष में लागू करने का प्रयत्न करके भारी भूल करेंगे।

पहले हमें वहाँ के क्रान्तिकारी आन्दोलन को सममने का प्रयत्न करना चाहिये। इस के क्रान्तिकारी आन्दोलन के रूप को सममने के पूर्व इसी राष्ट्र के स्वरूप को सममना नितान्त आवश्यक है। जैसा कि पहले हम कह चुके हैं, कि राष्ट्र को चिर, सत्य और सनातन मानना आन्तिपूर्ण है। इसके विपरीत यह परिवर्तनशील समाज के युग विशेष की एक विकसित परिवर्तित अवस्था है। पूँजीवाद के साथ इसका भी उद्य तथा विकास होता है। पिच्छमी युरोष के सभी राष्ट्र, इंगलैएड, फ्रान्स, जर्मनी, इटली आदि इस पूँजीवादी युग की ही उपज

हैं। िकन्तु पूर्वी युरोप में वास्तिविकता कुछ और है। पूँजीवाद का उद्य पूर्वी युरोप के मुल्कों में पीछे आकर हुआ है। जिससे इन मुल्कों में राष्ट्र तथा राष्ट्रीय राज का रूप पिन्छमी युरोप में भिन्न रहा है और ये इंगलैएड, फान्स, इटली जैसा विकसित न हो सके। इन देशों में बहुजातिक राज्यों की स्थापना हुई, जिनमें बहुत से राष्ट्र सम्मिलित थे। आस्ट्रिया और रूस में इसी प्रकार के राज्यों की स्थापना हुई थी। हस में घेट रिसयन (महान रूसी) विभिन्न राष्ट्रों को एक में मिलाने के लिये अगुआ बने, जिसका नेतृत्व प्रधानत: सैनिक नौकरशाही के हाथ में था, जा जार के अधीन थी।

राज के निर्माण का यह विचित्र उपाय उन्हों स्थानों में लाया गया, जहाँ सामन्त समाज श्रमी तक जीवित था श्रीर पूँजातादी समाज स्वतंत्र रूप से विकसित नहीं हो रहा था, श्रीर जहाँ पीछे ढकेले हुए राष्ट्र श्रमी तक सर्वाङ्गपूर्ण श्रखण्ड राष्ट्र का रूप धारण नहीं कर सके थे। किन्तु पिछड़े हुए राष्ट्र भ श्रधिक समय तक एक ही श्रवस्था में नहीं रह सकते, श्रपने श्रस्तित्व की रचा के लिये उन्हें भी उन्नतिशील राष्ट्रों की समता प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील होना पड़ता है। उन्नतिशील राष्ट्रों की विकसित श्रवस्था उन पर भी श्रपना प्रभाव डालती है श्रीर उनके विकास की पथ-प्रदर्शिका बनती है। यह समाज के विकास का ऐतिहासिक नियम है। इस नियम के श्रनुसार पूर्वी युरोप के राष्ट्रों में पूँजीवाद का विकास होने लगा, इसके साथ ही साथ व्यापार श्रीर यातायात के साधन भी विकसित होने लगे। श्रीर इसके क्वारण बड़े-बड़े शहरों का उदय होने लगा। श्रतः श्रार्थिक श्राधार पर राष्ट्र

क्रमशः संगठित होने लगे।

पूँजीवाद ने पिछड़े हुए राष्ट्रों के जीवन में स्फूर्ति स्त्रीर चेतना उत्पन्न कर दी। वे अपना उन्नति के लिये व्यप्न और क्रियाशील हो उठे। इसके फलस्वरूप छापाखाने, समाचार-पत्र त्र्यादि की स्थापना तथा विस्तार द्वनगति से होने लगा। राष्ट्रों में जीवन की लहर आई। साहित्य में उनके देश के गौरव की नीत गुंजित हुई। बुद्धिजीवी-वर्ग राष्ट्रीयता की भावना से श्रोत-प्रोत हो उठा। यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि पूँजी-वाद के विकास काल में बुद्धिजीवी राष्ट्रीय विचार के अपदूत होते हैं। पूँजीबाद के ऋाविर्भाव के साथ गुलाम राष्ट्रों की राष्ट्रीयता की भावना जागती है छोर वे अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील होते हैं, परन्तु ज्योंही उनकी क्रियायं व्वतंत्रता प्राप्ति के लिये होने लगती है, उसी समय शासक राष्ट्र की तरफ से इनका घोर विरोध किया जाता है, सम्पूर्ण शक्ति लगाकर उनको कुचलने का प्रयत्न किया जाता है। राज-पता जायति को नष्ट करने के जिये तथा स्वतंत्रता के आन्दोलन को कुचलने को एड़ी-चोटी का पसीना एक कर देती है। इसी प्रकार शास्ट्रिया ने जेक (Zacks) श्रीर इस ने पोलैएड, लेटन लिथुत्रानियाँ, यूक्रेन, जार्जिया को द्वा रखा था, जो अपने को पृथक् राष्ट्र समक्तर अपनी स्वतंत्रता के लिये जार के विरुद्ध लड़ रहे थे। बुद्धिजीवी वर्ग में राष्ट्रीय जायति सबसे अधिक थी। अतः वही इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहा था।

स्वतंत्रता की लड़ाई में नव-जात पूँजीवादी वर्ग भी सहयोग दे रहा था, क्योंकि संसार के सीमित बाजार में ऋल्प वयस्क होने के कारण वह प्रौढ़ पूँजी बाद के सामने टिक न सकते के कारण अपने घर के बाजार की सुरिचत चाहता है। उसे अपने अस्तित्व के लिये विदेशी पूँजीपतियों का अपने बाजार में घुसना खतरनाक मालूम पड़ता है। श्रतः संमार के बाजार में अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिये राष्ट्रीयना का गीन गाता है च्योर राष्ट्रभक्त वनकर स्वतंत्रता की लड़ाई में सहयोग देता है। किन्तु यह संवर्ष केवल आर्थिक चेत्र तक ही नहीं रहता, इसका निपटारा राजनांतिक मैदान में होता है। गुलामों की स्वतंत्रना की प्रवृत्ति के उभड़ने ही अर्ध्य सामन्त तथा अर्ध्य पूँजीवादी नीकरशाही दसन शारम्भ करती है और हर प्रकार से उनकी जाप्रति एवं भावना को नष्ट करने का प्रयत्न करता है पूँजीपति श्रौर बुद्धिजीवी वर्ग उन्नति-पथ में राजनीतिक परतंत्रता को बाधक समभकर तुरन्त उसे हटा फेंकने के लिये कटिवद्ध हो जाते हैं। आजादी के आन्दोलन पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है, मातृभाषा दवाई जाती है, स्कूल-कालेजों पर तरह-तरह के प्रतवन्ध लगाये जाते हैं, जिससे आजादी की भावना कभी भी ऋंकुरित न हो सके। स्वतंत्रता आन्दोलन को रोकने के लिये जारशाही पौलैएड में अपने हथकडे दिखला रही थी, वहाँ की भाषा पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था, स्कूल के लड़कों को पोलिश भाषा बोलने का अधिकार नहीं था। स्कूलों के बाहर भी यह प्रतिबन्ध रहता था। अतः पूँजी-वादी पितृभूमि का नारा बुलन्द करके और अपने स्वार्थ को राष्ट्र-हित के साथ संयुक्त करके साधारण जनता को अपने मंडे के नीचे आजादी के नाम पर संगठित करने लगे थे। पीड़ित-शोधित जनता दमन तथा जुल्म को चक्की में पीसी जाने

६० हिन्दुस्तान श्रीर पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेपण

के कारण शासन-सत्ता के विरुद्ध थी और तुरन्त पूँजीपितयों के साथ विद्रोह में शामिल हो गई। इस प्रकार राष्ट्रीय आन्दोलन का आविर्भाव हुआ और सभी जगह—पौलैएड; जार्जिया आदि—में ऐसा ही राष्ट्रीय आन्दोलन चल रहा था।

उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि महान् रूस (Great Russia) स्वतः ऐतिहासिक तथा भौगोलिक एकता के आधार पर निर्मित एक प्राकृतिक राष्ट्र नहीं था। बल्कि यह विभिन्न देशों, जो स्वतः पृथक राष्ट्र की परिभापा के अनुसार स्वतन्त्र गष्ट्र थे, को मिलाकर एक विशाल राष्ट्र बना हुआ था, जिसके गर्भस्थ राष्ट्र अपनी पृथकता के लिये निरन्तर संघर्ष कर रहे थे। जब तक इन राष्ट्रों में चेतना और जाप्रति नहीं आई थी, तब तक उन्होंने मौत को स्वीकार किया था, परन्तु जैसे ही इनमें उन्नतिशील राष्ट्रों के अनुगामी बनने की इच्छा जाप्रति हुई, वैसे ही इन्होंने अपनी-अपनी स्वतन्त्रता का नारा बुलन्द किया और अपने राष्ट्र को रूस का एक अंग बनाकर स्वतन्त्र अस्तित्व प्रदान करने की चेष्टा करने लगे।

इन्हीं, कारणों से रूस के अधीनस्थ प्रान्तों में पोलैएड, आर्मिनिया तथा जार्जिया आदि में राष्ट्रीय आन्दोलन का आविर्माव हुआ। "राष्ट्रों के आत्मिनिर्णय के अधिकार" सिद्धांत की पृष्टिभूमि रूस की उपरोक्त सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्था थी।

लेनिन को इन्हीं भौतिक परिस्थितियों के अन्दर शोषित-श्रमिक जनता की आजादी की लड़ाई को सबल एवं सफल बनाने के लिये उपरोक्त सिद्धान्त स्वीकार करना पड़ा था। देश

की शोषित-शासित जनता राष्ट्रीयता की छाया में पड़कर अपनी वास्तविक लड़ाई-शोपण-मुक्ति-के पथ से च्यत हो रही थी। राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रगति के साथ-साथ सर्वहारा वर्ग, शोषित-शासित श्रमिक जनता भी तेजी के साथ विभाजित हो रही थी। उनकी क्रान्तिकारी शक्ति संगठित होने के बजाय छिन्न-भिन्न हो रही थी; शासक राष्ट्र के दमन के कारण उनकी राष्ट्रीयता का रूप श्रीर भी उप्रतर तथा भयानक हो रहा था। शासक राष्ट्र के प्रति उनकी कदुता एवं घृणा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी श्रौर शासक देश के निवासियों को वह सन्देह की दृष्टि से देखते थे। इस घृणा श्रीर श्रावश्वास का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने अपना सेत्र अत्यन्त संकुचित कर दिया और व्यापक क्रान्तिकारी सिद्धांतों के स्थान पर उनके संगठन का आधार संकुचित, संकीर्ण जातीयता एवं धर्म वनने लगा। अलग-अलग होकर उन्होंने अपनी डफली और अपना राग छेड़ा, पोलैंग्ड में राष्ट्रीयता के स्थान पर शोविनिज्म (Chovinism) यहूदियों में जीविनिडम तथा तातार जातियों में संकीर्ण राष्ट्रीयता जड़ पकड़ने लगी। श्रामेंनिया, जार्जिया तथा यूक्रेन सभी अलग-अलग होने के लिये अपना बन्धन तुड़ा रहे थे। इन माड-मंखाड़ों के उग आने के कारण स्वतन्त्रता-वृत्त कमनोर पड़ने लगा। वन्द (Bund), जो पहले प्रजातन्त्र की स्थापना के उदेश्य से सहमत होकर सोशल डेमाक्रेटिक पार्टी में सिन्मिलित हो गये थे, ने सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया श्रीर धर्म के नाम पर मजदूरों का अलग संगठन करने लगे। अपने इस कृत्य से वे जनता को क्रान्ति-पथ से दूर रखने लगे। ड्यूमा निर्वाचन में भी उन्होंने चुनाव के लिये धार्मिक नारों का ही

६२ हिन्दुस्तान खोर पाकिस्तान का ऐतिइालिक विरलेग्णस्त्य लिया।

इन्हीं विकट परिस्थितियों, जो क्रान्ति के लिये घातक सिद्ध हो रही थीं, को हल करने के लिये लेनिन की सम्मति से स्टा-जिन ने निम्नांकित सुकाव सन् १६१३ ई० में सोगल डेमोक्रैट लोगों के सामने उपस्थित किया :-- "इस कठिन घड़ी में सोशल डेमोकैटिक पार्टी के कन्धों पर गुरुतर कार्य का भार आ पड़ा है, यह है राष्ट्रीयता के विरुद्ध साम्प्रदायिकता के संवर्ष के इस व्यापक संक्रामक गेंग से राष्ट्रीयता की रत्ता करना; क्यों कि केवल सोशल डेमोकेंट लोग ही इस काम को करने के योग्य हैं। त्रतः उन्हें राष्ट्रीयता के विकद्ध प्रमाणित तथा विश्वसनीय अस्व अन्तर्राष्ट्रीयता तथा वर्ग-संघर्ष की एकता एवं अखंडता को इसके सम्मुख लाना चाहिये। ज्यों-ज्यों राष्ट्रीयता की धारा का बेग प्रवल होता जाता है त्यों त्यों उतने ही उच स्वर से सोशल डेमोकेट लोगों को रूस के सभी राष्ट्रों के सर्वहारा वर्ग के बीच एकता और बन्धुत्व के नारे को देना पड़ा।" उनरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्टालिन एक स्थान पर लिखते हैं, "तूकानी और मंकर-पूर्ण समय हमारे मामने उपंस्थित है, इसीसे हमारे वर्तमान तथा भविष्य की लड़ाई जिसका ध्येय पूर्ण प्रजातंत्र स्थापित करना है, की उत्पत्ति चौर वृद्धि होगी।"

"इसी त्रान्दोलन के साथ-साथ हमें जातियों तथा राष्ट्रों के प्रश्न को भी सुलमाना होगा। जातियों तथा राष्ट्रों की समस्या केवल पूर्ण प्रजातंत्र की स्थापना के ब्राधार पर सुल-माई जा सकती है।"

भारतवर्ष में साम्प्रदायिक राष्ट्र और अल्पसंख्यक जातियों का प्रश्न

ज्योंही भारतीय राष्ट्रीय त्राजादी का त्रान्दोलन उग्रतर तथा भयानक रूप अपनाते ही बन्द कर दिया गया और सुधार-वादी रचनात्मक तथा वैधानिक कार्यक्रम का रूप इसने बहुगा किया, त्यों ही साम्प्रदायिक समस्या पेचीदा तथा भवानक रूप में प्रकट होती रही है। भारतीय पूँजीवाद के विकास तथा प्रगति के साथ साथ भारतीय पूँजीवादी वर्ग का आन्तरिक संघर्ष भी तीत्रतर होता गया। इसकी तीत्रता यहाँ तक बढ़ी कि पूँजीवादी वर्ग की दुष्कामना की सिद्धि के लिये साम्प्रदायिक आधार पर भारत-विभाजन की माँग की जाने लगी और अन्त में भारतवर्ष साम्प्रदायिक श्राधार पर हिन्दुस्तान में श्रीर पाकिस्तान में विभा-जित हो गया। वास्तव में भारतीय शोपित-श्रमिक जनता विभाजित की गई है, जो अभिक-शोपित पीड़ित जनता की मुक्ति की लड़ाई-ममाजवादी कान्ति-के लिये घातक है। पाकि-स्तान श्रीर हिन्दुस्तान के साम्प्रदायिकता के श्राधार पर कायम हो,जाने के उन्नन्त आज हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में सब के सामने यह प्रश्न मुख्य है कि किस प्रकार हिन्दुस्तान में पाकिस्तान और पाकिस्तान हिन्दुस्तान को मिला लिया जाये। इसका भी प्रधान आधार साम्प्रदायिकता ही है, जो श्रमिक-शोपित जनता की मुक्ति की लड़ाई के विकास तथा प्रगति के मार्ग में बाधक है। ऐसे समय में क्रान्तिकारी समाजवादियों का यह कर्तव्य होता है कि वे जनशक्ति को प्रतिक्रियाबादी साम्प्रवायिकता के हाथों में पड़कर नष्ट होने से बचाये और उसे संगठितकर समाजवादी क्रान्ति में परिवर्तित करें।

६४ हिन्दुस्तान श्रोर पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेषण

यह प्रश्न उठना भी स्वामाविक है कि इसे किस प्रकार कार्यान्वित किया जाये ? इस प्रश्न का हल भी निकालना वाकी है। इसके लिये हमें इथर-उधर भटकना नहीं है। इस प्रकार की समस्याएँ बहुधा क्रान्तिकारी समाजवादी लेनिन के सामने उपस्थित होती थीं। उनकी रूसी भौतिक पृष्टिभूमि का विश्लेपण करके हम उन्हें अच्छी तरह समफकर भारतीय समाज की समस्या का हल सहज ही में निकाल सकेंगे खीर व्यथं की माथा-पद्मी तथा गलत उपायों के अवलम्बन से उत्पन्न भयानक कुपरिणामों से बच जायेंगे।

इसके पूर्व कि हम उनके हल की खोज करें हमें अपने प्रशन को भली भाँति समक लेना चाहिये। हमारा प्रश्न वास्तव में महान रूस में राष्ट्रों का प्रश्न जैसा नहीं है, बल्कि प्रतिक्रिया-वादी साम्प्रदायिक छाधार पर भारतवर्ष के छस्वाभाविक विभाजन से निर्मित साम्प्रदायिक राष्ट्रों का श्रीर विभाजन से उत्पन्न अल्पसंख्यक जातियों का प्रश्न है। लेनिन ने राष्ट्रों के श्चातम-निर्णाय के श्रविकार के सिद्धांत को स्वीकार करके विभिन्न राष्ट्रों की समस्या को सुलका दिया था और जार के विरुद्ध लड़ाई में उन्हें संगठित करने में सफल हुआ था। परन्तु इतने ही से सब कठिनाइयों का निपटारा नहीं होगया, खब भी खलग-श्रलग राष्ट्रों में विभिन्न जातीय-सम्प्रदाय थे, जो अपने धर्म तथा संस्कृति के आधार पर स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का आन्दोलन कर रहे थे। पोलैएड में यहूदी, यूक्रेन में पोलिश, लिथुआनियाँ में लटावियन और काकेश में रूसियों ने इस प्रकार का वखेड़ा खड़ा कर दिया था, कोई भी प्रदेश एक-जातिक राष्ट्र नहीं था। राष्ट्रीयता के साथ इन अल्पसंख्यक जातियों का प्रश्न भी पेचीदा

होता जा रहा था। विखरी हुई ये जातियाँ अपने को एक अलग राष्ट्र में संगठित करने का प्रयास कर रही थीं। परन्तु अल्प-संख्यक जातियों के अलग राष्ट्र का स्थापना के लिये आम जनता उतनी उत्सुक एवं व्यप्न नहीं थी, जितना स्वार्थी पूँजीवादी खर्ग था, क्योंकि साधारण जनता अपने निवास प्रदेशों में पूर्ण नागरिक अधिकार चाहती थी। उनके असंतोष का कारण यह था कि उनकी अपनी भाषा को प्रयोगकर स्कूल आदि खोलने के विचार-स्वातन्त्र्य आदि अधिकारों का जारशाही हुकूमत द्वारा अपहरण कर लिया गया था। इन प्रश्नों के हल हो जाने पर जातीय एकता (National Unity) उनके लिये कोई महत्व नहीं रखती थी। वे प्रथक राष्ट्र की स्थापना में अपनी इन्हीं खोई हुई आजादी को प्राप्त करना चाहते थे। अतः उनकी (अल्पसंख्यकों को) समस्या का हल केवल उनके अपने अधिकारों की सुरन्ना का विश्वास दिलाकर ही किया जा सकता है।

इस प्रश्न पर स्टालिन लिखते हैं "...... अतः ऐसा भय किया जा सकता है कि वहु-संख्यक जातियाँ, अल्पसंख्यक जातियों को दबायंगी। किन्तु ऐसे भय का कारण तभी तक उपस्थित रहेगा, जक तक उसमें पुरानी व्यवस्था प्रचलित है। देश विशेष में पूर्ण प्रजातंत्र की स्थापना कर देखो, ऐसे कारण स्वयं आप से आप नष्ट हो जायँगे।" ठीक यह अवस्था सन् १६४७ ई० के १४ अगस्त के पूर्व भारतवर्ष की थी। कुछ अंश तक यह दशा पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में है। हिन्दुस्तान में अल्पसंख्यक मुसलमानों को इस बात का भय होता है कि बहुसंख्यक जाति के आगे उनको दबना पड़ेगा और पाकिस्तान

के भी अल्पसंख्यक जातियों को भी इससे कहीं ज्यादा भय हो रहा है। इन सब का प्रधान कारण है भारतवर्ष का साम्प्रदायिक आवार पर पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में विभाजन। इनके अतिरिक्त हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का प्ररत पेचीदा तथा विकट होता जा रहा है। अगर समकोता न हुआ हो।। और जनकान्ति के द्वारा बिटिश साम्राज्यवादी सरकार का ध्यंस होना और इसके अवशेष पर भारतीय स्वतंत्रता और पूर्ण प्रजातंत्र की स्थापना होती, तो आज ये सब प्रश्न भारत समाज के निर में चक्कर नहीं पैदा करते। राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास यह बतलाता है कि जब-जब राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रत्यच संवर्ष का उम रूप धारण किया, तब-तब किसी प्रकार के साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए और उसके विपरीत जब आन्दोलन को रोक दिया गया और सुधारवादी ग्चनात्मक कार्यक्रम और वैवानिक संवर्ष के द्वारा "स्वराज्य" की प्राप्ति का प्रयत्न होते, तब-तब साम्प्रदायिक दंगे जोर पकड़ने लगे।

रूस की अलगसंख्यक जातियों के आन्दोलन के विषय में पुनः एक स्थान पर स्टालिन लिखते हैं, "विखरी हुई आल्प-संख्यक जातियों को एक राष्ट्रीय सूत्र में बाँचना इस आंदोलन का मुख्य ध्येय है। किन्तु अल्पसंख्यक जातियों को जिस वस्तु की चाह है, वह कृत्रिम राष्ट्रीय एकता नहीं है, प्रत्युत जिन प्रदेशों में वे बसे हुये हैं, वहाँ उन्हें वास्तविक आधिकारों की प्राप्ति है। ये राष्ट्रीय संगठन पूर्ण प्रजातंत्र की स्थापना के विना उन्हें क्या दे सकते हैं? और जब उन्हें पूर्ण प्रजातंत्र की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर अलग राष्ट्रीय संघ की क्या आवश्यकता है।" ठीक यही अवस्था भारतवर्ष के विभाजन के पूर्व पाकिस्तान

की माँग की थी। यह मुस्लिम शोषित-श्रमिक जनता की माँग नहीं थी। वह पाकिस्तान के रूप में नकली जातीय एकता नहीं चाहती थी, जो त्राज भारत के विभाजन के उपरान्त हिन्दु-स्तान के मुसलमानों की अवस्था से स्पष्ट हो जाता है, बल्कि पूर्ण नागरिक अधिकार चाहती थी। अपनी रहन-सहन, धार्मिक आचरणों के किसी प्रकार के हस्तान्तेप के विकद्ध आश्वासन चाहती थी। यह तभी सम्भव होता, जब भारत में पूर्ण प्रजातंत्र की स्थापना हो जाती। पाकिस्तान की गाँग उन्हें मुलावे में खाले हुई थी। पाकिस्तान कायम होने तक और उसके बाद का इतिहास स्पष्ट कर देता है कि पाकिस्तान की स्थापना ने अल्प-संख्यक जातीय प्रश्न को हल नहीं किया और न कर सकती है।

अलप-संख्यकों की समस्या को खुलमाने के सम्बन्ध में स्टाजिन एक स्थान पर लिखते हैं, "हम देख चुके हैं कि जातीय सांस्कृतिक आधार पर जातीय सांस्कृतिक स्वतंत्रता अनुचित है।"

"प्रथम, यह कृत्रिम श्रीर श्रसाध्य है, क्योंकि यह कृत्रिम डपायों से उन जातियों में एकता स्थापित करना चाहती है, जिनको (इन) घटनाश्रों (इतिहास) की रीति ने देश के कोने-कोने में दुकड़े करके विखेर दिया है।"

"दूसरे, यह राष्ट्रीयता को उभाइती है, क्योंकि यह उन विचारों की छोर भुकाव रखती है जो जनता का विभाजन राष्ट्रीय प्रजातंत्र के अनुसार चाहते हैं और जातियों का संगठन जातीय विशेषताओं की 'सुरचा' और 'वृद्धि' के अनुसार चाहते हैं जो समाजवादी प्रजातंत्र के सर्वथा विपरीत है।"

"इस प्रकार से जातीय सांस्कृतिक आधार पर जातियों की

ध्न हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेपण 'स्वतंत्रता' भी इस समस्या को हल नहीं कर सकती।"

भारतवर्ष की मौजूदा माम्प्रदायिक अवस्था

त्तेनिन के अनुसार "जॉतीय सांस्कृतिक" आधार पर जातियों की स्वतंत्रता "अल्य-संख्यकों की समस्या का ठीक हल न था, क्योंकि इस तिद्धान्त के अनुसार जातियों में एकता स्थापितकर राष्ट्र रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया जा रहा था, जिन्हें ऐतिहासिक घटना-क्रम ने सारे देश को अलग-अलग बिखेर दिया था। यह उपाय विल्कुल अप्राकृतिक, असाध्य एवं कृत्रिम था। ठीक इसा प्रकार भारत में भी दो राष्ट्र-सिद्धांत उठाया गया त्रौर इसके त्राधार पर पाकिस्तान श्रौर हिन्दुस्तान में साम्प्रदायिक श्राधार पर भारतवर्ष विभाजित कर दिया गया। पाकिस्तान की स्थापना का उरिय रहा भारतीय ससल-मानों को एक राष्ट्र रूप देकर विभिन्न मुस्लिम राज्यों में संगठित करना और इस्लामी राष्ट्रीय राज्य की स्थापना था। यह ऐतिहासिक सत्य के प्रतिकृत था। ऐतिहासिक घटना-क्रम ने भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों में विखरी हुई मुस्लिम जातियों को अन्य भारतीय जातियों के साथ घुलमिलकर भारतीय राष्ट्र की नींव तैयार की थी। भारतीय मुसलमान विकसित राष्ट्र के अधिच्छेद अंग के रूप में विकसित हो रहे थे। अलग इस्लामी राष्ट्र श्रीर राष्ट्रीय राज्य पाकिस्तान के रूप में ऐतिह:-सिक सत्य के विपरीत है।

तथापि वास्तविकता से आँखें नहीं मूँदी जा सकती कि भारतीय मुस्जिम सम्प्रदाय वहुसंख्यक सम्प्रदाय की, किसी भी कारण से हो, सन्देह तथा श्रविश्वास की दृष्टि से अवश्य देखने लगा तथा साम्प्रदायिक कटुता दिन प्रतिदिन वढ्ती गई, जिसका कारण ऊपर हम उल्लेख कर चुके हैं, जो राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के साथ ही साथ बड़ी वेग से गृह-युद्ध में रूपान्तरित हो गई। इस विषमता की जिम्मेदारी केवल ब्रिटिश सरकार और मुस्लिम लीग का प्रतिक्रियावादी नेतृत्व नहीं है,बल्कि राष्ट्रीय कांग्रेस का सुधारवादो, पूँजीवादी, क्रान्ति-विरोधी नेतृत्व भी सबसे ज्यादा है। यह राष्ट्रीय कांग्रेस की पूँजीवादी सुधारवादी नीति का ही कुपरिग्णाम था कि दिन प्रतिदिन साम्प्रदायिक मनोमालिन्य वढ्ता गया जिसे श्रपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिये मुस्लिम पूँजीपति बढ़ते गये और इस्लाम के आड़ में धर्म-भीर मुस्लिम जनता को पाकिस्तान के रूप में श्रालगकर मनमाना उनका शोषण करने की चेष्टा की जा रही है। हिन्दू पूँजीपतियों के साथ पूँजीवादी होड़ में मुस्लिस पूँजीपति अपने को निर्बल पाता था और अपने विकास के लिये अवसर नहींपाता था। अवअलग मुस्लिम राष्ट्र और इस्लामी राष्ट्रीय राज स्थापित हो जाने के बाद मुस्लिम पूँजीपितयों के लिये शोधित-श्रमिक जनता का मनमाना शोपण करने का और अपने को पूर्ण विक्सित करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त हो गया है। अपने विकास तथा प्रगति के लिये भारत के मौजूदा विभाजन का कायम रखना यह आवश्यक समभता है। भारत विभाजन के उपरान्त भी मुस्लिम जनता को फिरका-परस्ती पिलाई जा रही है।

भारतीय समाज के सामने महत्वपूर्ण समस्या हिन्दुस्तान श्रीर पाकिस्तान में साम्प्रदायिक श्राधार पर भारतवर्ष के विभाजन के उपरान्त भी अल्प-संख्यक सम्प्रदाय समस्या हल नहीं हो सकी, बल्कि साम्प्रदायिकता के आधार पर स्थापित पाकिस्तान राज्य और हिन्दुस्तान राज्य में यह श्रीर भी पेचीदी तथा जटिली हो गई है। इन राज्यों में पहले से कहीं ज्यादा भयावह साम्प्रदायिक परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके त्र्यतिरिक्त हिन्दुस्तान और पाकिस्तान राज्य के स्वा-भाविक चापसी सम्बन्ध के कारण सामाजिक जीवन में साम्प्र-दायिक वैमनस्य और भी बढ़ता जा रहा है । हिन्दुस्तान में हिन्दू सम्प्रदाय के ऋधिकांश लोगों के दिसाग में यह वात भरी हुई है कि हिन्दू सम्प्रदाय एक पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र है श्रीर पूर्ण भारतवर्ष हिन्दू राष्ट्र का है । इस पर केवल इसी को राज्य करने का अधिकार है। यह प्राचीन काल से सर्वदा अखरह रहा और रहेगा। अतः तलवार के बल से पाकिस्तान के अस्तित्व की खत्मकर अख़रड भारतवर्ष स्थापित करना है। उधर पाकिस्तान के सुस्लिम सम्प्रदाय में यह साम्प्रदायिक भावना जोर से काम कर रही है कि मुसलमानों ने सदियों तक हिन्दुस्तान पर हुकूमत करते रहे थे और उनसे ही अंग्रेजों ने राज्य छीना था। इसलिये अंग्रेजी हुकूमत के खत्म होने के बाद मुस्तिम राज्य कायम करना उनका हक है। अतः पाकि-स्तान हिन्दुस्तान पर हमला करके पूर्ण भारतवर्ष पर इस्लामी राज्य की स्थापना मुस्लिम जाति का फर्ज है। आज भारतीय सामाजिक जीवन को अल्पसंख्यक-सम्प्रदाय-समस्या ही केवल द्पित नहीं कर रही है, विल्क इसके अतिरिक्त अप्राकृतिक दो राष्ट्रों के त्र्यापसी सम्बन्ध का गरन सी सासाजिक जीवन के विकास श्रीर प्रगति के मार्ग में रोड़ां बन गया है। आज पूर्ण भारतीय समाज के सामने यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि किस प्रकार अल्पसंख्यक सम्प्रदायों और अप्राकृतिक राष्ट्रों के सवालों को हल करके सामाजिक जीवन के विकास तथा प्रगति के पथ के रोड़े को दूर करे, जिससे भारतीय समाज अपने सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं को सफलता-पूर्वक हल करके मानवता की ओर अप्रसर हो सके। इसके लिये यह आवश्यक हो जाता है कि अल्पसंख्यक-सम्प्रदाय-समस्याओं के हल करने के किये गये प्रयत्नों के इतिहास के ऊपर हम एक आलोचनात्मक दृष्टि डालं और इन सब प्रश्नों का वैज्ञानिक हल विकसित करें।

हिन्दू-मुस्लिम समभौते के प्रयत्न

हम देख चुके हैं कि भारतीय जनता की वगावत की अवृत्ति को सुधारवादी मार्ग में ले जाने के हेतु राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन् १८८४ ई० में की गई थी। परन्तु इससे भी हिन्दू-सुस्लिम एकता के हढ़ होने का खतरा था, जो ब्रिटिश सरकार के लिये घातक होता। अतः सन १८८६ ई० में अलीगढ़ सुस्लिम कालेज के पिन्सपल मि० बेक के द्वारा दो राष्ट्र—हिन्दू और मुस्लिम पृथक् राष्ट्र हैं—के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया और मुस्लिम-पठित-मृत्य वर्ग के दिमाग में क्रमशः दो राष्ट्र के सिद्धान्त का इंजेक्सन वह देने लगा। आगे चलकर भारतीय आम जनता की एकता को भंग करने के हेतु सन् १६०६ ई० में प्रतिक्रियावादी नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई।

प्रथम साम्राज्यवादी युद्ध-काल में भारतीय पूँजीवाद का आविर्भाव स्पष्टतः स्वतन्त्र रूप में हो रहा था, पूँजीवादी वर्ग के अतिरिक्त भारतीय मध्यम वर्ग ने साम्राज्यवादी युद्ध-काल को आर्थिक उन्नति के लिये पर्याप्त प्रयोग और भारतीय पूँजी के विकसित होने में काफी सहायता दी। युद्ध के उपरान्त प्राप्त राजनीतिक सुधार को अपने आर्थिक तथा सामाजिक विकास एवं उन्नति के लिये प्रयोग करने के हेतु हिन्दू-मुस्लिम पूँजीवादी तथा मध्यम वर्ग के बीच सन् १६१६ ई० में सममौता हुआ जो "लखनऊ पैक्ट" के नाम से विख्यात है। इस पैक्ट के द्वारा राष्ट्राय कांग्रेस के सुधारवादी मध्यम वर्गीय नेतृत्व ने भारतवर्ष के सामाजिक जीवन में दो राष्ट्र के सिद्धान्त, जिसे मि० बेक ने सन् १८८६ ई० में बीजारोपण किया था, स्थापित कर दिया। इसके अनुसार "पृथक् निर्वाचनका सिद्धान्त" कार्यान्वित करने के लिये स्वीकार किया। बाद का इतिहास यह वतलाता है कि "लखनऊ पैक्ट" ने अल्पसंख्यक साम्प्रदायिक प्रश्नों को हल नहीं किया बल्क इसे और भी कठिन तथा पेचीदा बना दिया।

जब सन् १६२४ ई० के बाद संसार-व्यापी आर्थिक संकट विकिसित होने लगा, संसार के पूँजीवाद के लिये खतरा पैदा हाने लगा। भारतीय समाज इससे अञ्चला नहीं रहा, यहाँ के भी पूँजीवाद तथा पूँजीवादी वर्ग का अस्तित्व डावाँडोल होने लगा। भारतीय जन-शक्ति के दवाव से बिटिश सरकार कुछ राजनीतिक सुधार देने से वाध्य हुई। परन्तु, भारतीय तथा बिटिश पूँजीवादी वर्ग सर्वदा इस बात की कोशिश करते रहे कि किसी भी तरह राजनीतिक सुधार कान्तिकारी आन्दोलन के लिये प्रयोग न हो सके। अतः बिटिश सरकार तथा भारतीय पूँजीवादी वर्ग का संयुक्त प्रयत्न हिन्दू-मुक्लिम एकता के नाम से हिन्दू-मुक्लिम पूँजीपतियों के बीच मेल कायम करने के लिये हुआ। विलायत में दो-तीन "गोलमेज परिषद" बैठा। जब

१०४ हिन्दुस्तान श्रीर पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेषण

किसी प्रकार हिन्दू-मुस्तिम पूँजीपितयों के बीच सममौते के लिये संयुक्त निर्णय पर यह "गोलमेज परिषद" नहीं पहुँच सका, तब बिटिश साम्राज्यवादी सरकार की खोर से बिटेन के प्रधान मन्त्री मैकडानल्ड ने "साम्राज्यवादी साम्प्रदायिक बँटवारा" की घोषणा की जिसने वजाय खल्पसंख्यक सम्प्रदाय-समस्या को हल करने के खौर भी उलमा दिया। इसके बाद भी भारतवर्ष के खन्दर सम्प्रदाय-समस्या को सुलमाने का प्रयत्न किया गया। श्री मदनमोहन मालबीय के द्वारा प्रयाग में हिन्दू-मुस्लिम एकता-सम्मेलन खुलाया गया। लेकिन बिटिश सरकार की चालों के कारण यह भी खसफल ही रहा।

इसके वाद जब मन् १६३४ ई० में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यत्त श्री राजेन्द्र प्रसाद हुए, एक बार फिर इसे हल करने का प्रयत्न किया गया। स्वयं राजेन्द्र बाबू मुस्लिम लीग के सभापति जिल्ला साहब से बातें की। यहाँ भी अप्रफलता ही हुई। सन् १६३८ ई० में राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति नेता जी सुभाषचन्द्र बोल दुए, तब भी इन्होंने हिन्दू-मुस्लिम एकता के स्वाल को हल करने का प्रयत्न किया। जिल्ला से काफी बातें इनसे हुईं। ज्ञात होता था कि सम्भवतः यह समस्या सुलम जायेगी। लेकिन अन्त में इनका भी प्रयत्न व्यर्थ साबित हुआ। इन सब प्रयत्नों को देखते हुए यह स्वभावतः प्रश्न उठता है कि एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा प्रयत्न साम्प्रदायिक समस्या को सुलमाने का हुआ लेकिन सबों की एक ही गति क्यों हुई ? यह जान पड़ता है कि इन सब प्रयत्नों के भीतर एक ही प्रकार की मौलिक भूल होगी। इन प्रयत्नों के इतिहास का विश्लेपण करने से यह स्पष्टतः ज्ञात होता है कि ये सब प्रयत्न हिन्दू- सुरित्तम श्राम जनता के वीच द्याजादी की लड़ाई के द्याधार पर एकता का प्रयत्न नहीं था बल्कि हिन्दू-सुरित्तम पूँजीपति द्योर मध्यम वर्ग के बीच द्याम जनता को क्रान्तिकारी पथ पर द्यप्रसर होने से रोकने के लिये एकता का प्रयत्न था द्योर किस प्रकार राजनीतिक सुधार को ब्रिटिश सरकार के साथ मिल्कि कर भारतीय पूँजीवादी वर्ग क्रान्ति की वेग की गित को थाम सकेगा। द्यतः इसी मौलिक भूल के कारण सभी प्रयत्न द्यसफल रहे।

सन् १६३६ ई० के सितम्बर के प्रथम सप्ताह में दूसरा संसार-व्यापी सामाज्यवादी युद्ध प्रारम्भ हुआ। युद्ध के प्रारम्भ होते ही भारतवर्ष की भी परिस्थिति एकदम बदल गई । भारतीय शोपित-श्रमिक जनना युद्ध-काल को अपनी आजादी हासिल करने का सुत्रवसर समझने लगी और बड़ी ही तेजी के साथ क्रान्तिकारी परिस्थिति विकसित होने लगी । उधर भारतीय पूँजीयादी वर्ग भी अपने विकास।तथा उन्नति के लिये साम्राज्य-वादी युद्ध-काल को अच्छी तरह प्रयोग करना चाहता था। यह तभी सम्भव था कि किसी प्रकार के युद्ध-काल में भारत-वर्ष में श्रशान्ति न फैलने पाये । साथ हो साथ भारतीय पूँजीवाद के विकास के लिये राजनीतिक सुधार प्राप्त करना भी श्रावश्यक सममता था। यह तभी सम्भव हो सकता था जब हिन्दू-मुस्लिम पूँजीपतियों के बीच सममौता हो जाता और वे एक हो उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रयास करते। यहाँ पर हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि भारतीय पूँजीवाद के विकास तथा प्रगति के साथ-साथ भारतीय पूँजीबोदी वर्ग का अन्तरिक संघर्ष भी तीव्र हो उठा था, जिसके कारण इनके बीच एकता

१०६ हिन्दुस्तान श्रोर पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेषण

कायम नहीं हो सकी।

साम्राज्यवादी युद्ध की प्रगति के साथ युद्ध-परिस्थिति में परिवर्तन होता जा रहा था। मित्र-राष्ट्रों की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। धुरी राष्ट्र हर आक्रमण-चेत्र में विजयी होते जा रहे थे। यह ज्ञात होता था कि धुरी राष्ट्र के पत्त में युद्ध का निर्णय होगा । युद्ध की ऐसी परिस्थिति में जापान भी युद्ध में कूद पड़ा। प्रारम्भ में ही अमेरिका के उपनिवेशों पर आक्रमणकर उसने अपने कब्जे में कर लिया। प्रत्येक युद्ध-त्तेत्र में उसने अमेरिका और बिटेनको परास्त किया। भारतवर्षं की सीमा तक युद्ध पहुँच गया था। ब्रिटिश सरकार वेचैन हो उठी । केवल सैनिक शक्ति से ब्राक्रमण्यारियों का मुकाबिला नहीं किया जा सकता था, जबकि सारे देश में वगावत की प्रवृत्ति प्रवल हो उठी थी। ऋतः त्रिटिश सरकार के लिये यह आवश्यक हो गया कि भारतीय पूँजीवादी वर्ग तथा राष्ट्रीय सुधारवादी पूँजीवादी नेतृत्व का युद्ध के संचालन में सहयोग प्राप्त करे । इसके लिये यह भी आवश्यक था हिन्दू और मुस्लिम पूँजीपतियों के बीच किस प्रकार का मेल कायम किया जाय। इन उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु सन् १६४२ ई० के मार्च महीने में ब्रिटिश मन्त्रि-मंडल की श्रोर से एक प्रस्ताव लेकर सर स्टैफौर्ड किप्स भारत पधारे। ब्रिटिश युद्ध परिषद ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। इस प्रस्ताव के प्रारम्भ में कहा गया था कि "सम्राट्की सरकार ने इस मुल्क तथा भारत में भविष्य की भारत सम्बन्धी की गई प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के पत्त में प्रकट की गई तमाम उत्सुकतात्रों पर विचार करके यह न गीय किया है कि उन तमाम तरीकों को स्पष्ट शब्दों में कर

दे, जो, जहाँ तक सम्भव है, भारत को शीव्राति-शीव्र स्वायत्त-शासन प्रदान करने के लिये अमल में लाये जायेंगे। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य एकनवीन भारत संघ (New Indian Union)। की स्थापना करना है, जो अन्य उपनिवेशों की भाँति समान क्ष्म से समाद् के प्रति उत्तरदायित्व रखते हुए, एक उपनिवेश होगा, किन्तु यह हर मानी में अन्य उपनिवेशों के समान रहेगा और किसी भी तरह अपने आंतरिक, घरेल प्रबन्धों में परतंत्र नहीं रहेगा।"

इस प्रस्ताव में साम्प्रदायिक समस्या को भी सुलमाने के लिये इस प्रकार रखा गया था कि "यदि ब्रिटिश भारत का कोई प्रान्त अपनी वर्तमान वैधानिक अवस्था को बनाये रखने के लिये नवीन विधान को ही नहीं स्वीकार करता है, यदि यह निर्णिय करे, तो उसे अलग होने का अधिकार होगा।

"इस प्रकार के अलग होने वाले प्रान्तों के साथ, याद वे ऐसी इच्छा करें, सम्राट् की सरकार नया वैधानिक समम्मीता करने के लिये तैयार है, जिसके अनुसार इन प्रान्तों को भारतीय संघ के सभी अधिकार पूर्णक्रपेण प्राप्त होंगे और यह वैधानिक स्थान उन उपायों का अवलम्बन करके प्राप्त किया जा सकता है, जो यहाँ पर अंकित उपायों के समान होंगे।"

लेकिन यह प्रस्ताव भी असफल रहा । किसी भी प्रकार साम्प्रदायिक समस्याओं को यह नहीं सुलका सका । बिल्क इसने और भी उलका दिया। सर स्टैफर्ड किप्स विफल होकर इंगलैण्ड वापस चले गये । सन् १६४२ ई० के मई महीने में राष्ट्रीय कांग्रेस के अखिल भारतीय कमेटी की वैठक दिल्ली में हुई। इस

१०८ हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेषण

बैठक में श्री जगत नारायण लाल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया जो बहुमत से स्वीकृत हुआ:—"श्रखिल भारतीय कांग्रेस का यह हद मन है कि भारत के किसी अंगभूत राज्य अथवा प्रादेशिक इकाई को भारतीय संघ या फेडरेशन से सम्बन्ध-विच्छेद करने की स्वतंत्रता देना विभिन्न राज्यों, प्रान्तों तथा सम्पूर्ण देश की जनता के हित के लिये परम घातक होगा। अतः कांग्रेस ऐसे किसी भा प्रोधाम पर सहमत नहीं हो सकती है।"

राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति से बाध्य होकर राष्ट्रीय सुधारवादी पूँजीवादी नेतृत्व ने 'भारत छोड़ो का प्रस्ता ।' सन् १६४२ ई० के - श्रगस्त को पास किया। उसके उपरान्त कांब्रेस के नेताओं के जेलों में बन्द हो जाने से स्वतंत्र हो भारतीय जनता ने स्वतः विख्यात श्रगस्त कास्ति को संगठित श्रीर संचालित किया। सन् १६४४ ई० के मई में गांधी जी जेल से बाहर आये। युद्ध की परिस्थिति में परिवर्तन हुआ। युद्ध के प्रत्येक आक्रमण-चेत्र में धुरी राष्ट्र पीछे इटने लगे। उनकी हार पर हार होने लगी। अब यह स्पष्ट ज्ञात होने लगा कि मित्र राष्ट्रीं की विजय निश्चय होगी। इसके ऋतिरिक्त सन् १६४४ ई० की अगस्त क्रांति से भारतीय शोषित जनता के विकितित कान्तिकारी संयुक्त मोर्चे से त्रिटिश साम्राज्यशाही के अलावे भार-तीय पूँजीवादी वर्ग का भी अस्तित्व खतरा में पड़ा हुआ ज्ञात होने लगा। भारतीय पूँजीवादी वर्ग ब्रिटिश साम्राज्यवादी-पूँजी-वादी वर्ग के साथ सममौता के लिये बेचैन हो उठा। लोकन ब्रिटिश पूँजीवादी वर्ग के साथ सममीता तभी सम्भव हो सकेगा जव कि हिन्दू-मुस्लिम पूँजीपतियों के बीच किसी प्रकार का समभौता हो। इन उ. १२ यों की पूर्ति के लिये श्री राजगोपालाचार्य ने 'हन्दू-मुस्लिम समभौते के लिये एक मसविदा (formula) तैयार किया, जो ''सी श्रीर श्रीर कारमूला'' के नाम से विख्यात हो गया है। इसमें पाकिस्तान का समर्थन किया गया। साम्प्रदायिक श्रीधार पर भारत के विभाजन का भी समर्थन किया गया। यह फारमूला इस प्रकार का है:—

'भारतीय राष्ट्रीय तथा ऋखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच सममीने की शर्तें जिसमें गांधी जी तथा मि० जिल्ला सह-मत हों, कांत्रेस श्रीर लीग को स्वीकार कराने का यथाशिक अयत्न करेंगे।

- (१) "समभौते की शर्तों के अनुसार जहाँ तक स्वतंत्र भारत के विधान का सम्बन्ध है, सुस्लिम लीग भारतीयों की स्वतंत्रता की माँग को अंगीकार करती है। और परिवर्तन काल में अस्थायी सरकार की स्थापना में कांग्रेस के साथ सहयोग देगी।
- (२) "युद्ध की समाप्ति पर उत्तरी, पिन्छमी तथा पूर्वी भारत के बहुसंख्यक तथा निकटवर्त्ती सुस्लिम जिलों की सीमा की निर्धारित करने के लिये एक कमीशन की नियुक्ति की जायगी। इन सीमित चेत्रों में भारत से प्रथक होने के प्रश्न के द्यंतिम निर्णाय के लिये बालिंग मताधिकार या मत प्राप्त करने की द्यन्य किसी सम्भन उपाय का द्यवलम्बन करके सारे निवासियों का मत संग्रह किया जायगा। यदि बहुमत भारत से पृथक स्वतंत्र सब द्यायकार सुरचित राज्य की स्थापना का समर्थन करेगा, तो इस निर्णय को तुरन्त द्यमल में लाया जायगा।

११० हिन्दुस्तान त्र्योर पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेपण

- (३) "जनता के मत संप्रह के पूर्व सभी दलों के लोगों को जनता के बीच अपनें[विचारों के प्रचार की पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी।
- (४) "पृथक होने के अवसर पर रत्ता, व्यापार, यातायात तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर एक आपसी समकीता होगा।
- (४) "जनता का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना उसकी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर रहेगा।
- (६) "उपरोक्त रार्तों का बन्धन उसी दशा में होगा जब कि त्रिटेन भारत सरकार को पूर्ण अधिकार एवं जिम्मेदारी सींप देगा।"

स्टैलिनवादियों ने तहदिल से इस हा समर्थन किया था। भारत के श्रान्य सुवारवादियों के साथ इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिये साम्प्रदायिक एकता को ऋत्यावश्यक सिद्ध करने की चेष्टा की और सी० आर० फार्मृला को उपरोक्त उंश्य की पूर्ति के लिये आवश्यक प्रमाणित करने का प्रयत्न किया। यदि हम स्वयं इस फार्मृला के रचियता महोदय के तर्कों तथा फार्मृला का भी सूदग विश्लेषण करें तो हमें यह बात स्पष्ट रूप से दिखाई देगी कि इसके द्वारा किसी प्रकार से पूर्ण स्वतंत्रता की पाप्ति के लिये जनकांति की आयोजना नहीं की जा रही थी. बल्कि वास्तविकता इसके विपरीत थी । उनके तर्कों के विश्लेषण से इम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिये जनकांति को वे (स्टैलिनवादी) आवश्यक नहीं सममते और उनके दिमाग में यह बात घर कर गई है कि बिना किसी प्रकार की लड़ाई के श्रमिक-शोषित जनता शोषण तथा गुलामी से मुक्त हो जायेगी। अतः इस फार्मूला की व्याख्या स्वतंत्रता की लड़ाई के पच में करना उनके (स्टैलिनवादियों के) लिये स्वामाविक था और

साथ ही साथ यह केवल आतम प्रवब्चना ही नहीं बल्कि शोपित श्रमिक जनता को गुमराह करने के भी वे आपराधी थे। स्टै-लिनवादी जानवूमकर भारतीय श्रमिक जनता को गुमराह करने की धृष्टता कर रहे थे।

अब हम उक्त फार्मृला के अंग-प्रत्यंग का विश्लेषण कर्के देखं कि उनमें क्या रहत्य छिपा हुआ है । इस फार्मूला के प्रारम्भ में ही कहा गया है कि "जहाँ तक भारत की स्वेतंत्रता के विधान का प्रश्न है, मुस्तिम लींग भारतवासियों की स्वतं-त्रता की माँग को अंगीकार करती है और परिवर्तन काल में अस्थायी सरकार की स्थापना में कांग्रेस के साथ सहयोग करेगी।" इससे यह तो सप्ट हो जाता है कि मुश्लिम लोग से केवल भारतवर्षे को स्वतंत्रता की माँग का समर्थन श्रीर संक्रमण काल में अस्थायी सरकार की स्थापना में सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। इस फार्मूला के अनु-सार आजादी की लड़ाई के समर्थन तथा उसमें सहयोग प्रदान करने के लिये मुस्लिम लीग के सामने कोई प्रश्न नहीं उठता था क्योंकि रचयिता महोद्य स्वयं आजादी की लड़ाई की अना-वश्यक सममते थे। इस फार्मू ला की छान्तिम शर्त से स्पष्ट हो जाता है, जिसमें।कहा गया है कि उपरोक्त शतों का सम्बन्ध तभी लागू होगा, जब ब्रिटेन भारत सरकार को पूर्ण अधिकार तथा जिम्मेदारी समर्पित कर देगी। इस 'फार्मूला' में यह मान लिया गया था कि ब्रिटिश सरकार स्वयं राज्यसत्ता सींप देगी। उसके लिये भारतीय जनता को किसी प्रकार का प्रयतन नहीं करना होगा। अतः इसके अनुसार ब्रिटेन से सादर आप्त-राज्य व्यवस्था के संचालन का प्रश्न हैं, सशस्त्र जनकान्ति के

द्वारा राज्यसत्ता हस्तान्तरिक करने का प्रश्न नहीं है। इसके (फार्मूला के) पीछे गांधी जी का केवल आशीर्वाद ही नहीं था, बल्क इसे आधार बनाकर गांधी जी ने मि० जिन्ना के साथ हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक समस्या को सुलकाने के लिये बातें कीं। यह प्रश्न उठाना स्वाभाविक है कि श्री जगतनारायण जी के प्रस्ताव—जिसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बहुमत से स्वीकार किया था—के रहते हुए गांधी जी ने ऐसा क्यों किया ? इसे समक्तने के लिये हमें बहुत सी घटनाओं को समक्ता पढ़ेगा। उनसे अलगकर इसे ठीक-ठीक समक्तना सम्भव नहीं है।

यहाँ पर हम यह न भूलें कि राष्ट्र की राष्ट्रीय सुधारवादी नीति का संचालन प्रधानतः राष्ट्रीय कांग्रेस के सुधारवादी नेतृत्व के द्वारा होता रहा है, जिसकी बागडोर गांधी जी के हाथों में सन् १६२० ई० बाद रहता रहा। अर्थात् गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय कांग्रेस संचालित होती रही। कांग्रेस द्वारा संचालित सुधारवादी अपन्दोलन के प्रतिविभ्य गांधी जी सर्वदा खांची के आन्दोलन का प्रधान सेनानायक बनाये गये और सन् १६४० ई० में भी थे। राष्ट्रीय कांग्रेस में गांधी जी भावी राष्ट्रीय आजादी के आन्दोलन का प्रधान सेनानायक बनाये गये और सन् १६४४ ई० में भी थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वश्रेष्ठ स्थान पर होते हुए गांधी जी ने भारत-विभाजन के फार्मूले का स्थान गत किया, जिसका स्पष्ट अर्थ था, भारतीय श्रमिक-शोषित-पीड़ित जनता को कई दुकड़ों में बाँटना। विरोध की अपन की तेज को बनाये रखने के लिये वर्षों से आजादी के आन्दोलन में प्राणों की आहुति देने तथा सन् १६४२ ई० के भीषण स्वतंन्त्रता संग्राम में अकथनीय बलिदान के प्रधात भारतीय श्रमिक-

शोषित-पीड़ित जनता के विकसित कान्तिकारी संयुक्त मोर्चे को अंग करने के हेतु यह फार्मूला निर्मित किया गया था। इसे श्रीर स्पष्ट रूप से सममने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस के पिछले कुछ वर्षों के इतिहास पर दृष्टिपात करना आवश्यक है।

साम्राज्यवादी युद्ध की सम्भावना और भारताय राष्ट्रीय कांग्रेस

सन् १६२५ ई० के उपरान्त संसार-ज्यापी आर्थिक संकट विक-खित होने लगा था श्रीर सन् १६२६ ई० में मानव समाज के सामाजिक तथा श्रार्थिक जीवन में विशाल रूप में यह खड़ा हो गया था। इसके साथ ही साथ संसार के राजनीतिक आकाश में युद्ध के बादल उड़ते हुये दृष्टिगीचर हो रहे थे। यह आशंका होने लगी थी कि किसी भी चए ये यटायें मूसलाधार वृष्टि से सारे संसार को प्लावित कर देंगी। एसे समय सभी राजनीतिक सजीव शक्तियाँ अकस्मात् फट पड़ने वाली उस विपत्ति के बादल का सामना करने के लिये तदानुकूल कार्य्यवाही कर रही थीं। राष्ट्रीय कांत्रेस ने इस भावी साम्राज्यवादी युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार का फँसना अवश्यम्भावी समम-कर सन् १६२७ ई० से ही-मद्रास कांग्रेस से ही-हर एक कांत्रेस अधिवेशन में युद्ध-विरोधी प्रस्ताव पास करना प्रारम्भ कर दिया। सन् १९३२ ई० के आन्दोलन के जिफल होने के बाद भारत में सन् १६३४ ई० के विधान की घोषणा की गई। कांग्रेस ने अपनी बैठकों तथा अधिवेशनों में इसकी कड़ी आली-चना की और सर्वदा इसे ध्वंस करने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। इस विधान के अनुसार सन् १६३७ ई० के प्रारम्म

में प्रथम चुनाव भारतवर्ष के सभी प्रान्तों में हुआ। राष्ट्रीय कांग्रेस की श्रोर से चुनाव घोपणा-पत्र प्रकाशित किया गया। इसमें यह स्पष्टतः कहा गया कि यह विधान भारतवर्ष के लिये घातक है, श्रतः इसे ध्वंस करने के लिये ही कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। श्रतः सन् १६३४ ई० के भारतीय विधान को ध्वंस करने की नीति के श्राधार पर राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय जनता से वोट लिया, जिसके परिणामस्त्रक्षप ११ प्रान्तों में से ७ प्रान्तों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुत्रा। विधान को ध्वंस करने की नीति को ताख पर रखकर भारतवर्ष के सात प्रान्तों में कांग्रेस मन्त्रि-मंडल स्थापित किया गया।

सन् १६३७ ई० के जुलाई महीने में ७ प्रान्तों में कांग्रेस की मित्रमंडल की स्थापना हुई। जनता के द्वाव से फाँसी और गोली से बचे हुए मुद्दतों से जेलों में पड़े हुये क्रान्तिकारी बन्दी जेलों से मुक्त किये गये। हजारों की तादाद में वे जेलों के फाटक से बाहर आये। काकोरी पड्यन्त्र के प्रमुख नेता अमर राहीद सचीन्द्र नाथ सन्याल, साथी योगेशचन्द्र चटर्जी आदि भी बाहर आये। वर्षा तक वे जेलों के सींकचों के अन्दर बन्द रहे। दमन के सुधारवादी पूँजीवादी आन्दोलन के द्वारा भारतीय जनता को उनसे एकदम पृथक् करने का प्रयत्न किया गया था। परन्तु जनता के हृदय में अभी भी उनकी स्मृतियाँ शेप थीं, उनके प्रति चिरकाल संचित सनेह और सहानुभूति उन्हें देखते ही बड़े वेग से उमड़ पड़ी। अपार जन-सागर उनके दर्शन के लिये उमड़ पड़ा, देशवासियों ने उन पर पुष्प-वृष्टि की, उनके चर्णों की रज ली, उनकी प्रशंसा तथा गुणानुवाद करके वह आनन्द-विभोर हो उठी। क्रान्तिकारियों तथा जनता

के इस प्रेम-मिलन से राष्ट्रीय कांत्रेस के सुधारवादी पूँजीवादी नेतृत्व तथा ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार दोनों ही सम्र हो गये। ब्रिटिश सरकार ने यह विश्वास कर लिया था कि वर्ण से व्यहिसा और शान्ति का पाठ पड़ाकर राष्ट्रीय कांग्रेस के सुधार वादी पूँजीवादी नेतृत्व ने आम जनता को क्रान्ति-पथ से विमुख कर दिया था। राष्ट्रीय सुधारवादी नेतृत्व की भी यही आन्ति-पूर्ण धारण थी, किन्तु इस घटना ने उनकी बुद्धि पर से इस अम का पड़ा पर्दा उठा दिया और वास्तविकता को स्पष्ट कर दिया।

जनता द्वारा क्रान्तिकारियों के रवागन को देखकर यू० पी० का गवर्नर परेशान हो उठा था और इसे बन्द कराने के लिये उसने यू० पी० प्रान्तीय कांग्रेसी मन्त्रिमंडल पर द्वाव डाला। सर्वप्रथम कांग्रेस के बढ़े-बड़े नेतागणों ने कांग्रेस-जनों को स्वागत आदि से अलग रखने की चेध्टा की, पर जनता के सामने वे सफल नहीं हो सके। इधर इसे देखकर गांधीजी भी षेचैन हो उठे, क्रान्तिकारियों का जनता द्वारा किया गया यह सम्मान उन्हें असदा हो गया। तुरन्त ही उन्होंने इस आशय का एक बक्तव्य दिया कि "जनता का क्रान्तिकारियों का ऐसा रवागत करने का अर्थ होता है, क्रान्तिकारी आन्दोलन का समर्थन करना, जिससे भारत को काफी हानि पहुँची है और देश की स्वतंत्रता की लड़ाई पीछे चली गई है।"

काकोरी षड्यन्त्र केस के प्रमुख बन्दी श्री विष्णुशरण दुबिलश वर्षों तक जेल-जीवन व्यतीत करने के बाद जब द्यान्य क्रान्तिकारियों के साथ बाहर आये तब यू० पी० प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने प्रान्तीय कायेकारियी कमेटी का सदस्य उन्हें चुना। इससे भी यू० पी० गवर्नर के दिमाग में चकर आने लगा। उन्होंने स्पष्टतः कांग्रेस नेताओं से कहा कि कांग्रेस की प्रान्तीय कार्यकारिणी कमेटी के क्रान्तिकारी सदस्य होने का अर्थ, क्रान्तिकारियों का कांग्रेस के अपर प्रभाव है, जो भारत और ब्रिटेन के लिये घातक होगा। गवर्नर के दबाक डालने पर कांग्रेस के एक बड़े नेता ने भी विष्णुशरणजी से इस्तीका देने को कहा। परन्तु उन्होंने साफ-साफ कह दिया। के ऐसा नहीं हो सकता। जिन लोगों ने चुना है, वे ही वापस बुला सकते हैं। फिर कांग्रेसी सदस्यों से कहा गया। उन लोगों ने भी साफ-साफ कह दिया कि विष्णुशरणजी ही सदस्य रहेंगे।

सन् १६३५ ई० के भारतीय विधान को ध्वंस करने के नाम पर कांग्रेस के सुधारवादी पूँजीवादी नेतृत्व ने श्राम जनता से बोट लिया था। भारतीय श्राम जनता में इसने भारतीय विधान को भारतीय जनता के लिये घातक बताया था श्रीर वास्तव में था भी। परन्तु चुनाव के उपरान्त कांग्रेस का सुधारवादी नेतृत्व इसे (विधान को) कार्यान्वित करने लगा। श्राम जनता श्रमका गई श्रीर सन्न होकर एकटकी लगाकर देखने लगी कि हो क्या रहा है। फिर क्रमशः कांग्रेस-विरोधी भावना पैदा होने लगी। कांग्रेस के सुधारवादी नेतृत्व को ये सन्देह श्रीर श्रवि-रवास की दृष्टि से देखने लगे। कांग्रेसी मन्त्रिमंडल की स्थापना के बाद सन् १६३७ ई० में इलाहाबाद में एक श्राम जलस में बोलते हुए श्रीपुरुपोत्तमदास टंडन ने श्रीजवाहरलाल नेहरू से यह प्रश्न किया था कि "क्या व श्रपने सीने पर हाथ रखकर यह कह सकते हैं कि कांग्रेस, मन्त्रिमंडल बनाकर विधान- मंग करने के अपने वादे को पूरी कर रही है ?" वहाँ पर शी-नेहरूजी भी उपस्थित थे। श्रीटंडनजी के यह कहने का स्पष्ट अर्थ यह था कि कांग्रेस विधान को सफल बना रही थी। यह विचार केवल टंडनजी का ही नहीं था, बल्कि आम जनता भी इसी प्रकार सममने लगी थी। इससे परेशान होकर सन् १६३७ ई० में ही गांधीजी ने स्थिति को स्पष्ट करने के लिये एक बक्तव्य दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'कांग्रेस के द्वारा मन्त्रि-मंडल ग्रहण का उद्देश्य केवल सशस्त्र-क्रान्ति तथा भारतीय इतिहास में बेजोड़ भावी भयानक जन-आन्दोलन को रोकना है। यहाँ पर गांधीजी ने परिस्थितियों से बाध्य होकर कांग्रेस की क्रान्ति-विरोधी नीति को जनता के सामने रख दिया था। राष्ट्रीय कांग्रेस को पूँजीवादी वर्गाय पार्टी वनाने का प्रयास

श्रभी तक राष्ट्रीय कांग्रेस किसी वर्ग विशेष की संस्था नहीं हो सकी थी। यह किसी वर्ग विशेष के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली शुद्ध अर्थ में एक वर्ग विशेष की पार्टी नहीं हुई थी। इसमें जरा भी सन्देह नहीं था कि पूँजीवादी विचारधारा रखने वालों का ही इसमें बोल-बाला था और इन्हीं लोगों के द्वारा इसकी नीति भारतीय पूँजीवाद के विकास तथा प्रगति की दृष्टिकोण से निर्धारित होती थी। अर्थात् इसका नेतृत्व पूर्णतः सुधारवादी पूँजीवादी रहा। किन्तु साथ ही साथ अव तक यहाँ सभी विचार के लोगों का समावेश था—सभी अपने सामा-जिक उदेश्य की पूर्ति करने के लिये कांग्रेस का प्रयोग करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन सन् १६३० में इसका सुधार-वादी पूँजीवादी नेतृत्व सतर्क हो गया और इसे शुद्ध पँजीवादी वर्ग की पार्टी का रूप देना चाहा।

११८ हिन्दुस्तान ऋौर पाकिस्तान का ऐतिहासिक विरलेण्ण

इसी ब्रोर कांग्रेस के सुधारवादी पूँजीवादी नेतृत्व ने एक कदम श्रीर डठाया । हरिपुरा कांग्रेस में रियासत-सम्बन्धी एक प्रस्ताव पास किया, जिसके द्वारा कांग्रेस-जनीं को रियासतों में कांग्रेस के नाम पर संगठन करने से मना कर दिया गया। सन् १६३८ ई० के सितम्बर में ऋष्विल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई। सुधारवादी नेतृत्व ने सत्य और ऋहिंसा को स्वीकार कराने के लिये इसके सामने एक प्रस्ताव पेश किया । इसके विरोध में वामपची सभा भवन को छोड़कर चले गये। इसके बाद गांधीजी ने इस आशय का वक्तव्य दिया कि "कांप्रेस में दो परस्पर-विरोधी विचारधारात्रों का रहना सम्भव नहीं है, या तो इसमें वामपत्ती ही रहेंगे या दिवण-पद्मी ही।" गांधीजी इस समय इतने ज्यादे चातुर हो उठ कि कांत्रेस के इतिहास का वास्तविक रूप उनकी आँखों से आंमल हो गया। वे इस बात को भूलते हुये दिखाई पड़ रहे थे कि कांत्रेस कभी भी एक विचार वालों की संस्था नहीं रही थी। जब हम यह समफ जायंंगे कि उस समय समाजवादी विचारधारा जोरों के साथ देश भर में फैल रही थी, तो हमें गांधीजी का इस प्रकार आतुर और भयभीत हो जाना अस्वाभाविक नहीं प्रतीत होगा। राष्ट्रीय कांग्रेस तथा कांग्रेस आन्दोलन के गर्भ से कांत्रेस समाजवाद तथा कांत्रेस समाजवादी पार्टी का जन्म श्रीर राष्ट्रीय क्रान्तिकारी श्रान्दोलन से क्रान्तिकारी समाजवाद तथा क्रान्तिकारी समाजवादी आन्दोलन विकसित हुआ। समाजवादी विचारधारा दिन दूने रात चौगुने बेग से बढ़ रही थी। यहाँ तक कि हरिपुरा कांग्रेस के अध्यक्त पद से भाषण देते हुए नेताजी सुमायचन्द्र बोस ने समाजवादी निद्धान्त का समर्थन और प्रचार किया । भारतीय पूँजीवादी वर्ग का सुधारवादी पूँजीवादी नेतृत्व के द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में एक जन-संगठन के ऊपर प्रभुत्व कायम हो चुका था जिल्ला प्रभाव भारतीय जनता के ऊपर काफी था, वह इसे समाजवादियों के हाथों में जाने से रोकना चाहता था, इसके लिये इसे एक वर्ग विशेष की पार्टी में परिवर्तित करना चाहता था। गांधीजी का वक्तव्य इन्हीं परिस्थितियों का उपज था। सुधारवादी पूँजीवादी नेतृत्व अपने को सुरिक्त रखने के लिये कांग्रेस को सुधारवादियों का एक सुदृढ़ दुर्ग वनाने का प्रयत्न करने लगा।

त्रिपुरी कांग्रेस और वामपक्षी एकता

सन् १६३६ ई० त्रिपुरी कांग्रेस के लिये अध्यक्त के चुनाव में अपने प्रतिद्वन्दी श्रीपट्टाभीसीतारमैया को हटाकर सुभाप बाबू बहुमत से पुनः कांग्रेस का अध्यक्त निर्धाचित हुए। हरिपुरा कांग्रेस के अध्यक्त के पद से नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने समाजवादी विचारधारा का प्रचार किया था। इससे वे सुधार वादी पूँजीवादी दिल्ला-पन्नी नेताओं के दिल में खटकने लगे थे। अतः त्रिपुरी कांग्रेस के लिये अध्यक्त के चुनाव में सुभाष बाबू के विकद्ध में उन्होंने श्रीपट्टाभीसीतारमैया को सफल बनाने का काफी प्रयत्न किया। किन्तु उन्हें मुँह की खानी पड़ी; राष्ट्र ने पुनः सुभाप बाबू को राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित किया। सुभाप बाबू की इस सफलता के कप में वामपत्नी शिक्तयों की विजय से गांधीजी तथा कांग्रेस के अन्य सुधार वादी नेताओं की छाती पर साँप लोट गया, वे उनकी शक्तिवृद्धि को अपने अस्तित्व के लिये घातक समक्तने लगे। चुनाव के

परिणाम की घोपणा होते ही गांधी जी ने एक वक्तव्य दिया कि "यह पट्टाभीसीतारमैया की हार नहीं है, बल्कि मेरी हार है।" इसमें सन्देह नहीं कि यह गांधीजी की व्यक्तिगत हार न होते हुए भी वामपिचयों के मुकावले में सुधारवादी पूँजीयादी नेतृत्व की गहरी हार अवश्य थी। इस वक्तव्य के पश्चात् राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी से १४ सदस्यों में से ११ सुधारवादी सदस्यों ने त्याग-पत्र दे दिया । पूँजीवादी सुधार-वादी नेतृत्व बदहवाश हो रहा था। यह एक प्रकार से पंगु होकर धराशायी हो गया था श्रौर अन्तिम साँस लेने की अवस्था को पहुँच रहा था। परन्तु वह शीव ही होश में आया और तुरन्त श्रपने श्रास्तत्व को कायम करने के लिये जी-जान लगाकर प्रयत्न करने लगा। कांग्रेस की एकता के नाम से भारतीय समाज-वाद की वेदी पर कांमेस समाजवादी पार्टी के द्वारा वासपत्ती एकता की वाल चढ़ाई गई और वामपत्ती आन्दोलन के साथ विश्वासघात कर सुधारवादी समाजवादी नेतृत्व ने मरणासन्न सुधारवादी पूँजीवादी नेतृत्व को संजीवनी वृटी दे दी श्रीर वह पुनः सबल ऋौर सचेत हो उठ बैठा। ऋतः कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के सुधारवादी पूँजीबादी नेतृत्व के लिये वाम-पची किला-बन्दी का काम किया।

राष्ट्रीय कांग्रेस और वामपक्षी आन्दोलन

पुनः खोये हुए प्रमुत्व को सुधारवादी नेतृत्व ने प्राप्त किया।
एक प्रकार के नये जीवन का संचय हुआ। पुनः जीवन पाकर
सूखे शेर की भाँ ति यह (राष्ट्रीय कांग्रेस का सुधारवादी पूँजीवादी नेतृत्व) खूँ ख्वार हो उठा और कांग्रेस के अन्दर सदैव
के लिये वामपन्ना शक्तियों को समाप्त कर देने के लिये मुँह

फाड़कर वह दौड़ पड़ा। सबसे पहले उसने अध्यन्न के ऊपर आक्रमण किया और निगल गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कलकत्ता की बैठक में लाचार होकर सुभाष बाबू को अध्यत्त पद से त्याग-पत्र देना पड़ा और उसं बैठक में कांग्रेस विधान में परिवर्तन करने के लिये विधान उपसमिति नियुक्त की गई। इस कमेटी की बैठक जून सन् १६३६ ई० में वम्बई में हुई और इसने बहुमत से यह सिफारिश की कि कांग्रेस किसी भी अन्य राजनीतिक पार्टी के सदस्य को 'अपना सदस्य न बनाने का अपने विधान में यह परिवर्तन स्वीकार करे।'

सन १६३६ ई० के जून के अन्तिम सप्ताह में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, लेकिन कमेटी की यह सिफारिस वहाँ उपिथत न कर रामगढ़ कांग्रेस के लिये स्थिगत कर
दी गई। लेकिन इस बैठक में दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किये
गये। पहले प्रस्ताव के अनुसार कोई भी कांग्रेस-जन प्रान्तीय
कांग्रेस की आज्ञा के बिना किसान और मजदूरों के संघर्ष में
भाग नहीं ले सकेगा। दूसरे प्रस्ताव के अनुसार प्रान्तीय
कांग्रेस कमेटी के नियन्त्रण में कांग्रेसी मंत्रिमंडल स्वतंत्र है,
और कोई भी कांग्रेस-जन मन्त्रिमंडल की आलोचना नहीं कर
सकेगा। जनता में इस प्रस्ताव के विरोध का नेतृत्व सुभाष
वाबू ने किया, इस पर अनुशासन की कार्यवाही करके उन्हें तीन
साल के लिये कांग्रेस से अलग कर दिया गया। त्रिपुरी कांग्रेस
होने के कुछ समय पहले बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से यह सिफारिश की थी कि
"छ: महीने का अल्टीमेटम देने के प्रधात ब्रिटिश सरकार के

४२२ हिन्दुस्तान श्रीर पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लषण्

विरुद्ध आजादी की लड़ाई की घोषणा कर दी जाय।" लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस के सुधारवादी नेतृत्व ने इसे ठुकरा दिया।

द्सरे संसार त्यापी साम्राज्यवादी युद्ध का प्रारम्भ श्रीर भारतीय पूजीवादी वर्ग

साम्राज्यवादी पूँजीवादी देशों के वीच का संवर्ष दिन प्रति-दिन तीत्र होता गया स्त्रौर स्त्रन्त में सन् १६३६ ई० के सितम्बर महीने के प्रथम सप्ताह के प्रारम्भ में यह संसार्व्यापी साम्राज्य-वादी युद्ध में परिवर्तित हो गया। जर्मनी ने पोलैएड पर आक्र-मण किया। तुरन्त इसके ब्रिटिश श्रीर फ्रेंच साम्राज्यवादी सरकारों ने जर्मना के विरुद्ध युद्ध की घोपणा की और संसार-व्यापी युद्ध का डंका गूँज उठा। ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार के युद्ध में फँसते ही भारतीय श्रमिक-शोषित-पीड़ित जनता में श्तृ की दु:परिस्थिति से लाभ उठाने की आशा जाग उठी। भारतीय पूँजीवादी वर्ग भी युद्ध-परिस्थिति से लाभ उठाने के लिये आतुरे हो उठा, परन्तु पूँजीवादी वर्ग और शोषित जनता दोनों के लाभ उठाने के उपायों में आकाश-पाताल का अन्तर था। भारतीय शोषित जनता शत्रु को निर्वल तथा विवश देखकर सदैव के लिये च्यपनी गुलामी का बन्धन काट फेंकना चाहती थी, ऋर्थात् वह ब्रिटिश शासन सत्ता को समूल नष्ट कर देना चाहती थी। दूसरी स्त्रोर पूँजीपति इस युद्ध-जन्य परिस्थिति से अधिक लाभ उठाना चाहते थे। देशी बाजार विदेशी प्रतिद्वन्दियों से सुरिचत हो गया था। इस समय वे बिना रोक-टोक एक का तीन बना सकते थे । अपनी पाँचों उँगुलियों को घी में देख वे मौजूदा अवस्था को कायम

रखने के पत्त में थे। अर्थान् वे चाहतं थे कि शोपित जनता इस समय चुपचाप वैठी रहे और ब्रिटिश हुकूमत को किसी प्रकार की आँच न त्रावे, जिससे शान्तिपूर्वक वे धन पैदा कर सकें। इसके अतिरिक्त, वे यह अवश्य चाहते थे कि भारतीय व्यापार और उद्योग-धन्धों की पूरी उन्नति के लिये ब्रिटिश सरकार छुछ भारतीय विधान में सुधार के रूप में छुछ विशेष सुविधायें प्रदान कर दे। इसके अतिरिक्त, वे किसी प्रकार की अन्य राजनीतिक हलचल को अवांछनीय सममते थे। अपने स्वार्थ-सिद्धि में उन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस के सुधारवादी पूँजीवादी नेत्रत्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त था।

यहाँ पर यह उल्लेख करना द्यसंगत नहीं होगा कि भारतीय जनता राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभाव में थी। वह इसकी
(कांग्रेस की) छोर टकटकी लगाये देख रही थी कि उनके सव
दुखों को छन्त करने वाली कान्ति का संचालन कव राष्ट्रीय
कांग्रेस करती है। परन्तु इसके सुधारवादी पूँजीवादी नेतृत्व
का इच्ट तो छपने प्रिय पूँजीपितयों का ध्यान रखना था छौर
साधारण जनता को भी छपने प्रभाव से बाहर यह जाने देना
नहीं चाहता था। छत: उसने नये-नये स्वाँग भरना छारम्भ
कर दिया। सन् १६२७ ई० से लगातार अब तक तो कांग्रेस के
प्रत्येक वार्षिक छाविवेशन में यह युद्ध-विरोधी भस्ताव पास
करता रहा, किन्तु जब समस्च युद्ध छा धमका छोर पूँजीपितयों
की पौबारह पड़ी, तो उसने एकाएक छपनी नीति परिवर्तित कर
दी, युद्ध-विरोधी प्रस्तावों के स्थान पर सरकार से उसके युद्ध
देशों के स्पष्टीकरण की माँग की और दूसरी तरफ जनता
को मुलावे में डाल रखने के लिये तथा कान्ति से दूर रखने के

हेतु बिटिश सरकार के तथा युद्ध के विरुद्ध आन्दोलन का स्वाँग भी रचा जाने लगा। वर्धा की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में एक प्रस्ताव पास करके सरकार से युद्ध के उदेश्यों के स्पष्टीकरण की माँग की गई और दूसरा प्रस्ताव पास किया जिसके अनुसार बिना भारत की सम्मति लिये उसे साम्राज्यवादी युद्ध में यसीटने के कारण केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों को इसमें उपस्थित होने से मना कर दिया गया। अतः आम जनता को अपने प्रभाव में भी रखा और साथ ही साथ सुवारवादी नेतृत्व जन-प्रभाव के दवाव से राजनीतिक सुधार प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगा। इस ऊपर देख चुके हैं कि जनता की क्रान्तिकारी प्रवृत्ति को कुचलकर सदीव उसे सुधारवाद मार्ग पर ले जाने का प्रयत्न कांग्रेस का सुधारवादी नेतृत्व करता रहा था। दूसरे साम्राज्यवादी युद्ध के प्रारम्भ काल से ही यही क्रिया जारी थी।

परन्तु ज्यादा समय तक जनता इस प्रकार नहीं गसी जा सकती थी। उसके अन्दर असन्तोप की श्राम्न तीव्रता के साथ सुलगने लगी। दिन प्रतिदिन ब्रिटिश सरकार यिरोधी प्रवृत्ति तीव्रतर होती गई नो अन्त में विवश होकर राष्ट्रीय कांग्रेस का सुधारवादी पूँजीवादी नेतृत्व ब्रिटिश विरोधी आन्दोलन का नाटक रचने लगा। प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रीमण्डलों ने इस्तीफा दे दिया और रामगढ़ कांग्रेस में आन्दोलन संचालन करने के लिये गांधीजी प्रधान सेनापित के पढ़ पर नियुक्त किये गये। इसके उपरान्त गांधीजी की आज्ञा के अनुसार सभी कांग्रेस कमेटियाँ सत्यायह कमेटी में परिवर्तित कर दी गई। इसका प्रभाव यह हुआ कि मोली-भाली जनता यह अनुमान करने

लगी कि राष्ट्रीय कांग्रेस आन्दोलन प्रारम्भ करने जा रही थी। किन्तु वास्तविकता इसके विपरीत थी, अभी कांग्रेस का सुधारवादी पूँजीवादी नेतृत्व सममौते की आशा लगाये हुए था। यह नो केवल दिखावा था, भोले-भाले जनता को भूल-भूलइयाँ में डालने के लिये और सचमुच इसने भारतीय जनता का मुलाव में डाल दिया था।

ऐसी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्ररिस्थित में भारतीय जनता को माया-जाल में फँस कर साम्राज्यवादी विरोधी लड़ाई छेड़ने की लम्बी-चौड़ी डींग मारकर सुधारवादी पूँजी-बादी नेतृत्व उसे (शोपित जनता) क्रान्ति-पथ से विमुख करेने की चेष्टा में संलग्न था, बाम-पद्मी सुभाप बाबू के नेतृत्व में जनता को एक बास्तविक क्रान्तिकारी लेड़ाई के लिये संगठित करने का प्रयत्न कर रहे थे। सुभाष बाबू की अध्यक्ता में रामगढ़ कांग्रेस के साथ ही "समकौता विरोधी" कान्क्रोन्स भी हुई । इसके अतिरिक्त, स्वतंत्रता के महाअभियान की तैयारी के लिये "हालवेल मानुमेन्ट" आन्दोलन के रूप में पहला कदम उठाया गया। हम उपर देख चुके हैं कि कांग्रेस की सुधारवादी वैधानिक नीति के कार्यान्त्रित करने के प्रयत्न के परिणाम-स्वरूप साम्प्रदायिक कटुता लगातार बढ़ रही थी, कांग्रेसी मन्त्रि-संडल की स्थापना के बाद वह (साम्प्रदायिक करुता) चरम सीमा पर पहुँच गई। हिन्दू-मुस्लिम दंगा सामाजिक जीवन में नित्य प्रति की दैनिक कियाओं का एक अंग-सा हो गया था। परन्तु स्वतंत्रता के महाअभियान के पूर्व परस्पर विश्वास और सद्भावना आवश्यक थी, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये और श्राजादी की लड़ाई की पृष्टिभूमि तैयार करने के लिये सुभाव

१२६ हिन्दुस्तान ख्रोर पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेषण

वाबू के नेतृत्व में "हालवेल मानुमेन्ट" आन्दोलन संचालित किया गया। सिराजुदौला को भारतीय इतिहास में राष्ट्रीयता का प्रतीक प्रथम बार माना गया। उनके द्वारा अंग्रेजों के चंगुल से अपने देश को छुड़ाने के लिये किये गये उद्योगों का आभन्तन्द्रन किया गया। सिराजुदौला के चित्र को कलंकित करने के हेतु अंग्रेजों ने "हालवेल मानुमेन्ट" की स्थापना की थी, इसे तोड़ने के लिये आन्दोलन किया गया। हिन्दू-मुसलमान सभी इसमें शामिल हुए, आन्दोलन-कत्ताओं को विश्वास तथा सद्भावना उत्पन्न करने के प्रयत्न में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई।

व्यक्तिगत सत्याग्रह

राष्ट्रीय कांत्रेस का पूँजीवादी सुधारवादी नेतृत्व त्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार के साथ सममौता करने चौर जनता की क्रान्तिकारी प्रवृत्ति को दवाने के लिये चातुर हो रहा था। इस-की व्यम्रता निम्नं कित उदाहरण से स्पष्ट होती है। सन् १६४० ई० में युद्ध प्रारम्भ होने के थोड़े समय में फ्रान्स का पतन हो गया चौर भारतीय चाम जनता में यह विश्वास उत्पन्न हो गया कि युद्ध में मित्रराष्ट्रों की हार निद्धय होगी। इससे सशं-कित हो भारतीय जनता ने नोट का बहिष्कार करना प्रारम्भ कर दिया था, इससे भारतीय पूँजीपतियों तथा त्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार के लिये भयानक परिस्थिति पदा होने लगी थी, इसका स्पष्ट चर्थ था व्यापार कार्य चौर राज व्यवस्था का ठप हो जाना। पर राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा प्रस्तावित भावी चान्दोलन का प्रधान सेनानायक गांधीजी इस संकट काल में भारतीय पूँजीवादी वर्ग चौर ब्रिटिश साम्राज्यशाही सरकार की सहायता को दौड़ पड़े और भयावह भावी विपत्ति में उन्होंने (गांधीजी) उनकी रक्षा की। उन्होंने एक वक्तव्य दिया जिसमें भारतीय जनता से नोट लेने का अनुरोध किया था। इसके फलस्वरूप साधारण राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं के सभी किये-कराये पर पानी फिर गया।

सन् १६४० ई० के अगस्त में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय विधान में कुछ राजनीतिक सुधार करने की घोषणा की, पर यह भारतीय पूँजीवादी वर्ग को भी सन्तुष्ट नहीं कर सकी, फलतः कांग्रेस के सुधारवादी नेतृत्व ने भी उस प्रस्ताव के आधार पर युद्ध में सहायता देने से इन्कार कर दिया। परन्तु इसकी और से सममौते का प्रयत्न होता रहा। लगातार वर्षों से पास हुए युद्ध-विरोधी प्रस्तावों को ताक पर रखकर ब्रिटिश सरकार से सममौतां करने तथा युद्ध में सिक्रय सहयोग प्रदान करने के लिये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पूना की बैठक में एक प्रस्ताव पास किया गया, जो 'पूना आफर' के नाम से प्रसिद्ध है। इस समय गांधीजी अपने अनुयायी नेताओं को आशीर्वाद दे स्वयं कांग्रेस से अलग हो गये थे। परन्तु ब्रिटिश सरकार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया।

भारतीय जनता में असन्तोष की मात्रा काफी बढ़ गयी। गांधीजी ने फिर कांग्रेस के नेतृत्व की बगड़ोर प्रहण किया और फिर ब्रिटिश हुकूमत के साथ सममौते का प्रयत्न करने लगे। इस समय वह इतना ही चाहते थे कि वे यह कह सकें कि "युद्ध खराव है, इसमें सहायता देना अनुचित और पाप है।" ब्रिटिश सरकार इतने के लिये इजाजत देना खतरे से खाली नहीं सममती थी। अतः इसे भी उसने दुकरा दिया। फलतः

लाचार होकर गांधीजी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याप्रह का नाटक शुरू हुआ। सत्याप्रह के स्वाभाविक नियम के अनुसार सत्याप्रह प्रारम्भ करने के पहले गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में सरकार को जिखा था कि "इसका उदेश्य किसी तरह ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयत्नों में बाधा पहुँचाना नहीं है 1" श्रतः व्यक्तिगत गत सत्याग्रह के नियम भी इस ऋाधार पर ही बनाये गये थे, जिससे ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार के युद्ध प्रयत्नों को जरा भी चति न पहुँचे। सन् १६४० ई० में यह सत्यागह आरम्भ किया गया था और सन् १६४१ ई० के अन्त तक स्वतः खत्म हो गया । हजारों की संख्या में कांगेस-जन जेल गये। आन्दोलन का हास्यास्पद् अन्त देखकर चतुर और राजनीतिज्ञ व्यक्ति गांधीजी के इस नाटक का रहस्य सममने के लिये बेचैन हो उठे। हम भी इसका विश्लेषण करके देखें कि आखिर यह स्वॉग क्यों रचा गया था। काफी लिखा जा चुका है। अब यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि कांग्रेस सुधारवादी पूँजीवादी नेतृत्व में भारतीय पूँजीवादी वर्ग की अभीष्ट सिद्धि के लिये उनके हाथों की कठपुतली बनी हुई थी। किन्तु यह बात सदैव स्मरण रखनी चाहिये कि राष्ट्रीय कांग्रेस का सुधारवादी पूँजीवादी नेतृत्व इसे (कांग्रेस की) पुँजीवादी वर्ग का हित-सोधन जन-शक्ति के वल पर ही बनाता है। असन्तुष्ट जन-समूह को अपने साथ लेकर साम्राज्यवादी सरकार को जन-श्रान्दोलन के भय से श्रस्त करके वह पूँजी-बादी वर्ग के लाभार्थ राजनीतिक सुधार एंठता रहा। यदि जनता के ऊपर से उसका प्रभुत्व खत्म हो जाय तो वह शक्तिहीन पंगु हो जाता और फिर उसका चिल्ल-पों केवल

अरम्य रोदन हो रह जाता, और वह साम्राज्यवादी सरकार पर किमी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकता था । अतः उसके लिये यह अनिवार्य होता था कि वह जनना को अपने प्रभाव से बाहर न जाने दे। अपनी गुलामी अपर शायमा से मुक्ति की लड़ाई का नेना समभकर भारतीय जनता सुधारवादी ्पृँतावादी नेपृत्व का साथ देनी थी किन्तु जब उसका वर्गीय त्र्याचरण भारताय शोपित जनता के सामने स्पष्ट होने लगा था कि वह अपने निर्दिष्ट श्रेणी की स्वार्थ सिद्धि में लीन हो जनहित की उपेचा करने लगे तो जनता की श्रद्धा भी उन पर कम होना स्वामाविक था और भारतीय जनता सुभाव वाबू क नेत्रव में जन-मार्गेलन का संगठन करने वाले वाम-पित्रों की तरफ स्वमावतः भुक्रने लगी और आशा भरी निगाह से उनकी श्रोर बेचैनी के साथ देखने लगी। क्रमश: भावी जन-अपनदोतन के लिये उनके माएंड के नीचे एकत्र होने लगी। भारतीय पूँजीवादी वर्ग कतई जन-श्रान्दोलन सहन करने को तैयार नहीं था और न वामपित्यों के मंडे के नीचे जनता का एकत्र होना ही बर्गश्त कर सकता था। अतः वामपत्ती मंडे के प्रभाव में जाती हुई भारतीय जनता का रोकने के लिय सुधारवादी पूँजीवादी नेतृत्व ने व्यक्तिगत सत्याप्रह का स्वाँग रचा था। इसमें सन्देह नहीं कि सुधारवादी नेतृत्व ने ऐसा करके जनता को क्रान्ति-पथ से मोड़ने में पर्याप्त सफजता प्राप्त की।

अब तक भारतीय पूँजीवादी वर्ग तथा उसके दलाल भारताय शोषित-पीड़ित जनता को क्रान्ति-पथ से दूर रखने के उपायों का अवलम्बन कर रहे थे। पर सन् १६४१ ई० के

१३० दिन्दुस्तान श्रौर पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेषण

अन्त में और सन १६४२ ई० के प्रारम्भ में उनके विचारों में पिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगा । यह परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय जगत के भीषण परिवतनों का एक प्रतिविम्ब था। सन् १६४१ ई० के श्चन्त में जापान बड़े भीपण बेग के साथ प्रशान्त महासागर के अमेरिका और ब्रिटिश अविकृत टापुओं पर चढ़ दौड़ा। देखत-देखते एक-एक करके टायुद्यों को जापान ने उदरस्थ कर लिया। दोनों विशाल आंग्ल भाषा सम्राज्यवादी शक्तियाँ हाथ पर हाथ रक्खे देखती रह गई थीं और उनसे कुछ करते-धरते न बना; इतना हो नहीं जापान ने सिंगापुर श्रीर मजाया से ब्रिटिश फोजां को भगा दिया था और ब्रह्मा भी अब तब हो रहा था। सिंगपुर तथा मलाया की विजय से ब्रिटिश साम्राज्यबाद की शक्ति, प्रतिष्ठा को काफी धक्का लगा था, उसकी अजेयता पर लोगों को संदेह होनं लगा था। भारतीय पुँजोबादी वर्ग भी ऋति प्रशस्त ब्रिटिश शक्ति की होल में पीज देखकर मावी खतरे से सशंक हो उठा था। उसे विश्वास हो गया था कि ब्रिटिश सरकार अब बाह्य एवं श्रान्तरिक खतरों से उनकी रत्ता करने में असमर्थ है। इसकी प्रतिक्रियास्वरूप अपनी समृद्धि एवं सुख की रता के लिये जापान की कृपा श्रीर सदुभावना प्राप्त करने के लिय वह विकल होने लगा था। उसकी यह धारणा सर्वप्रथम गांधीजी के मुंब से प्रतिध्वनित हुई थी, जब कि उन्होंने अनायास ही काशी विश्वविद्यालय की रजतजयन्ती के अवसर पंर भाषण देते हुए जापन की उन्नति तथा विकास की . प्रशंसा की थीं।

जैताजी सुभाष चन्द्र बीम का भारत से बाहर चला जाना

भारतीय शोषित जनता के सामाजिक जीवन की भौतिक परिस्थिति ने शोषित-पीड़ित जनता को क्रान्ति-पथ से हटाने के सुधारवादी पूँजीबादी नेतृत्व क प्रयत्नों को विफल बना दिया था। बल्कि आर्थिक कठिनाइयाँ तथा अन्य युद्ध-जन्य विपत्तियाँ बराबर ही उसे क्रान्ति की ऋोर घसीटे लिये जा रही थीं। इसके ऋलावा, क्रान्तिकारी शक्तियाँ भी इस अवसर पर मौन न थीं, क्रान्ति की सुलगती हुई अग्नि को वायुका मकोरा दे रही थीं। भारतीय क्रान्तिकारी, सार्वजनिक श्रसन्तीष को एक संगठित जन-क्रान्ति में परिवर्तित करने के लिये प्रयत्नशील थे । जनकान्ति की सफलता के लिये सैनिक सहायता तथा सहयोग श्रीर वाहरी मदद श्रावश्यक होती है। सन् १६४१ ई० की जनवरी में सुभाप वाबू ब्रिटिश मरकार की आँखों में पूल मोंककर हिन्दुस्तान से निकल भागे और ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार के शत्रुओं से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगे। वह हर प्रकार से भारतीय जन-ऋान्ति को सफल बनाने का प्रयत्न करने लगे। मारतीय शोषित-पीड़ित जनता शोषण और गुलामी से मुक्ति के लिये सुभाष बाबू की स्रोर देखने लगी। उसे यह विश्वास हो गया था कि नेताजी सुभाप चन्द्र बोस के नेतृत्व में उसकी आजादी की लड़ाई शीघ ही सफल होगी।

उधर युद्ध-चेत्र में श्रंघेजी साम्राज्यवादी फीजों की बुरी दशा हो रही थी। बिटिश फीजों की पराजय से भारतीय जनता का रोम-रोम पुत्तिकत हो उउना था। बिटिश सरकार

को भी अपनी स्थिति डाँवाडोल होती दिखाई देने लगी, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय घटनायं प्रतिक्रण उसके प्रतिकृत घट रही थीं। इस समय बढ़ती हुई जापानी शांकि को रोकने के लिये उसे भारत की सहायता ऋीर सहयोग की आवंश्यकता मह्सूस होने लगी। भारत की सहायता और सहयोग प्राप्त करने के हेतु उसने एक धोषणा की थी जिसमें भारतीय विधान में पर्याप्त सुधार करने का अश्वासन दिया गया था श्रीर इसके श्राधार पर भारतवर्ष के साथ सममौता करने के लिये सर स्ट्रैफर्ड किप्स सन् १६४२ ई० के मार्च में भारत पहुँचे। अगर यह प्रस्ताव सन् १६४१ ई० में, युद्ध में जापान के शामिल होने के पूर्व आया होता तो भारतीय पूँजीवादी वर्ग तथा सुधारवादी पूँजीवादी नेतृत्व फूले न समाता। पर राष्ट्रीय और घंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में काफी परिवर्तन हो चुका था। भारत के निगाह में यह एक दिवालिये बैंक का चेक था, जिसे भुनाने के पहले ही बैंक के खत्म हो जाने की श्रिधिक सम्भावना थी; श्रतः क्रिप्स को भारत के सभी प्रमुख दलों से दो-दूक जवाब मिला श्रीर वेचारे को अपना मुँह लेकर वापस जाना पड़ा।

भारत त्राने पर सर स्टैफर्ड क्रिप्स बहुत से प्रमुख दलों तथा व्यक्तियों से मिले, पर उन्होंने भारतीय व्यापारी मण्डल से मिलने से इन्कार कर दिया था, हालाँकि भारत-स्थिति ब्रिटिश व्यापारी मण्डल से उन्होंने मिलना स्वीकार कर लिया था और वे मिले भी थे। भारतीय पूँजीपतियों की खोर से इसका घोर विरोध किया गया था। एक प्रमुख पूँजीपति, बाल चन्द्र का खप्रैल मास में इसके विरुद्ध में एक वक्तव्य

आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि "सर स्टैफर्ड किप्स ने भारतीय व्यापारी वर्ग से मिलने से इन्कार करके ब्रिटिश व्यापारी वर्ग को जो मिलने का मौका दिया है, उसका सुक्ते कुछ भो दुःख नहीं है, क्योंकि हम अपने को राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रमुख अंग सममते हैं—जिस प्रकार राजनीतिक नेतागण भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता के विना आर्थिक स्वतंत्रता असम्भव सममते हैं।"

जापान और कांग्रेस का "भारत छोड़ो" प्रस्ताव

हम उपर उल्लेख कर चुके हैं कि युद्ध की अवस्था ने बिटिश साम्राज्यवादी सरकार के प्रभाव और शक्ति में भारतीय पूँजीवादी वर्ग का विश्वास खत्म कर दिया था। अब उसके (भारतीय पूँजीवादी वर्ग के) सामने बिटिश सरकार से सम-मौता करने का या किसी प्रकार का सौदा करने का प्रश्न न था, बल्कि उसका वर्गीय स्वार्थ जापानियों के साथ जुट रहा था। उसे यह चिन्ता थी कि किसी प्रकार वह अपने भावी स्वामी के साथ अच्छे भावों में सौदा पटावे। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी की हलाहाबाद बैठक में गांधीजी द्वारा तैयार प्रस्ताव कुछ संशोधन के साथ बहुमत से स्वीकृत हुआ था। परन्तु पं० जवाहरताल नेहरूजी के विरोध के कारण वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पेश नहीं किया गया था। इस प्रस्ताव में यह कहा गया था कि "आजाद भारत का पहला काम जापान के साथ संधि करना होगा।" जापान के साथ भी अच्छे भावों में सौदा पटाने के लिये

जनता को अपने साथ रखना आवश्यक था. किन्तु जनता के बिटिश विरोधी भाव चएए चएए उम्र होते जा रहे थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के सुधारवादी पूँजीवादी नेतृत्व के चुपचाप वेठे रहने की नीति से निराश होकर भारतीय शोषित जनता नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की और भुकती जा रही थी श्रीर विटिश सरकार के विरुद्ध वगावत करने के लिये व्याकुल हो रही थी। श्रात: जनता को श्रपने साथ रखने के हेतु सुधारवादी पूँजीवादी नेतृत्व ने भारत छोड़ों का प्रस्ताव पाम किया।

"क्रिप्स प्रस्ताव"

त्रिटिश साम्राज्यवादः हुकूमत का पिछला इतिहास यह सिद्ध करता है सुधार सदैव शोषित-पीड़ित जनता की क्रान्ति-कारी शक्तियों द्वारा जबर्दस्ती ब्रिटिश सरकार के हाथों से ऐंठा गया है। सुधार देते समय ब्रिटिश सरकार सदैव इस बात का ध्यान रखता था कि सुधार किसी प्रकार भी आम पीड़ित जनता की कांतिकारी शंक्तियों की वृद्धि में सहायक न हो, बल्कि भरसक उसका प्रयोग साम्राज्यवाद-विरोधी शक्तियों को त्तीरा करने के लिये हो। सन् १६४२ ई० में आन्तरिक और वाह्य परिस्थितियों से भारतीय विधान में सुधार करने के लिये विवश होने पर भी बिटिश सरकार ने अपनी ऐतिहासिक परम्परा को कायम रखा ऋौर जहाँ तक सम्भाव हो सका था उसने सुधार के सुवर्ण-घर में फूट का विष-वीज रखने की कोशिश की। सन् १६४२ ई० में सर स्टैफर्ड किप्स जिस प्रस्ताव को लेकर भारतवर्ष आय थे, जिसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं, वह ब्रिटिश-युद्ध परिपद के द्वारा स्वीकृत हुआ था।

१३६ हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेषण

हम ऊपर किप्स प्रस्ताव देख चुके हैं। यही कहा जा चुक है कि ब्रिटिश युद्ध परिपद ने इसे पूर्ण रू। से स्वीकार किय था । युद्ध परिषद द्वारा स्वोकृत प्रस्ताव के अनुसार भारतवः को कई ऋंशों में बाँटने की कायोजना थी। यह पूर्णतः दो राष्ट्र सिद्धान्त का समर्थन था जिसका स्पष्ट उद्देश्य था—साम्प्र दायिक आधार पर भारत का विभाजन। ब्रिटेन के स्वतनः मजदूर दल के प्रधान मन्त्री फेनर बाकवे ने युद्ध परिषद द्वार प्रेपित क्रिप्स प्रस्ताव पर ऋपना विचार प्रकट करते हुए लिख था कि "प्रस्ताव से यह भय है कि वह भेद को और बढ़ावेग श्रीर लगातार उसको ज्यापक बनाता जायगा। भारत के विशाह शरीर पर अनेक अलस्टर का फैला रहना अत्यन्त भणवा है। सामाजिक उन्नति में इसका वाधक होना अवश्यम्भावी है श्रीर सामाजिक उन्नति बुरी तरह पीछे हट जायगी ु।" मिः ब्राकवे का कहना सर्वथा सत्य था, भारत विभाजन का अध क्रान्तिकारी शक्तियों का छिन्न-भिन्न होना था। शोषित-पीड़ित जनता के संगठन को-जनकान्ति के आधार को-ही नष्ट कर देना था। इसका स्पष्ट ऋर्थ था श्रमिक शोपित जनता की शोपण श्रीर गुलामी से मुक्ति की लड़ाई की प्रगति को निश्चित काल के लिये अवरुद्ध कर देना था। इसके परिणामस्वरूप भागतीय समाज के विकास तथा प्रगति का काफी समय के लिये शिथिल होना निश्चय था।

एक स्वर से सारे भारत में सभी प्रमुख राजनैतिक दलों तथा व्यक्तियों के द्वारा इस प्रस्ताव का विरोध किया गया था। सर स्टेफर्ड किप्स विफल हो इंगलैएड वापस चले गये थे। किप्स प्रस्ताव में दो राष्ट्र सिद्धान्त का समर्थन किया गया था

न्त्रीर साम्प्रदायिक श्राधार पर भारत विभाजन का भी श्रायो-जन था। इसके विपरीत, क्रिप्स के वापस होते ही कांग्रेस ने मई के महीने में श्री जगत नारायण लाल का अखरड भारत का प्रस्ताव पास किया था, जिसका उल्लेख हम उपर कर चुके हैं। इसके पहले सन् १६४० ई० में अपने लाहौर अधिवेशन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताय पास किया। इसका विरोध कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्त मौलाना आजाद ने रामगढ़ कांग्रेस में बोलते हुए विरोध किया था श्रीर कहा था कि 'यह भारत का प्रारच्घ था कि बहुत सी मानव जातियाँ, संस्कृति तथा धर्मा इसकी और प्रवाहित हुए श्रीर इसकी त्र्यतिथि-सेवी भूमि में बहुत से काफिलों ने चिरकाल के लिये अपना स्थान बना लिया। इन अनेक काफिलों में से अन्तिम काण्ठिला जिसने अपने पूर्वगामी काफिलों के पद-चिन्हों का अनुसरण किया, इस्लाम धर्म के अनुयायियों का था। इस काफिले के आगमन से दो भिन्न जातियों की विभिन्न सांस्कृतिक धारा का संयोग स्थापित हुन्त्रा। ... श्रीर यमुना की भाँति कुछ काल तक अलग-अलग दो धारायें बहती रहीं, किन्तु प्रकृति के परिवर्तनशील नियमों ने उनका सानिध्य तथा तत्पञ्चात् संगम स्थापितं कर ही दिया। हमारे जीवन के हजारों वर्षों ने हमें एक राष्ट्रीयता में डाल दिया, यह कृत्रिम ढंग से नहीं िया जा सकता था, प्रकृति की रचना की प्रच्छन्न प्रक्रिया सदियों के विस्तृत काल में सम्पन्न होती है, लेकिन अब हम साँचे में ढाल दिये गये हैं और प्रारच्य ने अपनी मुहर भी इस पर लगा दी है। अनिच्छा या इच्डापूर्वक हम एक अखंड एवं अविमाज्य भारतीय राष्ट्र के १३८ हिन्दुस्तान श्रौर पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेषण

रूप में बदल गये हैं। कोई भी काल्पनिक एवं कृतिम उपाय अब इस एकता को भंग नहीं कर सकता है।"

इसके ऋलावा, ऋन्य प्रभावशाली मुस्लिम संस्थाओं ने लीग द्वारा उपस्थित की गई पाकिस्तान की माँग का विरोध किया था। हमने इसी पुस्तक में अन्यत्र यथास्थान सन् १६४० ई० की श्राखिल भारतीय स्वतंत्र मुस्लिम लीग श्रधिवेशन के सभापति स्वर्गीय श्रलाः क्श तथा जमायतुल-उलेमा हिन्द के पाकिस्तान विरोधी प्रस्तावों तथा ज्याख्यानों को उद्घृत किया है। उनकी पुनरावृति की आवश्यकता नहीं है। इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि भारत के विभाजन के विरोध में केवल कांग्रेस तथा कांत्रेसजन ही नहीं थी, इनके अलाश मुसलमान भी इसके कट्टर विरोधी थे। गांधीजी ने तो यहाँ तक अपनी विरोध की भावना प्रकट की थी कि भारत विभाजन के पूर्व वे अपने शरीर के विभाजन तक के लिये प्रस्तुत थे। साम्प्रदायिक मनो-मालिन्य को वे कृत्रिम तथा तीसरे दल के कुकुत्यों की उपज मानते थे। सन् १६४२ ई० में उन्होंने (गांधोजी ने) पत्र प्रतिनिधियों द्वारा प्रश्न किये जाने पर स्पष्ट शब्दों में कहा था कि "निटिश सरशार के रहते हुए साम्प्रदायिक एकता असम्भव है श्रीर श्रान्दोलन शुरू करने के लिये कांग्रेस श्रीर मुस्लिम लीग सममीते की कोई आवश्यकता नहीं है। यह केवल त्रिटिश साम्राज्यवाद ी समाप्ति पर ही सम्भव है।"

राजनीतिक सुधार और साम्प्रदायिकता

भारतीय स्वतन्त्रता की लड़ाई का इतिहास यह बतलाता है कि आजादी की लड़ाई में भारतीय शोषित-पीड़ित जनता ने हमेशा एकता का परिचय दिया था। आजादी के जन-आन्दी-

लन के प्रारम्भ हो जाने पर साम्प्रदायिक विषमता और धार्मिक भिन्नता कभी भी बाधक नहीं बना था। खतंत्रता के संग्राम की तीत्र लहरों ने सदैव इन कृत्रिम भेद-भावों को दूर वहाकर भारतीय शोपित-पीड़ित जनता को एक धारा में मुक्ति की चौर प्रवाहित किया था। यह ऐतिहासिक वास्तविकता राष्ट्रीय कांग्रेस के सुधारवादी नेतृत्व से छिपी हुई नहीं थी, वल्कि कई वार नग्न रूप में उनके आँखों के सामने आई भी थी। इससे यह श्रीर प्रमाणित होता है कि सन् १६४२ ई० की श्रगस्त क्रान्ति के पूर्व गांधीजी ने स्पष्ट कहा था कि 'स्वतंत्रता संप्राम के पूर्व हिन्दू-मुसलमानों के सममौते की आवश्यकता नहीं है। साधारण हिन्दू-मुस्लिम जनता समान रूप से शोषण-दोहन की भुक्तभोगी है। अतः जब कभी अवसर आता है, तो वह कन्धे से कन्धा मिलाकर अपनी ऐतिहासिक लड़ाई में संलग्न हो जाती है, और जाये-फिरकायरस्ती पिलाकर जो नशा पहले चढ़ाई गई है, वह काफूर हो जाती है।

जब तक स्वतंत्रता संयाम में आम जनता व्यस्त रहती है, तब तक उसके सामाजिक जीवन में साम्प्रदायिकता की विषमता दूर रहती है। परन्तु जब स्वतंत्रता संप्राम शिथिल पड़ने लगता है और इसका नेतृत्व त्रिधान की खोर भुकने लगता है, जनता की कान्तिकारी राक्तियाँ तथा संगठन क्रमशः चीख होने लगता है और धीरे-धीरे सुधारवादी तथा क्रान्ति-विरोधा शक्तियाँ प्रवल हो उठती हैं, राजनीतिक रंग-मंच पर क्रान्ति-विरोधी तथा प्रतिक्रियाबादी शक्तियाँ साम्प्रदायिकता तथा धर्मे का कृत्रिम बाना धारण करके प्रगट होती हैं। भोली-भाली जनता धर्म तथा सम्प्रदाय के नाम प्रतिक्रियावादियों के हाथ की कठपुतली

१४० हिन्दुस्तान श्रीर पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेपण

वन श्रापना गला कटवाकर उनके स्वार्थ की सिद्धि में सहायक होतो है। राष्ट्रीय सुधारवादी नेतृत्व स्वयं स्वतंत्रता के त्रान्दो-लन को वास्तविक क्रान्तिकारी जन-त्रान्दोलन में परिवर्तित न होने देने के हेतु रोक देता रहा और तथाकथित रचना-स्मक कार्य-क्रम के द्वारा स्वतंत्रता की लड़ाई से जनता की उत्पन्न और विकसित क्रान्तिकारी एकता का गला घोटकर साम्प्रदायिक वैषम्य पदा करके फिर राजनीतिक संप्राम की सफलता के लिये साम्प्रदायिक एकता का नारा बुलन्द करता रहा। जब कभी त्रान्दोलन छेड़ने की त्रावश्यकता वे त्रानुभव करते, उस समय इस नारे का उनके लिये महत्व नहीं रहता था। वैधानिक सुधार क्ष्पी रोटी के टुकड़े को वाँटने के समय वे साम्प्रदायिक एकता का नारा बुलन्द करते थे त्रीर साम्प्र-दायिकता की विषमता प्रवल शक्ति के साथ सामाजिक जीवन पर त्राक्रमण करती थीं।

अगस्त-क्रान्ति की असफलता का कारण

सन् १६४२ ई० की अगस्त कान्ति का इतिहास यह बतलाता है कि इसके प्रारम्भ में तथा बीच में साम्प्रदायिक एकता कायम करने के लिये कृत्रिम प्रयत्नों की आवश्यकता नहीं पड़ी, भारतीय शोषित-पीड़ित जनता स्वतः भेदभाव भूलकर शत्रु का संगठित मुकाबला कर रही थी। क्रान्ति-पथ पर उतनी तीत्र गति से बढ़ने पर भी बागी जनता पर्याप्त कान्तिकारी नेतृत्व के अभाव के कारण अपने लव्य तक न पहुँच सकी। संसार के क्रान्तिकारी आन्दोलमों के इतिहास में अपने अद्वितीय साहस तथा क्रान्तिकारी शक्ति का परिचय

श्रास्त क्रान्ति से विकिति क्रान्तिकारी जन-शक्ति श्रीर राष्ट्रीय सुवारवादी नेतृत्व

श्रव इस बात को सममते की चेष्टा हमें करनी है कि किस प्रकार भारतीय पूँजीवादी वर्ग तथा उसका स्वार्थ सायक राष्ट्रीय सुधारवादी नेतृत्व हवा के रुख के साथ अपनी पीठ फेरकर बाजा बजा रहा था। साम्राज्यवादी युद्ध के

प्रारम्भ काल से सन् १६४१ ई० तक जत्र भारतीय पूँजीपतियों की पाँचों ऋँगुलियाँ घी में थीं उस समय जनता की भुलावे में डालकर जन-आन्दोलन रोकने के लिये क्या-क्या स्वाँग रचा गया, यह हस देख चुके हैं। सन् १६४१ ई० के अन्त से साम्राज्यवादी युद्ध की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होते ही इनकी नीति में भी मौलिक परिवर्तन हव्टिगोचर होने लगा। युद्र-चेत्र में बिटिश साम्राज्यवाद के पैग उखड़ने लगे श्रीर उधर भारतीय पूँतीवाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद-विरोधी मोर्चा खड़ा करने लगा, जिसका सौलिक आधार न भा सन् १६४२ ई० का "भारत छोड़ो" का ऐतिह सिक प्रस्ताव। लेकिन समय ने फिर पलटा खाया घौर साथ ही साथ भारतीय पूँजीपितयों की ब्रिटिश साम्राज्यवाद विरोधी नीति में उथल-पुथल हुई। सन्१६४३-४४ ई० में यह निश्चित रूप से ज्ञात होने लगा कि विजय भित्रराष्ट्रों के पत्त में होगी। भारत पर जापान के भावी हमले का भय भी दूर हो गया था और उसकी सफलता पर अविश्वास पैदा हो गया था। अन्तरिक परिस्थितियों में काफी परिवर्तन त्र्या चुका थः; सन् १६४२ ई० की क्रान्ति की भाषण छान्नि भी प्रत्यच रूप में शान्ति में वदली हुई विदित होती थी, भारतीय पूँजीपतियों के स्वार्थ स्टर्लिंग क बकाया के रूप में इङ्गलैएड से नथ चुका था, इसकी अब किसी अन्य साम्राज्यवादी शक्ति से सममीता करके लाभ उठावे की आशा खत्म हो चुकी थी। उनके सामने दो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जिन्हें हल करने के लिये भारतीय पूँजीपित व्याकुल हो रहा था। (१) प्रश्न यह था कि वे किस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्यवादी-पृँजीवादियों के रहते हुए अपनी उन्नति श्रीर विकास कर

सकते थे और (२) प्रश्न यह था कि किस प्रकार सन् १६४२ ई० की क्रान्ति से विकसित क्रान्तिकारी संयुक्त जन मोर्चे को भंग कर सकते थे। भारतीय पूँजीवादी वर्ग यह सममता था कि जन-त्राग्दोलन केवल ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार के ऋस्तित्व को ही ध्वस नहीं करेगा, बल्कि उसके (भारतीय पूँजीवादी वर्ग के) लिये भी घातक होता। गांधी-जी के "सत्य" और "अहिंसा" के मन्त्रों में उसे विश्वास न रहा। वह भलो-भाँति सममने लगा था कि जनता के कान्तिकारी को को उतारने के लिये मनत्र पर्याप्त नहीं रहा। क्रान्तिकारी जन-आन्दोलन को शक्ति को अनुभव कर लेने के पश्चात् जनता फिर सुधारवादी क्रान्ति विरोधी संकुचित परिधि के अन्दर सीमित नहीं रह सकती थी। भारतीय पूँजीवाद तथा पूँजीवादी वर्ग के विकास और प्रगति के लिये यह आवश्यक हो गया था कि किसी भी प्रकार ब्रिटिश सरकार के साथ गठबन्धन करके क्रान्तिकारी जन-शक्तियों को कुचले। ब्रिटिश सरकार के साथ सममौता करने के लिये भारतीय पूँजीवादी सुधारवादी नेत्रत्व ने सुधारवादी राष्ट्रीय श्चान्दोलन की नीति का पूर्ण परित्याग श्रीर सुधारवादी वैधानिक नीति का अवलम्बन श्रनिवार्य सममा । सन १६४२ ई० की श्रगस्त क्रान्ति के श्रवसर पर ब्रिटिश सरकार ने भी भारतीय श्राम जनता के ऊपर कांग्रेस का प्रभाव श्रीर शोषित जनता की क्रान्तिकारी प्रवृत्ति का अनुभव भली भाँति किया था। ऋत: भारतीय शोषित-पोड़ित जनता की क्रान्तिकारी श कियों को नष्ट करने के लिये तथा साम्राज्यवादी शोषण को कायम रखने के लिये ब्रिटिश साम्राज्यवादी पूँजीवादी

वग भारतीय पूँजीवादी वर्ग का सहयोग आवश्यक समफने लगा था और गठवन्धन करने के लिये प्रयत्नशील हो उठा। प्रत्येक जन-त्रान्दोलन से विकसित क्रान्तिकारी जन-शक्तियाँ के दबाब से बाध्य होकर ब्रिटिश सरकार भारतीय विधान में सुधार करने त्याई था। सन् १६४२ ई० की क्रान्तिकारी जन-आन्दोलन के उपरान्त भारतीय विधान मं मौजिक परिवर्तन करने के लिए वह वाष्य हो रही था। इस मौलिक वैधानिक सुधार की प्राप्ति के बाद किसी भी प्रकार का ब्रिटिश विरोधी आन्दो-लन का संचालन करना भारतीय पूँजीवाको सुधारवादी नेतृत्व नहीं चाहता था, इसे परित्याग करने के लिये व्यय हो उठा था। ब्रिटिश सरकार से प्राप्त राजनीतिक शक्ति को अपने विकास तथा प्रगति के लिये पूर्ण प्रयोग करना भारतीय पूँजीबादा वर्ग चाहता था । अब मारतीय शोषित जनता के जत-श्रान्दोत्तन का नेतृत्य करके राष्ट्रीय कांग्रेस का सुधारवादी पूँजीवादी नेतृत्व अग्नि के साथ खेल खेलना नहीं चाहता था। वह भारतीय जनता को क्रान्ति-विरोधी सुधारवादी पाठ पढ़ाकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में प्रयोग करता रहा था और जब तक जनता उसकी इच्छानुसार चलती रही थी, तब तक उसने उसका नेतृत्व किया था। पर जैसे ही इस मस्मासुर ने स्वयं वृषभनाथ के ऊपर ही हाथ रखकर उनके बरदान का उन्हीं पर प्रयोग करने की चेप्टा की, वे भाग खड़े हुए और उसके विनाश का उपाय हुँद्रने लगे।

भारतीय पूँजी वद तथा पूँजीवादी वर्ग के विकास तथा प्रमृति के लिये मौलिक वैधानिक सुवार प्राप्त करना अति

आवश्यक था - भारतीय भौतिक परिस्थिति की यह वास्तविकता थी जिसे ऋस्वीकार नहीं किया जा सकता था। यह तो राष्ट्रीय पुँजीवादी सुधारवादी नेतृत्व के द्वारा ही त्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार से प्राप्त होना था। लेकिन यह न जन-क्रान्ति के द्वारा शासन-सत्ता पर अधिकार करना चाहता था श्रीर न किसी प्रकार का जन-श्रान्दोलन का संचालन कर ही मोलिक वैधानिक सुधार की प्राप्ति ही करना चाहता था. वल्कि बिटिश सरकार के साथ सममौता करके राजनीतिक सधार प्राप्त करना चाहता था। यहाँ हम यह न भूलें कि ब्रिटिश सरकार ने बराबर इस बात की घोपणा की है कि यह "हिन्दू-मसजमानों की सम्मिलित माँग पर भारत की राजनीतिक श्रिविकार देने को तैयार है।" अनः जिस समय सन् १६४४ ई० में महात्मा गांधी श्रीर मि० जिन्ना साहव समसौते की बानें कर रहे थे, भारतीय पुँजीपित धड़कते हुए हृद्य से इसक फल की यतीचा कर रहे थे और सफलता के लिये अपने इष्टदेवों से रात-दिन प्रार्थना कर रहे थे।

गांथी-जिन्ना मिलन की त्रोर त्राशा भरी निगाह से भारतीय पूँजोपित देख रहे थे। इस मिलन में उनकी कितनी बड़ो जाशा केन्द्रित थी, यह इण्डियन-चेन्यस आफ कामर्स के सभापित के भाषण से स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। गांधी-जिन्ना मिलन के सम्बन्ध में 'चेम्बर' के सामने वोलते हुए उन्होंने कहा था, "इस समय जिनके हृदय में भारत का हित भरा हुआ है, वे गांधी-जिन्ना मिलन की सफलता की कामना कर रहे हैं, और यह इच्छा करते हैं कि वे एक ऐसे निर्णय पर पहुँचें, जा सभी लोगों के हित के लिये साफ और चिरस्थायी हो। हमें यह आशा

१४६ हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेषण

करनी चाहिये कि यह मिलन सरकार के साथ शीन ही एक सममीता करने में भी सकत होगा।" भारतीय पूँजीवादी वर्ग अपनी उन्नित और भिकास के जिये राष्ट्रीय सरकार के स्थापना को आवश्यक सममना था। वह यह भी सममना था कि हिन्दू-मुक्तिम मेत्र के आधार पर त्रिटिश छत्रछाया में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना सम्भव हो सकता था। राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिये वह कितना आतुर हो रहा था, यह भा सभापित के आगे के भागण से स्पष्ट हो जाता है। वे कहते हैं—"भारत के आर्थिक हित के लिये शीन्न राष्ट्रीय सरकार की स्थापना नितान्त आवश्यक है, इसी लिये वम्बई-योजना के निर्माणकर्त्ताओं ने इस पर इतना अधिक जोर दिया है।

"जनता की उन्नति के जिये निर्मित कोई भी योजना जनता का लगन के साथ महयोग नहीं प्राप्त कर सकती जब तक उसके पीछे वा तिक राष्ट्रीय सरकार न हो। अतः अविकारियों की यह भूल है कि वे बत्तमान राजनैतिक अवस्था को ज्यों का तो बनाये रखकर आर्थिक अवस्था का सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

"यह कहा जाता है कि द्यार्थिक उनित स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये मार्ग तैयार करेगी, पर क्या किसी ने कभी राजनैतिक पराधीनता के द्यन्तर्गत वांछित द्यार्थिक उन्नति की प्राप्ति के विषय में मुना है ? भारतवर्ष में हम लोगों को इसका कटु- घ्रानुभव प्राप्त है। हम यह जानते हैं कि भारत की ब्रिटिश की पराधीनता हमारे व्यापार, उद्योग-धन्यों और हमारी आर्थिक उन्नति के लिये क्या द्यर्थ रखती है।

"भारत के श्रौद्योगीकरण में इम सुन्यवस्थित, बहु सावत-

युक्त सम्पन्न बिदेशी कारपोरेशनों की प्रतियोगिता से बच नहीं सकते। यदि हमको वास्तव में इन विदेशी 'कारपोरेशनों' के सामने प्रतियोगिता में टिकना है तो हमारे उद्योग-धन्धों के पीछे एक ऐसी शक्ति का होना अनिवाय है, जो हमें अपने पेरों पर खड़े होने के योग्य बना सके। प्रथम उनको अपनी ही मरकार का सामना करना है, जो उनके प्रति केवल उदासीन ही नरीं बल्कि विरोधी भाव रखे हुये हैं, श्रीर दूसरे उन्हें सुव्यवश्थित विदेशी कारपोरेशनों के सम्मुख वैजोड़ प्रतियोगिता में अड़ता होगा।" यह केवल चेम्बर आफ कामर्स के सभापति का व्यक्तिगत विचार नहीं था, बल्कि भारतीय पूँजीबांदी वर्ग का भी यह हृदयोर्गार था। राष्ट्रीय सरकार के लिये इतनी उत्सुकता के कारण ही कांग्रेस, जिसने सन् १६४२ ई० के मई महाने में भारतवर्ष के विभाजन के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया था, साम्प्रदायिकता के ऋाधार पर भारत-विभाजन को एक प्रकार मुस्लिम लीग के साथ स्वीकार करने के लिये जतसुक हो उठी थी।

उपरोक्त राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की उपज सीव आर० फार्मू ला थी। इसे केवल गांधीजी का आशीबाद ही नहीं प्राप्त था, बिल्क हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक एकता के नाम पर हिन्दू-मुस्लिम पूँजापितयों की एकता स्थापित करने के लिये कांग्रेस तथा लीग के बीच सममीता का आधार इन्होंने (गांधी जी ने) मान लिया था और इसके आधार पर उन्होंने मुस्लिम लीग के अध्यत्त भि० जिला से मिले और सममीते की बात-चीत की, लेकिन वे असफल रहे। हालाँकि गांधीजी अभी तक भारत को एक अविभाज्य राष्ट्र तथा मुसलमानों को उसका अविभाज्य अंग स्वीकार करते रहे थे, किन्तु सी० आर० फार्म्ला को स्वीकारकर इसके आधार पर लीग के साथ समसौते के लिये वात-चीतकर दो राष्ट्र के सिद्धान्त का उन्होंने समर्थन िया। सी० आर० फार्मूला को मानकर हिन्दू-मुस्लिम एकता क नाम पर भारत का विभाजन मानकर पूँजीपतियों के वीच एकता स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे थे। इधर हिन्दू-मुस्लिम एकता कायम करने के लिये गांथी-जिन्ना मिलन हो रहा था, उधर ईद के श्रवसर पर मि० जिन्ना साहब ने भारतीय मुसलमानों को जो यधाई दी, उसमें वे अपने मनोभावों को न छिपा सके, श्रीर यह उनके वक्तव्य से स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान का श्रर्थ "पान इस्लाम" के ऋतिरिक्त और कुछ नहीं था। हालाँ कि गांधी जी के पूछने पर जिन्ना साहब ने पाकिस्तान का स्पष्ट अर्थ नहीं वताया था। जिन्ना साहव ने ईद के अवसर पर मुसलमानों को बधाई देते हुए कहा था कि "इस प्रकार के आनन्द तथा शुभ श्रवसर पर मैं भारत के प्रत्येक मुसलमान को बधाई देता हूँ अगर उनके लिये शान्ति प्रसन्नता श्रीर समृद्धि की कामना करता हूँ। रमजान का पवित्र महीना अभी-अभी समाप्त हुआ है, श्रीर रोजा की कठिन परीचा में श्राप लोग सफल हए हैं, श्राप लोगों ने इसे पूरा करने में उदाहरं शीय धैर्य और विश्वास का पिचय दिया है। चिर-प्रतिचित ईद के प्रात:काल ने आज प्रत्येक मुसलमान के घर में प्रसन्नता की उवल्यमान किर्गों विखेर दी हैं। आइये ! आज हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि यह किरणें हमको शान्ति और समृद्धि प्रदान करें। पिछले ईद के बाद से एक राष्ट्र की हैसियत से हमारी प्रगति स्थिर और ठोस रही है, हम चंए प्रतिच्ए प्रवलतर होते गये हैं। आज

सुमें यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि भारत के मुसलमानों को में संगठित तथा राष्ट्र के हित के लिये वड़े से बड़े बिलदान के लिये प्रस्तुत पा रहा हूँ। हमने वास्तिविक राष्ट्र की रचना एवं उन्नति का कार्य प्रारम्भ कर दिया है, जिसमें हमारे वास ग्थान का जो पाकिस्तान की रचना करते हैं, सामाजिक, श्रार्थिक शिहा सम्बन्धों तथा श्रीद्योगिक पुनर्निर्माण सम्मिलित है। हमें मुसलमानों के साथ विश्वासचात करने वाले पतितों का भी सामना करना है, जो हमारे वास स्थानों में ही हमारी उन्निर्माण मामना करना है, जो हमारे वास स्थानों में ही हमारी उन्निर्माण प्रमन्तित हुई है कि मुसलमान श्रपने उत्तरदायित्व को समसने लग गये हैं श्रीर मुल्तान के चुनाव में श्रपना मत प्रदान करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे सरलता के साथ छने नहीं जा सकते। श्राज हम एक तथा ठोप राष्ट्र के रूप में खड़े हैं।

"श्राप जानते होंगे कि दुनिया विशेषतः इस्लामी दुनिया छोर भारतीय मुस्लिम राष्ट्र विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। हमारी परीचा का कठिन अवसर है। लेकिन उसी धैर्य श्रीर उत्साह के साथ, जिसका परिचय आपने रमजान के महीने में दिये हैं, हमें आज इस शुम मुहूर्त्त में एक बार पुनः यह प्रतिज्ञा करना चाहिये कि जब तक हम इस स्वतंत्रता को नहीं पाप कर लेते तथा अपने अन्तिम लच्य पाकिस्नान तक सफलतापूर्व क नहीं पहुँच जाते हैं 'तब तक हम हर तरह का कप्र और विविदान करने के लिये सदैव प्रसुत हैं।"

एक ओर गांधी-जिन्ना मिलन हो रहा था और आम लोगों में यह ख्याल हो रहा था कि कांकेस और लीग के बीच कोई समम्मीता हो जायेगा, दूसरी ओर जिन्ना साहब उक्त उद्धृत जैसा वक्त- व्य दे रहे थे, जिसमें भारतीय एकता और आजादी का जिक्र न था। ऋपने वक्तव्य में उन्होंने केवल मुस्लिम दुनिया तथा पाकिस्तान का राग श्रलापा था। उनका वक्तव्य पान-इस्ला-मिज्म की भावना से स्रोत-प्रोत था। इस वक्तव्य में जिल्ला साहब ने राष्ट्र निर्माण के सम्बन्ध में मुसलमानों के उद्योग-धन्यों का विशेष रूप से उल्लेख किया था, जिससे स्पष्ट हो जाना है कि पाकिस्तान की माँग के पीछे मुस्लिम पूँजीपतियों का विशेष स्वार्थ रहा । साम्प्रदायिक आधार पर भारत-विभाजन की इस माँग को शोपित-पीड़ित मुस्लिम जनता की माँग कहना केवल सत्य के साथ आँख-मिचौनी करना था। भारत-विभाजन की यह माँग भारतीय श्रमिक शोपित-पीड़ित जनता के सामाजिक अंर श्रार्थिक जीवन के विकास तथा प्रगति के लिये कितनीं घातक होगी, इस पर पीछे काफी प्रकाश डाला जा चुका है। गांधी-जिन्ना मिजन की असफलता के बाद श्रीखिल भारताय जमयेतुलडलमाया हिन्द के सभापति मौलाना सटाद हुसेन अहमद मदनी ने कहा था कि "पाकिस्तान योजना केवल हानिकारक ही नहीं है, बल्कि असाध्य भी 音!"

भारतीय पूँजीपनियों को आपसी मेल की आवश्यकता

उपरोक्त वातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत की शोधित-पीड़ित जनता साम्प्रदायिक आधार पर भारत-विभाजन की समर्थक नहीं थी। पाकिस्तान की माँग के विकास के इतिहास से यह स्पष्ट होता है कि यह भारतीय शोधित-पीड़ित जनता की आजादी के आन्दोलन की उपज नहीं थी, बल्कि भारतीय पूँजीवादी वर्ग के आन्तरिक संघर्ष की उपज थी, जिसे न हम भारतीय आम जनता की माँग कह सकते हैं और न मुस्लिम शोषित-पीड़ित जनता की ही । यह स्पष्ट शब्दों नथा भावों में मुस्तिम पूँजीपतियों की माँग थी, जो अन्य भारतीय पूँजी-षतियों के साथ पूँजीवादो हाड़ में अपने को कमजार पाने के कारण एक व्यलगं स्वतंत्र द्वेत्र श्रमिक जनता का शोपण करने के लिये चाहते थे श्रौर पाकिस्तान के नाम से ये स्वार्थी धन-लोलुप पूँजीपति एक अलग कीड़ा-चेत्र की स्थापना करना चाहते थे। राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिवर्तित परिस्थितियों से विवश होकर उनके प्रतिद्वन्दी दूसरे पूँजीपति सामप्रदायिक श्राधार पर भारत के विभाजन के लिये तैयार हो गये थे। अपने विकास तथा प्रगति के लिये भारतीय पूँजीवादी वर्ग ब्रिटिश सरकार से मौलिक वैधानिक सुधार प्राप्त करना आव-श्यक सममता था चौर इनके लिये चापसी सममौता भी जरूरी था। इसलिये अन्य पूँजीपति दूसरे अतिद्वन्दी मुस्लिम पूँजीपतियों के साथ मेल कोयम करने के लिये आतुर हो उठे थे।

सा० आर० फार्मू ला अल्पसंख्यक सम्मदाय की समस्या का हल नहीं

भारतीय पूँजीपित आपसी गँठवन्धन केवल वैधानिक सुविधाओं के लिये ही नहीं कर रहे थे, प्रत्युत भावी जन-क्रान्ति से अपने अस्तित्व की रहा करने के लिये भी सन् १६४२ ई० की अगस्त-क्रान्ति की शक्ति को अनुभवकर ब्रिटिश सरकार तथा भारतीय पूँजीवादी वर्ग समान रूप से भयभीत हो गये थे। राष्ट्रीय सुधारवादी पूँजीवादी नेतृत्व ब्रिटिश विरोधी जन-

श्रान्दोलन का नेतृत्वकर शोषित जनता की क्रान्ति-उन्मुख शक्ति के जिस्कोट का अवसर नहीं देना चाहता था। उसकी एक मात्र चेष्टा किसी प्रकर भयोत्पादक अवस्था का करने की था। उसका यह स्वप्त तब तक सफल नहीं हो सकता था जब तक भारताय पूँजीपित आपसी मेल न कायम कर लेते। इन सब प्रश्नों को हल करने के लिये उनकी आपसी एकता आवश्यक हो रही थी। इसकी पूर्ति के लिये हिन्दू-मुस्तिम एकता का चोंगा पहनाकर सी० श्रार० फार्मूला उपस्थित किया गया था। हिन्दू-पुस्तिम एकता की स्रोट में वे अपनी दुष्कामनात्रों को पूरा करना चाहते थे। इस फार्मृला का एक मात्र ध्येय किसी प्रकार पूँजीपतियों में आपसी एकता स्थापति करना था। यह किसी प्रकार साम्प्रदायिक समस्या का हल नहीं था । इससे साम्प्रदायिक मनोमालिन्य किसी भी प्रकार कम नहीं हो सकता था, क्योंकि यह वैषम्य के आधार-भूत प्रश्न को स्पर्श तक नहीं करता, हल हूँ हना तो दूर रहा, वास्तविक प्रश्न व्यल्पसंख्यक समुदाय के व्यधिकारों का प्रश्न था, जिसे इस प्रस्ताव ने सरल बनाने के स्थान पर श्रीर जटिल वनाया। यह धर्म के आधार पर भारत का विभाजन करके क्षत्रिम राष्ट्रों की रचना करना चाहता था, जिससे श्रमिक-शोपित जनता की क्रान्तिकारी संयुक्त शक्ति विभाजिन हो निर्वल हो जायगी और पूँजीवित अधिक काल तक निर्वाय शोगण हरने में सफल हो सकेगा; और भारती श्रमिक-शोपित जनता हे सामाजिक तथा त्रार्थिक जीवन का विकास और उन्नति अनिश्चित काल के लिये धर्म और सम्प्रदाय के अन्धकार कूप में पड़कर उन्नति के पथ को भूली रहेगी

देसाई-लियाकत पैक्ट

गांधी जिल्ला मिलन कई दिनों तक चलने के बाद श्रमफलता के साथ समाप्त हुआ। इससे साम्प्रदायिक समस्या सुलभने के बजाय और भी उलभ गई। भरतीय पूँजीबादी वर्ग
निराशा के सागर में गोता खाने लगा। परन्तु इसकी यह
श्रवस्था ज्यादा दिन तक नहीं रही; इसका चिणक जीवन रहा।
बह चुपचाप नहीं वैठा रह सकता था।शीब ही वह प्रयत्नशील
हो उठा। सन् १६३६ ई० के सितम्बर के प्रथम सप्ताह के
प्रारम्भ में साम्राज्यवादी युद्ध के आरम्भ होते ही भारत की
श्रोर से निटिश भारतीय सरकार ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध
की घोषणा की थी जिसके विरुद्ध में सेन्ट्रल एसेम्बली के
कांग्रे सी सदस्यों को अखिल भारतीय कांग्रे स कमेटी की त्रोर
से सेन्ट्रल एसेम्बली की बैठक में शामिल नहीं होने के लिये
कहा गया था। तब से और सन् १६४४ ई० के प्रारम्भ तक वे
शामिल नहीं हुए थे।सन् १६४४ ई० के प्रारम्भ में दिल्ली में
केन्द्रीय एसेम्बली की बैठक होने जा रही थी। गांधीजी की राय

से श्री भुलाभाई देमाई-जो सेन्ट्रल एसेम्बली कांग्रेस पार्टी के नेता थे-ने कांत्रेसी सदस्यों को आगामी बैठक में सन्मिलित होने की हिदायत दी। श्री मुलाभाई देशाई ख्रीर मि० लियाकत श्रली खाँ के नेतृत्व में कांग्रेस अार लीग पार्टी ने ब्रिटिश सर-कार का संयुक्त विरोध किया। एसेम्बली में संयुक्त मोर्चे के श्रविरिक्त कांत्रेस-लीग समभौते की वातें हुईं, जिसके परि-गामस्वरूप इनमें एक सममौता हुआ। यह सममौता छाम तीर पर देखाई-लियाकत पैक्ट के नाम से विकात हुआ। श्री देसाई ने एक मसिवदा तैयार किया, जिसे गांधीजी स्रोर जिन्ना साहव का आशीर्वाद प्राप्त था। कांग्रेस की श्रोर से श्री मुलाभाई देवाई और लीग की और से मियाँ लियाकत खाँ ने उस पर हस्ताचर किया था और श्री देसाई ने वायसराय को इसे दिया। यह प्रस्ताव इस प्रकार था कि केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार की म्थापना शीव्र किया जाय जिसमें मुस्लिम लीग तथा राष्ट्रीय कांमेस के वरावर-बरावर प्रतिनिधि होंगे और इसकी स्थापना के उपरान्त राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतागण जेलों से मुक्त किये जायँगे ।

इसे पाते ही यायसराय ने जन्दन को इसे रशना किया। इस पर विस्तृत रूप से बातें करने के लिये ब्रिटेन के युद्र-परिपद ने वायसराय को जन्दन बुलाया। वायसराय श्रीर युद्ध-गरिषद के सदस्यों के तथा ब्रिटिश मन्त्रिमंडल के सदस्यों के बोच काफी बातें हुई। करीब छः-सात सप्ताह वहाँ रहने के बाद वायसराय भारत वापस श्राये। यहाँ वह एक नये प्रस्ताव के साथ वापस श्राये थे। भारत में पदार्पण करने के साथ-साथ उन्होंने राष्ट्रोय कांग्रेस की कार्यकारणी कमेटी के सदस्यों — जो अहमदनगर फोर्ट में बन्द थे—को जेलों से छोड़ने की आजा .दी। तुरन्त कांप्रेस के नेतागण जेलों के बाहर आ गये।

श्चगस्त क्रान्ति श्रीर सप्ट्रीय सुधारवादी पूँजीवादी नेतृत्व

इसी पुस्तक में अन्य स्थान में यह हम उल्लेख कर चुके हैं कि किस प्रकार की राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थित में राष्ट्रीय कांग्रेस ने "भारत हो हो" का ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया था, उसे यहाँ किर उल्लेख करना व्यर्थ झात होता है। इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि सम्भवतः जन-आन्दोलन का नेतृत्व करने में कांग्रेस समर्थ न होगी, इसके लिये नेतृत्व प्रदान करना सम्भव नहीं होगा। ऐसी हालत में प्रत्येक मारतवासी का अपनी बुद्धि, विचार तथा अवस्था के अनुसार इसे (प्रस्ताव को) कार्यान्वत करना कर्त्त व्य होगा। परन्तु अपने कार्यों के लिये वह स्वतः जिम्मेदार होगा।

इस ऐतिहासिक प्रस्ताय के पास होते ही राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी नेतागण तथा सभी प्रान्तों के प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ता जेलों में ठूँस दिये गये। भारतीय शोपित-शिइत जनता अपनी आजादी की लड़ाई के संचालन करने के लिये स्वतंत्र हो गई। वह स्वतंत्र हो स्वतः अपने ढंग पर अगस्त कान्ति का संचालन करने लगी। जिसकी आंग्न की तेज को अनुभवकर केवल त्रिटिश सरकार ही भयभीत नहीं हुई थी, बल्कि भारतीय पूँजीवादी वर्ग भी दहल उठा था और जन-आन्दोलन में अपने कब का स्वप्त देखने लगा था। संसार की जानकारी के लिये भारतीय अगस्त कान्ति के सम्बन्ध में

१४६ हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेपण

त्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार ने "ह्वाइटपेपर" के नाम से एक घोषणा-पत्र प्रकाशित किया था, जो प्रन्य मुल्कों में बड़ी संख्या में बाँटा एया था। इसकी विशेषता यह थी कि भारतीय श्रास्त क्रान्ति की जिम्मेदारी कांग्रेस के माथे पोता गया था।

पूँजीवादी संसार में कांग्रेस के नेताओं के जेजों में रखे जाने के खिलाफ आवाज उठने लगी थी। इधर भ रतीय पूँजावादी वर्ग तथा इसके अखबार राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ सममीता करने के हेतु आवाज उठाने लगे। इन सब के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि सन् १६४२ ई० को ६ अगस्त से जा कुछ हुआ और हो रहा है, सवों की जिम्मेदारी कांग्रेस नेताओं की है। सर्वप्रथम कांग्रेस नेताओं को अगस्त आन्दोलन की जिम्मेदारी को अश्वतिहासिक रण्ट्रीय प्रस्ताव को वापस लेना होगा। इसके वाद ही सरकार उनकी रिहाई के अगर गौर करेगी।

गिरफ्तार करके गांधीजी आगा खाँ पैलेस में रखे गये थे। गिरफ्तारी के बाद आगा खाँ पैलेस से उन्होंने ने अंबेजी सरकार को कई पत्र लिखा था। उनमें से एक पत्र में पण्ट शब्दों में उन्होंने लिखा था कि अगस्त क्रान्ति की जिम्मेदारी कांबेस के अगर नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि यह देश के लिये लाभदायक नहीं हुआ बल्कि घातक हुआ।

वम्बई में राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारणी कमेटी के सदस्य गिरफ्तार करके सब के सब अहमदनगर फोर्ट में रखें गये थे। केवल वावृ राजेन्द्र प्रसाद वहाँ नहीं थे। वह पटना जिला जेल में रखें गये थे। अगस्त कान्ति की जिम्मेदारी

ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के माथे मही। इसका जवाब अहमदनगर फोर्ट से कांग्रेस की कार्यकारणी कमेटी के सदस्यों की खोर से कांग्रेस के अध्यत्त मौलाना अबुल कलाम आजाद ने दिया। वायसराय के पत्र में इन्होंने लप्टतः लिखा कि कांग्रेस ने न तो जन-आन्दोलन का प्रारम्भ ही किया और न इसका संचालन ही किया। अतः इसकी जिम्मेदारी किसी भी प्रकार कांग्रेस की नहीं है। जेल के वाहर आने के वाद भी कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने इसी प्रकार का विचार प्रकट िया था, जिसके विरुद्ध में सन् १६४४ ई० के अन्त में श्रीमती आगणा आसफ अली और श्री अच्युत पटवर्धन ने फरारी की हालत में ही एक संयुक्त वक्तव्य दिया था।

हम उपर देख चुके हैं कि किस प्रकार की राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थित में गांधीजी जेल के बाहर आये थे। उसे फिर उल्जल करने की आवश्यकता नहीं है। हम यह भी देख चुके हैं कि भारतीय पूँजीजारी वर्ग अपने विकास तथा प्रगति के लिये ब्रिटिश सरकार के साथ सममौता करने के लिये आतुर हो उठा था। परन्तु इसके लिये अनुकूल अवस्था पैदा करना इसके (भारतीय पूँजीवादी वर्ग के) लिये सम्भव नहीं था। इसके इस प्रकार के कार्यों को तो वृद्धि-जीवी वर्ग सम्पन्न किया करता है। जेल से बाहर आने देर भी नहीं हुआ कि गांधीजी ब्रिटिश सरकार के साथ सममौते के लिये अनुकूल अवस्था तैयार करने में व्यस्त हो गये थे। हम देख चुके हैं कि अगस्त क्रान्ति से विकसित भारतीय शोषित-पीड़ित जनता के क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चे को फरारी जीवन व्यतीत करते हुए राजनीतिक कार्यकर्ता भाशी क्रान्तिकारी जन-आन्दो-

१४८ हिन्दुस्तान श्रीर पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेपण

लन के लिये संगठित कर रहे थे, जिसे भारतीय पूँजीवादी वर्ग तथा ब्रिटिश सरकार अपने अस्तित्व के लिये घातक सममती थी। इसे कायम रहते हुए भारतीय पूँजीवादी वर्ग के साथ समम्मीता करना ब्रिटिश सरकार व्यर्थ सममती थी। अतः सर्वप्रथम गांधीजी का आक्रमण भारतीय शोपित-पीड़ित जनता के क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चे के ऊपर हुआ। उन्होंने आदेश दिया कि जो लोग फरार थे, वे तुरन्त पुलिस को आत्म समर्पण कर दें। इसी जन-मोर्चे के ऊपर गांधीजी का दूसरा हमला यह हुआ था कि उन्होंने एक वक्तव्य में अगस्त क्रान्ति को देश के लिये घातक कहा था। इसके ऊपर इनका तीसरा आक्रमण यह था कि भारतवर्ष के साम्प्रदायिक विभाजन के आधार पर गुस्लिम लीग के साथ समभौते के लिये जिन्ना साहब से उन्होंने कई दिनों तक वातें की।

यहाँ यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि भारतीय शोपित जनता अगस्त क्रान्ति को क्या सममती थी। जेलों के वाहर आने पर कांचे स के सुधारवादी नेतृत्व ने यह अनुभव किया कि ब्रिटिश सरकार का दमन भी भारतीय जनता की क्रान्तिकारी प्रवृत्ति को कुचल नहीं सका। इसने यह भाँप लिया कि अगस्त क्रान्ति के खिलाफ आवाज उठाकर जनता को अपने प्रभाव में रखना सम्भव नहीं हो सकता था। अतः इसे अपनाना ही इसने बुद्धिमानी सममा। सर्वप्रथम जेत के बाहर होते ही श्री जवाहरलाज नेहक्जी ने एक वक्तव्य में स्वष्टतः कहा कि सन् १६४२ ई० की अगस्त क्रान्ति की सार्रा जिम्मेदारी कांचे स के उत्तर है और यह कांचे स का ही आन्दोलन था। हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। इसके बाद सभी कांग्रेसी नेतागण ने अगस्त कान्ति के सम्बन्ध में करीब-करीब इसी प्रकार का कहना प्रारम्भ किया। देश के सारे के सारे अखबार पूँजीपितयों के हाथों में थे और हैं। फिर क्या था, इन सबीं का यह प्रयत्न होने लगा कि इस प्रकार की अवस्था पैदा कर दें कि सभी भारतीय यही सममें कि अगस्त कर नित कांग्रेस के द्वारा संचालित हुई और यह कांग्रेस का आन्दालन था। इसमें इन्हें काफी सफलता प्राप्त हुई।

इस पुरतक में च्यन्य स्थान में हम देख चुके हैं कि राष्ट्रीय पूँजीवादी-सुवारवादी नेनृत्व ने क्रान्ति विरोधी होते हुए क्यों "भारत छोड़ो"का प्रस्ताव पास करवाया।इसे यहाँ फिर उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। हम देख चुके हैं कि तीव गति के साथ भारतीय शोषित जनता क्रान्ति पथ पर अयसर होती जा रही थी। हजार प्रयत्नों के बावजूद भी राष्ट्रीय सुधारवादी नेतृत्व उसे नहीं रोक सका। यह संसार का इतिहास बतलाता है कि जब सुवारवादी नेतृत्व आम जनता को कान्ति-पथ पर अयसर होने से नहीं रोक पाता, उस समय बिना किसी प्रकार के क्रान्तिकारी संगठन और क्रान्तिकारी तैयारी के क्रान्ति-कारी जन-त्र्यान्दोलन का नारा बुलन्द करता है और बजाय जन-आन्दोलन को जन क्रान्ति में विकसित करने को आराज-कता में परिवर्तित करने का प्रयास करता है। ठीक सन् १६४२ ई॰ में भारतीय सुधारवादी पूँजीवादी नेतृत्व ने किया। यह कभी भी कान्तिकारी जन-आन्दोलन को संचालित कर शासन सत्ता पर करजा करना नहीं चाहता था। श्रगर यह ऐसा चाहता, तो पहले जन-क्रान्ति के अनुकूल संगठन तथा तैयारी किय होता। नेताजी सुमायचन्द्र वीस के नेतृत्व में हिन्दुस्तान

१६० हिन्दुस्तान श्रीर पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेपण

के वाहर संगठित आजाद हिन्द फीज के साथ सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न करता। आजाद हिन्द फीज के साथ सम्पर्क कायम होने के वाद बाहर से नेताजी बोस के नेतृत्व में आजाद हिन्द फीज हिन्दुस्तान में कायम ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ऊपर आक्रमण करती और अन्दर में कांग्रेस के नेतृत्व में शोपित जनता क्रान्ति का मंडा फहराती। अगर ऐसा हुआ होता, तो इसके परिणामस्वरूप भारतवर्ष का इतिहास कुझ और ही होता। साम्प्रदायिक तथा धार्मिक आधार पर पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में भारतवर्ष का निमाजन नहीं हुआ होता और न पूँजीवादी वर्गीय सरकार की स्थापना हुई होती, विक आज किसान-मजदूरों की क्रान्तिकारी हुकूमत होती।

शिमला सम्मेलन

उपर हम यह उल्लेख कर चुके हैं कि बिटेन से वापस आते ही वायसराय ने कांग्रेस के नेताओं को जेलों से छोड़ने की आज्ञा दे दी थी। वे जेलों के बाहर आये। उघर वायसराय ने भारत के विभिन्न दलों के नेताओं को शिमला में बातें करने के लिये निमन्त्रित किया। राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग की कार्यकारिणी कमेटी के सदस्यों के रहने वगैरह का पवन्य भी किया। शिमला में जमघट जमा हुआ। गांधीजी भी वहाँ पहुँचे। लेकिन इस बार कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, बिल्क कांग्रेस के साथ-साथ बिटिश साम्राज्यवादी सरकार के प्रतिनिधि वायसराय के सलाहकार और दार्शनिक के रूप में यहाँ पहुँचे। नेताओं के शिमला पहुँचने के बाद वायसराय की अध्यक्ता में विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन प्रारम्भ हुआ और कई दिनों तक चलता रहा। इसकी प्रगति से यह ज्ञात होने लगा था कि केवल ब्रिटिश सरकार के साथ ही नहीं, बल्कि कांग्रेस और लीग के साथ भी सममीता हो जायेगा। यही कारण था कि प्रेस-प्रतिनिधियों के बीच वक्तव्य देते हुए राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्त मौलाना अवुल कलाम आजाद ने कहा था कि शीघ ही राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के बाद हम (भारतीय) अपनी लड़ाई लड़ेंगे।

कांत्रेस और लोग ने कुछ काल के लिए ब्रिटिश वायसराय का नेतृत्व स्वीकारकर उसकी अध्यत्तता में आपस में सममीता का प्रयास किया था। सम्मेलन के प्रारम्भ में अध्यत्त के पद से वायसराय ने भूलने और त्रमा करने 'forget and forgive' के लिए सबों से अनुरोध किया था। इसके बाद कुछ परिवर्षित क्य में सन् १६४२ ई० के मार्च के किएस प्रस्ताव को सम्मेलन के सामने रखा था। यह नया प्रस्ताव इस प्रकार का था कि तात्कालिक राष्ट्रीयसरकार की स्थापना के हेतु वायसराय की कौन्सिल फिर से गठित होगी, जिसमें पांच सदस्य राष्ट्रीय कांग्रेसी, ४ सदस्य मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि और तीन अन्य अल्प-संख्यक जातियों के प्रतिनिधि होंगे। इसमें मुस्लिम सदस्य ही केवल मुर्स्लिम लीग के प्रतिनिधि होंगे।

साथ ही साथ इस तथार्काथत राष्ट्रीय सरकार को सिक्रय हो युद्ध के प्रयत्न में भाग लेना होगा। युद्ध के उपरान्त आजादी भारतवप को प्रदान की जायगी।

करीब-करीब राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग इसे स्वीकार कर चुकी थी। लेकिन अन्त में इस सम्मेलन की भी वही हालत

१६२ हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का ऐतिहासिक त्रिश्लेषण

हुई जो पहले किये गये प्रयत्नों की हुई थी। केन्द्र में ब्रिटिश साम्राज्यवादी यूनियन जैक के नीचे वायसराय की राष्ट्रीय कीन्सिल में कांग्रेम श्रीर लीग के बराबर-बराबर सदस्य होंगे, इसे दोनों ने स्वीकार कर लिया था; लेकिन मुस्लिम लीग यह नहीं चाहती थी कि कांग्रेस किसी मुसलमान की नामजद करे, श्रीर कांग्रेस श्रपने राष्ट्रीय रूप की वनाये रखने के लिए इस बात पर श्रड़ी थी। श्रतः श्रन्त में श्रासफलता के साथ शिमला-सम्मेलन भी खत्म हुशा।

दु:ख के साथ सम्मेलन को खत्म करते हुए ब्रिटिश वायस-राय ने सबों से इस बात का अनुरोध किया था कि इसकी असफलता के लिए एक दूसरे पर दोषारोपण न करें। सबों ने ईमानदारी के साथ सममीता के लिए प्रयत्न किया, लेकिन इस विफल रहे। फैली हुई मौजूदा विषमना को बढ़ने न देने का इम सब प्रयत्न करते रहें। सममीते का प्रयत्न यहीं पर खत्म नहीं हो गया। आगे भी इम सब करते रहेंगे।

सम्मेजन की असफजता के उपरान्त गांधीजो ने साफ-साफ कहा—"हम विफज क्यों हुए ? इसलिए नहीं कि अंग्रेज बदमाश हैं, बल्कि इसलिए हम असफल रहे कि हम मूर्व और बदमाश हैं।"

गजनीतिक अवस्था

यह ठीक है कि सन् १६४२ ई० की अगस्त-क्रांति असफल हुई। यह भी ठीक है कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी दमन के कारण क्षणिक काल के लिए भारतीय जनता में आतंक अवश्य फैल गया था। भारतीय जनता की बगावत की प्रवृत्ति कुछ ठंडी अवश्य हो गयी थी; लेकिन यह कुचली नहीं जा सकी थी। अगस्त-क्रांति की अग्नि में भारतीय शोधित जनता का त्याग व्यर्थ नहीं गया। इससे (अगस्त-क्रान्ति से) भारतीय शोधित जनता का क्रान्तिकारी जन-मोर्चा विकसित हुआ। अगस्त के क्रान्तिकारी जन-आन्दोलन से काफी क्रान्तिकारी जन-शिक जत्यन्त हुई, जिसे फरारी की अवस्था में रहकर राजनीतिक कार्यकर्ता भानी क्रान्ति के लिए संगठित कर रहे थे और इन्हीं के नेतृत्व में इन जन-शिक्तयों के आधार पर शोधित अभिक जनता के क्रांतिकारी मोर्चे का निर्माण तथा विकास हो रहा था। सन् १६४४ ई० के प्रारम्भ में नेताजी सुभाष चन्द्र वोस के नेतृत्व में आजाद हिन्द फीज के आक्रमण ने इसे और भी दृढ़ और मजवूत बना दिया था। इसके परिणामस्वरूप भारतीय जनता का क्रान्ति की प्रवृत्ति क्रमशः उप रूप धारण करने लगा था।

अपने जीवन की सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था से परेशान होकर भारतीय नौजवान भारतीय जिटिश फौज में आर्थिक अवस्था की सुधारने के हेतु शामिल हुए थे। वे हिन्दुस्तान से बाहर साम्राज्यवारी युद्ध के विभिन्न मोर्च पर भेजे गये थे। अन्य आजाद सुल्कों की फौज के सम्पर्क में आने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ था। उनकी और अपनी अवस्था का ज्ञान उन्हें हुआ। उन्हें यह अनुभन होने लगा कि आजाद मुल्कों की फौजों के सामने गुलाम देश की फौज का विशेष महत्व नहीं रहता है, भले ही वे अधिक बहादुरी युद्ध-तेत्र में दिखायें। इसके कारण उनके अन्दर राष्ट्रीयता की उप मावना विकसित होने लगी और देश-भक्त कूट-कूट-कर अन्दर भरी जाने लगी। इतना ही नहीं, अभिक-शोषित

पींड़ित जनता की गुलामी श्रीर शोषण से श्राजादी की लड़ाई का प्रभाव उनके उत्पर पड़ने लगा।।हम सब जानते हैं कि यूनान की शोषित जनता की क्रान्तिकारी फीजों ने यूनान से जर्मन फीजों को मार भगाया था। जर्मन फीजों के यूनान से बाहर होते ही यूनानी शोषित-श्रमिक जनता शासन की बागडोर श्रपने हाथों में लेने का प्रयत्न करने लगी श्रीर कामयावी के साथ राजसत्ता पर कब्जा भी कर लिया था। लेकिन वहाँ की प्रतिकियावादी शक्तियों के साथ गठवन्धनकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद यूनानी शोपित-पीड़ित जनता की क्रान्तिकारी शक्तियों को कुचलकर यूनानी प्रतिक्रियावादियों के हाथों में शासनसत्ता सौंपने का प्रयास करने लगा। यूनानी शोषित जनता की क्रान्तिकारी शक्ति को कुचलने के हेतु भारतीय क्रिश साम्राज्यवादी फौजें भी भेजी गयीं। परन्तु बहुत से भारतीय सिपाहियों ने केवल लड़ने से ही इन्कार नहीं किया बलिक यूनानी जनता की क्रांतिकारी फौजों के साथ होकर यूनानी प्रतिकिया-वादी और ब्रिटिश साम्राज्यवादी फौजों के खिलाफ लड़ने लगी थीं। इस प्रकार की क्रान्तिकारी भावनाओं से भारतीय सेना स्रोत-प्रोत हो रही थी।

श्राटम् वस्व के प्रयोग के परिणामस्वरूप पराजय स्वीकार-कर मित्र-राष्ट्रों के सामने जापान साम्राज्यवाद ने भी घुटने टेक दिये। इसके पहले ही पंचायती रूस की लाल फौज के श्राक्रमण को नाजी जर्मनी सहन नहीं कर सका था और मित्र-राष्ट्रों की सेनाओं के सामने जर्मनी श्रात्म-समर्पण कर चुका था। जापान के घुटना टेकने के साथ-साथ दूसरे संसारव्यापी युद्ध का श्रन्त हुआ। श्राजाद हिन्द फौज के बहुत से सिपाही श्रीर सेनानायक गिरफ्तार करके भारतवर्ष को लाये गये। **उन्हें** कड़ो से कड़ी सजा देकर सरकार भारतीय ब्रिटिश फीज के अन्य सियाहियों को आतंकित करना चाहती थी। सर्वप्रथम म्राजाद हिन्द फौज के तीन प्रमुख म्राफिसर-शाहनेवाज, विज्ञन श्रीर सहराल के ऊपर दिल्ली के लाल किला में मुकदमा चलाया गया। स्राजाद हिन्द फीज के सिपाहियों को छुड़ाने के लिए देश भर में स्वतः जन-श्रान्दोलन होने लगा। दिन प्रतिदिन यह शक्तिशाली ही होता गया। सन् १६४२ ई० में भारतीय शोपित जनता ने क्रान्तिकारी जन-म्रान्दोलन को स्थिपित किया था, सन् १६४४ ई० में त्राजाद हिन्द फोज के वोरों को छुड़ाने के लिए उसने वहीं से प्रारम्भ किया था। इस समय भारतीय जनता जिस प्रकार की क्रान्तिकारी शक्ति और दृढ़ता का परिचय दे रही थी, वैसी दृढ़ता श्रीर शक्ति सन् १६४२ ई० की श्रगस्त-क नित में भी नहीं दिखाई दी थी। सन् १६४४ ई० के नवम्बर महीने के चौथे सप्ताह में कलकत्ता के विद्यार्थियों और आम जनता नेकान्तिकारीसमाजवादी पार्टी के नेतृत्व में जिस क्रान्ति-कारी हड़ता तथा शक्ति का परिचय दिया, उसे देखकर राष्ट्रीय पूँजीवादी सुधारवादी नेतृत्व तथा ब्रिटिश साम्राज्यवादीसरकार श्रवाक रंह गयी। स्वप्त में भी उन्हें ऐसी श्राशा नहीं थी। तीन दिनों तक लाखों की तादाद में सड़कों पर गोलियों के बीच श्राम जनता डटी रही। इस समय कलकत्ता की श्राम जनता साम्प्रदायिक भेद-भाव को कतई भूल गयी थी। हिन्दू-मुसलमान का खून एक हो धारा में वह रहा था। क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी के प्रमुख विद्यार्थी कार्यकर्ता अमर शहीद साथी रामेश्वर जनर्जी सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार की गोली के शिकार १६६ हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेपण

हुए। इनके वाद ही साथी आलम भी ब्रिटिश गोली के शिकार हुए। इस प्रकार एक के बाद एक बहुत से नौजवान गोलियों के शिकार तीन दिनों तक होते रहे। अन्त में जनता की दृढ़ता श्रीर शक्ति के सामने ब्रिटिश सरकार को सुकना पड़ा। यह थी भारतीय जनता की क्रान्तिकारी शक्ति।

यहाँ पर यह उल्लेख करना असंगत न होगा कि सन् १६४६ ई० के नवम्बर के क्रान्तिकारी जन-प्रदर्शन का नेतृत्व प्रधानतः क्रान्तिकारी समाजवादी विद्यार्थी कार्यकत्तांओं का था। इसका संचालन मुख्यतः बंगाल प्रान्तीय स्टुडेन्ट फेडेरेशन (१८ मिर्जापुर स्ट्रीट) के द्वारा होता था, जिसमें बहुमत क्रान्तिकारी समाजवादी कार्यकर्तांओं का था। कलकत्ता के इस जन-प्रदर्शन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि राष्ट्रीय कांग्रेस के सुधारवादी नेताओं के विरोध के बावजूद भी जनता हदता के साथ डटी रही और यह प्रमाणित कर दिया कि राष्ट्रीय कांग्रेस के सुधारवादी नेतृत्व के विना भी जनता का आन्दोलन संचालित हो सकता है। इसके अतिरिक्त, इससे स्पष्टतः यह भी ज्ञात होने लगा कि शोषित-पीड़ित जनता के अन्दर स्वतन्त्र कान्तिकारी नेतृत्व विकसित होने लगा था। कलकत्ता की तरह ही सारे देश में जन-आन्दोलन स्वतः संचालित हो रहा था। देश भर में और विशेषतः कलकत्ता के जन-आन्दोलन में

हड़ता और शक्ति तथा इसके खतंत्र क्रान्तिकारी नेतृत्व को विकसित होते देखकर ब्रिटिश सरकार के साथ भारतीय पूँजीवादी वर्ग तथा राष्ट्रीय सुधारवादी नेतृत्व भी भयभीत हो उठे। कलकत्ता की घटना के बाद तुरन्त ही ब्रिटिशसरकार ने यह घोषणा की कि किसी प्रकार का हिंसात्मक कार्य सहन नहीं किया जायगा। तुरन्त सैनिक शिक्त प्रयोग द्वारा कुचल दिया जायेगा। विनिट्स साम्राज्यवादी सरकार की इस घोषणा के तीन-चार दिनों बाद कलकत्ता में राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटी की बैठक हुई। गांधीजी भी बैठक में शामिल होते रहे। एक प्रस्ताय द्वारा कलकत्ता की घटना की निन्दा की गयी और कहा गया कि इस प्रकार का धान्दोलन देश के लिए घातक होगा और भारतीय जनता को अहिंसा के मन्त्र का पाठ फिर से सुनाया गया। इस प्रस्ताय का मुख्य उद्देश था ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार की घोपणा का समर्थन करना, जिससे सममीते का मार्ग साफ रहे।

भारतीय जनता ने इस प्रस्ताव की शोर विशेप ध्यान नहीं दिया। देता भी क्यों ? देना ही तो देश के लिए घातक होता। अपनी आजादी के बीर सिपाहियों को छुड़ाने के लिए उसने (भारतीय जनता ने) कमर कस ली था। दिन-प्रतिदिन उसका आन्दोलन उपतर तथा शिक्तशाली होता गया। उधर दिल्ला के लाल किले में नाटक खेला जा रहा था। कांग्रेस के वड़-बड़े नेतागण भी उसमें हाथ बटा रहे थे। अन्त में भारतीय शोषित-पीड़ित जनता की संयुक्त कान्तिकारी शिक्तयों के सामने विटिश सरकार को मुक्तना पड़ा और आजाद हिन्द फीज के सेनानायकों को मुक्त कर दिया। यही तो है जनता की कान्तिकारी शिक्त।

श्राजाद हिन्द फौज की क्रान्तिकारी भावनाओं का प्रभाव भारतीय श्राम जनता तक ही सीमित नहीं रह सकी। इसका प्रभाव ब्रिटिश भारतीय फौज के ऊपर भी हुआ। अभी श्राजाद हिन्द फौज के सिपाहियों को छुड़ने का जन-अन्दोलन खत्म भी होने नहीं पाया था कि कराँची, वम्बई वगैरह कई स्थानों में आर० आई० एन० ने बगावत कर दी। गोली का जवाब गोली से देना इन्होंने प्रारम्भ कर दिया। इसकी आग अन्य छावनियों में भी भभक उठने ही वाली थी कि कांग्रेस के सुवारवादी नेताओं ने प्रयत्न करके आत्म-समर्पण करवा दिया। राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के वाद भी वे वीर सिपाही जेलों के सींकचों के भीतर सड़े रहे हैं। फौज के अतिरिक्त, पुलिस, विशेषतः आर्मड पुलिस, में बगावत की मावना कमशः उपतर होती जा रही थी। रेलवे मजदूर हिन्दुस्तान में आम हड़ताल करने के लिए कमर कसे हुए थे। डाकखाने में काम करने वालों की हड़ताल हुई थी। स्कूलों के मास्टर सब आर्थिक अवस्था से परेशान थे। हर सरकारी महकमा में परेशानी और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। यह कहना यहाँ पर अनुचल भौतिक परिस्थित उत्पन्न हो गयी थी।

ऐसी विकसित भौतिक परिस्थिति में भारतीय केन्द्रीय और प्रान्तीय एसेन्बली का चुनाव प्रारम्भ हुआ। गैर मुस्लिम स्थानों से कांग्रेस सदस्य बहुमृत में चुने गये। वह चुने भी जाते तो क्यों नहीं ? सभी राजनातिक संस्थाएँ। आज तक इसका समर्थन करती रही थी। परन्तु मुस्लिम स्थानों से कांग्रेस सदस्य नाम-मात्र के चुने गये। बहुमत में मुस्लिम लीग के सदस्य चुने गये। इसी पुस्तक में यह देख चुके हैं कि सन् १६३० ई० के प्रान्तीय एसेन्बली के चुनाब में मुस्तम लीग के सदस्यों को कम बोट मिला था। लेकिन सन् १६४६ ई० में जबिक भारतीय जनता में राजनीतिक जागृति अधिक थी, तब मुस्लिम लीग

ऐसी प्रतिक्रियावादी संस्था को क्यों ऋधिक मुस्लिम वीट प्राप्त हुआ ? यह स्वाभाविक प्रश्न है।

हम डल्लेख कर चुके हैं कि सन् १६४० ई० में अपने लाहीर वार्षिक अधिवेशन में लीग ने पाकिस्तान की माँग का प्रस्ताव पास किया था। उस समय मुसलमान भी बड़ी तादाद में इसके विरोधी थे और इसके विरुद्ध प्रचार करते थे। उसके उपरान्त सममीते के प्रत्येक प्रयत्न में ब्रिटिश सरकार ने विशेषतः इसकी और ध्यान दिया है। सन् १६४२ ई० के किप्स प्रस्ताव हारा सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने इसका समर्थन किया था। उसके वाद सी० आर० फार्मृला के आधार पर गांधी-जिन्ना मिलन ने भी इसका समर्थन किया था। शिमला-सम्मेलन के सामने ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रस्ताव हारा भी इसका समर्थन हुआ। इस प्रकार भारतीय मुसलमान को यह जान पड़ने लगा कि मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की माँग सही है। इस प्रकार के ख्याल का होना मुसलमान जनता के लिए स्वभाविक ही था। पाकिस्तान के आधार पर मुग्लिम लीग चुनाव लड़ने लगी थी।

कांग्रेस जन-आन्दोलन की नीति की तिलांजिल दे चुकी थी। क्रान्तिवरोधी सुधारवादी वैधानिक नीति का अवलभ्वन इसने किया था। इसका असर मुसलमान जनता के ऊपर और भी सुरा पड़ा।

तीसरी वात यह थी कि मार्क्सवाद-लेनिनवाद के नाम पर भारतीय स्टेलिनवादी लीग की पाकिस्तान की माँग का समर्थन कर रहे थे। सन् १६४२ ई० की अगस्त-क्रान्ति में भारतीय जनता के विरुद्ध ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार के साथ देने के कारण तथाकथित कम्युनिस्ट कांग्रस से अलग कर दिये गये थे। उसके उपरान्त उनका नारा कांग्रेस-लीग-कम्युनिस्ट एकता का था। 'गाधीजी राष्ट्रीय पिता और जिन्ना साहेव राष्ट्रीय चाचा हैं' के आधार पर इस एकता के नारे को देश भर में स्टालिनवादी बुलन्द कर रहे थे। राष्ट्रीय मुसलमानों के खिलाफ पाकिस्तान के आधार पर चुनाव में लागी सदस्यों का समर्थन तथा सहायता वे कर रहे थे। इसका भी असर भारतीय आम मुसलमानों के ऊपर मुस्लिम लीग के पन्न में ही पड़ा। अतः इन सब वातों से प्रभावित होकर अधिक बहुमत में मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के सदस्यों को चुना और चुनना भो तो स्वामाविक ही था।

ब्रिटिश कैबिनेट भिशन

युद्ध के प्रारम्भ हाते ही कुछ महीने के अन्दर फांस का पतन हो गया था। फांस से बुरी तरह जान बचाकर ब्रिटिश फीजें भाग सकीं। यह झात हो रहा था कि थोड़े दिन के अन्दर ब्रिटेन भी नात्सी जर्मनी की फीजों के सामने घुटना टेक देगा। युद्ध की ऐसी अवस्था में ब्रिटेन के शासन की बागडोर भि० चर्चिल ने अपने हाथों में ली और सन् १६४४ ई० तक ब्रिटेन के प्रधान-मन्त्री के पद पर विद्यमान रहे। इसके नेतृत्व में युद्ध-अवस्था अन्त में ब्रिटेन के पत्त में परिवर्तित हो गयी थी। इसके सफल नेतृत्व में ब्रिटेन पराजय होने से ही नहीं बचा, नास्सी जर्मनी को परास्त करके हिटलर की फीज को एक दम ध्वंस कर डाला। इसके कारण ब्रिटेन के राष्ट्रीय वीर थे। परन्तु वहाँ (ब्रिटेन) की अमिक जनता युद्ध से परेशान हो रही थी, युद्ध के संचालन के बोम से दबी जा

रही थी। वह अनुभव करने लगी थी कि यह युद्ध प्रधानतः ब्रिटेन के साम्राज्यवादी-पूँजीवादी वर्ग के स्वार्थ में ही संचालित हो रहा है यही कारण था कि मि०चर्चिल "राष्ट्रीय वीर" होने के बावजूद भी बिटेन की श्रमिक जनता उसकी साम्राज्यवादी-पुँजीवादी वर्गीय पार्टा- 'कन्जर्वेटिव पार्टी" - के खिलाफ हो रही थो । अभी सं तार्व्यापी साम्राज्यवादी युद्ध खत्म नहीं हुआ था। पंचायती कुस की लाल सेना की चोट से नात्सी जर्मनी की फौज चकनाचूर हो गयी थी छौर मित्र-राष्ट्रों की फीजों के सामने जर्मनी श्रात्म-समर्पण कर चुका था। लेकिन संसार के अन्य चेत्रों में युद्ध चल रहा था। ऐसी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में ब्रिटेन ने नये चुनाव की घोषणा की। वहाँ की जनता ने मजदूर पार्टी के सदस्यों को बहुमत में चुना । त्रिटिश पार्लियामेण्ट में लेबर पार्टी का बहुमत हुआ। अभी तक मि० चर्चिल के नेतृत्व में "संयुक्त सरकार" थी। चुनाव के परिणाम-स्वरूप सन् १६४५ ई० में चर्चिल कैबिनेट खत्म हुन्ना चौर मि० एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश लेबर पार्टी ने शासन की वागडोर अपने हाथों में ली ।

त्रिटेन में लेबर पार्टी की हुकूमत होने के उपरान्त भारत के साथ सममीते का प्रयत्न होने लगा था। सब-प्रथम यह प्रयत्न शिमला-सम्मेलन के रूप में सामने आया। इसमें असफल होने पर भारतीय पूँजीवादी वर्ग और ब्रिटिश साम्राज्य-वादी-पूँजीवादी वर्ग हताश होकर बैठ नहीं गये। इनका प्रयत्न जारी रहा। शिमला-सम्मेलन की असफलता के वाद भारत वर्ष की केन्द्रीय और प्रान्तीय एसेम्बलियों के शीव चुनाव की घोषणा की गयी। कुछ महीनों के अन्दर चुनाव हुआ, जिसमें

१७२ दिन्दुस्तान श्रीर पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेषण

हिन्दुओं ने बहुमत में कांग्रेस सदस्यों को श्रीर मुसलमानों ने मिस्लम लीग के सदस्यों को बहुमत में चुना इससे स्पष्ट हो गया कि किसी भी कारण से भारतीय मुसलमान श्रिषकांश मुस्लिम लीग के साथ हैं। वंगाल श्रीर सिन्ध में मुस्लिम लीग मन्त्रि-मण्डल, पंजाब में युनियनिग्ट-कांग्रेस संयुक्त मन्त्रि-मंडल श्रीर बाकी प्रान्तों में कांग्रेस मन्त्रिमंडल की स्थापना हुई।

चुनाव का नतोजा प्रकाशित होते ही ब्रिटेन के ब्रिटिश कैबि-नेट मिशन के भारत में पदार्पण की घोषणा की गयी। कुछ दिनों के अन्दर यह मिशन दिल्ली में पहुँच गया। हफ्तों तक विभिन्न द्तों के प्रतिनिधियों तथा व्यक्ति विशेष के साथ यह बातें करता रहा। राष्ट्रीय कांग्रेस श्रीर मुस्लिम लीग के बीच किसी प्रकार का समम्तीता कराने का प्रयत्न उसने किया। यहाँ यह उल्लेख करना असंगत न होगा कि भारतीय पूँजीवादी वर्ग का आंतरिक संवर्ष ब्रिटिश और भारतीय पूँजीवादी वर्ग के बीच के संघर्ष से कहीं ज्यादा तीत्र हो रहा था जिसके कारण त्रिटिश सरकार के खिलाफ भारतीय पूँजीवादी वर्ग किसी भी अकार का आन्दालन चलाने को तैयार नहीं था। यहाँ पर हम यह न भूतों कि भारतीय पूँजीवाद का विकास छन्य पँजीवादी देशों के जैसा स्वाभाविक रूप से नहीं हुआ था, छीर दूसरी बात यह है कि दूसरे संसारव्यापी युद्ध-काल में इसका श्रधिक विकास हुआ था। इसके साथ ही साथ भारतीय पूँजीवादी वर्ग का आन्तरिक संघर्ष तीत्र गति से भयानक रूपे धारण करता गया। पूँजीवादी होड़ में मुस्लिम मूँजीपति हिन्दू-पूँजीपतियों के सामने अपने को खड़े होने में कमजोर अनुभव करते रहे; अतः अपने विकास तथा प्रगति के लिए साम्प्रदायिक आधार पर भारतवर्ष का विभाजन आवश्यक सममते लगे थे। परन्तु हिन्दू पूँजीपित अपने पूँजीवादी शोषण के चेत्र के कम होने के भय से इसे स्वीकार करने में हिचक रहे थे। अतः हफ्तों तक बातचीत होने के अपरान्त इसकी भी वही हालत हुई जो और प्रयत्नों की पहले हो चुकी थी। इसके विफल होते ही ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत से प्रस्थान करने की तैयारी करने लगा।

ब्रिटिश कैनिनेट मिश्चन और भारतीय वामपक्षीय पार्टियाँ

श्राज भारतवर्ष में बहुत-सी वामपत्ती पार्टियाँ हिटिगोचर हो रही हैं। यहाँ पर हम सबों की कैबिनेट मिशन के प्रति नीति का उल्लेख नहीं कर सकेंगे। केवल क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी स्टालिन-घादी) श्रीर फारवर्ड व्लाक की नीति का हम उल्लेख करेंगे।

हम ऊपर देव चुके हैं कि किस प्रकार की राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थित में ब्रिटिश कैविनेट गिशन का भारतवये में आगमन हुआ। उसे उल्लेख करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। एक और भारतीय श्रमिक-शोषित-पीड़ित जनता की क्रान्तिकारी शिक्तयों के खिलाफ ब्रिटिश साम्राज्य-यादी सरकार भारतीय सुधारवादो पूँजीवादी नेतृत्व के सहयोग से ब्रिटिश साम्राज्यवादी-पूँजीवादी वर्ग और भारतीय पूँजीवादी वर्ग के प्रतिक्रियावादी गुट का निर्माण करने के लिए आतुर हो रही थी। इस उद्देश्य की पूर्ति के हेतु ब्रिटिश कैविनेट मिशन का हिन्दुस्तान में आगमन हुआ था। दूसरी और लीग और कांग्रेस के नेतृत्व से अलग हो अपने आन्दोलन से कान्तिकारी नेतृत्व का निर्माण तथा विकास करने में भारतीय शोपित-

१७४ हिन्दुस्तान स्त्रीर पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेषण

पीडित जनता व्यस्त थी। ऐसी परिस्थिति में "भारतीय समाज-चाद" के कांग्रेस सांशालिस्ट नेतागण जेलों के वाहर आये और तुरन्त श्रमिक-शोपित जनता को गुमराह करने का प्रयास करने लगे। कांग्रेस के सुधारवादी-पूँजीवादी नेतृत्व के प्रभाव से निकलकर भारतीय शोषित जनता स्वतंत्र नेतृत्व की स्थापना कर रही थी, जो भावी क्रान्ति के लिए आवश्यक था। कांग्रेस सोशलिस्ट नेतागण क्रान्ति की बातें तो ऊँची आवाज में फरते थे लेकिन उनकी क्रान्ति की बड़ी-खड़ी बातों में तलवार छिपी थां, जिसे भारतीय समाजवाद की बलि-वेदी पर भारतीय शोषित जनता के विकसित क्रान्तिकारी नेतृत्व की हत्या फरने के हेतु तेज किया जा रहा था। क्रान्ति की बड़ी-बड़ी वातं करते हुए कांग्रेस सोशालिस्ट नेतागण यह कहा करते थे कि भावी क्रान्ति में प्रान्तों के हमारे प्रधान-मन्त्री लोग स्वयं गिरफ्तार नहीं होंगे, बिक गवर्नर की गिरफ्तारी की आजा देंगे। इन सब बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस के नेतृत्व में भावी क्रान्ति होगी । स्त्रर्थात् भावी क्रान्ति का संचालन कांग्रेस का सुधारवादी-पूँजीवादी नेतृत्व करेगा, जिसके प्रभाव से जनता ऋलग हो रही थी। कैबिनेट मिशन के विषय में वे मौन थे। कई स्थानों में श्री जयप्रकाश नारायण-जी ने यह सफ्ट कर दिया था कि हमें समस्तीते के विषय में चिन्ता नहीं करनी है। हमारे राष्ट्रीय नेता काफी योग्य हैं। वे देश को नहीं वेचेंगे । वे जो कुछ करेंगे देश के लाभ की दृष्टि से ही करेंगे। इस प्रकार सुवारवादी-वूँजीवादी नेतृत्व को हुद करने में कांग्रेस सोशलिस्ट नेतागण लगे हुए थे। अभी भी कांग्रेस-लीग-कम्युनिस्ट-संयुक्त मोर्चे का नारा

कम्युनिस्ट बुलन्द कर रहे थे। ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के प्रति पंचायती रूस की क्या नीति है, कम्युनिस्टों को ब्रात नहीं हुई थी। अतः यह भी इसके सम्बन्ध में उदास थे अर्थात् इसके सम्बन्ध में मौन रहकर इसका समर्थन कर रहे थे। फार्वर्ड ब्लाक अपने उदय-काल से ही ब्रिटिश सरकार के साथ किसी भी प्रकार के समभौता के खिलाफ रहा और हमेशा ब्रिटिश सरकार के साथ समभौते का विरोधी था। अतः ब्रिटिश कैबिनेट मिशन का भी यह विरोधी था।

यहाँ पर यह कहना अनुचित नहीं होगा कि केवल क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी ने कैबिनेट मिशन के उरेश्य की सममा श्रीर इसके वर्गीय बाचरण का विश्लेषण करके भारतीय शोपित जनता के सामने रखा। सर्व प्रथम क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी के यू० पी० प्रान्त के प्रथम ऋघिवेशन में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया गया था. जो मास्को से रेडियो पर ब्राडकास्ट किया गया था :-- "क्रान्ति-कारी समाजवादी पार्टी" (R.S.P.I) का यह प्रान्तीय सम्मेलन ब्रिटिश स्त्रामात्य-मंडल के भारत-त्रागमन और उसके द्वारा चलाये जानेवाले समम्भीते के खाँग को बड़ी गंभीरता के साथ देखता है। सर्वहारा वर्ग की पार्टी के नाते क्रान्तिकारी समाज-वादी पार्टी भारतीय श्रमिक वर्ग को आगाह करती है कि यह सममीता उसके श्रीर 'ब्रिटिश जनों', के बीच न होकर देशी (हिन्दुस्तानी) पूँजीपतियों और ब्रिटिश पूँजीपतियों के बीच होने जा रहा है। दीर्घकालीन विश्वव्यापी महायुद्ध के फल-स्वरूप दुनिया में जो क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं, उससे ब्रिटिश पूँजीवाद की हालत बहुत ही चिन्ताजनक हो गयी है। विश्व

१७६ हिन्दुस्तान चोर पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेपण

की प्रगिशित शिक्तयों के विरुद्ध, जिनमें सोवियट रूस सबसे प्रमुख शक्ति है, श्राज ब्रिटिश वंक पूँजीशाह अपने एक विश्वव्यापी गुट का निर्माण करने में व्यस्त हैं। हिन्दुस्तान के क्रान्तिकारी आन्दोलन की प्रगति ने, जिसमें बढ़ते हुए आर्थिक संकट और बेकारी ने और तेजी ला दी है, उन्हें इस काम के लिए और भी मजबूर कर दिया है।

"भारतीय पूँजीवाद भी दुनिया के वाजारों में हिस्सा बँटाने के लिए ब्रिटिश वंकशाहों से साँठ-गाँठ करने को उतावला हो रहा है। इसलिए इस सममीते की सफलता भी भारतीय श्रिमिक शोषित वर्गों के हित में न होकर देशी पूँजीपितयों के हित में है। पार्टी यह भी घोषित कर देना आवश्यक सममती है कि श्रिमिक वर्ग की आजादी केवल एक श्रिमिक जन-क्रान्ति के द्वारा ही सम्भव नहीं हो सकतो है। इसलिए भारतीय सर्वहारा वर्ग का यह कर्तव्य है कि वह इन थोथे सममीता के जाल में न पड़कर सत्ता को अपने हाथों में लेने के लिए कृषक-मजदूर-जन-मोर्चा को इद बनाये और अपने क्रान्तिकारी संवर्ष को तब तक अविराम गित से चालू रखे, जब तक कि वर्त्त मान पूँजीवादी-साम्राज्यवादी ढाँचे का विश्वंस नहीं हो जाता।" यू० पी० पार्टी के प्रान्तीय सम्मेलन के इस प्रस्ताव को पार्टी के प्रथम दिल्ली कान्वेसन ने भी स्वीकार किया।

े १६ मई की त्रिटिश सरकार की घोषणा

इसी पुस्तक में ऊपर अन्य स्थानों में हम देख चुके हैं कि सन् १६३४ ई० के भारतीय विधान की घोषणा के पूर्व सन् १६३१ ई० में लन्दन में गोलमेज परिषद भारतीय विधान में मौलिक परिवर्तन करने के लिए बैठा। ब्रिटिश प्रधान मन्त्री मि॰ मैकडोनल्ड की अध्यत्तता में हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक समस्यात्रों का हल करने के लिए नाटकीय प्रयत्न किया गया। इसे सुलमाने के प्रयत्न के साथ-साथ उलमाने का भी प्रयत्न हुआ। जब यह संयुक्त प्रयत्नों से नहीं सुलमाया जा सका, तब ब्रिटिश प्रधान मन्त्री ने भी साम्प्रदायिक वँटवारा (कम्यनल एवार्ड) की घोषणा की, जिसने वजाय हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक समस्याओं को सुलमाने के और भी उलमा दिया। इस घोषणा ने नये-नये मसले खड़े कर दिये हैं।

सन् १६४६ ई० की १६ मई को ऋपने साम्राज्यवादी स्वार्थ तथा स्वभाव से मजबूर होकर निम्नलिखित घोपणा एक साथ दिल्ली और लन्दन से की गई। इसके विश्लेषण से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि यह ब्रिटिश साम्राज्यवादी स्वार्थ की भावना से त्रोत-प्रोत थी। यहाँ पर हम यह न भूलें कि दूसरे साम्राज्य-वादी युद्ध के खत्म होते देर भी नहीं हुई कि साम्राज्यवादी-पूँजीवादी देशों के बीच गुटवन्दी प्रारम्भ हो गर्या। संसार के पूँजीवादी हाड़ में अपने अस्तित्व की रक्ता के हेतु विभिन्न साम्राज्यवादी पूँजीवादी देश प्रतिक्रियावादी गुट के निर्माण में व्यस्त हो रहे थे। ब्रिटेन भारत को अपने गुट में शामिल करना चाहता था। इसके लिए यह त्रावश्यक था कि संयुक्त भारतवर्ष में किसी न किसी प्रकार का केन्द्रीय शासन अवश्य हो। दूसरी बात यह थी कि भारतीयों के हाथों में शासन सत्ता के हस्तांतरित हो जाने के उपरान्त भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद का श्वस्तित्व भारतवर्ष में कायम रहे। इसका साम्राज्यवादी आर्थिक स्वार्थ भारतीय बाजार में कायम रहेगा। साम्प्रदायिक

१७८ हिन्दुस्तान चौर पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेषणा

श्राय। एर भारत के विभाजन से यह काफी दिनों तक कायम रह सकेगा। उक्त साम्राज्य गदी स्वार्थ की भावनाओं से श्रोत-प्रोत होकर ब्रिटिश कैबिनेट भिशन ने 'भारतवर्ष की राजनीतिक समस्यात्रों को हलं करने के लिए एक योजना पेश की, जो लन्दन तथा दिल्ली से एक साथ ता० १६-४-४६ को घोषित की गर्या।

हम सब देख चुके हैं कि संसार-ज्यागी युद्ध अभी चल ही रहा था कि ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ और ब्रिटिश मजदूर दल की सरकार कायम हुई। इसके फलस्वरूप परिस्थिति बदली। ता० १६-२-४६ को हिन्दुस्तान के वास्ते राज्यमन्त्री मि० पैथिक लारेन्स ने भारत की राजनीतिक समस्या को हल करने की हदना की घोषणा की और साथ ही साथ उन्होंने यह भी घोषित किया कि इसके लिए ब्रिटिश मन्त्रिमंडल के तीन सदस्यों का एक मिशन शीघ ही भारतवर्ष जायगा।

ता० १४-३-४६ को त्रिटिश प्रधान-मन्त्री एटली ने ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में भारत के आजार्दा के अधिकार को स्वीकार करते हुए और भारतीयों का आजादी हासिल करने में सहायता करने की अपनी सरकार की टढ़ता को भी व्यक्त करते हुए ऐतिहासिक घो णा की और कहा कि अल्पसंख्यक को बहुसख्यक की प्रगति के मार्ग में ब्रिटिश सरकार अड़चन नहीं डालने देगी। हिन्दुस्तान के वास्ते राज्यमन्त्री भि० पैथिक लारेन्स के नेतृत्व में ब्रिटिश कैविनेट मिशन ने-जिसके सदस्य सर स्टेफोर्ड किप्स और मि० ए० वी० एलैक्जेएडर थे-भारतवर्ष में पधारा। इसके पधारने के उपरान्त शिमला में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग तथा ब्रिटिश

सरकार के प्रतिनिधि शामिल हुए। यह सफल हुआ, लेकिन इसमें जो विचार-विनिमय हुआ था, उसने १६ मई की ऐतिहासिक योपणा के लिए अनुकूल मार्ग तैयार किया।

राष्ट्रीय कांग्रेस श्रीर मुस्लिम लीग के बीच सममौता कराने के प्रयत्न में श्रमफल होने पर ता० १६-४-४६ को भारतवर्ष की वैधानिक समस्याद्यों के समाधान के सम्बन्ध में ऐतिहासिक घोषणा कैविनेट मिशन ने की। यह प्रधानतः तीन हिस्सों में विभाजित की जा सकती है:—

- (१) भारतीय विधान का आधारित रूप,
- (२) विवान निर्माण की मशीन की आयोजना,
- (३) अन्त:कालीन सरकार की स्थापना।

१४ पैराप्राफ के अन्तर्गत भारतीय विधान का निम्नितिखित आधारित रूप होगा:—

- (१) भारतवर्ष का एक संघ (यूनियन) होगा, जिसमें विटिश भारत तथा देशी रियासतें शामिल रहें भी खीर इसे निम्नलिखित विषयों पर खिषकार प्राप्त रहेगा :— वैदेशिक कार्य, रज्ञा खीर यातायात और इनकी पृति के लिए अर्थ प्राप्त करने का भी खिषकार होगा।
- (२) संघ (यूनियन) की एक केन्द्रीय कार्यकारिणी और धारा सभा होगी, जिसमें ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अगर धारा सभा में साम्प्रदायिक प्रश्न उठता है, तो इसके निर्ण्य के लिए इसके बहुमत की तथा इन मुख्य दोनों सम्प्रदायों में प्रत्येक के प्रतिनिधि को बोट देने तथा उपस्थित सदस्यों को बोट करने की आवश्यता होगी।

१८० हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेषण

- (३) संघ (यूनियन) के मातहत विषयों के अतिरिक्त सभी विषय तथा सभी अधिकार प्रान्तों के हाथों में होंगे।
- (४) संव (यूनियन) के मौंपे गये अधिकारों के अर्वारक्त सभी अधिकार तथा विषय रियासतों के हाथों सें रहेंगे।
- (४) प्रान्तीय कार्यकारिणी तथा घारा-सभा में से प्रत्येक गुट बनाने के लिए स्वतंत्र है और इस प्रकार बने हुए प्रत्येक गुट प्रान्तीय विषयों को सामूहिक रूप में लाने के लिए निर्णय कर सकता है।
- (६) संघ (यूनियन) तथा गुट के विधान में ऐसा नियम होना चाहिए कि प्रारम्भिक १० वर्ष के उपरान्त कोई भी प्रान्त अपनी धारा-सभा के बहुमत के द्वारा अपने विधान के नियमों के अपर फिर से विचार करने की माँग कर सके।
- II विधान-निर्माण की मशीन की योजना निम्न प्रकार रखी है:--
- (श्र) त्रावादी के त्राधार पर प्रत्येक प्रान्त को प्रतिनिधि भेजने का त्राधिकार होगा।
- (व) यान्त के हिस्सों को प्रमुख सम्प्रदाय—मुस्लिम, सिख तथा श्राम श्रन्य लोगों—के बीच विभाजित किया जायगा।
- , (स) प्रत्येक सम्प्रदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव वहाँ की घारा-सभा में उस सम्प्रदाय के प्रतिनिधियों के द्वारा होगा।

इस प्राधार पर कैबिनेट मिशन ने विधान-निर्माण के हेतु. संस्था का निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :—

(i) ब्रिटिश भारत के लिए भारतीय विधान-परिपद में कुल २६६ स्थान होंगे।

(अ) सेक्सन ए:--

| प्रान्त | श्राम | मुस्लिम | कुल |
|----------------|-------------------|----------------|--|
| मद्रास | 88 | × | 38 |
| बम्बई | 38 | २ | 23 |
| यू० पी० | 8= | | ሂ ሂ |
| विहार | ३१ | ¥ | ३६ |
| मी० पी० | १६ | 8 | ?৩ |
| ग ड़ीसा | 3 | ٥ | 8 |
| | (Annual Marketon) | - | designation of the last of the |
| | १६७ | २०. | १८७ |

नोट: किमश्नर-प्रान्तों—दिल्ली, अजमेर-मारावाड़ तथा कुग के तीन प्रतिनिधि इसमें श्रीर होंगे, जिससे कुल १६० होंगे।

(व) सेक्सन बी:-

| (,) ., | | | 1 | |
|------------|--|---------|-------|----------------------|
| प्रान्त | श्राम ' | मुस्लिम | ं सिख | छ ुल |
| पंजाब | 5 | १६ | 8 | २८ |
| उत्तरं पशि | चम | | | |
| सरहदी प्र | ान्त ० | ३ | ٥ | ą |
| सिन्ध | १ | 3 | 0 | 8 |
| | Safety Company of the | - | | disduscion asymmetre |
| ν . | 3 | २२ | 8 | 3.8 |

नोट: इसमें वेल्चिस्तान का एक प्रतिनिधि और होगा जिससे कुल ३६ होंगे।

१८२ हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेषण

(स) सेक्सन सी:-

| प्रान्त | श्राम | मुस्लिम | कुल |
|---------|-------|---------|-------------------|
| बंगाल | ₹:9 | ३३ | ६० |
| श्रासाम | હ | . ३ | १० |
| | | | spiniste spiniste |
| | 38 | ३६ | ७० |

(ii) विधान-परिषद में रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या ६३ से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iii) अन्त:कालीन सरकार की स्थापना :--

"शीघ से शीघ ही अन्तःकालीन सरकार की, जिसे प्रमुख राजनीतिक पार्टियों का समर्थन प्राप्त हो, स्थापना का बहुत अधिक महत्व देता है। इस सन्वन्ध में वाइसराय प्रयत्न कर रहे हैं, और शीघ ही इसे स्थापित करने की आशा करते हैं; जिसमें युद्ध-विभाग से लेकर सभी विभाग हिन्दुस्तान के नेताओं के हाथों में होगा—जिसे आम जनता का विश्वास प्राप्त होगा।

भारतीय विधान-परिषद और अन्तःकालीन सरकार की स्थापना

१६ मई की त्रिटिश घोपणा के प्रकाशित होते ही भारतीय राजनीतिक चेत्र में नयी चहल-पहल दिखायी देने लगी। देश भर में सममौते की नयी आशा की लहरें उठने लगी। यह प्रतीत होने लगा कि केवल त्रिटिश सरकार के साथ ही सममौता नहीं होगा, बल्कि शीच्र ही हिन्दू-मुस्लिम समस्या भी सुलम जायगी। इसमें ऐसी कौन-सी विशेषता थी जिससे लोगों में उक्त धारणा बनी थी। वाम्तव में पहले के और प्रस्तावों से यह अवश्य कुछ भिन्न रहा। इसकी विशेषता यह थी कि इसने न तो हिन्दुस्तान को विभाजित ही किया और न श्रविभाजित ही रखा। कांग्रेस और लीग दोनों को इसमें खुश करने का प्रयत्न किया गया था। अपने-अपने ख्याल के अनुसार इसकी व्याख्या करके इसे कार्यान्त्रित करके अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए प्रयोग करने की कल्पना करने लगे थे दोनों ने वायस-राय तथा ब्रिटिश सरकार से बहुत-सी बातों का स्पष्टीकरण करवाया। इसके उपरान्त ता० ६-६-४६ को सर्व-प्रथम अखिल

भारतीय मुस्लिम लीग की कौन्सिल ने १६ मई की कैंबिनेट मिशन की घोपणा के ऊपर एक प्रस्ताव पास किया और मिशन की इस बात—"पाकिस्तान का न वड़ा और न छोटा स्वतंत्र राज्य साम्प्रदायिक समस्याओं का इल कर सकता है"—का कड़ा विरोध करते हुए मिशन के इस विचार को "अनावश्यक, अन्यायपूर्ण तथा तर्कहीन" कहा, और साथ ही साथ "स्वतंत्र पाकिम्तान की स्थापना हिन्दुस्तान के मुसलमानों के अपिटवर्तित ध्येय हैं" की माँग को दोहराया, और "इसकी प्राप्त के लिए आवश्यकता पड़ने पर, हर प्रकार के उपाय को प्रयोग करेंगे और किसी प्रकार के त्याग तथा तंकलीफ को बहुत वड़ा नहीं समसेंगे।" साथ ही साथ इसमें इसने यह भी कहा कि "कैंबिनेट मिशन की आयोजना के अन्दर विधान-निर्माण के मशीन के साथ विधान-निर्माण में पूर्ण सहयोग मुस्लिम लीग करेगी, क्योंकि इससे यह आशा है कि अन्त में इससे पूर्ण, स्वतंत्र पाकिस्तान की स्थापना होगी।"

यहुत-सी वातों का स्पष्टीकरण होने के उपरान्त अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में अपनी व्याख्या के साथ राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रस्तावित विधान-परिपद में स्वतंत्र संयुक्त प्रजातान्त्रिक भारतवर्ष का विधान निर्माण करने के हेतु शामिल होना स्वीकार किया। साथ ही साथ १६ मई की घोषणा के बहुत से अंशों, विशेषतः केन्द्रीय सरकार के अधिकारों की सीमा तथा प्रान्तों के गुटबन्दी के ऊपर गहरा मतभेद प्रकट किया। यहाँ यह उल्लेख करना असंगत न होगा कि इस ऐति-हासिक घोषणा के अनुसार मजबूत केन्द्रीय संघ-शासन की स्थापना की सम्भावना नहीं थी। इसके अनुसार प्रत्येक प्रान्त में स्वायत्त शासन कायम करने की आयोजना थी। रज्ञा, वैदेशिक नीति, यातायत के साधन, वगैरह चन्द चीजों को छोड़-कर प्रत्येक प्रान्त अपनी आन्तरिक व्यवस्था का प्रवन्ध करने के लिए स्वतंत्र होता। इसके अतिरिक्त अगर कोई प्रान्त अथवा कई प्रान्त भारतीय यूनियन से खलग हो रर स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहते, तो इसका उन्हें पूर्ण अधिकार प्राप्त था, बशर्ति कि वहाँ के रहनेवालों का बहुमत अलग होने के पक्त में हो। राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्णतः इस घोषणा को स्वीकार किया था। कांग्रेस के इस प्रस्ताव में जो भाव दृष्टिगोचर होता था, उससे भिन्न भाव इसके अध्यत्त के भाषण से प्रकट होता था। राष्ट्रीय कांग्रेस के मूल प्रस्ताव और इसके अध्यन्न के भाषरा के बाच इस प्रकार की भिन्नता क्यों हुई ? यह कॉग्रेस के लिए स्वाभाविक ही था। इसके वर्गीय त्राचरण का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभी तक यह किसी वर्ग विशेष की वर्गीय पार्टी का रूप धारण नहीं कर सकी थी। अभी तक इसके प्रधानतः तीन वर्गीय रूप थे। जहाँ तक यह ब्रिटिश विरोधी श्रान्दोलन का संचालन करता रही थी, वहाँ तक भारतीय जनता की ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का प्रतिनिधित्व यह करती रही थी। जहाँ इसकी सदस्यता का प्रश्न था, वहाँ निम्न मध्यम वर्ग के सदस्यों का श्रधिक बहुमत था श्रीर इस दृष्टिकोण से यह निम्न मध्यम वर्ग का संगठन थी, श्रीर जहाँ इसके नेतृत्व का सवाल था, यह (इसका नेतृत्व) पूर्णतः पूँजीवादी सुधारवादी नेतृत्व था और इस दृष्टिकोण से यह पूँजीवादी संम्था थी। अतः यह किसी वर्ग-विशेष की संस्था नहीं थी, बल्कि राष्ट्रीय संगठन के रूप में अभी तक विद्यमान

शी। हम यह न भूलें कि परिवर्तित राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय भौतिक परिग्थित में इसने आन्दोलन की नीति को कर्तई छोड़ दिया था और पूर्ण रूप से यह सुधारवादी वैधानिक नीति को अपना चुशी थी। अतः भारतीय शोषित जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व यह नहीं कर सकती थी और न करती ही थी। हम ऊपर देख चुके हैं कि इसका पूँजीवादी-सुधारवादी नेतृत्व भारतवर्ष के सामप्रदायिक विभाजन के अधार पर भी भारतीय पूँजीवादी वर्ग के आपसी मेल और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ सगमीते के लिए ज्याकुल हो रहा था। अतः ब्रिटिश साम्राज्यवादी ऐतिहासिक घोषणा को पूर्णतः स्वीकार करना इसके लिए स्वाभाविक ही था। परन्तु भारतीय निम्न मध्यम वर्ग साम्प्रदायिक आधार पर भारत के विभाजन के पत्त में नहीं था। अतः उसे सन्तुष्ट करके सुधारवादी नेतृत्व के प्रभाव में रखने के लिए कांभेस के अध्यत्त का उस प्रकार का भाषण होना स्वाभाविक ही था।

डघर वायसराय अन्तःकालीन सरकार की स्थापना के हेतु राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के वीच सममीता कराने का प्रयत्न कर रहे थे। कुछ महत्वपूर्ण वातों के मम्बन्ध में लार्ड वेवल ने जिल्ला साहब को अश्वासन दे दिया था। ता० १६-६-४६ को अपने प्रयत्नों के अनुभव के आधार पर वायसराय ने अन्तःकालीन राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की एक आयोजना घोषित की कि उच जातीय हिन्दू और मुसलमानों के बराबर जगह सरकार में होगी, जिसमें राष्ट्रीय मुसलमान सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। सम्पूर्ण मुस्लिम जगहें मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों को प्रदान होंगी। इसे राष्ट्रीय कांग्रेस ने श्रस्वीकार किया। परन्तु मुस्लिम लीग ने इसे इस श्राशा से स्वीकार किया था कि बिना कांग्रेस के भी श्रन्त:कार्लान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना होगी।

परन्तु, कैबिनेट मिशन, जिसने लम्बे अरसे की आयोजना को प्रस्तुत किया था, बिना कांग्रेस के अन्त:कालीन सरकार की स्थापना के पत्त में नहीं था। ता० २६-६-४६ की इसने यह घोषित किया कि कुछ समय बाद फिर अन्तःकालीन संयक्त सरकार की स्थापना का प्रयत्न किया जायगा, तब तक के लिए सात सरकारी अधिकारियों की प्रवन्ध करनेवाली सरकार की नियुक्ति वायसराय करेंगे। इस घोषणा के उपरान्त १६ मई की घोषणा के उपर मुस्लिम लीग की स्वीकृति जिन्ना साहब ने वापस लेने का निश्चय कर लिया । श्रतः ता० २६-७-४६ वो श्रिखिल भारतीय मुस्लिम लीग की कौन्सिल ने कैबिनेट मिशन की १६ मई की घोषणा के उपर अपनी खीकृति वापस ले ली। श्रीर "पाकिस्तान हासिल करने, श्रपने अधिकार को कायम रखने, सम्मान को स्थापित करने, वर्तमान गुलामी से छुटकारा पाने श्रौर हिन्दू राष्ट्र की भावी गुलामी से बचने के हेतु "डाइरेक्ट एक्शन" (सीधी कार्यवाही) का प्रस्ताव पाम किया।"। "सीधी कारवाई" प्रारम्भ करने की तिथि भी १६ श्रगस्त सन् १६४६ निश्चय की गर्या। बंगाल की मुस्लिम लीगी सरकार ने १६ अगस्त को सरकारी छुट्टी दिवस एलान किया।

यहाँ पर यह उल्लेख करना ऋसंगत न होगा कि राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव और इसके ऋध्यत्त के भाषण की जैसी प्रति-किया मुस्लिम लीग के राजनीतिक त्रेत्र में हुई, वह ऋस्वाभाविक नहीं थी। कांग्रेस के प्रतिमुस्लिम लीग का सन्देह श्रीर भी वढ़ता गया। मुस्लिम लीग के अध्यक्त ।मि० जिन्ना ने इस ब्रिटिश घोपण। को स्वीकार करने से साफ इन्कार कर दिया था। उसने यह साफ-साफ एलान कर दिया कि १६ मई की ब्रिटिश घोपणा में जो ब्रिटिश भाव निहित हैं, उसे कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया है, बल्कि अपने ख्याली व्याख्या के साथ उसने स्वीकार किया था। अतः मुस्लिम लीग इसे स्वीकार नहीं कर सकती।

इसके बाद वायसराय ने इसका और भी सप्टीकरण किया। इसके उपरान्त कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने १६ मई की ऐतिहासिक घोपणा को वायसराय की व्याख्या के साथ स्वीकार किया। मि० जिन्ना और वायसराय के बीच काफी पत्र-व्यवहार तथा मुलाकातें हुई थीं। परन्तु अन्त तक मुस्लिम लीग ने घोषणा को स्वीकार करने से इन्कार किया था। ब्रिटिश सरकार की ओर से पहले यह एलान किया जा चुका था कि जितनी पार्टियाँ इसे स्वीकार करेंगी, उन्हें लेकर इसे कार्यान्वित करने का प्रयास किया जायगा। ता० २० द-४ को पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में बिना लीग के भी अन्तःकालीन सरकार की स्थापना की घोषणा वायसराय ने की और साथ ही साथ यह भी एलान किया कि जब ४६ मई की घोषणा मुस्लिम लीग स्वीकार करेगी, तब उसे पाँच जगहें प्राप्त होंगी।

इस घोषणा के अनुसार अन्तःकालीन राष्ट्रीय सरकार की स्थापना और स्वतंत्र भारत के भावी विधान के निर्माण के हेतु भारनीय विधान परिषद कायम होने वाला था। यहाँ हम यह न भूलें कि भारतीय आम जनता को भारतीय विधान-परिषद के सदस्यों को चुनने का अधिकार नहीं था अर्थात् आम भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित विधान-परिषद् की स्थापना नहीं हो रही थी, बल्कि १० फी सदी मुख्यतः पूँजीपित मध्यम वर्ग, जमींनदार और तालुकेदार, धनी किसान वगेरह द्वारा चुने हुए प्रान्तीय एसेम्बली के सदस्यों द्वारा निर्वाचित हुए प्रतिनिधियों और देशी रियासतों के नुमाइन्दों को लेकर भारतीय विधान-परिषद् की स्थापना होने जा रही थी। विधान-परिषद् के सदस्यों के प्रान्तीय एसेम्बिनयों द्वारा निर्वाचन में मुस्लिम लीग ने भाग लिया था। परन्तु जब इसकी कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी, तब मुस्लिम लीग ने शामिल होने से इन्कार कर दिया था।

इस ऐतिहासिक घोपणा के अनुसार केन्द्र में अन्तःकालीन राष्ट्रांय सरकार की स्थापना होना आवश्यक था। इसमें भी शामिल होने से मुस्लिम लीग ने साफ-साफ इन्कार कर दिया था। कांग्रेस के अध्यक्त श्री पं० जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सन् १६४६ ई० में दूसरी सितम्बर को प्रथम अन्तःकालीन अद्गं राष्ट्राय पूँजीवादी सरकार की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग द्वारा बाहण्कत होने के कारण कांग्रेस ने गैर मुस्लिम लीगी मुसलमानों को इसमें शामिलकर इसकी स्थापना की। इसकी खुशी में और भोली-भाली भारतीय जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए कांग्रेस ने हिन्दुस्तान भर में पहली दिसम्बर को घर-घर दीपावली मनाने का आदेश दिया था। बहुत हद तक इसे पालन भी किया गया था। दूसरी ओर सारे देश में घरों पर दूसरी सितम्बर को काला मंडा फहराने का आदेश अधिल भारतीय मुस्लिम लीग की और से दिया गया था।

:१६० हिन्दुस्तान श्रौर पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेषण

हिन्दुस्तान के अधिकांश मुसलमानों ने अपने-अपने घरों पर काले मंडे फहराये थे। एक और खुशी मनायी गयी और दूसरी और मातम। ऐसी परिस्थिति में दूसरी सितम्बर को गैर मुस्लिम लागी सदस्यों को लेकर कांग्रेस ने प्रथम अन्त:कालीन राष्ट्रीय सरकार को स्थापना की, जिसके साथ-साथ मारतीयों के हाथों में शासन-सत्ता सौंपने का सिलसिला प्रारम्भ किया गया था। अन्त:कालीन सरकार की स्थापना के उपरान्त भा हमेशा बायसराय तथा पंडित नेहरू जी मुस्लिम लीग को इसमें शामिल होने के लिए आमन्त्रित करते रहे।

हम देख चुके हैं कि प्रथम तो १६ मई की त्रिटिश साम्राज्य-बादी घोषणा का ऋखिल भारतीय मुस्तिम लीग ने स्वीकर कर लिया था। लेकिन ऋखिज भारतीय कांग्रेस कमेटी अस्ताव और इस ह अध्यत्त के भाषण के बाद मुस्लिम लीग को सन्देह होने लगा था। इसके अध्यव भि० जिल्ला ने यह ऐलान . किया कि अखित भारतीय कांत्रेस कमेटी के प्रस्ताव और इसके अध्यत्त के भाषण के बाद मुस्लिम लीग १६ मई की त्रिटिश घापणा को स्त्रीकार नहीं कर सकी थी। अतः श्रन्तः कालीन राष्ट्रीय सरकार में किसी प्रकार का भाग लेने से मुिलम लीग ने कर्तई इन्कार किया। राष्ट्रीय सरकार के अलावा विधान-गरिषद का भी इसने बहिष्कार किया, हालाँकि इसके चुनाव में इसने भाग लिया था और इसके सदस्य भार-ताय नियान-परिषद् के सदस्य चुने भी गये थे। मि० जिल्ला ने जारदार शब्दों में अपनी पूर्व माँगों को दोहराया और कहा कि हिन्दुरतान एक राष्ट्र नहां है, यहाँ हिन्दू-मुस्लिम दो राष्ट्र अलग-अलग हैं। मुस्तिम राष्ट्र किसी भी तरह सम्पूर्ण भारत

वर्ष के एक केन्द्रीय शासन को स्वीकार नहीं कर सकता। अगर वह ऐसा करता है, तो मुसलमानों के लिये हिन्दुओं की गुलामी स्वीकार करता है, जा किसी भी तरह सहन नहीं किया जा सकता था।

बिटिश सरकार के निखय के अनुसार मुस्लिम लीग के विहिच्चार के बावजूर भी यूनियन जैक के नीचे कांग्रेस के श्रध्यत्त श्री पं० जब हरलाल नेहरू के नेतृत्व में श्रन्त:कालीन राष्ट्रीय सरकार की स्थापना पहली सितम्बंर १६४६ ई० को को गयो। ब्रिटिश सरकार ने पहले ही यह घोषित किया था कि चाहे कोई दल न भी शामिल हो, इस घोषणा को कार्यान्त्रित किया जायगा। जत्र मुस्तिम लीग ने देखा कि इसके चहिष्कार करने की घोषणा करने पर भी पूँजीपति और त्रिटिश सरकार ने अन्तःकालीन सरकार की स्थापना की और मारतीय विधान-परिषद का निर्माण करने पर तुली हुई है, तब मुस्लिम म्राम जनता को साथ लेकर मुस्लिम लीग ब्रिटिश सरकार ऋौर हिन्दू पूँ जीवतियों पर पाहिस्तान की माँग की स्वीकार करने के हेतु दबाव डाजना चाहती थी। अन्तःकालीन सरकार की स्थापना के पूर्व १६ अगस्त को हिन्दुस्तान भर में मुस्लिम लीग की स्रोर से "डाइरेक्ट एक्शन डे" मनाया गया था, जिसके परिगाम-स्वरूप कई दिनों तक कलकत्ता में दोनों सम्प्रदायों के बीच कत्लग्राम हुआ था। यहाँ से हिन्दुस्तान भर में हिन्दू-मुस्लिम-युद्र प्रारम्भ हुआ था, जिसके त्रिषय में बाद में हम उल्लेख करेंगे।

दूसरी सितन्बर १६४६ ई० को भारतीय पूँजीवादी वर्ग के हाथों में भारतीय शासन-सत्ता हस्तान्तरिक करने का सिलसिला

१६२ हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेषण

"यूनियन जैक" के नाचे प्रारम्भ किया गया था। हस्तान्तरित करने का लिलसिला कांग्रेस के पूँजीवादी सुधारवादी नेतृत्व के द्वारा संचालित हो रहा था। हम पहले देख चुके हैं कि भारतीय शोधित-श्रमिक जनता इस नेतृत्व के प्रभाव से खलग होती जा रही थी। यह इसे अच्छी तरह खनुभव कर रहा था। खतः पहली सितम्बर को खाजादी के ऊषा-काल के रूप म मनाकर खाम जनता को खपने प्रभाव में इसने रखने को सोचा। राष्ट्रीय कांग्रेस की खोर से पहली सितम्बर को सारे देश में दीपावली मनायी गयी।

हम पहले कह चुके हैं कि मुस्लिम लीग द्वारा लगातार यह प्रचार किया गया था कि समूचे भारतवर्ष के एक केन्द्रीय शासन-सत्ता की व्यापना का अर्थ है मुसलमानों के लिए हिंदुओं की गुलामी, जिसे हिन्दुस्तान के मुसलमान बद्धारत नहीं कर सकते। अतः जब पहली सितम्बर को अन्तःकालीन राष्ट्रीय सरकार के रूप में भारतीय केन्द्रीय शासन की स्थापना होने जा रही थी, उस समय उक्त भावना को दृढ़ करने के हेतु हिन्दुस्तान में प्रत्येक मुस्लिम घर पर काला मंडा फहराने का आदेश अधिकां भारतीय मुसलमानों ने इसे पालन किया। घरों में उन्होंने मातम मनाया। इसके फलस्वरूप मुसलमानों में साम्प्रदायिकता का विष रूपी वृत्त और भी फेल गया था।

हम देख चुके हैं कि बिना मुस्लिम लीग के भा कांग्रेस के नेत्रत्व में अन्तःकालीन सरकार की स्थापना हो चुकी थी। परन्तु अभी तक विधान-परिषद की बैठक प्रारम्भ नहीं हुई थी। हम देख चुके हैं कि इसके चुनाव में मुस्लिम लीग ने भाग

लिया था और इसके काफो सदस्य चुने भी गये थे। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसमें भाग लेने से साफ-साफ इन्कार कर दिया था। श्रन्त:कालीन सरकार की स्थापना के उपरान्त इसमें और विधान परिषद में शामिल होने के लिये बिना १६ मई की घोषणा की श्रास्वीकृति के श्रपने प्रस्ताव को वापस लिये ब्रिटिश सरकार ने लीग के साथ काफी बातें कीं। इसके परिणामस्वरूप अन्त:कालीन सरकार में अक्टूबर में मुल्लिम लीग शामिल हुई, जिसके बाद बास्तव में केन्द्रीय सरकार दो गुटों में विभाजित हो गई। वायसराय द्वारा नेहरूजी को आस्वासन देने पर कि अन्त:-कालीन सरकार में शामिल होने पर मुस्लिम लीग विधान परिषद में अवश्य शामिल होगी, परन्तु इसके अध्यन मिहार जिला ने अस्वीकृति के प्रस्ताव की वापस लेने के लिये कोई भी कदम नहीं उठाया। भारतीय राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के उपरान्त वायसराय जन्दन बुलाए गये। इनके साथ-साथ मुस्तिम लीग के अध्यत्त मिस्टर जिन्ना और भारत के प्रधान मन्त्री, श्री जवाहरलाल नेहरू भी वहाँ बुलाये गये। ये दोनों भी लएडन पहुँचे। वहाँ एक गोलमेज कानफ्रेंस हुई, जिसमें नेहरू जा और जिल्ला साहेब शामिल हुये। लीग और कांग्रेस के बीच सममौते की कोशिश की गई। इसकी असफलता के बाद ता० ६-१२-४६ ई० को ब्रिटिश सरकार ने यह घोषित किया कि प्रान्तों के गुटबन्दी की व्यवस्था को स्वीकार कर्ने को प्रत्येक बाध्य हैं। गुटों में बोट की प्रथा सदस्यों की बहुमत से होगा, श्रान्तों का विधान प्रत्येक पान्त के प्रतिनिधि के द्वारा नहीं बनेगा बिलेक पूरे गुट के द्वारा। वायसराय तथा जिल्ला साहव लन्दन में ही रुक गये और पंडित नेहरू जी भारत वापस आ गये।

१६४ हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेषण

ता० ६-१२-४६ को "यु नेयन जैक" के नीचे डाक्टर सिच्चदा-नन्द सिनहा की अध्यक्ता में भारतीय विधान परिषद की प्रथम ऐतिहासिक बैठक स्वतंत्र भारत के भावी विधान के निर्माण करने के हेतु प्रारम्भ हुई। इसके प्रथम अध्यक्त के और प्रथम भारतीय प्रधान मन्त्री के भाषण के उपरान्त इसके श्थाई अध्यक्त का निर्वाचन हुआ। डाक्टर राजेन्द्रप्रसादजी सर्वसम्मति से भारतीय विधान परिषद के ऐतिहासिक अध्यक्त निर्वाचित हुए। इसके उपरान्त इनकी अध्यक्तता में स्वतंत्र भारत के भावी विधान तैयार करने का कार्य शुक्त किया गया।

२० फरवरी की ब्रिटिश घोषणा

१६ मई की बिटिश सरकार की ऐतिहासिक घोषणा होने के उपरान्त राष्ट्रीय सरकार और विधान परिषद में मुस्लिम लीग को शामिल करने के हेनु विटिश सरकार की ओर से काफी प्रयत्न हुआ। लेकिन ये सब व्यर्थ साबित हुये थे। अन्तः- कालीन सरकार के कायम होने के बाद भी प्रयत्न होता रहा। अन्तः में अन्तः कालीन सरकार के कायम होने के बाद भी प्रयत्न होता रहा। अन्तः में अन्तः कालीन सरकार में शामिल होने के लिये मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया था। गैरमुन्लिम लीग मन्त्रीगण त्यागपत्र देकर अलग हो गये मुस्लिम लीग के बीच हमेशा संघर्ष चलता रहा। एक ओर मुस्लिम लीग अन्तः कालीन सरकार में शामिल था और दूसरी और विधान परिषद को वहिएकार किये हुए थी। सरकार में एक साथ होने पर भी लीग और कांग्रेस में मेल नहीं था। हमेशा अन्दर और बाहर संघर्ष चल रहा था। केन्द्रीय सरकार में कभी-कभी आन्त्रिक संघर्ष इतना विकट हो जाता था कि प्रधान मन्त्री इस्तीफा देने

को भी तैयार हो जाते थे। उधर ६ दिसम्बर १६४६ को ब्रिटिश घोषणा को प्रान्तीय स्वतंत्रता के विपरीत सममते हुए कांग्रेस ने ता० ६-१-४७ को एक प्रस्ताव द्वारा इसे भी स्वीकार किया। साथ ही साथ पंजाव, वंगाल और आसाम के विरोध का सामना करने के लिये प्रान्त को तथा प्रान्त के अंश को कर्य की खाजादी भी दे दी।

यह प्रस्ताव भो मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिये पर्याप्त नहीं था। ता० ३१--१-४० को मुस्तिम लीन की कार्य-कारिएी कमेटी ने एक बड़ा प्रस्ताव पास किया कि "विधान परिषद का चुनाव और उसके बाद इसकी बैठक अवैधानिक है। इसे जारो रहना और इसके निर्णय सब के सब अवैधानिक होंगे। अतः शोध से शीध इसे भंग कर देना चाहिये। इस प्रस्ताव के बाद अन्त:कालीन सरकार के अन्दर भारी संकर उत्पन्न हो गया। यह प्रश्न उठना स्वामाविक दी था कि जो पार्टी "डाइरेक्ट एक्सन" की आयोजना करती है. वह इसके अन्दर कैसे रह सकती है। इसे स्पष्ट करने के हेतु नेहरूजी ने कांग्रेस की त्रोर से वायसराय की लिखा कि संयुक्त व्यन्तःकालीन सरकार की परम्परा का मुस्लिम लीग ने उलंघन किया है, जो नेहरूजी को वायसराय द्वारा दिये गये आश्वासन के विपरीत है। क्या लीग के कराँची के घातक प्रस्ताव के बाद भी मुस्लिम लीग अन्तःकालीन सरकार में कायम रह सकती है ? इन सभी परनों का स्पष्टीकरण करने को वायसराय को कहा गया। इसके बाद मुस्लिम लीग की श्रोर से सरकार को लिखी गया कि लीग के सदस्य यह मानते हैं कि अगर १६ मई की घोषणा की स्वीकृति ही गाप है तो मुस्लिम लीत ने सर्व- प्रथम इसे स्वीकार किया था, जिसे बाद में वापस ले लिया क्योंकि किसी और पार्टी ने इसे स्वीकार नहीं किया। दूसरी और उनका कहना है कि किसी भी समय कांग्रेस ने इसे स्वीकार नहीं किया। है और न ६ जनवरी के प्रस्ताय के ही द्वारा इसने इसे स्वीकार किया। वर्तामान परिस्थित में लीग के सदस्यों की अन्तः कालीन सरकार के अन्दर बने रहने का उतना ही अधिकार है जितना कांग्रेस के सदस्यों का। वायसराय ने लीग के इस पत्र का भी लन्दन भेज दिया। इसके पूर्व पंडित नेहरूजी का पत्र भेजा जा चुका था। इसके उपरान्त प्रेस प्रतिनिधियों के बीच शी सरदार बल्जमभाई पटेल ने कहा कि अगर ऐसी हालत में सुस्तिम लीग अन्तः कालीन सरकार में बनी रहती है, तो कांग्रेस इससे अलग हो जायगी।

विदिश कैबिनेट के आगमन के उपरान्त भारतीय साम्प्र-दायिक-राजनातिक समस्याएँ और भी उलमती गईं। इसे सुलमाने के हेतु ता० २०-२-४७ की विदिश मजदूर प्रधान मन्त्री एटली ने निम्निजिखित घोषणा की:—' यह अति दुख की बात है कि अभी भी सरकार देखती है कि हिन्दुस्तान की पार्टियों के बीच काफी मतभेद फैला हुआ है, जा विधान परिपद के कार्य में रुकावट डाल रहा है, इसका जैसा कार्य होना चाहिये था वैसा नहीं हो रहा है। यह आयोजना का तत्व है कि विधान परिपद पूर्णक्ष से प्रति-निध्य करे

"लेकिन कै बिनेट मिशन की आयोजना के अनुसार ब्रिटिश सरकार सभी पार्टियों द्वारा स्थीकृत विधान के द्वारा स्थापित अधिकारों के हाथों में शासन सत्ता सौंपना चाइती है। लेकिन अभाग्यवश यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि इस प्रकार के विधान तथा अधिकार का उदय होगा। अनिश्चयता की वर्तमान परि-न्थिति खतरा से खाली नहीं है और यह अनिश्चय काल के लिये जारी नहीं रखी जा सकती है। ब्रिटिश सरकार यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि यह उसकी निश्चय राय है कि सन् वह १६४५ के जून तक जिम्मेदार हिन्दुस्तानियों के हाथों में शासन-सत्ता सौंपने का प्रयत्न करेगी। ""ऐसी सरकार, जो जनना के समर्थन पर कायम हो, जो व्यवस्था तथा शान्ति कायम रख सकेगी, और जो न्याय तथा चमना के सथ शानन प्रवत्य कर सकेगी, के ही हाथों में शासनसत्ता सौंपने के जिये ब्रिटिश सरकार इच्छुक है। इसिलये यह आवश्यक हो जाता है कि सम्भी पार्टियाँ अपने मत-सेद को दूरकर के शासन का बोक उठाने के लिये प्रस्तुत हो जायें, जो दूसरे साल आने वाली है।

" लेकिन अगर यह ज्ञात हो कि ऐसा विधान पूर्ण विधान परिषद के द्वारा समय निश्चय के पूर्व तैयार नहीं हो सकता, तो बिटिश सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि किस-के हाथ में यह भारत के केन्द्रीय शासन का भार निश्चित कर सौंपे। बिटिश भारत के किसी प्रकार की केन्द्रीय सरकार के पूर्णक्ष्म में या कुछ चेत्रों में मीजूदा प्रान्तीय सरकारों या दूसरी तरह, जो हिन्दुस्तान की जनता के हित में हा …

"यह भी घोषित किया गया कि युद्ध के उपरान्त लाई वेवल की नियुक्ति खत्म की जाय और इनके स्थान में एडिमिरील विस्कोन्ट मीन्टवैटन की नियुक्ति की जाती है और मार्च के महीने में यह शासन प्रवन्ध की जिस्मेदारी प्रहण करने।"

ता० २२-२-४० को इस घोषणा पर वक्तव्य देते हुचे नेहरूजी

१६८ हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेपण

ने कहा कि यह "बुद्धिमतापूर्ण तथा साहसी कार्य है।" उन्होंने कहा कि विधान परिषद के कार्य को श्रीर भी तीत्रता के साथ बढ़ाना चाहिये। जो लोग श्रभी तक इससे श्रलग हैं, उन्हें इसमें शामिल होने के लिये उन्होंने श्रावाहन किया कि डर श्रीर शंका को त्यागकर इस ऐतिहासिक कार्य में वे हाथ वटावें।

दूसरी श्रोर २० फरवरी की ब्रिटिश घोपणा के उपरान्त मुस्लिम लीग सन् १६४५ ई० के जून के बाद ब्रिटिश शासन-सत्ता के खत्म होने के उपरान्त सिन्ध में स्वतंत्र राज्य घोपितकर मुस्लिम लीगी सरकार कायम करने का प्रयत्न करने लगी। इस विचार से सिन्ध के शिच्चा मन्त्री ने मिस्टर जिल्ला से एक विधान परिपद की नियुक्ति के हेतु श्रमुगेध किथा, जो स्वतंत्र सिन्ध राज्य के लिये स्वतंत्र भावी विधान तैयार करेगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी लिखा कि श्रंप्रेजों के जाने के बाद राज्य-शक्ति हस्तांतरित करने के लिये हम श्रामी से तैयार हों।

इसके उपरान्त देश में विशेषतः पंजाब में साम्प्रदायिक युद्ध विकट रूप प्रह्मा करने लगा।

पजाब और बंगाल के विभाजन की माँग

जब हिन्दू पूँजीपितयों ने यह सममा कि बिना पाकिस्तान स्वीकार किये मुस्लिम पूँजीपितयों के साथ समभौता नहीं हो सकता। हिन्दू और मुस्लिम पूँजीपितयों के बीच एकता कायम करने के लिये पाकिस्तान की माँग स्वीकार करना आवश्यक ज्ञात होने लगा। हिन्दू पूँजीपितयों ने अपने आर्थिक स्वार्थ के लिये यह आवश्यक सममा था कि

जहाँ तक सम्भव हो सके, वहाँ तक कम से कमा चेत्र पाकिस्तान में हो। श्रतः सर्वप्रथम सिखों के श्रकाली दल ने पंजाब के विभाजन की माँग पेश की। इसे समर्थन करते हुए कांग्रेस के सुधारवादी पूँजीवादी नेतृत्व ने यह माँग वेश का कि अगर पाकिस्तान की स्थापना होती है, तो जिस श्राधार पर यह स्थापना होगी. उसी त्राधार पर पंजाब स्त्रीर वंगाल को भी विभाजित किया जाये। वंगाल के जिन जिलों में मुसलमान बहुमत में हैं, वह तो पाकिस्तान में हो खार जिन जिलों में हिन्दू बहुमत में हैं, वह हिन्दुस्तान में शामिल किया जाये। पंजाब और बंगाल के साम्प्रदायिक आधार पर विभाजन की मॉग का कांग्रेस के पूँजीवादी सुधारवादी नेतृत्व ने भारतवर्ष के साम्प्रदायिक त्राधार पर विभाजन को स्वीकार किया और श्याम मुस्लिम जनता के ऊतर यह असर पैरा किया कि मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की माँग भारतीय मुसलमानों के जीवन के विकास और उन्नत के लिये उचित और आव-श्यक है।

२० फरवरी की घोनिटिश पणा के उपरान्त राष्ट्रीय कांमेस की कार्यकारिणों की बैठक ता० ८-३-४७ को हुई श्रीर इसकी श्रोर से २० फरवरी की घोषणा के ऊपर निम्नितिखित प्रकाव प्रकाशित किया गया:—'राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य-कारिणी कमेटी ने इस घोपणा का स्वागत किया, जिसमें सन् १६४८ ई० के जून तक भारतीयों के हाथों में राज्य-सत्ता हस्तांतरित कर देने की निश्चित इच्छा व्यक्त की गई श्रीर इसके इष्टिकीण से आगे के सभी कदम चठाये जायेंगे।……इस प्रस्ताव में यह भी वहा गया है कि निटिश कैविनेट मिशन की

२०० हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेषण

१६ मई की आयोजना को कांग्रेस पहले स्वीकार कर चुकी थी और इसके बाद ६ सितम्बर की बिटिश कैबिनेट की १६ मई की घोषणा की व्याख्या को भी स्वीकार कर चुकी है। इसके अनुसार विधान परिषद भाी विधान के निर्माण के कार्यों में व्यस्थ है।

विधान परिषद का कार्य ऐच्छिक है। बहुधा कार्यकारिणी कमेटी ने यह घोषित किया है कि इसके लिये कोई बाध्य नहीं किया जा सकता। " यह स्पष्ट कर दिया गया है कि विधान परिपद द्वारा निर्मित विधान केवल वहाँ लागू होगा, जहाँ यह स्वीकृत होगा। यह भी सोचना चाहिये कि कोई भी प्रान्त या किसी प्रान्त का कोई भी हिस्सा, जो इसे स्वीकार करता है और जो संव (यूनियन) में शामिल होना चाहता है, ऐसा करने से रोका नहीं जा सकता। अतः किसी भी तरह का दबाब नहीं होगा। और जनता अपने भविष्य का स्वतः निर्णय करेगी।

इस घड़ी में जब अन्तिम निर्णय करना है और हिन्दुस्तानियों के दिमाग तथा हाथ से भा त का भविष्य गढ़ित होने जा रहा है, कांग्रेस कायकारिणी कमेटी सभी दलों, गुटों और खास तौर से सभी भारतीयों से यह माँग करती है कि हिन्सात्मक तथा प्रतिरोधी तरीकों को छोड़ दें और विधान तैयार करने में शान्तिपूर्ण तथा प्रजातान्त्रिक तौर से सहयोग करें। निर्णय करने का समय आ गया है, कोई इसे रोक नहीं सकता, न अलग रह सकता और न अलूना ही रह सकता है। " कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिलने के लिये मुस्लिम लीग को इसने निमन्त्रित किया। " और इसके सम्बन्ध में प्रस्ताव में कहा कि नये विकास की दृष्टि से, जो तीव्रता के साथ

भारतीयों के हाथों में शासन-सत्ता हस्तान्तरित कर देने के लिये हो गहा है, यह भारतीयों के लिये ऋति आवश्यक हो गया है कि सामूहिक तथा सहयोगी के ह्रप में इसके लिये तैयारी करें, जो सभी के लिये हितकर होगा।

साथ ही साथ कांग्रेस कार्यकारिग्णी कमेटी ने पंजाव के विभाजन की भी माँग की।

साम्प्रदायिक दंगा

२०वीं सदी के पूर्व हिन्दू-मुस्तिम दंगे का नाम कभी सुनने में नहीं आता था। हाँ ! जब से २०वीं सदी में ब्रिटिश विरोधी श्रान्दोलन चलने लगा था श्रोर श्रान्दोलन को बन्दकर मध्यम वर्गीय नेतृत्व ने सुवारवादी वैधानिक पथ में देश को ले जाने का प्रयत्न किया, उस समय देश में साम्प्रदायिक दंगे होने लगे। प्रथम साम्राज्यवादी युद्ध के श्रवसर पर एक श्रोर-मशस्त्र क्रान्ति का प्रयत्न विफल हो गया था और दमन के द्वारा क्रान्तिकारी शक्तियाँ बुरी तरह कुचली गई थीं, दूसरी श्रीर युद्ध काल में मध्यम वर्ग तथा मध्यम वर्गीय राष्ट्रीयसुधार-'वादी नेतृत्व ने जी-जान से ब्रिटिश सरकार को साम्राज्यवादी-युद्ध संचालन में महायता की थी और युद्ध के उपरान्त भारतीय विधान में कुछ सुधार होने वाला था। ऐसी मौतिक परिस्थिति में सन् १६१७ ई० के सर्वप्रथम भारतवर्ष में हिन्दू-मुस्लिम दंगा आरम्भ हुआ था। और तब से आज तक विभिन्न रूप में सर्वदा होता रहा है। हिन्दुस्तान में हिन्दू-मुस्लिम दंगे के इतिहास के विश्लेषण से यह स्पष्टतः ज्ञात होता है कि जब कभी भारतीय जनता की क्रान्तिकारी शक्तियों के दबाव से ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक सुधार रूपी रोटी के दुकड़े फेंके हैं, उस समय

मध्यम वर्ग तथा बुद्धिजीवी वर्ग भी आपस में बाँटने के प्रयत्न में साम्प्रदायिक दंगे का शरण लेते रहे। इससे यह भी विदित होता है, कि जब तक सुधार रूपी रोटी के दुकड़े के बटवारा करने का प्रश्न भारतीय मध्यम तथा बुद्धिजीवी वर्ग के सामने रहा, तब तक साम्प्रशायिक दंगे का रूप एक प्रकार का रहा था। किन्तु भारतीय समाज के साधानिक जोवन की भौति ह अवस्था के परिवर्तन के साध-साथ राजनीतिक अवस्था में भी मौलिक परिवर्तन होना आवश्यक था। सन् १६३७ ई० के पूर्व भारतीय समाज की भौतिक तथा राजनीतिक अवस्था एक प्रकार की थी और साम्प्रदायिक दंगे का रूप भी उसके अनुसार ही रहा करता था। परन्तु सन् १६३७ ई० के उपरान्त भारतीय समाज के भौतिक तथा राजनीतिक अवस्था में मौलिक परिवर्तन ज्ञात हो रहा था। अतः हिन्दूग्रुस्लिम दंगे का रूप भी परिवर्तित हो गया था।

द्वितीय साम्राज्यवादी युद्ध काल में भारतीय पूँजीवाद ने काफी विकास तथा प्रगति की थी। भारतीय विधान में राजनीतिक सुधार केवल होने से भारतीय पूँजीवाद तथा पूँजीवादी वर्ग की स्नावश्यकता पूरी नहीं हो सकती थी। युद्ध के उपरान्त इसके सामने राजनीतिक सुधार प्राप्त करने का प्रश्न नहीं था खिल भारतीय शासन-सत्ता के हस्तान्तरित होने का प्रश्न था। बिना भारतीय शासन-सत्ता के हस्तान्तरित होने का प्रश्न था। बिना भारतीय पूँजीवाद तथा पूँजीवादी वर्ग का विकास तथा प्रमति सम्भव नहीं ज्ञात होती थी। उधर भारतीय शोषित-श्रमिक जनता का त्रिटिश विरोधी जन-स्नान्दोलन दिन प्रति-दिन उपतर होता जा रहा था, जिसकी प्रवलता तथा भया-

नक रूप को अनुभव करके बिटिश सरकार के साथ-साथ भारतीय पूँजीवादी वर्ग भी दृश्त उठा था। वर्षों तक संसार- ठयापी साम्राज्यवादी युद्ध के संवालन के परिणाम-स्वरूप बिटिश साम्राज्यवाद पहले जैसा शांकशाली नहीं रहा था। युद्ध के उपरांत भारत जैसे औपनिवेशिक देश में साम्राज्यवादी शासन नायम रखना बिटिश साम्राज्यवाद के लिय कठिन सा हो गया था। अपनी परिवर्तित भौतिक अवस्था में साम्राज्यवादी शोषण भारतवर्ष में कायम रखना बिटिश सरकार के लिये सम्भव नहीं ज्ञात होना था। अतः राष्ट्रीय और अन्तर्शिक्ष मौतिक परिस्थिति से बाध्य होकर सन् १६४६ ई० वी १६ मई को भारतीयों के हाथों में शासन-सत्ता सौंप देने की घोषणा बिटिश सरकार ने की थी। भारतीयों के हाथों में शासन-सत्ता हस्तांतरित होने का सिलसिला पहली सितम्बर सन् १६४६ ई० को इस ऐतिहासिक घोषणा के अनुसार प्रारम्भ होने जा रहा था।

परन्तु भारतीय पूँजीशद के विकास तथा प्रगति के साथ-साथ भारतीय पूँजीवादी वर्ग का च्यान्तरिक संघर्ष क्षेत्रतर होता गया। यह इतना तीत्र हो गया था कि च्याविभाजित हिन्दुस्तान के रहते हुए उनके वीच सममौता सम्भव नहीं ज्ञात होता था। सुस्लिम पूँजीपति पूँजीशदी संसार में च्यपने विकास तथा प्रगति के लिये साम्प्रदायिक च्याधार पर भारतवर्ष का विभाजन च्यावश्यक सममता था। परन्तु हिन्दू-पूँजीपति च्यीर ब्रिटिश साम्राज्यवाद भारत-विभाजन को च्यपने लिये लाभदायक नहीं सममते थे। हिन्दुस्तान च्यीर पाकिस्तान के रूप में भारत विभाजन को वे खांकार करने के लिये तैयार नहीं थे। सुस्लिम

२०४ हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का एतिहासिक विश्लेपण

मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि मुस्लिम लीग ने यह सममा कि विना उसके भी अन्तःकालीन राष्ट्रीय सरकार और भारतीय विधान परिषद की स्थापना कांग्रेस के नेतृत्व में होने जा रही है, जिसे मुसलमानों के लिये वह घातक वताने लगी । एक श्रोर तो सममौते की बातें हो रही थीं श्रौर दूसरी श्रोर सारे देश में साम्प्रदायिक दंगे की तैयारी तथा संगठन किया जा रहा था। साम्प्रदायिक दंगे के संचालन तथा संगठन के लिये ऋखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने केन्द्रीय "कौन्सिल आफ ऐक्सन" की नियुक्ति की थी, जिसकी शाखा प्रत्येक प्रान्त में स्थापित की गई थी। यहाँ हम यह न भूलें कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किसी प्रकार के आन्दोलन को संचालित करने के हेतु मुस्लिम ंलीग की 'कौन्सिल खाफ ऐक्सन" की स्थापना नहीं की गई थी। हम उत्पर कह चुके हैं कि भारतीय पूँजीवादी वर्ग का स्रान्तरिक संघर्ष ब्रिटिश स्त्रीर भारतीय पूँजीवादी वर्ग के बीच के संघर्ष से कहीं ज्यादा तीत्र हो गया था, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आन्दोलन चलाने का उनके सामने प्रश्न नहीं था। चल्कि मुख्य प्रश्न था आन्तरिक संघष के संचा-लन का। अतः हिन्दू-मुस्जिम दंगे को मंचालित तथा संगठित करने के लिये ही मुस्लिम लीग से कौन्सिल आफ ऐक्सन की स्थापना की थी।

उत्पर के विश्लेषण से यह सफ्ट होता है कि साम्प्रदायिकता के निप-वृत्त के बीजारोपण, विकास तथा फैलाव की जिम्मेदारी वेशक बिटिश सरकार की फूट पैदा करके शासन करने की नीति, मुस्लिम लीग के प्रतिक्रियाबादी नेतृत्व के साथ-साथ राष्ट्रीय कांग्रेस की पूँजीवादी सुवारवादी वैधानिक नीति के ऊपर अवश्य रही है। परन्तु साम्प्रदायिक दंगे की जिम्मेदारी से वामपद्मी बरी नहीं हैं। भारतीय स्टाजिनवादी (कम्युनिस्ट) के अपर सबसे ज्यादा इसकी जिम्मेदारी है। सन् १६३७ ई० के उपरान्त यह लगातार कांग्रेस-लोग के समभौते का नारा ब्रुलन्द करते रहे। सन् १६४० ई० में पाकिस्तान की माँग का प्रस्ताव पास करने के उपरान्त विशेषतः १६४२ ई० से तो कांत्रेस-लीग सममौतापर विशेष जोर लगाया। सन् १६४६ ई० में जब मुस्लिम लीग पाकिस्तान के आधार पर केन्द्रीय तथा प्रान्तीय एसेम्बली का चुनाव लड़ रही थी, उस समय भी राष्ट्रीय मुस्लिम के खिलाफ मुस्लिम लीग का केवल समर्थन ही उन्होंने नहीं किया बल्कि पूरा सहयाग देकर पाकिस्तान की माँग का समर्थन किया। मुस्लिम लीग के प्रतिक्रिणवादी नेतृत्व के प्रभाव को आम मुस्तिम जनता के ऊपर मजबूत करने में कम्युनिस्टों का बर्त बड़ा हाथ रहा है। एक ओर मुस्लिम लीग देश भर में साम्प्रदायिक दंगे के संचालन तथा संगठन की तैयारी कर रही थीं, दूसरी श्रोर स्टालिनवादी कांत्रेस-लीग-कम्युनिस्ट एकता का नारा बुलन्द कर रहे थे। भारतीय स्टालिनवादियों की क्रान्ति-विरोधी नीति ने सामप्रदायिक दंगे को विकसित होने में सहायता की, जिसे इतिहास चमा नहीं कर सकता ।

तथाकथित वामपत्ती भारतीय समाजवादी भी साम्प्रदायिक विष-वृत्त के फैलने के लिये कुछ ऋंश तक जिम्मेदार अवश्य हैं। आगस्त क्रान्ति और नेताजी सुभाप चन्द्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिन्द फीज के आक्रमण के उपरान्त, जब भारतीय शोषित जनता के साथ विश्व संघात करके भारतीय पूँजीवादी

२०६ हिन्दुस्तान श्रीर पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेषण

वर्ग ब्रिटिण साम्राज्यवादी-पूँजीवादी वर्ग के साथ क्रान्तिकारी जनशक्तियों के खिलाफ प्रतिक्रियावादी गुट का निर्माण करने में व्यस्त था, उस समय वामपिच्यों का यह ऐतिहासिक कार्य था कि सन् १६४२ ई० की क्रान्ति से थारतीय शोषित जनता की विकसित राजनीतिक चेतना को क्रान्तिकारी वर्ग नथा समाजवादी चेतना में रूपान्तरित करना आवश्यक था। परन्तु भारतीय समाज या कांग्रेस सोशितिस्टों ने ऐसा न करके पूँजीवादी सुधारवादी नेतृत्व के प्रभाग में भारतीय जनता को रखने का प्रयत्न करते रहे। श्रातः ये भी साम्प्रदायिक दंगे के लिये कम जिम्मेदाग नहीं हैं।

सन् १६४६ ई० की पह नो सितम्बर को सुस्तिम लीग के विना अन्तःकालीन राष्ट्रीय सरकार की स्थापना राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में होने जा रही थी। इसके खिलाक आम मुस्लिम जनता को करने के लिये ऐतिहासिक तिथि १६ आ स्त को हिन्दुस्तान भर में मुस्तिम लीग की ओर से "डाइरेक्ट ऐक्सन डे" मनाया गया था। जिन प्रान्तों में मुस्लिम लीगी मन्त्रिमंडल था, वहाँ पर इसके लिये विशेष रूप से तैयारी की गई थो। मुस्तिम लीगी मन्त्रियों ने अपनी शिक्त को इसके संचाजन में प्रयोग किया था। बंगाल के मुस्लिम लीग मंत्रिमंडल ने विशेषतः वहाँ के प्रधान मन्त्री सुहरावदीं ने काफी तैयारी तथा संगठन किया था। कलकत्ता के पुलिस हेड क्वार्टर में ४८ घंटे तक रह कर फोन से साम्प्रदायिक दंगे को १६-१७ अगस्त को संचालित किया था, जिसके विषय में अखबारों में काफी उन्लेख हो चुका था। परन्तु इसका परिणाम मुस्लिम लीग के विपरीत हुआ था। हिन्दुओं से कहीं उयादा मुसलमानों का कत्ल हुआ था। मुस्लिम

लीग की मकसद हासिल नहीं हुई थी।

प्रथम साम्प्रदायिक युद्ध के संचालन के उद्देश्य की पूर्ति में मुस्लिम लीग कलकत्ता में असफल रही था । बंगाल में हिन्दुओं के लिये सबसे कमजोर स्थान नावाखाजी बगैरह को मुस्लिम लीग ने अपने आक्रमण का निशाना बनाया। यहाँ के प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में दूसरे साम्प्रदायिक युद्ध की तैयारी तथा संगठन होने लगा। मुस्लिम लीग के देख-भाज में आखो-जना तैयार की जाने लगी। इसके परिणामस्त्रह्म सैकड़ों हिन्दू कत्ल किये गये। हाहाकार मचा। यही ज्ञात होता था कि धर्म के नशा ने मनुष्य को इन्धान से हैवान बना दिया था। वह यह भूल गये थे कि वह इन्सान हैं। यह दंगे नहीं हो रहे थे बल्कि इसने कलकत्ता से ही साम्प्रदायिक युद्ध का रूप अप-नाया था। व्यक्तिगत हमले इसकी विशेषता नहीं थो, बल्कि इसकी विशेषता सामृहिक आक्रमण था।

हिन्दुग्तान के और प्रान्तों में नोवाखाली वगैरह के साम्प्रदा-यिक युद्ध की बहुत बुरी प्रतिक्रिया हुई थी। सर्वप्रथम इस प्रति-क्रिया का शिकार बिहार हुआ। यहाँ स्पष्ट रूप में साम्प्रदायिक युद्ध होने लगा। बिहार के कई जिलों में एक साथ यह युद्ध होने त्ता। हजागें मुस्लिम मारे गये। जो बचे थे, उनमें अधिकांश अपने घर को छोड़कर भाग गये थे। दूसरे स्थानों में शरणार्थी जीवन व्यतीत करने को बाध्य हुए थे। यहाँ और भी मनुष्यता को दबाकर मनुष्य की राह्मसी प्रवृत्ति काफी प्रवृत्त हो उठी थी और मनुष्यता का एकदम लोप कर दिया था। इहिन्दू सभ्यता का मुख्य आधार सहनशीलता का कहीं नाम भी नहीं था। सचमुच साम्प्रदायिकता तथा धर्म के नशा में मनुष्य

२०८ हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेपण

पागल हो उठा था। नावाखाली की प्रतिक्रिया बिहार तक ही सीमित नहीं रही थी। संयुक्त प्रान्त में भी यह हुइ। विशेपतः गढ़मुक्तेश्वर इस प्रतिक्रिया का बुरी तरह शिकार हुआ था।

साम्प्रदायिक युद्ध तक ही अपने कार्य-क्रम की मुस्लिम लीग ने सीमित नहीं रख छोड़ा था। बल्कि इसके अलावे और भी इसके कार्य-क्रम थे । जिन प्रान्तों में मुस्लिम बहुमत था श्रीर वहाँ गैरमुस्लिम लीगी मन्त्रिमंडल था वहाँ उसके खिताफ जन-श्रान्दोलन को संचालित तथा संगठित करके उसे हटाने का प्रयास मुस्लिम लीग कर रही थी। सर्वप्रथम पंजाब अपेर फ्रान्टियर की प्रान्तीय सरकार इनका शिकार होने लगी। फ्रान्टियर में कांग्रेसी मन्त्रिमंडल और पंजाब में युनियनिए-कांग्रेसी संयुक्त मन्त्रिमंडल था। पंजाब के मित्रमंडल ने मुस्लिम लीग के नेशनल गार्ड श्रीर राष्ट्रीय स्वयंसेयक संघ को गैरकानुनी घोषित कर दिया था और दफा १४४ लगा दिया था। नागरिक स्वतंत्रता के नाम पर मुस्लिम लीग ने इसका विरोध जन-त्रान्दोलन का संवालन करके किया। हजारों की तादाद में मुसलमान जेलों के सीकचों के भीतर बन्द कर दिये गये थे। इसके परिणाम-स्वरूप पंजाव मन्त्रिमंडल खत्म कर दिया गया और गवर्नर-शासन कायम किया गया था। अभी तक यह आन्दोलन गान्तीय सरकार के खिलाफ सीमित था परन्तु मन्त्रिमंडल के खत्म होने और गवर्नर-शासन केकायम होते ही इस त्र्यान्दोलन ने पंजाव के पश्चिमी जिलों में साम्प्र-दायिक युद्ध का रूप ऋपना लिया। उधर फ्रान्टियर, के कांग्रेसी मन्त्रिमंडल के खिलाफ मुस्लिम लीग का आन्दोलन चल रहा था। बहुत से मुसलमान जेलों में भरे गये। ३ जून की ब्रिटिश

सरकार की ऐतिहासिक घोषणा के उपरान्त मुस्लिम लीग का यह ज्यान्दोलन बन्द किया गया था।

एक श्रोर तो मुस्लिम लीग अन्तःकालीन राष्ट्रीय सरकार में शामिल होकर अन्दर से विभिन्न प्रकार का श्रवृङ्गा डाल रही थी श्रीर भारतीय विधान परिषद का विहण्कार किये हुए थी। दूसरी श्रोर देश भर में वह साम्प्रदायिक युद्ध को संगठित एवं संचालित कर रही थी। अजव परिस्थिति पेदा हो रही थी। ज्यादा दिन तक इसे जारी रखना भारतीय समाज के लिये विशेषतः भारतीय पूँजीवादी वर्ग के लिये बहुत ही घातक गिरमाणित होता। यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिये भी कम श्रानिकारक नहीं था। अतः ब्रिटिश सरकार श्रीर भारतीय पूँजीवादी वर्ग की राय से सन् १६४० ई० की अन्त में, भारतीय पूँजीवादी वर्ग की राय से सन् १६४० ई० की ३ जून को ब्रिटिश सरकार में विदिश सरकार भी कारतीय पूँजीवादी वर्ग की राय से सन् १६४० ई० की ३ जून को ब्रिटिश सरकार में अन्त में की हिटिश सरकार भी स्वारा की निर्देश सरकार भी स्वारा की स्व

३ जून को अंतिम ब्रिटिश घोषणा

पंजाब में साम्प्रदायिक युद्ध बन्द होने के बजाय तीत्रतर होता गया। मार्च के तृतीय सप्ताह में पं नेहरूजी ने लाहौर में प्रेस प्रतिनिधियों के बीच बोलते हुए कहा, "पंजाब में जो कुछ हो रहा है उसका सम्बन्ध भारतीय राजनीति है।" तये वायसराय मौन्टबैंटेन मार्च के चौथे सप्ताह के प्रारम्भ में पधारे। शपथ लेने के उपरान्त दिल्ली के शाही दरबार भवन में ता० २४–३–४० को बोलते हुए उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के अन्दर भारतीय समस्या का समाधान अवश्य प्राप्त होगा। प्राप्ते कहते हुये उन्होंने कहा कि सन् १६४८ ई० के जून तक

२१० हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेयण

शासन-सत्ता भारतीयों के हाथों में हस्तांनरित कर देने का निश्चय ब्रिटिश सरकार ने कर लिया है। इसके लिये नये वैधानिक प्रवन्य अवश्य करना है और शासन-सम्बन्धी बहुत से पेची रे सवालों को हल करना है, जो शीघ्र ही काम में लाया जायेगा, जिसका स्पष्ट अर्थ है, कुछ महीनों के अन्दर हल खोज निकालना।

इसके बाद ता० २४-३-४७ को वायसग्रय ने नेहल्जी तथा मियाँ लियाकत चली सं बातें को। ता० २७-३-४७ को मि० जिल्ला ने पाकिस्तान के आधार पर संधि के लिये आबाहन किया। ता० ३-४-४७ को मिस्टर जिल्ला के पाकिस्तान के आधार पर सन्धि के लिये आबाहन पर चहमदाबाद में बोलते हुए सरदार पटेल ने कहा कि "पाकिस्तान का सिद्धांत एक बहुत बड़ा मजाक है" और "एक बच्चे का खेत हैं।" केवल न्याय के आधार पर हो पाकिस्तान की स्थापना हो सकती है, न कि तलवार के वल से।

बंगाल को हिन्दू और मुग्लिम बंगाल में विमाजित करने की माँग बंगाल से उठने लगी। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में वंगाल की प्रांतीय कांग्रेम कार्यका रिगी कमेटी ने निम्नलिखन प्रस्ताय पास किया कि बिटिश सम्कार मीजूदा बंगाल सरकार के हाथों में शान्त-सत्ता सींपने को मोच रही है, जो स्तंत्र पृथक् बंगाल राज्य की स्थापना के लिये हद है फिर जिस प्रकार में यह गढ़ित है वह एक साम्प्रदायिक पार्टी सरकार है। बंगाल का ऐसा हिस्सा, जो भारतवर्ष के संघ (यूनियन) में रहना चाहती हो, रहने देना चाहिये और हिन्दुस्तान के संघ (यूनियन) में एक अलग प्रान्त के रूप में गढ़ित करना चाहिये।

पंजाब के कांग्रेसी तथा सिख नेताओं ने पंजाब धारा समा में कहा कि पंजाब की कठिन राजनीतिक स्थिति का एक मात्र हल है पंजाब का विभाजन। उधर कांग्रेस और लीग के वीच सममौते का प्रयत्न बायसराय कर रहे थे।

जिल्यानवाला बाग दिवस पर बोलते हुये नेहरूजी ने कहा कि समय अब ऐसा आ गया है कि हम इधर या उधर का निर्णाय करें। यह समय की आवश्यकता की मग है कि बहुत सी राजनीतिक पार्टियों के जिम्बेदार व्यक्ति एक गोलमें ज कान्प्रें स में बैठकर अन्तिम निर्णाय करें। ...

उन्होंने दुख के साथ कहा कि करीब ४० दिन पहले कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटी ने वातें करने के लिय लोग को निमन्त्रित किया था, लेकिन इसका जवाब लोग ने नहीं दिया। "आगे उन्होंने कहा कि मुन्लिम लीग के पाकिस्तान का सवाल केवल दो तरह से—पारस्परिक वाद-विवाद के या युद्ध के द्वारा—ही हल हो सकता है, कोई तीसरा रास्ता नहीं है। "" देश में साम्प्रदायिक युद्ध के ऊपर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसके पहले भी हिन्दुस्तान में दंगे हुये थे, लेकिन वे इतने बड़े नहीं थे, जैसा आज देश में हो रहा है। सन् १६४६ ई० के अगस्त से साम्प्रदायिक दंगा ने एक नया रूप अपनाया है। जब से लोगों ने समक्ता कि तीव्रता के साथ हिन्दुस्तान परिवर्तित हो रहा है, उस समय से ही दंगे प्रारम्भ हुए। सम्भवतः यह इसलिये कि कुछ दलें दवाब डालना चाहता हैं और कुछ अंश में यह चाहती हैं कि ब्रिटिश यहाँ से चले जायँ।

२१२ हिन्दुस्तान श्रौर पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेषण

आगे नेहरूजी ने कहा कि अब यह समय आ गया है कि हम यह निर्णय कर लें कि हम संयुक्त भारत चाहते हैं या विभाजित। यह सवाल शीघ से शीघ तय हो जाना चाहिये। हम किसी प्रान्त या देश के किसी भी अंश को यह नहीं चाहते कि वह दिन्दुस्तान में या पाकिस्तान में शामिल हो। सिन्ध ने सन् १६४८ इ० के जून में ऋंग्रेजों के चले जाने के बाद स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी है। "इसी प्रकार बंगाल और पंजाब के कुछ हिस्स अलग होना चाहते हैं। उन्हें ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता है। इन सब के बावजूद देश भर में विशेषतः पंजाब में साम्प्रदायिक युद्ध विशाल रूप श्रपनाता जा रहा था। इसे शान्त करने का प्रयत्न वायसराय कर रहे थे। इसके फलस्वरूप गांधीजी तथा जिन्ना साहब ने संयुक्त रूप से साम्प्रदायिक युद्ध को बन्द करने की भारतीय जनता से अपील की:-- "हम देश भर में फेले हुए हिन्सा तथा भ्रष्टता के कार्यों से काफी दुः स्वी हैं, जिसने हिन्दुस्तान के स्वच्छ नाम को कलंकित किया है और जिसने बिना किसी प्रकार का विचार किये भारतीय जनता के ऊपर श्रकथनीय कठिनाई ला दी हैं।

"हम सर्वदा राजनीतिक हित की सिद्धि के लिये हिन्सा को इस्तेमाल करने का विरोध करते रहे हैं, श्रीर हिन्दुस्तान के सभी सम्प्रदायों के लोगों—चाहे जिस धर्म के मानने वाले हों—को श्रावाहन करते हैं कि वे केवल हिन्सा के कार्यों श्रीर श्रायाजकता से ही दूर न रहें बल्कि वह कोई उभाइने वाली बातें न कहें श्रीर न लिखें।"

हस्ताचर—एम० ए० जिन्ना

हस्ताचर-एम० के० गांधी

ता० १६-४-४० को सूरत में भाषण देते हुए सरदार पटेल ने मुस्लिम लीग से कांग्रेस के निमन्त्रण पर गौर करने का अनुरोध किया और कांग्रेस के साथ बातें करने के लिये प्रति-निधि भेजने को कहा, जिससे गजनीतिक मसले मैत्रीपूर्ण ढंगसे हल हो जायँ। अगर ऐसा हम नहीं करते तो सन् १६४८ ई० के जून तक राज्य सत्ता हस्तांतरित करने के लायक हम नहीं हो सकेंगे। ""कुछ समय तक और भारत में रहने को ब्रिटिश सोचेंगे।

उत्तर-पश्चिम सरहदी प्रान्त में कांग्रेसी मन्त्रिमंड ज को हटाने के हेतु मुस्लिम लीग को ओर से कांग्रेसी सरकार के जिलाफ आन्दोलन चलाया जा रहा था, जिससे साम्प्रदायिक युद्ध और भी भभक उठा था। हजारों की संख्या में मुसलमान जेलों में बन्द थे। गांधी-जिन्ना अपील के उपरान्त उत्तर-पश्चिम सरहदी प्रान्त की सरकार ने एक प्रेस वक्तव्य में कहा कि "गांधी-जिन्ना अपील के साथ सरहदी प्रान्तीय सरकार दिल से साथ होती है और प्रान्त की जनता से अनुरोध करती है कि व इसकी सच्चाई वा प्रतिवादन करें।.....

"अपनी त्रोर से उसके अनुसार, जो राजवन्दी हिन्सात्मक कार्य के सम्बन्ध में जेलों में बन्द नहीं हैं, उन्हें विना शर्त के छोड़ देने का निश्चय करती है।

"शान्तिपूर्ण सभा तथा राजनैतिक विचारों को व्यक्त करने की आजादी में किसी प्रकार का विष्न डालने का विचार सर-कार का नहीं है।"

दिल्ली में एक आम सभा में भाषण करते हुए डाक्टर श्यामाचरण मुकर्जी ने बंगाल-विभाजन की माँग की और कहा २१४ हिन्दुस्तान श्रोर पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेषण

कि इसके सिवाय दूसरा और कोई हल नहीं है।

ता० २४-४-४० को जिल्ला साहब ने मुस्लिम लीग के कार्य-कत्तांश्रों से अनुरोध किया कि "कई दिनों तक वायसराय से वातें होने के फलस्वरूप सरहदी सरकार ने उक्त घोपणा की है। "वायसराय वहां की परिस्थित स्वयं अनुभव करने के हेतु वहाँ जा रहे हैं। " मैं आम मुसलमानों से और विशेषतः मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताश्रों से अमन-चैन तथा शान्ति बनाये रखने का अनुरोध करता हूँ, जिससे वायसराय को परिस्थित के सममने का पूरा मौका मिल सके।"

ता० ३०-४-४८ को भारतीय विधान परिषद के अध्यद्य श्री डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने प्रस प्रतिनिधियों की भेंट में कहा कि "अगर भारत का विभाजन होता है तो यह जितना सम्भव तथा पूर्ण हो सके, उतना हो, जिसमें बंगाल तथा पंजाब विभाजन शामिल हो, जिसमें किसी प्रकार के मगड़े के लिये गुँजाइश न रह जाये। पंजाब और बंगाल के विभाजन की जोरदार माँग के उठते ही मुश्लिम लीग परेशान होने लगी। वही सहरावदीं, जो कलकत्ता के कल्ल-आम के लिये जिम्मेदार हैं, तथा अन्य मुश्लिम लीगी नेतागण शान्ति कायम रखने के हेतु अपील करने लगे।"

वायसराय के प्रयत्न के फलस्वरूप ता० ६-५-४० को गांधी-जिल्ला मिलन हुआ। इस मिलन की असफलता के उपरान्त गांधीजी की स्वीकृति से जिल्ला साहब ने यह वक्तव्य प्रकाशित किया कि "दो बातों पर हमने बातें की। एक थी पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में भारतवर्ष को विभाजित करने की बात। गांधीजी विभाजन के सिद्धान्त को नहीं स्वीकार करते हैं। वह सोचा हैं कि भारत का विभाजन अनिवार्य नहीं है। लेकिन में पाकिस्तान को केवल अनिवार्य ही नहीं सममता बल्क भारतवर्ष की राजनीतिक समस्या का एकमात्र हल है। दूर्रा चीज यह है, जो बातें हमने की हैं यानी एक पत्र जिस पर हमने हस्ताचर किया है जिसमें शान्ति बनाये रखने की अपील जनता से की है और इस सम्बन्ध में हम इस निर्ण्य पर पहुँचे हैं कि हम अपने-अपने चेत्र में यह प्रयत्न करें कि हमारी अपील मानी जाय और इसके लिये हम पूर्ण प्रयत्न करें।"

ता० १०-४-४७ को शिमला के वायसराय भवन से यह प्रकाशित हुआ कि ता० १७-४-४७ को वायसराय ने नेहरूजी, जिल्ला साहब, सरदार पटेल, लियाकत अली, तथा सरदार बलदेवसिंह को मिलने के लिये बुलाया है। ता० ११-४-४७ को नेताओं का मिलन स्थिगत कर दिया गया। ता० ११-४-४७ को सरदार पटेल को जवाब देते हुए मिस्टर जिला ने कहा कि अगर ब्रिटिश सरकार भारतवर्ष के विभाजन करने का निश्चय करती है, तो केन्द्रीय सरकार को भंग कर देना होगा और सभी सत्ता दो विधान परिषदों के हाथों में दे देना होगा, जो हिन्दुस्तान और पाकितान में बनेगी और उनका प्रतिनिधित्य करेगी।

ता० १४-४-४७ को ब्रिटिश सरकार ने वायसराय को लन्दन बुलाया। पंजाब में सिखों तथा मुसलमानों के वीच सममौता करवाने के लिये वायसराय ने पटियाला के महा-राजा को जिल्ला साहेब से बातें करने को भेजा परन्तु सफल नहीं हुए।

२१६ हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का ऐति इासिक विश्लेषण

ता० १८-४-४० को वायसराय लन्दन के लिये रवाना हुए। यहाँ उनकी श्रायोजना के साथ काफी सम्मत थी। ता० १६-४-४० को मद्रास में भाषण करते हुए राजेन्द्र बाबू ने कहा कि श्रगर पंजाब श्रोर बंगाल का विभाजन मुस्लिम लीग नहीं मानती, तो कांग्रेस भारतवर्ष के विभाजन को नहीं स्वीकार करेगी। ता० २१-४-४० को बंगाल श्रोर पंजाब के विभाजन का विरोध मि० जिल्ला ने किया श्रोर पंजाब तथा बंगाल को मिलाने के हेतु यू०, पी० तथा विहार से दहलीज (Corridor) की माँग की।

ता० २३-४-४७ को राजेन्द्र बाबू ने इसका विरोध किया।
मुस्लिम लीग की श्रोर से अन्तःकालीन सरकार के कानून-मंत्री
श्री योगेन्द्र मंडल, हरिजन नेता ने बंगाल के विभाजन का
समर्थन किया।

ता० ३०-४-४७ को प्रार्थना-भवन में गांधीजी ने यह घाषित किया कि १६ मई की घाषणा के अनुसार विधान परिपद कार्य कर रहा है। आगे गांधीजी कहते हैं कि ४६ मई की घोषणा के कांग्रेस तथा सरकार ने स्वीकार किया है, जो इससे पीछे हट गया, वह दूसरे के साथ अविश्वास करेगा।

यह हम देख चुके हैं कि २० जनवरी की बिटिश-बोषणा भी हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक प्रश्न को हल नहीं किया बल्कि इससे और भी उलक्ष गया। यह भी हमने देखा है कि एक और तो अन्तःकालीन राष्ट्रीय सरकार में शाभिल होकर अन्दर से मुस्लिम लीग अड़ङ्गा लगा रही थी। अभी तक विधान परिषद का विरोध मुस्लिम लीग कर रही थी और दूसरी और सार देश में साम्प्रदायिक युद्ध का संचालन और संगठन मुस्लिम लीग के नेतृत्व में हो रहा था। लीग श्रीर कांग्रेस के बीच सममौते के सारे प्रयत्न विफल रहे। उस समय के मौजूदा वायसराय लार्ड वावेल ब्रिटेन को वापस बुला लिया गया श्रीर लार्ड माउन्टबैटेन वायसराय के पद पर नियुक्त किये गये। यहाँ पदापण करने के बाद लार्ड माउन्टबैटेन ने लीग श्रीर कांग्रेस के नेताश्रों से काफी बातें की श्रीर उन्होंने यह भलीभाँ ति श्रनुभव किया कि कांग्रेस-लीग सममौते पूँजी-वादी वर्ग की श्रान्तरिक श्रमंगितयों के कारण कर्त्व सम्भव नहीं हैं। साम्प्रदायिक श्राधार पर पाकि तान श्रीर हिन्दुस्तान में भारतवर्ष के विभाजन के बिना साम्प्रदायिक प्रयत्न के रूप में भारतीय पूँजीवादी वर्ग का श्रान्तरिक राजनीतिक ममला हल नहीं हो सकता था। श्रतः लाचार हो कर हिंदू पूँजीपतियों श्रीर ब्रिटिश साम्राज्यवादी-पूँजीवादी वर्ग भारत-विभाजन करने को प्रस्तुत हो गये थे। सन् १६४० ई० की ३ जून को ब्रिटिश सरकार ने निम्रालिखित घोषणा की:—

(१) "ता० २०-२-४७ को बिटिश भारत में हिन्दुस्तानि में के हाथों में सन् १६४८ ई० के जून तक शासन सत्ता दे देने की घोषणा की गई था, श्रीर यह आशा की थी कि १६ मई की कैबिनेट मिशन की श्रायोजना को कार्यान्वित करने में प्रमुख पार्टियाँ सहयोग करेंगी श्रीर भारतवर्ष के लिये एक विधान तैयार करेंगी, जो सभी के वीकार करने योग्य होगा। यह श्राशा नहीं पूरी हुई।

(२) "मद्रास, संयुक्त प्रान्त, सी० पी० श्रीर बरार, श्रासाम, उड़ीसा, बिहार श्रीर उत्तर-पश्चिम सरहद प्रान्त, श्राजमेर-मारवाड़ तथा कुर्ग के श्रिधकांश प्रतिनिधियों ने नये २१८ हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेषण

विधान तैयार करने में काफी प्रगति की है। दूसरी ऋोर मुस्लिम लीग पार्टी तथा बंगाल और पंजाब के अधिकांश प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लेने से इन्कार कर दिया है।

- (३) "यह सर्वदा ब्रिटिश सरकार की इच्छा रही कि हिन्दुस्तानी जनता की इच्छा के अनुसार शासन-सत्ता सींपा जाय। भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच सममौते हो जाने से यह कार्य सरल हो जाता। इसके अभाव में भारतीय जनता की इच्छा के अनुसार शासन-सत्ता सींपने की आयोजना तैयार करने का ब्रिटिश सरकार के ऊपर आयो है। भारतवर्प के नेताओं के साथ पूर्ण परामर्श के उपरान्त निम्निलिखत आयोजना लागू करने का निश्चय ब्रिटिश सरकार ने किया है। यह स्पष्ट कर देती है कि यह किसी प्रकार का भारतवर्ष के लिये अन्तिम विधान तैयार करने की इच्छा नहीं रखती है, यह तो भारतीयों का काम है और न इस बायोजना में संयुक्त भारत के लिये सम्प्रदायों के बीच सममौते के लिये प्रस्तावना ही करती है।
- (४) "मौजूदा विधान परिषद के कार्य में किसी प्रकार का विझ डालने का ख्याल ब्रिटिश सरकार का नहीं है। सरकार यह आशा करती है कि इस घोषणा के उपरान्त मुस्लिम लीग विधान परिषद में अवश्य शामिल होगी।

विभाजन की आयोजना

(४) "बंगाल श्रीर पंजाब के प्रान्तीय धारा सभा (इन यूरोपियन सदस्यों के श्रलाब)—इनमें से प्रत्येक दो हिस्से में बैठेगी, एक में मुस्लिम बहुमत जिलों के प्रतिनिधि श्रीर दूसरे में प्रान्त के बाकी हिस्सों के प्रतिनिधि बैठेंगे। प्रान्त की

आवादी का निर्णय करने के लिये सन् १६४७ ई० का जन-गणना अधिकार रूप में माना जायगा। इस घेषणा के परि-शिष्ट में मुस्लिम लीग बहुमत जिलों का नाम दे दिया गया है।

- (६) "प्रत्येक प्रान्तीय धारा सभा के दो भागों में बैठे हुए सदस्यों को प्रान्त विभाजित हो या नहीं पर बोट देने का अधिकार होगा। अगर दोनों हिस्सों में कोई भी भाग के मदस्यों का बहुमत प्रान्त के विभाजन के पन्न में मन देता है तो विभाजन माना जायगा और इसके लिये प्रवन्ध किया जायगा।
- (७) "विभाजन के प्रश्न पर निर्णय करने के पूर्व प्रत्येक हिस्से के प्रतिनिधियों का यह जानना आवश्यक है कि दो भागों के संयुक्त प्रान्त रखने के निर्णय के उपरान्त प्रान्त किस विधान परिषद में शामिल होगा। इसके लिये अगर कोई सदस्य ऐसी माँग पेश करे, ती प्रान्तीय धारा सभा के सभी सदस्यों (यूरोपियन सदस्यों को छोड़कर) की वैठक होगी, जिसमें यह निर्णय किया जायगा कि प्रान्त किस धारा-सभा में शामिल होगा। अगर इसके दोनों भाग एक ही साथ रहने का निर्णय करें।
- (११) "उत्तर-पश्चिम सरहदी प्रान्त की अवस्था भिन्न है। इसके तीन सदस्यों में से दो भारतीय विधान परिषद में भाग ले रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि इसकी भौगालिक स्थिति तथा अन्य दूसरी चीजों को देखते हुए, अगर पंजाब का कोई भी भाग पूर्णतः मौजूदा विधान परिषद में शामिल नहीं होने का निर्णय करता है, उस समय उत्तर-पश्चिम सरहदी प्रान्त को फिर से विचार करने का अवसर देना आवश्यक हो जाता

है। इसके अनुसार, ऐभी हालत में मौजूदा प्रान्तीय धारा के वोटर मत देंगे कि यह किस विधान परिषद में शामिल हो। जनमत लेने का प्रवन्ध प्रान्तीय सरकार की सलाह से गवर्नर-जनरल के मातहद होगा।

(१२) "ब्रिटिश बेल्चिस्नान का सदस्य मौजूदा विधान परिषद में बैठ रहा है। इनका मौगोलिक परिस्थिति के कारण इस पर फिर विचार करने का इसे अवस्य देना चािये कि यह किस विधान परिषद में शामिल हो। यह कैसे हा सकता, इस पर गवर्नर जेनरल गौर कर रहे हैं।

(१३) "यदापि श्रास म प्रधाननः गैरमुस्लिम प्रान्त है। इसके सिलहट जिले में, जो बंगान से मिला हुआ है, श्रिधकांश मुसलमान रहने हैं। यह माँग रही है कि बंगाल के विभाजन के उपरान्त इसे बंगाल में मुस्त्रिम भाग के साथ मिला देना चाहिये। इसके श्रमुक्त, श्रगर बंगाल का विभाजन निश्चय हा जाना है, तो श्रासाम की प्रान्तीय सरकार की सलाह से गवर्नर-जेनरल के मातहद सिलहट जिले में जनमत लेग होगा कि क्या यह श्रासाम का श्रंश होकर रहेगा या पूर्वीय बंगाल के नये प्रान्त में शामिल होगा। श्रगर यह प्रान्त स्वीकार करे श्रीर पूर्वीय बंगाल में शामिल होने के पत्र में जनमन होता है, तो बंगाल श्रीर पंजाब को तरह सीमा-निर्धारण कमीशन नियुक्त होगा।

दिल्ली से बोलते हुए वायसराय ने इस घोषणा को भारतीय जनता के सामने पेश किया। कांग्रेस की छोर से इसका स्वागत करते हुए पंडिन नेहरूजी ने भारतीय जनता से इसे स्वीकार करने की छापील की छोर कहा कि गांधीजी भी इससे सहमत हैं। मिस्टर जिन्ना ने भी अपनी व्यक्तिगत स्वीकृति प्रकट करते हुए कहा कि इस पर लाग क निसल शीघ ही निएए करेगी। ता० ४-६-४६ का प्रार्थना के बाद गांधीजी ने देश को इसे स्वीकार करने की सलाइ दी और कहा कि इसे कांग्रेस द्वारा स्वीकृत होने के कारण वे कांग्रेस के खिलाफ बगावत न करें बल्कि आज की परिध्यित में वे इसमें इसके साथ खड़े हों।

ता० ७-६-४७ को वायसराय ने हिन्दुस्तान के सात नेताओं से बातें की कि भारत-विभाजन के सम्बन्ध में क्या कर्म उठाया जाये। ता० ६-६-४७ को मुस्लिन लीग की कौन्तिल ने ३ जून की ब्रिटिश त्रायोजना को स्वीकार किया, साथ ही साथ प्रान्तों के विभाजन पर रोष व्यक्त किया। ता० १२-६-४७ को पैथिक ऐसम्बली पार्टी, श्री सिरोम ए त्राकाली दल की कार्यकारणी तथा प्रतिनिधि पैन्थिक बोर्ड को संयुक्त कान्फ्रोन्स हुई। उसमें पंजाब के विभाजन के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया। साथ ही साथ यह भी ऐलान किया गया कि पंजाब का ऐसा विभाजन, जो सिख सम्प्रदाय को विभाजित करेगा, सिख सम्प्रदाय सहन नहीं करेगा।

ता० १४-६-४७ को द्याखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई। ३ जून की ब्रिटिश घोषणा को स्वीकार करने की इसे सलाह देते हुए गांधीजी ने कहा कि यह ख्याल रखना चाहिये कि कांग्रेस कार्यकािणी कमेटी उनके प्रतिनिधि के रूप में है। वह इसे स्वीकार कर चुकी है। यह त्राखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कर्तव्य है उनके पीछे खड़े होना। अगर इस परिस्थिति में यह इसे अस्वीकार कर देती है, तो संसार क्या सोचेगा। सभी दलों ने इसे स्वीकार किया है। यह

कांग्रेस के लिये अपनी बांतों से पीछे हटना उचित नहीं होगा। अगर आप लोग इने काफी महसूस नीं करते, और इसे अस्वीकार कर दिशा तो यह देश के लिये घानक होगा। इसका परिणाम यह होगा कि आप लोगों को नये नेता तलाश करना होगा, जो केवल कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटी को नहीं बनायेंगे, बल्कि शासन की भी जिम्सेदारी ले सकें। अन्त में, आखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ३ जून की घोषणा स्वीकार किया।

ता० १६-६-४७ को कांश्रेस कार्यकारिणी कमेटी की बैठक हुई, उसने एक प्रस्ताव हारा उत्तर-पश्चिम सरहदी प्रान्त में जनमत तेने का विरोध किया।

ता० २३-६-४० की पंजाब एसेन्बलों के पूर्वी पंजाब के सद्-स्यों की एक बैठक हुई और ४० सदस्यों ने पंजाब के विशाजन के पद्म में और २२ सदस्यों ने विभाजन के विषद्ध में मत दिया। पश्चिमी पंजाब के सदस्यों ने बहुमत से पंजाब िभा-जन के विरुद्ध में प्रस्ताव पास किया। पंजाब एसेन्बली की बैठक में इसके ६१ सदस्यों ने नये विधान परिपद में और ७७ सदस्यों ने मीजूदा विधान परिपद में शामिल हाने के पद्म में मत दिया।

ता० १-७-४७ को सेना सम्बन्धी यह निर्णय किया गया कि १४ श्रमस्त से श्रीर जब तक सेना का विभाजन पूरा न हो जाये, तब तक, मौजूदा, कमांडर-इन-चीफ, संयुक्त सेना का सुश्रीम कमार्डर होगा।

भारतवर्ष में सभी मौजूदा सेना एक प्रबन्धकर्त्ता नियन्त्रण के तब तक मातहद होगी, जब तक यह दो स्पष्ट हिस्सों में विभाजित न हो जाये, श्रीर दोनों सरकार इसके प्रयन्ध—पेतन, भोजन, कपड़ा, श्रीर हथियार वगैरह से श्रपनी सेना को सुसज्जित करने – के लायक न हो जाँय। [क्योंकि दानों—हिन्दुस्तान तथा पाकिस्तान में पूँजीवाद तथा पूँजीवादी व्यवस्था को सुरक्तित रखने के लिये यह करना उनके लिये श्रावश्यक था।]

ता० ४-७-४७ को ब्रिटिश पार्लियामेग्ट में भारतीय स्वतंत्रता का जिल पेश किया गया, जिसके अनुसार हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दो अलग-त्रलग उपनिवेश कायम हुए ता० १०-७-४७ को ब्रिटिश पार्लियामेन्ट ने यह घोषित किया कि मिस्टर जिल्ला पाकिस्तान के गवर्नर-जेनरल और माउन्ट-बैटेन हिन्दुस्तान के गुवर्नर-जेनरल मुस्त्रिम लीग तथा कांग्रेस की सिफारिश से नियुक्त किये गये। ता० १३-७-४७ को सिलहट जिजा ने पूर्वी वंगाल में शामिल होने का निर्णय किया। ता० १४ ७-४७ को विधान परिषद के चौथे सेशन में मुस्लिम लीग भी शामिल हुई। तां० १४-७-४७ को भारतीय स्वतंत्रता कानून (बिल) पास हो गया। ता० १४-७-४७ को इसे सम्राट् की स्वीकृति प्राप्त हो गई श्रीर पार्लियामेन्ट से यह घोषित किया गया और तब से दो उपनिवेश अस्तित्व में आये । ता० १६-७-४७ को अन्त:कालीन सरकार की स्थापना की गई। इसकी घोषणा वायसराय-भवन से की गई।

ता० २०-७-४७ को उतरी-पश्चिमी सरहदी प्रान्त में जनमत लंने के उपरान्त प्रतिशदी ४० ४६ ने पाकिस्तान में शामिल होने के पत्त में मत दिया।

२२४ हिन्दुस्तान ऋौर पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेपण

इस घोषणा के अनुसार सन् १६४७ ई० के १४ अत्रा को साम्प्रदायिक आधार पर पाकिस्तान श्रीर हिन्दुस्तान की स्था-पना होने जा रही थी। इसके अनुसार पंजाब और बंगाल हिन्द और मुस्लिम में बाँटा जायेगा। जिन जिलों में मुसलमान बहुमत में हैं, वे जिले पाकिस्तान में शामिल किये गये और जिन जिलों में हिन्दू बहुमत में थे, वे जिले हिन्दु ग्तान में शामिल किये गये। ऋासाम प्रान्त में जहाँ मुस्लिम बहुमत रहा, वहाँ इस बात पर जनमत लिया जायेगा कि वहाँ के लोग पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या हिन्दुस्तान में। अभी तक उत्तरी-पश्चिमी सरहदी प्रान्त के मुसलमान कांग्रेस के प्रभाव में थे। वहाँ के बारे में इस घोषणा के अनुसार प्रान्त भर में इस बात पर जनमत लिया जायेगा कि वहाँ के लोग पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहते हैं यह हिन्दुरतान में। यह सब १४ अगम्त के पूर्व समाप्त हो जाना था। साथ ही साथ १४ अगस्त के पूर्व पाकिस्तान श्रीर हिन्दुस्तान की सीमा भी निर्धारित हो जाती थी।

कांग्रेस, लीग और ब्रिटिश सरकार के नुमाइन्दों को लेकर घोषणा के बाद तुरन्त सीमा निर्धारित कमेटी का निर्माण हुआ, जिसने बिना बिलम्ब कार्य प्रारम्भ कर दिया था । उत्तरी-पश्चिमी सरहदी प्रान्त और आसाम के मुस्लिम बहुमत भागों में जनमत लिया गया और वे पाकिस्तान में शामिल होने के पद्म में मत दिया। इस ऐतिहासिक घोषणा के अनुसार भार-तीय शासन-सत्ता भारतीयों के हाथों में हस्तांतरित होने को थी। अतः १४ अगस्त को हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में शासन-सत्ता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के हाथों में हस्तांतरिक की गई, जिसका सिर्लासला सन् १६४६ ई० की पहली सितम्बर को प्रारम्भ हुआ था और सन् १६४७ के १४ अगस्त को समाप्त हुआ।

१५ अगस्त, भारतोय इतिहास में ऐतिहासिक दिवस

यह ऐतिहासिक नियम है कि गुलामी के साथ-साथ आजादी की लड़ाई भी प्रारम्भ हो जाती है। हो भी तो क्यों नहीं। इसी में तो जीवन है, और तभी तो गुलामों की वेड़ी को तोड़कर व तंत्रता देवी का स्वागत होता रहा है। ठीक़ भारतीय जनता स्ने भी इस ऐतिहासिक नियम का पालन किया। जब से भारतीय जनता गुलामी की वेड़ी में जकड़ी गई थी, तभी से इसे नोड़ फेंकने का प्रयत्न करती रही थी। कभी-कभी इस प्रयत्न ने प्रवल्त कर धारणकर क्रान्ति में क्यान्तिरत होता रहा था। आजादी-प्राप्ति के प्रयत्नों में हमेशा भारतीय जनता एकता का परिचय देती रही थी। परन्तु जब स्वतंत्रता देवी का स्वागत करने का अवसर उसे प्राप्त हुआ; उस समय वह एकता भारतीय समाज से लोप हो चुकी थी। ऐसी परिस्थित में भारतीय स्वतंत्रता का पदार्पण हुआ।

३ जून की ब्रिटिश साम्राज्यवादी घोषणा को कांग्रेस श्रीर लीग ने पूर्णतः स्वीकार किया श्रीर भारतीय सोशलिस्ट पार्टी श्रीखल भारतीय कांग्रेस कमेटी की दिल्ली की बैठक में ३ जून की घोषणा को स्वीकार करने के प्रश्ताव पर तटस्थ रहकर इसका समर्थन एक प्रकार से किया श्रीर भारतीय स्टालिन-वादियों ने पाकिस्तान श्रीर हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय सरकार को पूर्ण सहयोग का श्रश्वासन दिया था। पाकिस्तान श्रीर हिन्दुस्तान में भारतीयों के हाथों में पूर्ण शासन-सत्ता १५ व्यासन को सौंपी जाने वाली थी। दिल्ली में हिन्दुस्तान के प्रधान मन्त्री के छोर पाकिस्तान में भी प्रधान मन्त्री के हाथों में १५ व्यास्त को धूमवाम से शासन को बागडोर थमाई गई।

सदियों की गुनामी की वेड़ी के दूरने की करानाकर भार-तीय जनता उमंग में गोता ग्याने लगी । बड़े-बड़े शहरों में महीनों से स्वतंत्रता देवी की आरती उतारने की तैयारी हो रही थी। कराची छौर दिल्ली में विशेष रूप से लाखों रुपये खर्च करके तैयारी की गई थी। १४-१५ अगस्त की १२ बजे रात को दिल्ली में और कराची में स्वतंत्रता देवी का आगमन हंआ। बड़े-पड़े शहरों में साने श्रीर चाँदी के फाटक खड़े किये गंचे ? खड़े भी क्यों नहीं होते ? पूँजीवादी समाज की विशेषता भी तो यही है कि स्वतंत्रता देवीं का स्वागत दरिद्रता तो कर महीं सकती, यह सीभाग्य लच्मी की ही प्राप्त होता है। ठीक १४ श्रीमंत को भारत में भी दरिद्रता के बजाय लदमी ने बड़ी श्रम-धाम से बड़े-बड़े महलों में स्वतंत्रता देवी का स्वागत किया। भार-तीय पूँजीपितयों ने दिल जोलकर इसके स्वागत में धन खर्च किया, जितना धन स्त्रागत में खर्च किया उसका दंशवाँ यंश भी इसकी प्राप्ति के प्रयत्न में इन्होंने नहीं खर्च किया था । आज खर्च करना स्वामाविक ही था क्योंकि वास्तवं में इनकी ही स्वतंत्रता हुई थी। भारतीय श्रमिक-शोषित-पीड़ित जनता की मोप इयों में इसका ग्वागत करने के लिये धन कहाँ था ? इसके स्वागत से वंचित रहना उनके जीवन की भातिक श्रवस्था की ही भाँग थी। शोवित-पीड़ित जनता के घरों में दिवाली के लिये बी कहाँ था। किरासन टेल भी किलना

सम्भव नहीं था। कोपड़ियों के अन्धकार में ध्मापत में संलग्न होकर स्वतंत्रता देवी की कल्पना उन्होंने अवश्य की।

१५ अगस्त को १२ वजे रात से यूनियन जैक के स्थान में तिरंगा फहराने लगा था। यह वह तिरंगा नहीं था, जिसके नीचे भारतीयों ने आजादी की लड़ाई में खून बहाया था। चर्खे का स्थान चक्र ने ते तिया था। परिवर्तित तिरंगे के नीचे सर्वप्रथम विभाजित भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थानना हुई।

एक श्रोर भारत के बड़े महलों में खुशी का गान हो रहा था खीर स्वतंत्रता के नशे में चूर हो रहे थे। दूसरा छोर साम्प्र-दायिकता के नशे में चूर हो कर भारतीय नरसंहार कर रहे थे। श्राज श्राजादो दिवस के श्रवसर पर स्वतंत्रता के नाम पर साम्प्रदायिकता की वेदी पर लाखों शोपित-पीड़ित जनता विल चढ़ाई गई। हम देख चुके हैं कि पंजाब के पश्चिमी जिलों में ३ जून के पूर्व मुसलमानों के सामृहिक आक्रमण गैरमुस्लिम सम्प्रदायों के अपर होने लगे। हजारों की तादाद में काम आ गये। जून घोषणा के उपरान्त स्वभावतः साम्प्रदायिक युद् कुछ काल के लिये अस्थिगित कर दिया गया था, जिसका कतई ऋर्थ यह नहीं था कि ३ जून की घोपणा के उपरान्त साम्प्रदायिक युद्ध खत्म हो गया। वड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक युद्ध की तैयारी तथा संगठन होने लगा था। ज्योंही १४ अ मत को भारत आजाद हो गया और भारतीयों के हाथों में शासन-सत्ता सौंपी गई, त्योंही पंजाब के सम्प्रदायों ने भी अपने को श्राजाद समफकर एक दूसरे के खून की नदी बहाने लगे। कुछ ग्रंश तक कलकत्ता ने भी पंजाब का अनुकरण करने का २२८ हिन्दुस्तान और पाकिस्तान वा ऐतिहासिक विश्लेषण

प्रयत्न किया था, लेकिन शीघ ही शान्ति हो गई थी। इसके परि ग्राम-स्वरूप लाखों की तदाद में पंजाब के अन्दर मारे गये और करोड़ों की तदाद में बघर-बार के पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में मारे-मारे फिर रहे हैं। न रहने का ठिकाना और न खाने का। आजाद भारत में आज सामाजिक जीवन की ऐसी भौतिक अवस्था हो गई है कि सामाजिक जीवन के विकास सथा अगति अगर असम्भव नहीं तो कठिन अवस्थ हो गई है।

90

उपसंहार

मानव समाज के इतिहास के विश्लेपण से यह स्पष्टतः ज्ञान होता है कि आधुनिक सभ्यता का विकास नवीन प्रान्तर कालीन सभ्यता के उद्य से प्रारम्भ होता है, जिसे जन्म देने का गौरव भारतवर्ष को प्राप्त है। इतना हा नहीं, सोलह शे मदी में सर्वप्रथम भारतवर्ष में सामन्त-समाज के गर्भ में मूंजीवाद का अंकुर उनने और बढ़ने लगा था। परन्तु इसके पूर्व कि यह अण्यासाज सर्वोङ्ग पूर्ण हो सामन्त से इसका गर्भ से जन्म लेगा, विदेशी व्यागरियों के आगमन से इसका गर्भ में ही हत्या कर दिया गया। अतः सवप्रथम पूंजीवादी सभ्यता भारतवर्ष में ही विकसित होने लगता था, लेकिन समय की गति ने इसकी गति को भी परिवर्धित कर दिया और भारत के आधार पर ब्रिटेन में इसका विकास होने लगा। सालहवीं और सबहवीं सदी में भारतवर्ष में पूँजीवाद के अंकुर के गाय-साथ राष्ट्र तथा राष्ट्रीयता भी विकसित होने लगी था। परन्तु अंग्रेज तथा अन्य विदेशी व्यापारियों के भारतवर्ष में आगमन से भारतीय पूँजीवाद

का विकसित होते हुए ऋंकुर मुरमाने लगा और भारतीय व्यापार पूर्णतः ब्रिटिश व्यापारियों के हाथों में चले जाने के साथ-साथ यह एकदम सूख गया। क्योंकि श्रंत्रेजों के हाथों में भारताय व्यापार चले जाने से, भारतीय श्रिमक जनता के श्रम का श्रितिरक्त मूल्य बजाय हिन्दुस्तान में एकत्र हो पूँजी का रूप श्रहण करता, हिन्दुस्तान के बाहर प्रधानतः ब्रिटेन में एकत्र होने लगा, जिसके श्राधार पर सर्वप्रथम पूँजीवाद का विकास ब्रिटेन में हुआ था। इसका ऐतिहासिक परिणाम यह हुआ कि एक श्रोर भारतीय पूँजीवाद तथा विकसित होते हुए का हत्या कर खाला गया श्रीर दूसरी श्रोर ब्रिटिश पूँजीवाद का उदय हुआ, जिसके श्राधार पर संसारव्यापी पूँजीवादी व्यवस्था की स्थापना हुई।

ज्यों-ज्यों भारतीय श्रमिक जनता के श्रम का श्रांतिरक्तं मूल्य भारतवर्ष से बाहर जाकर ब्रिटेन में एकत्र होने लगा, त्यां-त्यों ब्रिटेन पूंजीवाद के उदय की पृष्ट-भूमि वनता गया। समय की गति के साथ भारतवर्ष की श्रमिक जनता के श्रम के श्रांतिरक्त मूल्य का मात्रा तथा ब्रिटेन में श्रागमन की गति भी तीत्र होती गई। श्रोर यह (श्रांतिरक्त मूल्य) कमशः पूँजी में क्यांन्तिरत होता गया, जिसके परिणामस्वरूप पूँजीवाद के विकास की गति कमशः तं व्रतर होती गयी। इसका प्रभाव ब्रिटेन के श्रांथिक जीवन तक ही केवल सीमित नहीं रहा था, ब्रांकि इससे ब्रिटिश सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन भी प्रभावित होने लगा था। पूँजीवाद के उदय तथा विकास के साथ-साथ ब्रिटिश सामन्तवादी ढाँचा भी क्रमशः पूँजीवादी ढाँचे में परिवर्तित होती गई। जिसके श्राधार पर पूँजीवादी

राजनीतिक व्यवस्था व्यवस्थित होने लगी थी। एक और भागतवर्ष की सामन्तवादी राज-शक्ति, अकवर वादशाह के युग में केन्द्रभूत होकर शक्तिशाली हो रही थी, क्रमशः चीए होती गई थी और दूसरी और ब्रिटेन में राज-शक्ति केन्द्रभूत होकर दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होती जाती थी। जिसके परिणाम-स्वरूप भारतवर्ष । ब्रिटेन की गुलामी की जंजीर में वैंथता गया था।

जब अंग्रेज भारतवर्ष में व्यापार करने के लिए आये थे, उस समय भारतवर्ष का अधिकांश एक मजवून केन्द्रीय शासन द्वारा व्यवस्थित हो रहा था। परन्तु जब व्यापार के अतिरिक्त शासन-सत्ता को हस्तान्तरित करने की नीति यह (अंग्रेज) कार्यान्वित करने लगे थे, उस समय तक यह (भारतवर्ष) सामन्तशाही राजाओं के मातहद दुकड़े-दुकड़े हो गया था और सरलतापूर्वक एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे को अपनी गुलाभी की जंजीर में बॉबता ग्या था। ब्रिटिश पूँजीवाद के विकास तथा प्रगति के लिए और ब्रिटिश सरकार के लिए सामन्तवादी दुकड़ों में भारत-विभाजन लाभ-दायक नहीं था। अतः सारे भारत को एक केन्द्रीय शासन के भातहद गूँथने का प्रयास ब्रिटिश सरकार ने किया और एक म जबूत और दृढ़ केन्द्रीय शासन-सत्ता की स्थापना की थी।

एक और केन्द्रीय शासन-सत्ता की स्थापना के कारण भागतीयों में त्वभावतः एकता का भाव उदय तथा विकसित होने लगा। साथ ही साथ बिटिश गुलामी के साथ-साथ बिटिश विरोधी आजादी की लड़ाई भारताया में दिन प्रतिद्न एकता की भायना नो भावतृत और दृद करता गयाथा, जिसकी प्रवल

२३२ हिन्दुस्तान च्योर पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेषण

शिक्ति को अंग्रेज सरकार ने सन् १८४७ ई० की प्रथम आजादी की लड़ाई के अवसर पर अनुभव किया था। दूसरी और विविद्य साम्राज्यवाद की छत्र-छाया में भारतीय पूँजीवाद का अंकुर उनने लना था। इसके साथ-साथ भारतीय राष्ट्र और राष्ट्रीयवाद का भी स्वभावतः उदय होने लगा। भारतीय समाज के विकास तथा प्रगति के साथ यह भी विकसित होता गया, परन्तु यह (भारतीय राष्ट्र और राष्ट्रीयवाद) पूर्णक्ष में विकसित नहीं हो सका था।

उक्त विश्लेपण से यह झात होता है कि भारतीय पूँजी-वाद का स्वभाविक विकान नहीं हो रहा था। ब्रिटिश सामा-ज्यवाद की छत्र-छाया में जन्म लेने के कारण यह (भारतीय पूँजीवाद) अपने उद्य काल से ही विरोध का सामना करते हुए विकित होता रहा था। एक और त्रिटिश केन्द्रीय शासन-सत्ता की स्थापना और इसके विरोध जाजादी की लड़ाई के संचालन से भारतीय जनता की एकता की भागना राष्ट्रीयवाद में रूपांत-रित हो रही थी श्रीर सारतवर्ष श्राधुनिक राष्ट्र में विकक्षित होने लगा था। दसरी और उन राष्ट्रीयनाहा भावनाओं को विक-सित होते देख कर त्रिटिश सरकार ज्याने ज्यस्तित्व के लिये सयभीत होने लगी थी। इसे भंग करने के प्रयास में यह सबधा व्यस्त रहने लगी। इस प्रयास की सफत बनाने में भारत की प्रतिक्रियाबादी शक्तियों तथा राष्ट्राय-सुवारवादी-पूँजीवादी नेरुत्व के सुधार यादी वैवानिक नीति से सर्वथा पर्व्याम सहायता इसे (ब्रिटिश सरकार) प्राप्त होती रही थी। ज्यों-ज्यों भारतीय शोपित-श्रमिक जनता की क्रान्तिकारी शक्तियों के दगाव से ब्रिटिश सरकार भागतीय मध्यम वर्ग के

वार्थों में राजनीतिक सुधार प्रदान करती गई त्यों-त्यों मारतीय शोषित-श्रमिक-जनता के अन्दर फूट पेदा होता गया और क्रमशः उनकी एकता भी भंग होती गई। जब सन् १६४७ ई० के १४ अगस्त को भारनीय शासन-सत्ता भारतीयों के हाथों में सोंपी गयी, उस समय सम्प्रदायिक आधार पर पाकिस्तान और हिन्दुस्तान केवल विभाजित नहीं था, बल्कि इस भीगोलिक विभाजन के अतिरिक्त भारतीय शोपित-श्रमिक जनता भावनाओं में भी विभाजित थी, जो उसकी पूँजीवादी गुलामी और शोषण के विलाफ मुक्ति की लड़ाई के लिये घातक है।

सन् १६४६ ई० से साम्प्रदायिक युद्ध ने सदियों से ब्रिटिश विरोधी व्याजादी के वान्दालन से विकसित भारतीय जनता की एकता को एकद्म भंग कर दिया। इतना ही नहीं आज भारतवर्ष केवल हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में अलग-अलग राज्य की स्थापना की गई है, विनक भारतीय जनता में एक की भावना करम हो गई है और इसका स्थान एक दूसरे सम्प्रदाय के प्रति व्यविश्वास ने पहुण कर लिया है। आज हिन्दुस्तान के अन्दर वास्तविकता यह है कि मुसलमानों के अति गैरमुसल्गानीं का विश्वास कर्तई जाता रहा। यह (गैर-मुसलमान) समफते हैं कि पाकिस्तान की स्थापना में हिन्दुस्तान के मुसल्मानों का बहुत बड़ा हाथ रहा। वे कमा भी हिन्दुस्तान के प्रति ईमानदार नहीं होंगे। श्राज साम्प्रदा-चिकता इप ऋप में विद्यमान हो गही है। पाकिस्तान में भी गैरमुसलमानों के गति गुनलमानों का फांपर र्यावरवास है। चे (मुसलमान) जनवाने हैं कि यह (गेरमुस्लिम) हमेशा पाकिस्तान की स्थापना का निरोध करता रहा था, इसकी २३४ हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेपए

स्थापना के बाद वह कभी भी इसके प्रति ईमानदार हो सकेगा। पाकिस्तान में भी इस प्रकार की भावनात्रों के रूप में साम्प्रदा-विकता विकसित होती जा रही है।

यहाँ हम यह न भूलें कि सन् १६४७ ई० के १४ छा।स्त को क्रान्ति के द्वारा भारतीय शोषित-श्रमिक जनता ने शासन-सत्ता हस्तांतरित नहीं की चिल्क इसकी बढ़ती हुई कान्तिकारी शक्ति को देखकर भारतीय और बिटिश पूँजीवादी वर्ग च्यातुर हो उठा च्यौर भारतीय प्रतिक्रियावादी शक्तियों तथा भारतीय पूँजीवादीवर्ग के साथ गठवन्धन करके समफीता द्वारा ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार ने भारतीय शासन की वागडोर भारतीय पूँजीवादी वर्ग के प्रतिनिधियों के हाथों में सींप दी जो प्रधानतः सारतीय पूँजीवादी तथा मध्यमवर्ग के लिये अधिक लाभदायक है। अभी उनके यह भूत सवार है कि कहीं श्रीमक-शोपित जनता संगठित हो उनके आस्तत्व को ध्यंस न कर दे। यहीं कारण है कि जहाँ कहीं शोपण के खिजाफ शोपित-पीड़ित जनता डट जाती है स्रोर ऋत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करती है, तुरन्त और आम जनता की सहानु-भूति को खत्म करने के हेतु यह नारा बुलन्द करने लगते हैं कि राष्ट्र खतरे में हो गया है। खतरे के समय यह सब राष्ट्रीय सरकार को कमजोर करने का प्रयत्न कर रहे हैं श्रीर राष्ट्र तथा राष्ट्रीय आजादी के लिये ये सब घातक हो रहे हैं। इस प्रकार की बातें दोनों राज्यों में आज चल रही हैं। आज इस प्रकार की भौतिक परिस्थिति से दोनों राज्यों में श्रमिक-शोपित जनता की मुक्ति की लड़ाई गुजर रही है।

यह ठीक है कि सन् १६४७ ई० के १४ द्यास्त को भारतीयशासन-सत्ता भारतीयों के हाथों में सींपी गई है। लेकिन अमिकशोपित-पीड़ित जनता के सामाजिक तथा द्यार्थिक जीवन की
भीतिक द्यवश्या में किसी प्रवार का परिवर्तन नहीं हुआ।
धाज भी उनका जीवन भारतीय पूँजीवादी द्योर ब्रिटिश साम्राज्यवादी शोपण से सुक्त नहीं है। द्याज भी अमिक-शोपित
जनता पूँजीवादी शोपण और गुलामी के द्यन्दर जीवन व्यतीत
करने का बाध्य हो रही है। जीवन की यह द्यवस्था तब तक
कायम रहेगी, जब तक कि पूँजीवाद तथा पूँजीवादी व्यवस्था
ध्वंस न कर दिया जाय और इसक द्यवश्या साम्यवादी वर्गराहत व्यवस्था की स्थापना न हो जाय। यह तब तक सम्भव
नहीं है, जब तक मीजूदा पूँजीवादी व्यवस्था के द्यादर जीवन
से परशान हो बदांश्त करने को तयार न हो द्यार न शोपक
शासक वर्ग ही पुरान हंग से शासन कर सक।

यहाँ हम यह न भूलें कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान साम्प्रदा-यिकता के आधार पर आज दो स्वतंत्र राज्य के रूप में भार-तीय स्वतंत्रता के साथ-साथ स्थापित हुए हैं। इन दोनों राज्यों भें पृंजीपांत पूर्ण राष्ट्रीय राज्य के रूप में इन्हें विकसित करने का भ्यास कर रहा है। अतः आज हम यह स्वीकार करके आगे बहें कि पाकिस्तान और हिन्दुरतान अलग-अलग दो स्वतंत्र पृंजीवादी राज्य के रूप में विद्यमान हैं। यह ठीक है इस भकार के साम्प्रदायिक आधार पर भारतवर्ष का विथा-जन होना भारतीय सामाजिक जीवन के विकास तथा प्रगति के लिये चातक अवश्य रहा है और है। हम पूँजीवादी वर्ग तथा इसके दलाल के जाल में फँसकर वास्तविकता को न भूलें।

२३६ हिन्दुस्तान श्रीर पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेपण

आत इन दोनों पूँ जोवादी राज्यों में यह जोरों से प्रवार् िकया जाता है कि जब तक यह दूसरे को अपने में हजम नहीं कर लेता है, तब तक जीवन की मौतिक आप्या में विशेष उन्नित होने की संभावना नहीं आत होती है। दोनों राज्यों की शोषित-अमिक जनता को यह भूलना नहीं है कि अगर किसी भी तरह अपन ले (पूँ जीवादा वर्ग के द्वारा) पाकिस्तान हिन्दुस्तान में या हिन्दु-तान पाकिस्तान में भिला दिया जाना है, ता यह केवल पूँ जीपिनियों के लिये ही लाभदायक हो गया और इसके द्वारा शोपित-अमिक जनता की गुनामी और शोपण की बेड़ी मजतून होगी. यह इनके सामाजिक और आर्थिक जीवन के विकास के लिये घानक अवश्य होगा। इसके परि-गामस्थळप आज प्रतिक्रियावादी वर्ग के द्वारा शोषित-पीड़ित जनता के बीच पैदा किया हुआ द्वार और भी चौड़ा हो लायगा, जो केवल पूँ जीवादी वर्ग के लिये हो लामदायक होगा।

यह भी हम अस्वीकार नहीं करते हैं कि माम्प्रदाधिक आधार पर भारतवर्ष के जिभाजन के परिगामस्यस्य शोपित-श्रमिक जना। की क्रान्तिकारी शिक्त भी आज विभाजित हो गई है, जो श्रमिक-शोधित-पीड़िन जनना के सामाजिक एवं आधिक जीवन के विकास तथा प्रगति के मार्ग में बड़ा भारी अड़चन पैदा हो गया है। परन्तु इससे पूँजीवादी वर्ग का आस्तित्व कुछ काल के लिये सुरचिन ज्ञान हाने लगा है। मानव समाज के इतिहास के विश्लेषण से यह स्पष्टतः ज्ञान होता है कि पूँजीवाद तथा पूँजीवादी व्यवस्था के कायम रहते हुये शोषित-श्रमिक-गीड़िन जनता के पूँजीवादी शोषण और गुलामी

के जीवन का विकास तथा प्रगति सम्भव नहीं हो सकती है। यह तभी सम्भव हो सकेगी, जब पूँजीवादी तथा पूँजीवादी ज्यवस्था को ध्वंसकर संसारज्यापी साम्यवादी वर्गरहित ज्यवस्था की स्थापना हो।

उक्त बातों का कतई यह अर्थ नहीं है कि संसारव्यापी पूंजीवाद तथा पूंजीवादी व्यवस्था का ध्वंस करने के हेतु ससार भर में एक साथ एक ही समय और एक ही तरह की समाजवादी क्रान्ति होगी। जो ऐसा समस्ता है, वह साम्य-वादी अर्थात् क्रान्तिकारी समाजवादी नहीं है और न वह साम्यवाद के सिद्धानतों का ही जानता है। विभिन्न देशों की भिन्न भौतिक व्यवस्था के व्यतुसार विभिन्न समय, विभिन्न रूप में और विभिन्न प्रवार की होगी। समाजवादी क्रान्त एक बहुत बड़ा सिलसिला है जी एक देश में पूजीबाद तथा पूँजी-वादी व्यवस्था की व्वेसकर पचायती व्यवस्था की स्थापनी होती और इसके बाद दूसरे देश में और दूसरे के बाद तासरे देश में पूँजीबाद तथा पूँजीबादी व्यवस्था के अवशेष पर पंचायती व्यवस्था कायम की जाती है। जो संसारव्यापी भावी साम्यवादी व्यवस्था की नींव होगी। इसके लिये यह श्रावश्यक है कि ज्यों-ज्यों भिन्न देशों में पचायती व्यवस्था स्थापित होती जाये त्यां त्यां पंचायता समाजवादी संब विकसित होता जाय और विश्व पंचायती समाजवादी संघ के रूप में स्थापित हा जाये; जिसके आधार पर संसारव्यापी पूँजीवाद और पूँजीवादी व्यवस्था को ध्वंसकर संसारव्यापी सोम्यवादी वर्गरहित व्यवस्था की स्थापना सम्भव हो सकेगी। अलग-अलग छोटे-छोटे स्वतंत्र राज्यों के श्वस्तित्व इसके २३८ हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का ऐ तेहा सिक विश्लेपण

विकास के मार्ग में बड़ा भारी रोड़ा होगा। आज पूँजीवादी संसार भी ऐसा ही अनुभव कर रहा है और यह प्रयत्न कर रहा है कि अधिक में अधिक पूँजाबादी देतां का एक संयुक्त अजातांत्रिक संघ की स्थापना की जाये।

हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की भौतिक अवस्था की आज यह ऐतिहासिक साँग है कि अपने-अपने यहाँ शोषित-अनिक जनता मीजूरा पूँजी गरी व्यवस्था को ध्वंस करके इसके अवशेष पर समाजवादी पंचायती व्यवस्था शीघ्र से शीघ्र स्थापित करे, त्र्याधार पर माज्यवादी वर्गरहित व्यवस्था बह विकसित का सकेगी। उक्त ऐतिहासिक कार्य की सम्पन्न करने के लिये यह आवश्यक है कि उनके (शोषित-श्रमिक जनता के) अन्दर एकता की भावना हो। एकता की यह भावना पाकिस्तान त्योर हिन्दुस्तान को एक कर देने से नहीं होगी। चगर पूँजी गतियों के चापस के मेल से दोनों एक कर दिया जाता है, इसका स्पष्ट व्यर्थ है इसके द्वारा पूँजीवादी व्यवस्था श्रीर भी मजबूत तथा दृढ़ बनाना और पूँजीबादी शोषण और गुलाभी की जब को मजबूत करना, तिसे शोषित-पीड़ित श्रीमक जनता के लिये सहन करना उसके जीवन के लिये घातक होगा। अतः उधर से एक करने के प्रयता को विफल बनाना शोधित-श्रमिक का ऐतिहासिक कार्य है।

आज शोषित श्रमिक जनता के सामने हिन्दुस्तान श्रोर पाकिस्तान को एक करने का मुख्य सामाजिक प्रश्न नहीं है। बल्कि वाग्तविक प्रश्न उसके सामने श्राज है, हिन्दुस्तान श्रीर पाकिस्तान में शोषित जनता के बीच एकता की भावना पैदा करना, जिसका एकदम श्रभाव श्राज सामाजिक जीवन है।

यह अपर से नहीं पैदा की जा सकती बल्कि अपर से किये गर्ये प्रयत्नों से इसका प्रश्न और भी जटिल हो जायेगा। इसकी सम्भावना केवल नीचे से किये गये प्रयत्नों से ही है। यह पूँची-वादी शोपण और गुलामी के खिलाफ वर्ग संवर्ष के द्वारा उनके सामाजिक जोवन में विकसित होगी। जब सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति के लिये संवर्ष की आर्तिगन कर दमन और भात्याचार के बीच जीवन व्यतीन करने लगेंगे, उस ससय क्रमशः उनके अन्दर एक दूसरे के प्रति फैज़ा हुआ। अधिश्वास दूर होता जायेगा श्रोर एक दूसरे में जीवन-मरण के संघर्ष के द्वारा विश्वास उत्पादन हागा, जा उनकी एकता की भावना का मुख्य आधार होगा। यतः याज सभी प्रगतिशील व्यक्तियों का यह ऐतिहासिक सामाजिक कार्य है कि पाकिस्तान चौर हिन्दुस्तान में श्रमिक-शोवित जनता को वर्ग संवर्ष के आधार पर स्वतंत्र वर्ग संगठन में सङ्गाठतकर उसके वर्ग संघर्ष को संचातित करें ऋौर इसे देशव्यापी वर्ग संवर्ष में विकितन करके समाजवादी क्रान्ति में रूपान्तरित करके पूँजीवाद तथा पूँजीवादी व्यवस्था को ध्वंसकर् इसके अवशेष पर दोनों राज्यों में समाजवादी पंचायती व्यवस्था कायम करें । समाजवादी पंचायती व्यवस्था के अन्दर पूँजीवादी गुलामी और शोषण से रहित सामाजिक तथा आर्थिक जीवन को व्यतीत करने में यह अभिक जनता अनुभव करेगी कि समाज के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन के विकास एवं प्रगति के लिये हिन्दुस्तान श्रीर पाकिस्तान के संयुक्त समाजवादी पंचायतो संघ की स्थापना श्रावश्यक है श्रीर उनके सामूहिक प्रयत्नों के परिणामस्वरूप संयुक्त भारतीय समाजवादी पंचायती संघ की स्थापना हो

२४० हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का ऐतिहासिक विश्लेषण

सकेगी जो निश्व समाजवादी संय ना आधार होगा।

ज्ञाज के सामाजिक जीवन के विश्लेपण से यह स्पष्टतः ज्ञा होता है कि साम्प्रदागिकता के विप ने निम्न-मध्यम तथा बुद्धि-जीवी वर्ग के सामाजिक जीवन को अधिक प्रभावित किया है। आज इनके बीच अभिक अविश्वाम फेना हुआ है क्यौर यह शोपिन-श्रमिक जनना को भी अपने विचारों से प्रभावित करते रहते हैं। इनके बीच सद्भावना पैदा करना निहायत जरूरी है। यह आवश्यक होता है कि पाकिस्तान और हिन्दुरतान में इसके लिये प्रगतिशील शक्तियाँ लहें कि अल्पसंख्यक सम्प्रदाय के किसी भी प्रकार के अधिकार पर अक्रमण न हो। उन्हें भी पूर्ण नागरिक अबि । रनथा धार्मिक त्य। सांस्कृतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो । उनकी भाषा तथा सादित्य की पूर्ण रच्चा की जाये। इस बात की खार विशेष ध्यान देना चाहिये कि उन्हें जीवत दंग से उनके अधिकार के अनुसार नौकरी वगैरह दी जाये। उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो। अगर होता हो तो उसे दूर करने के हेतु जन-आन्दोलन का संचालन फरें। अल्पसंख्या सम्प्रदाय के होने के नाते उनके नागरिक अधिकार के ऊपर किसी प्रकार का अड़बन न श्राने पावे।

